LOK SABHA DEBATES

(Eleventh Session)



(Vol. XLI contains Nos. 31-40)

LOK SABHA SECRETARIAT NEW DELHI

Price: Re. 1.00

CONTENTS

No. 48—Thursdo	ry, Ap	ril 29	, 196	5/Vai	sakha	9, 188	87 (Sa	ka) Columns
Oral Answers to Questions-	_							3020
*Starred Questions Nos. 10		1078	, 108	30 to 1	1082, 1	1085	and	
1086		. ′						. 11 747—85
Written Answers to Question	s 							
Starred Questions Nos.	1079,	1084	and 1	087 to	1 09 6	;		. 11785—92
Unstarred Questions Nos.	2759 1	to 280	06, 28	08 to	2811,	2813	to 28	r8
and 2820 to 2823							•	11 792— 830
Papers laid on the Table								. 11830-31
Estimates Committee -								
Eighty-third Report								. 11831-32
Public Accounts Committee-	<u>.</u> .							
Thirty-eighth Report								. 11832
Committee on Government A		-		•	•		•	1052
Third Report	LISSUITA	nces-	_					
Demands for Excess Grants (Gana	-al\ 1		•	•	•	•	. 11832
Statement presented	Gene	(au), 1	902-0	3				***
Representation of the People	· (Ama	ndma	· ne\ B	;11 7.			•	. 11832
Demands for Grants .	(Ame	name	iii) B	ιμ—μ	uroau	cea		. 11833
Demands for Grants .	•	•	•	•	•	•	•	11833—981, 11984—12006 12010—26
Ministry of Food and Ag	gricult	ure	•	•	•		•	11833—981, 11984—12006, 12010—26
Shri Radhelal Vyas								. 11835—41
Shri Balakrishnan								. 11841-44
Shri Brij Raj Singh								. 1184455
Shri Jena .								. 11855—59
Shri R. S. Tiwary								. 11859-66
Shri Alvares				•				. 11866-72
Shri Reddiar .								. 11873-77
Shri Chandriki								. 11877—83
Shrimati Satyabhama I	Devi							. 11883-86
Shri Narendra Singh I	Mahid	а						. 11887 94
Shri Shashi Ranjan								11894-900
Shri Sumat Prasad			•	•	•			. 11900-06
Shri Vishram Prasad								. 11906—15
Shri Lahtan Chaudhry	,							. 11915—19
*The sign 1 merked shove the name of a Member indicates that the Question								

^{*}The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked or the floor of the house by that Member.

								COLUMNS
	Shrimati Shashank Manjar	i						. 11919—23
	Shri R.G. Dube .							. 11923—26
	Shri D.R. Chavan							. 11926—42
	Dr. L.M. Singhvi .							. 11942-49
	Shri Inder J. Malhotra							. 11950—54
	Shri Jagdev Singh Siddhar	nti						. 11954-59
	Shri Balgovind Verma							. 11959—66
	Shri K.N. Pande .							. 11967—72
	Shri Warior .							. 11972—76
	Shri P. Venkatasubbaiah							. 11977—81
	Dr. M.S. Aney .							. 11984—87
	Shri Maniyangadan .							. 1198893
	Shri Onkar Lal Berwa							. 1199397
	Shri N. N. Patel .							11997-12003
	Shri Gulshan							. 1200306
	Shri K.N. Tiwary .				٠.			. 12010-15
	Shrimati Ganga Devi							. 12015-20
	Shri Shivaji Rao S. Deshi	mukh	٠.				٠.	. 12020—25
Repor	ted Ceuse-fire talks on Ku	tch-Si	nd b	order	•	•	•	. 11981—83

1747

LOK SABHA

Thursday, April 29, 1965/Vaisakha 9, 1887 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[Mr. Speaker in the Chair]
*ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत सहायता सहयोग की बैठक

भी म० ला० द्विषेती :
भी स० वं० सामन्त :
भी प्र० रं० चकवर्ती :
भी सुबोध हंसदा :
भी रामसेवक यादव :
भीमती रेणुका बड़कटकी :
भी प्र० वं० वक्या :
भी यशपाल सिंह :
भी पं० वंकटासुख्या :
भी राम हरल यादव :
भी राम हरल यादव :
भी नारली मनोहर :

क्या विक्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

*1076.

- (क) क्या यह सच है कि 17 मार्च, 1965 को पेरिस में हुई भारत सहायता सह— योग की बैठक में तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रन्तिम वर्ष के लिये भारत की भावश्यकता पर चर्चा हुई थी;
- (ख) यदि हां, तो भारत ने कितनी सहायता मांगी थी भौर सहयोग ने कितनी सहायता देना स्वीकार किया;

(ग) इस बैठक में भाग लेने वाले भारू-

11748

तीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कौन कौन थै;

- (घ) क्या भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये भारत की विदेशी मुद्रा की ग्रावश्यकता भी पेश की थी; ग्रौर
- (ङ) यदि हो तो उसका क्या परिणाम निकला ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भनत) ६ (क) जी, हां।

- (ख) सहायता की कोई निश्चित रकम नहीं मांगी गई थी, लेकिन इतना बता दिया गया था कि भविष्य में हमें जो विभिन्न कार्यक्रम पूरे करने हैं उनके लिए कुल 600 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की ग्रावश्यकता होगी । पेरिस की बैठक में कोई वायदे नहीं किए गए । लेकिन बाद में, 21 तारीख को वाशिगटन में जो बैठक हुई उसमें इन वायदों की घोषणा कर दी गई । संघ (कंसिंशियम) ने कुल मिला कर 1 ग्रदब 2 करोड़ 70 लाख हालर की सहायता देने का वचन दिया है ।
- (ग) भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता वित्त सचिव, श्री एस॰ भूतींलगम थे। प्रति— निधिमण्डल के ग्रन्य सदस्य थे—वित्त मंत्रा— लय के मुख्य भाषिक परामगंदाता श्री भाई॰ जी॰ पटेल, वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सी॰ एस॰ कृष्णमूर्ति भौर युरोपीय मा— थिक समुदाय (यूरोपियन इकोनामिक कम्यु—निटी) में राजदूत श्री के॰ बी॰ लाल।
 - (घ) अपी, नहीं।
 - (ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

भी म० ला० द्विवेदी ! मैं जानना चाहता हूं कि भारत ने ग्रपनी जिन ग्रावश्यकताग्रों के लिए ऋण की प्रार्थना की थी उसकी पूरी रकम क्यों नहीं मिल सकी, ग्रीर क्या भविष्य में उस के मिलने में ग्राशंका, ग्रीर इसके पूरे न होने के क्या कारण है ?

भी य० रा० भगत: जो देने वाला है यह तो उसकी ताकत पर निर्भर करता 'है। वे इतना ही दे सके। और जो रकम मिली है, पिछले साल जो रकम मिली थी यह उससे एक ही मिलियन डालर कम है। इसलिए हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि काफी कम मिली है।

भी म० ला० दिवेबी : मैं यह जानना चाहता हूं कि चौथी योजना के दौरान में प्रतिरक्षा सम्बन्धी आयश्यकताओं का भी क्या इसमें उल्लेख या श्रीर क्या उनके लिए मांग की गयी थी ?

भी ब॰ रा॰ भगत: इसमें चौथी योजना का सवाल नहीं है। प्रतिरक्षा सम्ब-न्धी वातें कनसारिणयम में नहीं लायी जातीं।

Shri S. C. Samanta: May I know whether the foreign exchange that we get through the Aid India Consortium is allotted according to our requirements or whether they have a say in the different projects?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): Broadly, they try to meet our requirements. It is not the projects that are considered by the Aid India Consortium, but policies behind the projects, these are explained to them. I would like to add to what my hon. colleague has said that there is no reason be dissatisfied with the aid promised, though we had outlined that what we would need would be about million dollars. We have taken into account that some of the promises made would spill over to the next year and a commitment made would help the projects.

Shri P. R. Chakraverti: May I know whether a substantial portion of this aid can be used in the form of non-project aid to finance. Imports for maintaining the Indian economy, and if so, what the terms are?

Shri T. T. Krishnamachari: During the last year about 49 per cent of the aid was in the shape of non-project aid. We have been asking for a little enlargement of this sphere. I think that these matters will have to be decided by bilateral talks, and not in a talk in the Consortium.

Shri Subodh Hansda: As I understand, the full requirements of foreign exchange needed by us have not been met by the Consortium. May I know whether this will affect the rest of the period of the Third Five Year Plan?

Shri T. T. Krishnamachari: As I have said, the amount that has been given is more or less the same as last year. There has been a slight difference in regard to the amount given by Germany, but that has been compensated by other sources.

I have indicated that our rough estimate was 1260 million dollars, but some of these are supposed to be commitments which would spill over to the next year. I do not think that our present requirements in the last year of the present Plan would be affected adversely because we do not get all that we wanted.

Shri P. C. Borooah: May I know whether it is a fact that the loans that would be given by the Consortium would be carrying a higher rate of interest than what is chargeable for the IDA loans and if so, why?

Shri T. T. Krishnamachari: Naturally, the International Development Association gives what are called soft loans. The World Bank gives loans which are not soft but which are extended. The loans from the USA have a longer duration. Outside the Consortium, whatever we get from Soviet Russia also bears a lower rate.

of interest. But these loans vary from country to country. Some of the aid promised is rather in the shape of commercial aid. So, it is not possible to ask people who give the loans to conform to the pattern of the IDA loans which are pronouncedly soft loans.

भी यशपाल सिंह : क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बतला सकते हैं कि क्या कोई ऐसा भी देश है जिससे सरकार ने लोन लिया हो श्रीर रिटर्न कर दिया हो ?

श्री ४० रा० भगत: हम हर साल बजट में विश्वातें हैं कि हम इतना रुपया वा— पस कर रहे हैं।

बी यशपाल सिंह : कुल हिसाब बेबाक कर दिया ?

श्री **व**ं रां भगतः यह बेवाक किया जाएना । यह कई सालों में वेबाक होता हैं, एफ साल में नहीं होता ।

Shri P. Venkatasubbalah: Before sanctioning this particular loan by the Consortium, has our performance in respect of utilisation been scrutinised by a Committee? If so, what is our performance in relation to utilisation?

Shri T. T. Krishnamachari: There is no question of scrutiny. We give them a report of our performance in respect of utilisation. I am glad to say that during last year our utilisation has been the best so far.

श्री राम हरका यावव : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो कनसारशियम से रूपया मिलता है इस को कनसारशियम की मर्जी के मुताधिक ही खर्च करना पड़ता है या हिन्दु— स्तान को प्रक्रियार है कि जिस तरह से चाहे अपने काम में लावें ?

श्री व० रा० भगतः । जैसा वित्त मंत्री जी ने बतलाया कुल कितनी राशि प्राजैक्टस् के लिए मिलेगी भीर कितना लोन नान-प्रो-जेक्ट लेना होगा, यह जो देश पैसा देते हैं उन से भ्रापसी वातचीत से तय किया जाता है। कनसारशियम में यह तय नहीं होता।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय: इस कनसार— शियम के कौन-कौन देश सदस्य हैं, भ्रीर कन-सारशियम ने जो लोग दिया है, वह फिस शतं पर दिया है भ्रीर कितने वर्षो बाद भारत सरकार यह लोन भ्रदा करेगी।

श्री क रा० भगत : इस कनसार-शियम के सदस्य हैं : श्रास्ट्रिया, बेलजियम, कनाडा, फांस, जर्मनी, इटली, जापान, नी-दरलैंड, यू० के०, यू० एस० ए०, वर्ष्ड बैंक श्रीर श्राई० डी० ए० ।

Shri Kapur Singh: Is there any substance in the prevailing apprehension amongst intelligent people that our foreign debt liabilities are almost about to cancel out our surplus GNP? If so, is this policy of growing fat by eating your own tail going to be abandoned or going to be persisted in?

Shri B. R. Bhagat: The whole thing is a figment of imagination not borne out by facts.

Shri Warior: Have any substantial changes been made in the terms of repayment of this loan from those loans which we had contracted earlier?

Shri B. R. Bhagat: The exact details of the loans will be worked out when we enter into the agreements in the course of the coming months.

Rural Industries Projects

*1077.

Shri S. C. Samanta;
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shri B. K. Das;
Shri Abdul Ghani Goni:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of Planning be pleased to refer to the reply given to

Starred Question No. 359 on the 4th December, 1964 and state:

- (a) the location of the forty-five rural industries projects in various States;
- (b) whether their annual progress reports have been called for and scrutinised;
- (c) whether some difficulties have been referred to the Rural Industries Planning Committee; and
 - (d) if so, the nature thereof?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) The list of the areas selected for 45 Rural Industries Projects in various States and four Union Territories is placed on the Table of the House. [Placed in Library, See No. LT-4304/65].

- (b) Annual Progress Reports ending March, 1965 have been called for from the States and are expected to be received in the Planning Commission by the end of April, 1965.
- (c) and (d). Since Progress Reports for the year 1934-65 from the States have not been received so far, it is difficult at this stage to indicate the difficulties, or their nature, encountered in the implementation of the programme.
- Shri S. C. Samanta: Each rural industrial project consists of several CD blocks which have their own budget for rural industries. May I know whether there is any conflict between this project and the block development areas?
- Shri B. R. Bhagat: The organisation acts at the field level and sees that there is no such conflict.
- Shri S. C. Samanta: May I know whether, before selecting such projects, due consideration is given to the availability of raw materials and other things? May I know whether political considerations also have a place?

Shri B. R. Bhagat: The list that I have placed on the Table οf House will show that it represents the entire country, and that States selected these areas. All these considerations of availability of raw materials, infra-structure and facilities, concentration of population etc., had all been gone into. Political consideration should notnormally.

भी म० ला० द्विवेदी: श्रभी सामन्त जी के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महीदय ने बतलाया उस सम्बन्ध में मुझे कुछ शंका है इसलिए मुझे यह पूछना है कि यह जो श्रापकी इंडस्ट्रीज का प्रोग्राम देहातों में लगाया जायेगा वहां जो ब्ला-क्स हैं उनके भी उद्योग धन्धे वहां पर चलते हैं, दोनों जगह एक सा कार्याक्रम चलाया है तो उस में जो संघर्ष श्राता है वह कैसे बचाया जाता है ?

श्री बि॰ रा॰ भगतः यह तो क्वेश्चन विलकुल ग्रलहदा है। जहां तक व्लाक्स का ताल्लुक है तो वह तो सारे देण में बने हुए हैं बाकी इस रूरल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट के लिए सारे देण में केवल 45 रथान चुने गये हैं ग्रीर यह देखा गया है कि वे स्थान सब तरह से मुग्नाफिक हों ग्रीर जैसा मैं ने बतलाया कि जो इस के काम करने की कमेटी है, ग्रार्गेनाइजेशन है वह इसको देखती है कि उन तमाम बातों को वहां पर करने में कोई दिक्कत पैदा न हो।

श्री म० ला० हिषेबी: ग्राघ्यक्ष महो— दय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं ग्राया । मैं स्वयं जानता हूं कि मेरे वहां एक मऊरानीपुर नाम का ब्लाक है वहां विकास खण्ड की तरफ से यह उद्योग चलते हैं ग्रीर यह जो रूरल इंड— स्ट्रीज प्राजेक्ट खोले गये हैं तो इससे उन में कोई संघर्ष तो नहीं होगा इसके बारे में मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है ?

भी ब० रा० भगतः । भगर माननीय सदस्य मुझे झलग से इस की सूचना देंगे तो मैं तहक़ीकात करके उसके बारे में उन्हें इत्तिला देद्ंगा।

Shri Subodh Hansda: There are State-level committees for these industrial projects. I would like to know which are the interests represented on these committees.

Shri B. R. Bhagat: It is an officials committee of the Government. There may be some non-officials who known for their interest in social work and other things. They be there.

Shri P. C. Borooah: May I know whether the rural industries opened in the co-operative sector are suffering for want of availability of raw materials, and whether some arrangements are going to be made for making raw materials available to them?

Shri B. R. Bhagat: That There is the industry outside this. general question of shortage of raw materials available to small-scale industries even in the co-operative sector, for which the Minister Industry has said that a committee is looking into it. But in this thing, one of the considerations is that local raw materials should be available, and therefore that question should not arise in a project of this nature.

Shri Surendranath Dwivedy: What is meant by rural industries? there particular industries which will be in the rural areas, or whatever industry that is there in the rural area is called rural industry?

Shri B. R. Bhagat: The scope has been defined. The object of the project is that industries in the areas should be based on local materials and tapping local

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या गांवों में जो साधारण उद्योग धंधे हैं जैसे लकडी का काम, खेती के काम में भाने वाले भौजार, यह लोहा, मिटटी भीर चमडे के जो धंधे हैं उनको उन्नत करने के लिए भीर उनको बढावा देने के लिए क्या सरकार इस योजना में कोई कार्य कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत: सारी योजना तो बहुत ज्यादा विस्तृत है। यह तो जैसा मैंने कहा जिन जिन इलाकों को चना गया है उनमें यह सारे उद्योग धंघे रक्खे गये हैं ताकि उस इलाक़े में जो भ्राटिजंस भीर कैफट्समैन है उनको ग्रधिक काम करने का अवसर मिले लेकिन माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है वह तो बहुत बड़ा ग्रीर विस्तृत सवाल है।

भी जगवेब सिंह सिद्धान्ती : 45 में ही सही लेकिन कीजिये तो ।

श्री ब रा० भगतः वह हो रहा है।

Shri Balakrishnan: May I know whether these industries are started in the cottage industries sector or in the mechanised industries sector?

Shri B. R. Bhagat: As I have not yet got the full reports; We will get the reports and we place them on the Table House.

Shri Shashi Ranjan: In Bihar this project is being run at three places; that is also mentioned in the ment. This project is run there since the last three years or so. know the total expenditure on project in Bihar and the percentage of progress made, and may I also know whether the Government satisfied with the progress made?

Shri B. R. Bhagat: I have answered in the main question that we will get the report.

Shri Shree Narayan Das: May know whether the Planning Commission has itself taken over the administration of these projects, and, if so, why they have not been given to the Industries Department? What are the special circumstances in which the Planning Commission has over this administration?

Shri B. R. Bhagat: The administration has not been taken over by the

11758

Planning Commission. The whole organisation, is that there is a steerlevel in which all other organisations and departments are represented.

भी हुकम चन्द कछ्वायः मैं यह जानना चाहता हं कि यह जो 45 स्थान चुने गये हैं यह किन किन राज्यों में हैं श्रीर क्या इस सम्बन्ध में कुछ राज्य सरकारों से सुझाव स्राये थे कि किस म्राधार पर यह स्थान छाटे जायें ?

ी ब॰ रा॰ भगत: इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें कि सब सूचना दी गई है भौर वह हाउस की टेब्ल पर रख दिया गया है।

Benefits from Planning

*1078. Shri Kapur Singh: Shri P. K. Deo: Shri P. K. Ghosh: Shri P. R. Chakraverti:

Will the Minister of Planning pleased to state:

(a) whether Government's tion has been drawn to the statement of Chief Minister of Maharashtra as reported in the 'Patriot' dated 19th January, 1965 that planning should be so designed that people may start getting benefits after the expiry of five years; and

(b) if so, the reaction of Government vis-a-vis the Fourth Plan?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) Yes, Sir.

(b) In the Memorandum of the Fourth Five Year Plan, which is to serve as a basis for further work on the formulation of the Fourth Plan, due emphasis has been laid on the measures to be adopted to wherever possible benefitsjoutput from the initial years of the Fourth Plan.

Shri Kapur Singh: I want to know whether the Government are prepared to permit the whole question of free economy, and consumer goods, oriented developmental programme versus policies modelled on Russian developmental programmes to be subjected to scrutiny in context of the Indian experience and, if not, why not?

Shri B. R. Bhagat: I do not think this question is related to that.

Shri Kapur Singh: Ιt arises in this connection, Sir. (Interruption).

Mr. Speaker It is a question of much wider policy which cannot be answered.

Shri Ranga: The whole question itself is based on a wider policy.

Mr. Speaker: Shri Ranga may then put a question.

Shri Ranga: We want to know how the benefits are to come to the people. Here is one criticism made by Chief Minister of Maharashtra here is a suggestion made by the hon. Member.

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): We had it verified from the Chief Minister of Maharashtra. He said he was referring to the question of the production of cement. We agree not only that any expenditure during the Plan period should produce results before the end of the Plan but it should also produce results during the Plan period. The present thinking in respect of the production of cement for the fourth Plan is such that assuming that it succeeds, -I hope it would-we will perhaps reach more than half the target by the middle of the fourth Plan. idea is more or less in conformity with the thinking of the Chief Minister of Maharashtra.

Shri Kapur Singh: Are the Government prepared to permit an independent examination of the fundamental question involved here?

Shri T. T. Krishnamachari: If Government submits itself to being scrutinised, being examined, being criticised, being perhaps condemned by this House, I do not think any other independent body is necessary for that purpose.

Shri Ranga: The point is whether they would examine the question.

Shri Kapur Singh: They have wevaded the question.

भी यशपाल सिंह: क्या सरकार यह बतला सकती है कि कैश कोप्स के सिलसिले में अगले साल कितना रुपया खर्च होगा ? कर्माशयल कीप्स के सिलसिले में जो कारखानों में रुपया सगता है वह पांच-छै साल के लिए लगता है ?

श्री ब॰ रा॰ भगत : यह सवाल इसमें कैसे उठ सकता है ?

Shri Sham Lal Saraf: From the experience obtained through the last three Plans, may I know what are the new measures taken to stimulate the Economic growth, in order to achieve quicker and better results and accelerate the results in the fourth Plan, and what are those steps which are introduced?

Shri B. R. Bhagat: Some of them have been indicated in the memorandum on the Fourth Plan. Broadly, the idea is that we must plan in greater detail and in greater depth and we must take certain advance action so that the benefits along with the capacity should accrue in the minimum possible time.

Pensions

•1080. Shri P. R. Chakraverti: Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) whether Government have appointed a study team to go into the procedure and policy governing pensions;
- (b) if so, the personnel of the team and its terms of reference: and
- (c) the date by which the report will be submitted?

The Minister of Planning (Shri. B. R. Bhagat): (a) No. Sir.

(b) and (c). Do not srise.

Shri P. R. Chakraverti: May I know whether the Government has given some broad indications to the study team to probe into this question; if so, what are they?

Shri B. R. Bhagat: I said "No" to part (a) of the Question. Therefore, there is no question of giving any broad indications.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: May I know whether at any stage the attention of the Government has been drawn to the demand of existing pensioners for some kind of relief for them due to rise in prices and all that?

Shri B. R. Bhagat: Yes, Sir; there has been a representation in the past.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: What was the decision taken by the Government on that?

Shri Ranga: Sir, several of these pensioners had also written to me and I think I have addressed the Ministry some time back about this matter. In view of their representation, may I know whether the Government have given their careful consideration or are they considering this matter and would they be prepared to give any kind of hope of some early action and relief to these people in view of the fact that everybody else has been given relief in the light of inflation and rise in prices and these poor people alone are made to suffer?

Mr. Speaker: I would request hon. Members not to enlarge the scope of the question. The question is whether Government have appointed a study team. The second part of it is about the personnel of the team and the third is about the date by which the report of that study team is crepected.

Shri Ranga: The fourth is about the representations made, what action they propose to take on the representations they have received. Mr. Speaker: That fourth is not with me.

Shri Ranga: They have admitted that representations had been received by them. I am asking whether on those representations they would be good enough to take some action.

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): Sir, it is recognised that the cost of living has gone up and people with fixed income are hit badly. That is a fact which is recognised. But the point so far as Government is concerned is that they have to meet the demands of the people who are now in employment. We have done that and an announcement was made on Monday morning, which means that Government have to find additional resources to the tune of about Rs. 27 crores to Rs. 28 crores. The issue from there arises about State Government ployees, about local government entployees, about teachers and so Naturally, the pensioners have also asked. I have no difficulty in saying that we will consider it sympathetically provided the resources are available, but at the present moment the resources are not in sight.

Mr. Speaker: Next Question—Shri Vishwa Nath Pandey—

Shri Nath Pal: Sir, have you passed on to the next Question. Sir, the Government is the biggest employer and we have hundreds of thousands of pensioners.

Mr. Speaker: The supplementaries that were put, I said, were also not relevant to the original question. The question is whether a team has been appointed?

Shri Nath Pai: Sir, you do not know whether my question is relevant or irrelevant because you did not atlow me to put it.

Mr. Speaker: The original question is simply whether a study team has been appointed, who are the personnel and when is the report likely to be submitted.

Shri Nath Pai: I would like to ask the Finance Minister about some social obligations to those who served the State so loyally. As he himself was good enough to admit that there is rise in prices, do not we owe any obligation to these people?

Mr. Speaker: We do, but not in this question.

Shri Nath Pai: But I do wish this to go on record, Sir, that I received a very large number of letters from these people, but we are not allowed to put questions. The pensioners write pathetic letters to us. What are we to do when we are not allowed to ask questions here?

Mr. Speaker: When it is not relevant, how can I allow that?

Shri Nath Pai: On certain matters we need to be more elastic.

Mr. Speaker: How can we do that in this. He may table a separate question.

Vikas Dal

+

Shri Vishwa Nath Panday:
| Shri Yashpal Singh:
| Shri Kapur Singh:
| Dr. Ranen Sen:
| Shri S. M. Banerjee:

Will the Minister of Planning bepleased to state:

- (a) whether Government are considering a scheme to constitute a 'Vikas Dal' to work in villages to push development at the grass-roots; and
- (b) if so, when it is to be constituted on the total amount of cost of such a scheme?

The Minister of Planning (Shri R. R. Bhagat): (a) and (b). Certain suggestions made in connection with such a scheme are being studied in the Planning Commission. No firm proposals have been formulated so far.

ी विश्वनाय पाण्डेय : जिस स्कीम पर प्लानिंग कमीशन ने विचार किया है, क्याके सम्बन्ध में सामुदायिक विकास मन्द्रालय से भी राय ली गई है ?

श्री व॰ रा॰ भगत । उनसे भी बातचीत हुई है।

ी विश्वनाथ पाण्डेय । जब गांवों में ग्राम सेवकों के जरिये विकास-कार्य किया जा रहा है, तो फिर इस बात की क्या ग्राव-श्यकता है कि इस विकास दल को भी कायम किया जाये ग्रीर उस पर विचार किया जाये?

कि रा० भगतः । यह तो एक सलाह
मिली है कि हमारे पढ़े-लिखे नवयुवकों को
प्रशिक्षित करके गांवों में काम करने के लिये
तैयार किया जाये, ताकि वे वहां पर विकास
के कामों को करें। इस सलाह पर विचार हो
रहा है। जैसा कि मैंने प्रभी बताया है, इस
बारे में सामुदायिक विकास मन्त्रालय से भी
बात हो रही है और उसके ग्रलावा शिक्षा
मन्त्रालय से भी बात हो रही है। इस स्कीम पर
विचार करके ग्रगर इसको व्यावहारिक ग्रौर
उचित समझा जायेगा, तो इसको लागू किया
जायेगा।

श्री कापाल सिंह । मारत की विल्लेख कम्युनिटी को किसी दल या रिसर्च की खरूरत नहीं है। प्राज हमारे गांवों में विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि वहां साधन नहीं हैं। बजाये इसके कि उनको साधन विये जायें, उनको नये नयें दल और नई नई एडवाइस दी जा रही है, जिसकी उनको खरूरत नहीं है। क्या सरकार बतायेगी कि कब तक विल्लेजिख को इस प्रकार सैल्फ-सफ़िसेंट किया जायेगा कि वे प्रपना विकास खुद कर सकें?

श्री व॰ रा॰ भगतः । यह तो माननीय सदस्य की ग्रपनी राय है कि बिना ग्रादिमयों के ही गांवों में काम हो जायेगा।

श्री यशपाल सिंह । उन का ज्ञान श्राप से ज्यादा है। Shri Kapur Singh: May I know whether Government are alive to the inherent liability of all Government constituted and oriented institutions to escalate into corruption and negation of local initiative; if so, whether Government propose to examine the question of all such institutions in the light of this observation?

Shri Range: They would not examine it.

Shri B. R. Bhagat: All these liabilities will also be borne in mind.

Dr. Ranen Sen: Is it a fact that when the idea was first mooted, the idea of Vikas Dal, the Government considered the suggestion that these Vikas Dals should be based on the Congress organisations in the villages; if so, may I know what are the reasons behind this suggestion that weighed with the Government?

Shri B. R. Bhagat: The Scheme that the Planning Commission is considering is not based on that.

Pr. Sarojini Mahishi: When there are the existing institutions like the panchayats, the village volunteer force and other institutions, may I know why the Government was compelled to think of this Vikas Dal to add to those institutions?

Shri B. R. Bhagat: They may be complementary to this scheme.

श्री सरक्ष्याच्येयः मैं यह जानना चाहता? हूं कि जो विकास दल गठित किया जा रहा है, क्या उसके सदस्यों को कोई तनस्वाह भी दी जायेगी या उन से विकास का काम मुपल लिया जायेगा।

श्री ब । रा० भगतः श्रभी तो इस पर विचार किया जा रहा है। जब स्कीम मंजूर हो जायेगी, तब देखा जायेगा।

Shri Ranga: He is giving the impression, Sir, as if they have already decided in favour of it and, therefore, he has been giving all these answers in support of it even though

they have not decided whether to have it or not.

Shri B. R. Bhagat: I have never given the impression that they have already been decided upon. I do not know how the hon. Member gets that impression.

Shri Kapur Singh: He has given the impression that the Government are going to decide in a certain way.

Shri B. R. Bhagat: I said that they are under consideration.

Mr. Speaker: What the scheme would be is not known.

श्री युडवीर सिंहः जिस ग्रादमी ने सर-कार को विकास दल स्थापित करने का सुझाव दिया है, क्या उसने कुछ भ्राधार या तर्क सर-कार के सामने उपस्थित करके भ्रपनी बात की पुष्टि कि है कि विकास-खण्ड के सब कर्मचारियों के रहते हुए भी इस विकास दल को स्थापित करने की क्या भ्रावश्यकता या भीचित्य है, जिन को दुष्टि में रख कर सरकार इस सुझाव पर विचार करने जा रही है ?

श्री ब॰ रा॰ भगतः यह सुझाव हमारे पास डिप्टी चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन, के द्वारा ग्राया है। उनके सुझाव में कहा गया है कि हमारे नवयुवकों को प्रशिक्षित श्रीर संगठित करके गांवों में काम करने के लिए तैयार किया जाये, लाकि वे गांवों में रह कर विकास-कार्य कर सकें। भ्रभी हम इस सुझाव पर विचार कर रहे हैं भीर अभी इस पर कोई निश्चित फ़ैसला नहीं हुमा है।

Shri S. Kandappan: I would like to know what is the meaning of this term "Vikas Dal". I would also like to know whether the Government would give some intellgible term to

Mr. Speaker: He has tried to explain what it means.

Shri S. Kandappan: There is no use giving such a vague term.

श्री धर्मेकार लाल बेरवा : क्या यह दल प्रधान मन्त्री ने जो कहा था कि विकास ग्रधि-कारियों से जीपें वापिस ले ली जायेंगी. उस पर भी विचार करेगा. उसके बारे में भी कोई निर्णय करेगा ?

धाष्यक महोदय : श्री हकम चन्द कछ-

श्री हकम चन्द कख्वाद : यह जो विचार चल रहा है इस योजना पर, मान लो कि विचार करने के बाद इसको मान लिया जाए भीर इसको लागू कर दिया जाए तो ऐसे कितने लोगों को इसक अन्दर काम मिलेगा ?

बध्यक महोदय : फैसला तो हो जाने दीजिये पहले। यह तो देख लीजिये कि किस शक्ल में श्राता है सामने ।

श्री हकम अन्य कञ्चवाय । सरकार के सामने कोई लक्ष्य तो होगा ।

धम्यक भहोदयः ग्रभी लक्ष्य बनेगा।

Tridib Kumar Chaudhuri: After the onset of the 1962, the gency in with proval of the Planning Commission, the Ministry of Community Development instituted volunteer schemes all over the country in panchayats. I understand that it has since been dissolved. Is there any idea of reviving it?

Bhagat: Shri B. R. This is The idea. Ministry a separate of Community Development is also associated with this consideration. All these things will be gone into.

> विदेशी मुद्रा भी मबु लियये : डा॰ राम मनोहर लोहिया : भी किशन पटनायक :

क्या क्लि मन्द्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि** :

(क) क्या सरकार ने विदेश जाने वाले भारतीयों को विदेशी मुद्रा दिये जाने के सम्बन्ध में कोई नियम बनाए हैं ;

- (ख) क्या भारतीयों को विदेशी मुद्रा देकर छोटी शत्य चिकित्सा के लिए विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है;
- (ग) क्या विदेशों में छोटी शल्य चिकि-त्साओं के लिये विदेशी मुद्रा मंजूर करते समय साघारण नागरिकों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी० ग्राइ० पी० लोगों) में भेदभाव किया जाता है; और
 - (घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्री (भी व० रा० भगत) : (क) जी, हां।

- (ख) डाक्टरी इलाज के लिये विदेशी मुद्रा, सम्बद्ध राज्य के प्रशासकीय चिकित्सा प्रधिकारी (एडिमिनिस्ट्रेटिव मैडीकल प्राफिसर) द्वारा इस प्राशय का डाक्टरी प्रमाण-पन्न पेश किये जाने पर दी जाती है कि इस तरह का इलाज या तो भारत में हो नहीं सकता या भारत में अच्छे से प्रच्छा इलाज होने पर भी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और रोगी के स्वास्थ्य के हित में यह जरूरी है कि उसका इलाज विदेश में कराया जाय।
 - (ग) जी, नहीं।
 - (घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

श्री मणु लिमये: घांख की शस्त्र किया के लिए हाल ही में राष्ट्रपति जी ब्रिटेन गये थे। मैं जानना चाहता हूं....

Shri Raghunath Singh: Sir, I rise on a point of order. Can any question be asked about the President? (Interruptions).

बी मचु लिसये :: हल्ला ये बार बार करते हैं, इसका क्या मतलब है ? ग्रध्यक्ष महोदय, इनको जरा कुछ कहिये।

अध्यक्त महोदयः उनको मैं कह रहा हूं। श्री मधु लिमये : यही तमाशा ये हर रोज करते हैं।

श्री किशान पटनायक : ये कार्रवाई में बाबा डाल रहे हैं।

श्रम्यक्ष महोवय : मैं कहूंगा कि ग्राप राष्ट्रपति जी के सम्बन्ध में सवाल न पूछें।

श्री मधु लिमये ः भेरा सवाल सुन लीजिये। उसके बाद ग्रगर इजाजत नहीं देते हैं तो बात दूसरी है।

ध्ययक महोदय ः राष्ट्रपति जी के सम्बन्ध में भ्राप से मैं कह रहा हूं कि श्राप सवाल न पूछें।

श्री मणु लिम गः यह श्राप कैसे कह सकते हैं, यह मुझे जरा समझाइये। किस संविधान की धारा के अन्दर या नियम के अन्दर श्राप यह कह रहे हैं। इसको हमें आप समझा दीजिये।

प्राच्यक्त महोदय: मैं समझा सकता हूं। अब तक ऐसा होता रहा है कि राष्ट्रपति जी की जिस में कोई नुक्ताचीनी आए, उसको हम यहां ले नहीं सकते हैं....

भी मथु लिमये : कहां नुक्ताचीनी कर रहा हूं। कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जानकारी हासिल करना चाहता हूं। नुक्ताचीनी धगर मैं करूं तो आप इजाजत न दें।

बार्यक महोदयः जब उनको लायेंगे दर्म्यान में तो जरूर....

श्री मधु लिमये : उस वक्त घाप मुझ को रोक दीजिये। घगर मैं कोई नुक्ताचीनी का ऐसा शब्द कह देता हूं तो घाप मुझे नियमित कीजिये।

ब्रध्यक्ष महोदय : प्रच्छा कहिये, क्या सवाल करना चाहते हैं।

11770

श्री मध् लिमये : प्रश्न यह है कि शस्त्र किया के लिए हाल ही में राष्ट्रपति जी ब्रिटेन गये थे...

एक माननीय सदस्य : शल्य ऋया।

श्री मध् लिरुये : मोतिबिन्दु की शस्त्र किया ठीक शब्द है। इस यात्रा के लिए कितनी विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक की श्रोर से या वित्त मंत्रालय की ग्रोर से राष्ट्रपति जी को दी गई थी?

श्री भागवत झा आजाद: यह सवाल नहीं किया जा सकता है।

भध्यक्ष महोदय : कोई इस में ऐतराज की बात नहीं है। इसके बारे में इनफार्मेशन देदी जाए।

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Sir, I rise on a point of order.... (Interruptions). Will I be allowed to make my submission on the point of order?

श्रध्यक्ष महोदय : इस में क्या प्वाइंट ग्राफ मार्डर है?

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: My point of order arises out of this. The expenditure incurred on Rashtrapati Bhavan and the President's establishment is supposed to be a charge on the Consolidated Fund of India. As it is of the nature of a charge on the Consolidated Fund of India, itis not subject to the vote of this House.

Shri Harl Vishnu Kamath: This is not being voted.

Mr. Speaker: I have heard him.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Any question which tends to ask for information of a nature of expenditure which is a charge on the Consolidated Fund of India is ultra vires.

भी मधु लिसये : ये कुछ नहीं जानते

Shrimati Subhadra Joshi: May I make a submission? I would just like to say that if no criticism is made and

no aspersions are meant; but if it is just to ask for information, it should be allowed.

Shri Hari Vishnu Kamath: The Speaker has allowed it.

Mr. Speaker: The point of order that has been raised is quite a distinct one. That does not affect this. We are not voting on the Demands that are to be given for his Secretariat or for his own expenses. This is a different thing. What amount of foreign exchange was given-only this information is asked for.

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): The expenditure in regard to the President's stay in London has been incurred by the Indian High Commission. We have not got any details yet of what expenditure has been incurred. case of the President it is not a question of granting foreign exchange, the Indian High Commission is asked to bear the expenditure. We have not got the details yet.

Shri Kapur Singh: Will the hon. Minister gather this information and then pass it on to the House?

श्री मध् लिमये : मंत्री महोदय ने प्रपने बयान में कहा या कि पहले हम इस बात की जानकारी हासिल करते हैं कि क्या ऐसी शस्त्र किया भारत में हो सकती है या नहीं भीर उसके बाद ग्रगर इस बात का पता चलता है कि शस्त्र किया तो हो सकती है लेकिन ठीक तरह से नहीं हो सकती है तो उसके बाद हम इजाजत देते हैं। मैं जानना चाहता हं कि राष्ट्रपति जी पर जो शस्त्र किया भ्रभी ब्रिटेन में हुई है उसके बारे में भी कोई इस तरह की. जानकारी पहले हासिल की गई थी या नहीं की गई थी?

Shri T. T. Krishnamachari: It is perfectly clear, I think, it is better to answer the question than take shelter under the fact that we should not discuss the President. An operation that was done for the President in regard to one eye was not successful; therefore there was a considerable risk in regard to the operation of the other eye because the infection spread to the other eye. Therefore it was decided that this operation has to be done under circumstances where any possible risk could be avoided. That is why the President was advised to undertake the journey to London and get the operation done. I have no doubt that the House will feel gratified that the President has fully recovered.

डा॰ राम मनोहर लोहिया: क्या लंदन क्लिनिक जोकि दुनिया की शायद सब से खर्चीली क्लिनिक समझी जाती है नई ग्रांख लगाने में यहां के ग्रस्पतालों से ग्रच्छी है ग्रौर क्या सरकार के पास हिन्दुस्तान के डाक्टरों ने एक योजना भेजी है कि उनकी मदद की जाए तो दस बरस के ग्रन्दर ग्रन्दर हिन्दुस्तान को वे दुनिया का सब से ग्रच्छा देश बना सकते हैं ग्रांख के इलाज के बारे में?

Shri T. T. Krishnamacharl: I am not aware of any such offer having been made.

डा॰ राम मनोहर लोहिया: ग्राप से मैं कहूंगा, उन से मुझे कुछ नहीं कहना है।

ग्रष्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इस कं मेरे पास कोई इत्तिला नहीं है कि कोई इस तरह की योजना डाक्टरों....

डा॰ राम म ोहर लोहिया । लंदन क्लि-र्वनिक वाली बात ?

ग्रम्यक महोवय : वह बात कैसे पैदा होती है ? ग्रगर डाक्टरों ने यहां कहा कि हम

डा॰ राम मनोहर लोहिया: वह पहली बात थी। खर्चीली है या नहीं, इसके बारे में उनको क्या कहना है। मैंने पहले यह नहीं कहा कि राष्ट्रपति जी वहां गये थे।

अध्यक्ष महोदय: ग्रापको सवाल की इजाजत दे दी गई थी, उसका जवाब भी भा गया श्राप भव मुझे भागे जाने दीजिये। श्री किशन पटनायक : क्या यह सही है कि सरकार ने जो सफाई दी है कि हिन्दुस्तान में उस किस्म की शस्य किया हो नहीं सकती थी उस पर शिकायत कई डाक्टरों ने भेजी है यह कह कर कि ऐसी सफाई देना हिन्दुस्तानी डाक्टरों के लिए भपमानजनक इसलिए है कि यहां के डाक्टर भी ऐसी शस्य किया कर सकते हैं?

Shri T. T. Krishnamachari: No insult was meant to any eminent doctor in India. I have mentioned the circumstances under which the journey had to be undertaken by the President and I do not think I have anything to add to that.

Mr. Speaker: Have any doctors written to the Minister that they could have done it?

Shri T. T. Krishnamachari: As I said, the peculiar circumstances were that the operation that was done in regard to the other eye had caused complications. Therefore that had to be avoided.

श्री किशन पटनायक । जवाब ठीक तरह से नहीं दिया जा रहा है। सवाल यह था कि शिकायत श्राई थी या नहीं श्राई थी। इसका जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया है। इसका जवाब उनको देना चाहिये।

श्री रामसेवक यादव : घ्रध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो साफ़ है धौर घाप ने भी इस प्रश्न को साफ़ समझते हुए मंत्री महोदय से जानकारी मांगी। लेकिन उस जानकारी को न दे कर मंत्री महोदय कुछ भौर बातें कहते हैं।

ग्रध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे इस लिये ऐसा किया गया।

श्री हुकन चन्द कड़वाय : कोई शिकायत बाई है या नहीं। खतरा मोल लेने की बात नहीं है। वह जानना चाहते हैं कि ऐसी कोई शिकायत भाई है या नहीं।

Shri T. T. Krishnamachari: I have no personal knowledge of it.

श्री हुकम चन्द कछ बाय ! मैं यह चाहता हूं कि सामान्य तौर पर श्रभी तक इलाजों के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी है ग्रौर कितने लोगों को दी है।

्ष्यक्ष महोदय: सामान्य तौर पर किन लोगों को दी है, ऐसी कोई इन्फार्मेशन है क्या।

श्री हुकम चन्द कछवायः लोगों के लिये नहीं।

ग्रम्पक्ष महोदय : ग्रांखों के इलाज के लिये सामान्य तौर पर कितना दिया गया है।

श्री ब॰ रा॰ भगतः इस की तफसील के लिये सूचना चाहिये।

Dr. Sarojini Mahishi: I am resricting my question to part (a) of this Question. May I know whether any discrimination is made in allowing foreign exchange between an ordinary citizen going for Haj and a V.I.P. going for Haj? For example, the amount allowed to Sheikh Abdullah in this matter....

Mr. Speaker: He did not go for an eye operation. Next Question.

Shri Kapur Singh: Sir, before we pass on to the next Question, will you permit us to put on record that in whatever questions have been put here there has been no intention whatsoever of importing any suggestion that we took any exception to the arrangements that were made in connection with the eye operation of our President.

India's Credit to Foreign Countries.

Shri Raghunath Singh:
Shri P. C. Borocah:
Shri Madhu Limaye:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Tula Ram:
*1085. Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Murli Manchar:
Shri Ram Harkh Yaday:
Shri Koya:
Shri Brij Basi Lal:
Shri Kanakasabai:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) whether Government have decided to provide some credit to Nepal, Ceylon and Sudan in order to assist them in setting up industrial units;
- (b) if so, the amount of credit to each country; and
- (c) the particulars of the projects to be financed therewith?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) Yes, Sir.

- (b) The amount is Rs. 1 crore for Nepal and Rs. 5 crores each for Sudan and Ceylon.
- (c) A formal loan agreement was signed with the Royal Nepalese Government, providing a credit of Rs. 1 crore on 29th September, 1964. The discussions with the Government of Ceylon and the Government of Sudan will be taken up shortly to finalise the credit arrangements.

भी रचुनाच सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि यह जो रुपया दिया गया है क्या वह किसी प्लेन के लिये दिया गया है, भौर जो रुपया दिया जायेगा, वह काइन्ड में दिया जायेगा या कैंग में दिया जायगा।

श्री वि ए। भगतः : ग्रभी तक तो कोई रुपया नहीं दिया गया है । लेकिन ग्रागे जो दिया जायेगा उस से यहां से कैपिटला इक्विपमेंद्रस भेजे जायेंगे । श्री रचुनाच सिंह: यह रुपया किसी योजना के लिये दिया जायेगा या किसी श्रीर काम के लिये दिया जायेगा।

श्री **व**० रा० भगत: यह उन देशों में इंडस्ट्रीज की स्थापना के लिये या उद्योगों को प्रोत्साहन देने के कामों के लिये दिया जायेगा। जो स्कीम श्रायेगी उस के मुताबिक होगा।

Shri P. C. Borocah: May I know whether it is a fact that under the concentrated scheme Indian collaborators will be allowed to participate in the capital structure of industrial units in these countries and also in the supply of capital goods, technical knowhow, etc. and, if so, what are the basic terms which have been laid down by the Government.

Shri B. R. Bhagat: As I said, the agreement has been signed with Nepalese Government. But no formal proposal, or scheme, has come. All this will be borne in mind when an individual scheme comes. If the Nepalese nationals want that in addition to this, they want some equity participation, it will depend in what form the proposals come.

श्री विश्वनाथ पाण्डेय: जो धन नैपाल, सूडान श्रीर लंका को देने का सरकार विचार कर रही है उद्योगों की स्थापना के लिये, उस के सम्बन्ध में उन सरकारों ने भारत सरकार से प्रार्थना की थी या कि भारत सरकार पृपने से दे रही है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इस के पहले क्या इन देशों को श्रीद्योगीकरण करने के लिये सरकार ने कुछ श्रीर सहायता दी है।

श्रां ब॰ रा॰ भगतः यह तो न्नापस की बात बीत के हिसाब से चलता है, भौर जैसा माननीय सदस्य को मालूम होगा भन्तर्राष्ट्रीय ग्राधिक सहयोग में देश एक दूसरे की मदद करते हैं। भारत दूसरों की मदद करता है ग्रीर दूसरों से मदद लेता है। भगर हम ऐसी स्थित में हैं कि पास पड़ीस

के देश को नदद दे सकें तो हमारी सदा यह इच्छा रहती है कि हम उन्हें मदद करें। इसी विश्वास के साथ यह स्कीम चलती है।

श्री राम हरल यादव: मैं जानना चाहता हूं कि जो कर्जा दिया जा रहा है, कोसी प्रोजैक्ट और गंडक प्रोजैक्ट उस के ग्रलावा हैं या उसी में शामिल हैं।

श्री **व**० रा० भगत: कोसी ग्रीर गंडक का सवाल ग्रलग है। यह वहां उद्योगों की स्थापना के लिये है।

भी भागवत का भाजाद : मैं जानना चाहता हूं कि शतों में नया यह भी शतें है कि उन का स बन्ध योजना विशेष से होगा ग्रीर उन के लिये भारतीय तकनीकी पर्सोनल भी जायेंगे या यह कर्ज मुक्त है भीर वे जिस प्रकार से ग्रीर जहां चाहें खर्च कर सकते हैं। या उस कर्जे से जो सामान भारत में प्राप्त है वह उन को भेजा जायेगा।

श्री **प० रा० भगत** : यह कर्ज उन चीजों को खरीदने के लिये हैं जो यहां से सामान भेजा जायेगा, खास कर कैंपिटल इक्विपमेंट । ग्रगर उस को लगाने के लिये वह सहायता मांगेंगे तो वह भी दी जायेगी ।

श्री सरब् पाण्डेय: श्रभी मंत्री जी ने बतलाया कि जो देश पास पड़ौस के हिन्दुस्तान से पिछड़े हुए हैं

श्री व॰ रा॰ वगतः मैं ने पिछड़े हुए नहीं कहा ।

श्री सरक्ष्य पाण्डेय: मैं जानना चाहता हूं कि जब ग्रपना देश इतना पिछड़ा हुग्रा है तो ग्रपनी तरक्की न कर के पास पड़ौस के देशों की तरक्की करने की चिन्ता हमें ज्यादा क्यों रहती. है।

श्री रामेध्यरामण्य : मैं जानना चाहत ा है कि नैपाल और दूसरे पड़ौसी देशों क है जब भारत ऋण देरहा है तो उन देशों वे पहले हम से कितना ऋण लिया है भीर भारत अर्घ के ऊपर कितना विदेशी ऋण है?

श्री ब॰ रा॰ भगत: इस की मुझे सूचना मिले तो मैं बतला सकता हूं।

Shri P. Venkatasubbaiah: It is very creditable on the part of Government to have come to the aid of our neighbouring countries, as a gesture of good-will. May I know whether the same aid will be extended to the other African countries which may enter into a contract with us for purchase of our machinery etc.?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): Including Pakistan.

Shri B. R. Bhagat: In addition to this, we have some arrangement with Uganda, Kenya, Ghana and Nigeria etc.

श्री शिवाजी राव शं० वेशमुख: क्या मैं जान सकता हूं कि विदेश विकास के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई धनराशि संरक्षित रक्खी गई थी या नहीं। ग्रगर नहीं तो यह ज्यय किस धन में से होता है।

श्री बि॰ रा॰ भगतः यह तो मुझे ज्ञात नहीं है कि तीसरी पंजवर्षीय योजना में कितनी राशि रक्खी गई थी।

श्री हुकम चन्द कछ राय : मैं जानना चाहता हूं कि हम विदेशों को जो ऋण देते हैं उस के लिये हम ने क्या कोई शर्ते रक्खी हैं। उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है या नहीं भौर ग्रगर मिलता है तो कितना ?

श्री ब॰ रा॰ भगत: नेपाल से जो तय हुआ है वह पन्द्रह साल के लिये 3 प्रतिशत इंटरेस्ट है। बाकी दूसरे देशों से, जैसा मैं ने कहा, प्रभी एपीमेंट हुआ नहीं है। इस लिये उन के बारे में बतलाना मुश्किल है।

श्री बज्ञपाल सिंह: इसी ग्रादरणीय सदन में माननीय वित्त मंत्री जी ने बतलाया श्रा पिछले वर्षे कि पाकिस्तान की तरफ हमारा 9 ग्ररब रु० कर्ज है। मैं जानना चाहता हूं कि उस 9 ग्ररब रु० में से कितना रुपया बाकी है ग्रीर कितना वसूल हो चुका है।

ग्रध्यक्ष महोवय : वह ग्रलग सवाल है।

श्रीयशपाल सिंह: इस में लिखा हुग्रा है। इस की हैडिंग में फारेन लिखा हुग्रा है। विदेशी ऋण।

भ्रध्यक्ष महोदय: वह ऋण दिया नहीं। भ्रगर कोई जबर्दस्ती ले कर बैठ जाये तो क्या किया जाये।

श्री यशपाल सिंह : वापस लिया है या नहीं ।

श्री हुकम अन्द कछ आय: क्या हम ने उन से जबर्दस्ती वसूल किया है।

Shri Heda: May I know the procedure adopted when an Indian industrialist exports machinery from India to those countries for setting up industries there? May I know whether the price of that machinery is reimbursed to him out of this loan or whether that amount is kept in credit in his name and he is paid that amount only when the money comes back or is returned from those countries?

Shri B. R. Bhagat: This is not a supplier's credit; this is a government to government credit. So all those questions do not arise.

Shri Nath Pai: The aid-receiving countries, though needing aid, are often very sensitive and also suspicious, as we know from our own experience, and often aid is mistaken as a form of extension of influence, as has been shown by the way Burma and Indonesia rejected U.S. aid. May we know whether the conditions under which aid is being given are such as to ensure that these receiving countries feel that we are interested in their development, not in extending Indian influence or helping a few

Indian capitalists? Are these precautions being taken by the Finance Minister?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): That objective is always kept in view.

Demolition of Jluggis

*1086. Shri Maurya: Will the Minister of Works and Housing be pleased to state:

- (a) whether two thousand jhuggis and jhoparies have been demolished since 1st April, 1965 in localities of Sarai Rohilla, Bhooli Bhatiyari and Wazirpura in Delhi;
- (b) whether it is a fact that some jhuggis and jhoparies were burnt by the demolishing squad and on resistance ladies and children were lathicharged;
- (c) whether the Prime Minister had given an assurance to the Republican leaders that the hut dwellers upto 31st December, 1962 will be provided alternate suitable site before demolition: and
- (d) whether it is a fact that jhuggis and Jhoparies referred to in part (a) above were in existence before December, 1962?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) No. The number of huts demolished was about 680.

- (b) No.
- (c) No. Under the Jhuggis and Jhoparies Removal Scheme, only those squatters are eligible for allotment of alternative accommodation who started squatting on Government and public lands prior to the 31st July, 1960. However, since eligible and ineligible squatters are inter-mixed in most of the localities Government is providing camping sites of 25 sq. yards even to ineligible squatters. These squatters are, however, not entitled to get plots of 80 sq. yards or built tenements.
- (d) The jhuggis and jhoparis in Serai Hohilla and Bhooli Bhatiyari had 496(Ai) LSD—2.

been constructed recently. Those in Wazirpur, were in existence before December 1962, but none of their occupants had census slips in proof of their occupation of the site prior to July, 1960.

श्री मीर्थ: श्रीमान्, ये झुग्गी झौंपड़ी निराकरण योजना के नोटिस जो झुग्गी झौंपड़ियों में रहते हैं उन को दे दिए जाते हैं, और तुरन्त ही झुग्गी झौंपड़ियों को तोड़ा जाता है, जैसा कि वजीराबाद में हुआ जहां सन् 1946 से लोग रह रहेथे। इन को तोड़ा ही नहीं जाता, बिल्क कहीं कहीं आग लगाने के भी सबूत मिले हैं, और बच्चों और औरतों को मारा पीटा जाता है। यह नोटिस मेरे हाथ में है। मैं इस को पढ़ कर नहीं सुनाना जाहता कि इस में क्या शर्तें दी गयी हैं। पर उन को खाना बदोश बना कर ट्रांजिट कैम्प्स में रख्ना जाता है, वहां पर ...

ब्रध्यक्ष महोदय : ग्राप का सवाल क्या है ?

श्री मौर्यं : मैं यह कहना चाहता हूं कि जो झुग्गी झौंपड़ियां तोड़ी जाती हैं उन के लिए क्या मंत्री महोदय यह व्यवस्था करेंगे कि एक विशेष समय दिया जाए, और उस के बाद में उन को ट्रांजिट कैम्प्स में न रक्खा जाए बल्कि परमानेंटली उन को 80 गज का प्लाट म्नलाट कर दिया जाए । प्रधान मंत्री जी ने हम से ऐसा वायदा किया था ।

श्री मेहर चन्द खन्ता : जहाँ तक प्रधान मंत्री के बायदे की बात है, वह सूचना गलत है। जहां तक झुग्गियों का सवाल है, मैं यह कह सकता हूं कि इस झुग्गी झौंपड़ी स्कीम को हम हमदर्दी से चला रहे हैं। इन लोगों का..

श्री मौर्ष: गलत बयानी मत करिये।

श्री नेहर चन्द सन्नाः मैं दिल्ली का रहने वाला ज्यादा जानता हूं या माननीय सदस्य जो ध्रमीगढ़ के रहने वाले हैं ज्यादा जानते हैं।

हम बड़ी हमददीं से इस तमाम स्कीम को चला रहे हैं। करीब 60 हजार फैमिलीज हैं। इन के लिए मैं जमींदारों से जमीन एक्बायर कर रहा हं भ्रीर इन की 25 गर्ज भीर 80 गज के प्लाट दे रहा हं, भीर फिर भी हम से भ्राप नाराज हो रहे हैं।

Oral Answers

श्री मौर्य : राम नगर, मुलतानी ढ़ांढ़ा, नाली नबी करीम, पहाड़ गंज, में करीब दस हजार धर बने हुए हैं, 14-15 साल से। क्या उन को इस तरह के नोटिस दिए गए कि ग्राप इसका हरजाना दीजिए। वहां पर पुलिस भाती है, लूटमार कर के चली जाती है, वहां पर तीस हजार से पचास हजार तक के नोटिस लोगों को हरजाने के दिए गए हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना जब तक किसी खास कालीनी के मुताल्लिक सवाल न किया जाए जवाब देना मुश्किल है। श्राज मेरी हाजत यह है कि झुग्गी झोंपड़ी वाले मुझे मजब्र कर रहे हैं कि उन्हें जल्दी उठाया जाए ताकि वह नजदीक जा सकें फ्रीर उन को जमीन मिले। जो माननीय सदस्य कहते हैं. वह मेरा तजरबा नहीं है।

श्री मौर्य: मेरी बात का जवाब नहीं ध्राया । मेरे पास नोटिस मौजूद है कि पहाड़गंज के एरिया में दस हजार ग्रादिमयों को तीस हजार से पचास हजार तक का हरजाना देने के लिए नोटिस दिए गए हैं। इन को खाना-बदोश बना कर हटाया जा रहा है। सिपाही म्राकर उन का माल लुट ले जाते हैं।

ग्रध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि यह दुरुस्त नहीं है।

श्री मौर्य: क्या इस की रोक थाम की जाएगी ?

म्रध्यक्ष महोदय: ग्राप बैठ जाइए।

Shri Shiv Charan Gupta: I want to know how many families have been provided alternative accommodation in the Jhuggi Jhompri Scheme so far, and out of that, how many on 80 square yards and how many on 25 square yards, and in the 25 square

yards how many are ineligible.

Shri Mehr Chand Khanna: Speaking from memory, the number of plots that we have developed of 25 square yards is somewhere in the neighbourhood of 15,000. Similarly, we have developed 4,000 plots of 80 square yards. We have also got three to four thousand tenements under construction. '

My difficulty today is this, that when we remove a certain sector, there are eligibles and ineligibles, and unless I remove the whole lot of them, the problem remains as before. So, we are providing accommodation even to those who are ineligible, but we do not want to put them on a par with those who are eligible, because in that way the whole of Delhi will become a squatters' paradise

The number of families on 80 square yards is three to four thousand, and on 25 square yards about 15,000.

Shri Ranga: In view of the fact that Government have themselves decided in favour of allotting plcts of up to 80 square yards, why is it that they want to allot them in the beginning 25 square yards, encourage them to put up their jhaggis again, and afterwards to shift them once again to another place? That is causing them too much trouble. First their jhuggis are being removed, again on 25 equare yards plots their jhuggis would be put up, and a third time they would be displaced again. Cannot something be done to avoid this?

Shri Mehr Chand Khanna: There is some force in what the hon. Member has said. My problem today is that I have to find nearly 20,000 acres of land. That land has to be acquired, that land has to be developed. the meanwhile, this problem is going on multiplying. So, what we are doing today is this. An average jhuggi dweller in Delhi has not got more than 10 to 12 square yards. We are giving them 25 square yards. But in those areas, we are also making arrangements to ultimately convert three plots into one, and make it into 80 square yards. If I wait today for developing plots of 80 square yards, the time factor would be so great and the problem will become so extensive that it will entirely go out of control.

श्री हुकम चन्द कछवाय: मंत्री महोदय ने कहा कि जो लोग सन् 1960 के बाद के हैं उन को उजाड़ने का इन्तिजाम सरकार कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के सन् 1962 की वोटर्स लिस्ट में नाम हैं उन को क्या सरकार मकान बनाने के लिए लोन देगी या उन के लिए आठ आठ और नौ नौ मंजला महान बना कर उनको उनमें बसायेगी?

भी मेहर चन्य लगा: जहां तक उजाड़ने का ताल्लुक है मैं ग्रर्ज करना चाहता हूं कि कुछ ऐसी ग्रादत पैदा हो गयी है कि जो ग्रच्छा काम भी किया जाए उसे बुरा कहा जाए । दूसरी चीज रह है कि मैं ने कहा कि हम इन लोगों को बसाने जा रहे हैं ग्रीर बसाने के मामले में वे लोग हमारे साथ हैं। तीसरी मेरी दिक्कत यह है कि जहां से ग्रानरेबिल मेम्बर ग्राते हैं उन की कोशिश यही है कि वह तमाम इलाका खाली हो जाए ग्रीर वहा के तमाम लोग दिल्ली में ग्राते जायें।

Shrimati Renu Chakravartty: What kind of answer is this?

श्री हुकम चन्द कछ्वाय: मैं ने पूछां था कि क्या उन को सरकार मकान बनाने के लिए कर्जा देने का विचार कर रही है, या उन के लिए भाठ भाठ नौ नौ मंजिला मकान बना कर उन को उन में बसाना चाहती है ?

श्री मेहर चन्द खन्नाः हम कोई लोन नहीं देंगे। जो प्लाट भी दिए जा रहे हैं उन पर तीन या चार हजार पर फैमिली खर्च होगा।

श्री हुकम चन्द कछ श्रायः सरकार उनको ब्राठ ब्राठ ब्रीर नौनौ मंजिल मकान बना करक्या उनमें बसाएगी? **प्रध्यक्ष महोदय** : वह लोन देने को ही मना करते हैं, तो मकान बनाने का सवाल कैसे उठ सकता है ।

Shri Nath Pai: Mr. Speaker, the impression one gets by reading the descriptions of the way in which the demolition of the juggies is carried out by the demolition squad is a harrowing picture; the demolition squad attacks these juggies and jhompries with a greater enthusiasm and drive and vigour than is necessary, as if it is attacking some enemy territory in Delhi. May I know, if in carrying outthis unfortunate work, steps will first be taken to see, as the other hon. Members have asked, that alternative accommodation is made available them and also to see that as little force as is necessary is used by the demolition squads?

Shri Mehr Chand Khanna: We use no force. (Interruption).

Shrimati Renu Chakravartty: What is it he is saying, Sir?

Shri Mehr Chand Khanna: Let me finish what I want to say. I know what I am doing.

Mr. Speaker: Let him finish his sentence. He may modify it or add something; the English language is such. (Interruption).

श्री हुकम चन्द कछवाय : लोग जान से मारे गये हैं। इस के प्रलावा प्रभी परमों एक गर्भवती स्त्री की झग्गी तोड़ कर ट्रक में डाला गया तो ट्रक में ही 10 मिनट बाद उस के बच्चा गैदा हो गया . . .

ग्राध्यक्ष महोदय : ग्रार्डर, ग्रार्डर । बंठिये । श्राप सुनिए ।

श्री मौर्य : झुगी वालों के साथ बुरा व्यवहार किया गया ग्रीर . . .

श्री मेहर चन्द खन्ना : श्रलीगढ़ मैं श्राऊंगा ।

Shrimati Renu Chakravartty: He is a very provocative Minister.

Shri Mehr Chand Khanna: I am a very provocative Minister. I have been here for years. I know all that, I am not going into those things. Let me answer the question. What I am trying to say is this. (Interruption).

Shri Nath Pai: I am waiting for the reply.

Shri Mehr Chand Khanna: We use no force. We provide trucks and we take them in the trucks. As far as any difficulty with regard to this is concerned, if any one case is brought to my notice where a juggi dweller has been dealt with harshly, I am prepared to look into the case.

Shri Maurya: There are thousands of cases. I will tell you, thousands of cases are there. हजारों ऐसे केसेज हैं मेरे साथ चलिये मैं ग्राप को दिखा सकता हूं।

श्री मेहर चन्द सन्ना: मनी नहीं फिर द्याप को साथ ले कर देखने चलुंगा । माखिर मैं यहीं दिल्ली से चुन कर माया हूं में अबद देखांगा।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

D.V. C. Dams

*1079. Shri Mohammad Elias: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

- (a) the quantity of water earmarked for Flood Control, Irrigation and Power from the Tilaiya, Konar, Maithon and Panchet Hill Dams of the Damodar Valley Corporation as indicated by Mr. Voorduin in his prelimi-Unifled nary memorandum on the Development of the Damodar and the actual quantity of water available at present and its allocation to each of the above three objects on the basis of which cost of the Dam has been apportioned between them;
- (b) the reasons for difference, if any, between the planned quantity and actuals;

- (c) the irrigation potential for kharif and rabi irrigation as per the original scheme and the present position after completion of the Dams and reasons for the difference,
- (d) whether the original scheme envisaged the Navigation and Industrial Water Projects also?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) to (d). A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House. [Placed in library. See No. LT-4305/ 65].

Central Control over Power Generation

•1684. Shri D. C. Sharma: Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

- (a) whether some States have opposed the move of Centre assuming the direct responsibility for power generation; and
- (b) if so, the names of the States and the reaction of the Centre thereto?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Yes, Sir.

(b) The representatives of the Government of U.P., Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra and Mysore did not generally agree to the idea of central generation of power at a meeting of the Sub-Committee of Industry, Power and Transport of the National Development Council, held on the 2nd January and 23rd February, 1965.

It is proposed to hold further discussions and arrive at an understanding on the subject.

Accounts of Indians in Foreign Banks

*1087. Shri Hari Vishnu Kamath: Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 790 on the 8th April, 1965 regarding the release of foreign exchange to Indian businessmen going abroad and state:

- (a) whether the information—'a lot of information'—received from time to time about accounts of some Indians in foreign banks has led to any inquiry or investigation into the matter:
 - (b) if so, the outcome thereof; and
- (c) the action taken or proposed to be taken in the matter?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) to (c). During 1964, the Director of Enforcement adjudicated 14 cases involving maintenance of accounts in foreign banks.

Namrup Thermal Plant

*1088. Shri P. C. Borooch: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

- (a) whether the Namrup Thermal Power Plant has been recently commissioned;
- (b) if so, the cost involved in its construction and installation and its foreign exchange content; and
- (c) the generating capacity of the plant and the areas to be catered therewith?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Yes, Sir.

- (b) The estimated cost is Rs. 813.51 lakhs (Generation portion only) and its foreign exchange content is 8 million (Rs. 381.6 lakhs).
- (c) The generating capacity of the thermal station will be 69 MW comprising 3 sets of 23 MW on completion of its first stage. This station will supply power to the Industrial complex that would be located in Namrup area and also to the adjoining areas of Tinsukia, Makum, Dibrugarh, Doomdooma, Sibsagar, Digboi, Jorhat, Mariani and Golaghat.

Concentration of Income

•1089. Shri P. R. Chakraverti:
Shri Daji:
Shri Warior;
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) whether the survey of income distribution by the National Council of Applied Economic Research has revealed that there is a greater degree of income concentration in India than in U.S.A. and Pritain;
- (b) whether the degree of income inequality is greater in urban areas;and
- (c) whether the per capita income in rural areas is about half of that in urban areas?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) to (c). Yes Sir. These findings of the survey by the National Council of Applied Economic Research are given in their publication "All India Rural Household Survey 1962—A Summary Statement on Income Distribution in Rural and All India".

Indian Peace Corps

Shri P. C. Borocah:
Shri Yashpal Singh:
Shri Kapur Singh:
Shrimati Renuka Barkataki:
Shri P. Venkatasubbaiah:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Shree Narayan Dass:
Shri Ravindra Varma:

Will the Minister of Planning be pleased to state:

- (a) whether Government propose to constitute an Indian Peace Corps for service in developing countries in Africa and Asia; and
- (b) if so, the precise functions and constitution of the contemplated corps?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Dearness Allowance to Government Employees

Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri R. S. Pandey:
Dr. Chandrabhan Singh:
Shri Wadiwa:
Shri R. S. Tiwary:
Shri Radhelal Vyas:
Shri Parashar:
Shri Tula Ram:

Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

Shri Bade:

- (a) whether Government are aware that the grant of enhanced dearness allowance to Central Government employees without grant of corresponding increase in dearness allowance by State Governments to their employees has generated widespread discontent among State Government employees; and
- (b) if so, whether Government propose to consider the grant of suitable financial assistance to such State Governments as are anxious to grant such an increase to their employees, but are unable to do so owing to inadequacy of their own resources?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) It has been from time to time brought to the notice of the Government of India by some State Governments that there is discontent among their employees on this account.

(b) No, Sir.

Seizure of Gold with Chinese Markings

*1092. Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri D. C. Sharma:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Indrajit Gupta:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Customs authorities scized 30 tolas of gold with Chinese markings on the 13th April, 1965 from a tourist of West German nationality at Calcutta; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu): (a) The Customs authorities seized, on 13-4-65, 300 grams of gold, bearing foreign markings appearing to be Chinese, valued, at the international rate at Rs. 1638 (approx.), from a West German tourist at Calcutta.

(b) The Calcutta Customs authorities have initiated departmental adjudication proceedings against the person concerned.

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार

*1093. श्री मधु लिमये: क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के ग्रनुसार ग्रामीण क्षत्रों में रोजगार बढ़ाने के कार्यक्रम का कोई मुल्यांकन किया गया है; ग्रौर
- (ख) यदि हां, तो उस के नतीजे क्या हैं ग्रीर चौथी पंचवर्षीय योजना पर उस का क्या ग्रसर होगा ?

योजना मंत्री (श्री ब॰ रा॰ भगत):
(क) 14, 15 ग्रीर 16 ग्रप्रैल, 1965 को
नई दिल्ली में हुए घन्तःराज्य सम्मेलन में
इस कार्यक्रम का मृल्यांकन किया गया।

(ख) तीसरी योजना के म्रन्तिम वर्षं में इस कार्यक्रम में मोटे तौर पर साल में लगभग 350,000 लोगों को 100 दिनों का रोजगार मिल जायेगा। इस योजना के म्रामीण निर्माण कार्यों पर कुल व्यय 18 से 19 करोड़ रुपये तक होने की सम्भावना है। सम्मेलन ने प्रस्तावित किया है कि चौथी योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान यह कार्यक्रम 1500 से 2000 विकास खण्डों में चालू किया जाय। फिलहाल, चौथी योजना के लिए इस कार्यक्रम के बारे में जांच-पड़ताल की जा रही है।

Corruption in Revenue Departments

- *1094. Shri P. R. Chakraverti: Will the Minister of Finance be pleased to state:
- (a) whether any intensive study has been made on the probable modes of corruption in the Revenue Departments viz., Income-tax, Customs and Excise;
- (b) whether conscious and purposeful action has been devised and resorted to by the Departmental Head; to reduce the prevolent corruption in the Revenue Departments;
- (c) whether the Special Police Establishment has indicated certain procedures in the light of investigations so far made; and
- (d) if so, whether these have been put to effective operation?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu): (a) and (b) Yes, Sir.

- (c) The Special Police Establishment in consultation with the Departments of Income-tax customs and Central Excise have drawn up a programme for an intensive drive to reduce corruptions in these Departments.
- (d) The measures suggested by the Special Police Estat...*hment are being implemented.

National Projects Construction Corporation

Shri P. C. Borooah:

*1095. { Shri Yudhvir Singh: | Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

- (a) whether he has received any complaints from certain members of Parliament against the working of the National Projects Construction Corporation;
- (b) if so, the nature of the complaints;
- (c) whether he has instituted any enquiry into the complaints; and

(d) if so, the result thereof?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Yes, Sir.

- (b) The complaints mostly related to specific personnel and organisational matters.
- (c) The complaints were looked into; but no directions were considered necessary.
 - (d) Does not arise.

Constitution House Hostel

- *1096. Shri Hari Vishnu Kamath: Will the Minister of Works and Housing be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that the Constitution House Hostel, New Delhi was demolished more than a year ago;
- (b) whether Government propose to build a multi-storeyed hostel on that site:
- (c) if so, when the work of construction will commence; and
- (d) whether a plaque commemorative of Constitution House will be put up, as promised by him (the Minister) in the course of his reply to the Debate on his Ministry's grants on the 6th April, 1964?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes.

- (b) and (c). it was originally intended to build a multi-storeyed hostel on the site. In view of tht acute shortage of hotel accommodation in Delhi, which is adversely affecting our tourist traffic, it has been decided to build a hotel there. This hotel will have about 600-800 beds. The plans should be ready within about a year.
 - (d) Yes.

Loans Granted to Foreign Countries

- 2759. Shri Rama Chandra Mallick: Will the Minister of Finance be pleased to state:
- (a) whether loans have been granted by the Government of India to some countries in various forms;

- (b) if so, the names of those countries, the amount of loan given so far with details thereof; and
- (c) the total amount given by the Government of India till the 31st December, 1964?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Loans have so far been granted to U.A.R. (Egypt), Burma and Nepal. The amounts given and the balance outstanding as on date are as given below:

Amount of	Balance		
loan	outstanding		

U.A.R. (Egypt) Rs. 650 lakhs Rs. 15 lakhs

Burma Rs. 1998 lakhs Rs. 1167 lakhs

Nepal Rs. 87 lakhs Rs. 87 lakhs

Training of Doctors Abroad

2760. Shri Dharmalingam: Will the Minister of Health be pleased to state:

- (a) the names of programmes under which Doctors are sent abroad for further studies;
- (b) the number of Doctors sent abroad during the last three yaers, State wise;
- (c) the number of applications received under the above scheme from each State; and
 - (d) the mode of selection thereof?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) The Ministry of Health send doctors abroad only for practical training in different specialities under the various Technical Aid Programmes viz. Colombo Plan, Indo-French Technical Cooperation, USAID, WHO etc. Doctors are also deputed for training from time to time on some other ad-hoc offers of fellowships from foreign international organisations such as Ford Foundation, Population Council, Worcester Foundation, Nuffield Foundation and Rockefeller Foundation etc.

(b) and (c). A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House. [Placed in library, see No. LT-4306/65].

(d) Selection of doctors for training abroad is made by the Central Selection Committee constituted by the Ministry of Health. The selection made by this Committee is subject to approval by the Technical Assistance Selection Committee in the Ministry of Finance in respect of some of the programmes.

Goldsmiths

2761. Shri V. V. Thevar: Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) whether any priority is given in the allotment of poramboke land to the goldsmiths displaced on account of Gold Control Order who are prepared to bear the cost;
- (b) whether it is a fact that the certificates given by an M.P.M.L.A.President of Panchayat Board, stating that such and such person is affected by Gold Control Order are being ignored on the advice of village officials who give contradictory reports;
- (c) if so, the action being taken against the officials who give such false reports; and
- (d) whether it is possible to route the certificate enquiries only through the Panchayat Union so as to avoid contradictory and false reports?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) The Government of Madras have directed that for purposes of assignment of lands for goldsmiths cultivation, displaced should be given priority below exservicemen and above other landless persons. They have also displaced goldsmiths directed that who are poor and who do not own a house or house site be assigned house sites free of land value and with priority over other house-less persons. Other State Governments have been requested to consider the possibility of taking similar action.

- (b) No such case has come to the notice of Government.
 - (c) Does not arise.

(d) Since the work of certification and rehabilitation has been entrusted to different grades of officials in different States depending on the circumstances in each State, it is not considered desirable to make any modification, so as to entrust the work uniformly to the Panchayat union.

Hospitals and Dispensaries

- 2762. Dr. Keher: Will the Minister of Health be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 2657 on the 30th April, 1964 and state:
- (a) whether the information regarding the number of hospitals and dispensaries established by foreign missions in India has been collected from various State Governments; and
 - (b) if so the particulars thereof?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). A copy of the Statement in fulfilment of the assurance is laid on the Table. [Placed in library. See No. LT-430/65].

Irinav Regulator

- 2763. Shri A. K. Gopalan: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:
- (a) whether Government have received any complaint from the Public about the functioning of the Irinav Regulator in Cannanore district, Kerala;
- (b) whether it has breakages and salt water is getting into pure water kept in the Dam through these breakages:
- (c) if so, whether Government have taken any measures to remedy this defect;
- (d) whether Government have received a memorandum from the peasants stating that they are not getting water in time from the Dam; and
- (e) if so, the action being taken in the matter?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) to (e). The requisite information is being collected from the Government of Kerala and will be laid on the Table of the House

Agricultural Crops in Trichur District

- 2764. Shri A. K. Gopalan: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:
- (a) whether Government are aware that the agricultural crops of Mullur Kayal area in Trichur District (Kerala) are facing destruction because of scarcity of water; and
- (b) if so, the steps Government propose to take to save the crops in this area?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) and (b). There was unauthorised pumping of Peechi water which caused scarcity of water in Mullur Kayal area. This has been detected and stopped by the Government of Kerala.

Hospitals in Kerala

- 2765. Shri A. K. Gopalan: Will the Minister of Health be pleased to state:
- (a) the number of hospitals in Kerala at the District Headquarters;
- (b) the number out of them where separate facilities are provided for women;
- (c) the average number of inpatients in each hospital per mensem;
- (d) whether the number of beds provided is far short of the requirements;
- (e) whether there is a shortage of X-Ray films in these hospitals;
- (f) whether there is also a shortage of staff; and
- (g) if so, the measures proposed to rectify these?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) to (g). Information is awaited from the Kerala Government and will be laid on the Table of the House when received.

Tax Collection

2766. Shrimati Savitri Nigam: Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that applications for rectification of mistakes in the income-tax assessment orders which would result in reduction of demand and grant of refund therefor are unnecessarily kept pending for years together as the time for passing such orders is four years under the law; and
- (b) if so, the steps Government propose to take to expedite the disposal of such applications?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली

2767. श्री यज्ञपाल सिंह: क्या निर्माण ग्रीर ग्राबास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि साउथ ब्लाक में, जहां प्रधान मंत्री का कार्यालय है, ब्रिटेन की सरकार का चिह्न दीवार पर लगा हुमा है, जब कि नार्य ब्लाक में वैसा ही चिह्न कुछ समय पूर्व हटा दिया गया था; ग्रीर
- (ख) यदि हां, तो यह कब तक हटाया जायेगा ?

निमाण तथा ग्रावास मंत्री (श्री मेहर चन्द सन्ना): (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 1965 के भ्रन्त तक।

Income-Tax on Artists

2768. Shri Yashpal Singh: Shri Bibhuti Mishra:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) whether his attention has been drawn towards the protest made by leading painters, sculptors and graphic artists at a meeting held at Hyderabad on the 13th January, 1965, against the unsympathetic attitude of the Incometax and Customs authorities;
- (b) if so, whether they have been asked to submit specific instances of harassment; and
 - (c) the action taken in the matter?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) No such protest has been brought to the notice of the Income-tax and Customs Departments.

(b) and (c). Do not arise.

Ayurvedic Dispensary in Delhi

2769. Shri Yashpal Singh: Will the Minister of Health be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 807 on the 17th September, 1964 and state the up-to-date progress made in the setting up of an Ayurvedic Dispensary under the C.G.H.S. in Sarojini Nagar area of New Delhi?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): It has not yet been possible to acquire any suitable accommodation for opening a C.G.H.S. Ayurvedic Dispensary in Sarojini Nagar. The matter is under consideration in consultation with the concerned Ministry.

द्मापरेशन के समय रक्त स्राव

2770. श्री द्वां ना तिवारी: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या सरकार का घ्यान ब्रिटिश मैडिकल जरनल के नवम्बर-दिसम्बर, 1964 के ग्रंक में प्रकाशित इस समाचार की ग्रोर दिलाया गया है कि ब्रिटेन के डाक्टर आपरेशन के समय रक्त स्नाव को रोकने के लिए सोने के वर्क (गोल्ड लीफ) का प्रयोग करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में यही तरीका ग्रपनाने का है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा॰ सुझीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) मनुष्यों के ग्रापरेशन की पद्धित में इस के प्रयोग का ग्रभी वैज्ञानिक ढ़ंग से मुल्यांकन किया जाना है।

"Science Equipment for Schools"

Shri P. K. Deo: 2771. Shri Kapur Singh: Shri P. K. Ghosh:

Will the Minister of Planning be pleased to state:

- (a) the names of the States, where a survey proposed by the Planning Commission to ascertain the science equipment requirements for schools has been undertaken; and
- (b) whether the agency to determine the standard for these equipments has been determined?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) The Panel for Science Education in Secondary Schools, set up by the Committee on Plan Projects, Planning Commission, has stressed the need for a planned programme to step up the production of scientific apparatus for schools and have recommended that the State Governments should undertake a survey of the Science equipment required for schools during the Fourth Plan period. In pursuance of this recommendation of the Panel, the Planning Commission have set up a Working Group consisting of representatives of various Ministries and other concerned Organisations to go into the question of requirements of scientific equipment for educational institutions at all stages during the

next ten years with particular reference to the Fourth Plan. The survey to ascertain the science equipment requirements for schools has not been taken up so far.

(b) The Department of Science Education of National Council of Educational Research & Training is working out proposal for setting up a semi-autonomous agency to lay down norms and standards for Science apparatus and equipment at the school stage.

Guide Book for Making Black Money

↑ Shri P. R. Chakraverti: 2772. ₹ Shri Indrajit Gupta: ↑ Shri Daji:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) whether the Income-tax Department in Calcutta has come across a 'Guide to Success' in making black money claimed to be an authoritative publication with an All-India circulation;
- (b) the specific instructions given in the guide; and
- (c) the steps taken by Government to guard against the anti-social practices, resorted to by the members of business community, who adhere to the codes of behaviour, enunciated in the Guide Book?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Irrigation Benefits

2773. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether the Central Government are considering the question of overcoming difficulties in the construction of field channels to remove bottlenecks in speedy utilisation of irrigation benefits; and

(b) if so, when the difficulties are likely to be removed?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) The Governments of Madras, Gujarat, J. & K., Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab and U.P. have already enacted legislation for excavation and maintenance of field channels by the beneficiaries and in case of default to get the work executed through panchayats or by Government. The question is under the consideration of the State Governments. The progress achieved by these measures is under constant review.

(b) A number of major and medium projects are being taken up in each Five Year Plan. Efforts are, therefore, continuously being made to overcome the difficulties in the way of speedy utilisation of irrigation potential.

Seizure of Smuggled Gold

2774. Shri Vishwa Nath Pandey: Shrimati Johraben Chavda:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) the quantity of smuggled gold seized by Government in the country from the 31st October, 1964 to 31st March, 1965 State-wise with their locations and the names of the smugglers; and
- (b) the steps taken against them so far?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) and (b). A statement showing the quantity and value of the gold seized by the Customs, Land Customs and Central Excise authorities from the 31st October, 1964 to 31st March, 1965, Statewise, as smuggled, the places where the seizures were made and the number of persons involved in the seizures is laid on the Table of the [Paced in Library, see No. LT-4308/65].

Out of this a total quantity of 119.2 Kgms. approximately valued about Rs. 6,38,800 has been confiscated. Out of the 388 persons involved in these seizures, prosecution proceedings have been launched as on 1st April, 1965, against 31 persons, out of whom, 7 have been so far convicted and 3 acquitted, by the courts. Personal penalties aggregating Rs. 1,36,950 as on 1st April, 1965, have also been imposed on the persons involved in the cases adjudicated departmentally. The remaining cases are under different stages of investigation adjudication including possible proceedings in Courts of Law. Pending completion of these, it would not be desirable to give the names of the persons involved.

Loan to Orissa

2775. Shri Ramachandra Ulaka: Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) whether the Central Government have granted any loan to the Government of Orissa for the improvement of their ways and means position during 1964-65; and
 - (b) if so, the details thereof?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) and (b). A ways and means advance of Rs. 8 crores was granted to the Government of Orissa in June, 1964. It carried interest at 3 per cent per annum and was repaid by the State Government during 1964-65.

Flood Control in Orissa

2776. Shri Ramachandra Ulaka: Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) the nature and extent of Central assistance given to the Orissa Government for flood Control Schemes during 1964-65; and

(b) the names of the schemes for which the assistance was granted?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) A loan of Rs. 45 lakhs was sanctioned to the Orissa Government for financing flood control and drainage works in the State for the year 1964-65.

(b) The loan sanctioned was not for any specific scheme, but for the programme of flood control and drainage works taken up by the State Government in 1964-65, consisting of a large number of schemes for construction of embankments, raising and strengthening of existing embankments, river training works, drains, improvement of channels, etc.

Leprosy Centres

2777. Shri Ramachandra Ulaka: Shri Dhuleshwar Meena: Shri Rama Chandra Mallick:

Will the Minister of Health be pleased to state:

- (a) the number of Leprosy Control Centres at present in Orissa;
- (b) the number of patients for whom provision has been made in these Centres; and
- (c) the total amount of loan or grant given by the Centre to these Centres during 1964-65?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) At present 20 Leprosy Control Units and 17 Survey, Education and Treatment Centres are working in Orissa under the National Leprosy Control Programme. Besides, these, one Voluntary Organisation is also participating in the leprosy control programme.

(b) A Leprosy Control Unit usually covers a population of 1.5 lakhs. A unit is expected to detect and provide treatment for 1800 to 2000 leprosy cases. Orissa being a moderately endemic State, each unit in that State is at present catering to about 1650 patients on an average.

(c) According to the existing procedure for the release of Central assistance, allotment of funds is not made scheme-wise but the grant-inaid is sanctioned at the end of each year for broad groups or categories of health schemes. Three-fourths of the total Central assistance allocated for a financial year is, however, released in lumpsum ways and means advances to the State Governments during the course of the year. Information regarding the exact amount of Central assistance released to the State for the Leprosy Control Centres during 1964-65 is, therefore, available. The State Government have, however, stated that Rs. 2.59 lakhs was spent by them on National Leprosy Control programme during the year 1964-65. In accordance with the sanctioned pattern of Central assistance to the National Leprosy Control Programme, State Government would be eligible to draw 75 per cent of the non-recurring and 50 per cent of the recurring expenditure incurred by them on this scheme. Total III Plan provision for leprosy control in the Orissa Plan is Rs. 11.00 lakhs.

Seizure of Currency Notes in Bombay 2778. Shri Vishwa Nath Pandey: Dr. Mahadeva Prasad:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Railway Police seized currency notes worth Rs. 2.1 lakhs in the first week of March, 1965 at Bombay Central Station from a first class passenger who was boarding Saurashtra Mail for Baroda;
 - (b) if so, the details thereof; and
- (c) the action taken by Government in the matter?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) to (c). The Railway Police seized on the 5th March, 1965, currency notes worth Rs. 2.1 lakhs and certain documents from a first class passenger boarding the Saurashtra Mail at Bombay Cent-

Station for Baroda. As the case was suspected to involve violation of the Foreign Exchange Regulations, it was taken over by the Enforcement Directorate. On conclusion of the necessary investigations, the case was adjudicated by the Director of Enforcement, who found the accused guilty of contravention of section 5(1) (c) of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 read with section 23B ibid. The Director imposed a penalty of Rs. 5000 on the accused and confiscated the amount of Rs. 2.1 lakhs. The party has since paid the penalty.

भारत में चीनी माल का चोरी-छिपे लाया जाना

2779. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या बिक्त मंत्री यह बताने की कृपा_करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि निदया जिले में पूर्व रेलवे पर गेडे रेलवे स्टेशन के जिरये चीन द्वारा निर्मित वस्तुएं भारत के बाजार में बिकने के लिये चोरी-छिपे ग्रा रही हैं; ग्रौर
- (ख) यदि हां, तो चीनी सामान का भ्रवैध रूप से इस देश में ग्राना रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

दिस मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी):
(क) और (ख). 4 जनवरी, 1964 से मार्च,
1965 की स्रवधि के दौरान चीन में बने
माल की चोरी छिपे रूप में लाने के प्रयत्न से
सम्बन्धित एक मामला गेंडे स्टेशन पर पकड़ा
गया श्रीर तीन दूसरे मामले समीपवर्ती
बानपुर पड़ताल चौकी पर पकड़े गये ।
जहां तक सरकार को पता है, चीन में बनी
बस्तुएं सामान्यतः इस रेलवे-स्टेशन के जरिये
चोरी छिपे रूप में नहीं लाई जाती हैं। तथापि
सीमा-शुल्क पदाधिकारी सतर्क हैं।

Re-Employed Military Personnel

2780. Shri P. R. Chakraverti: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the Central Government have issued instructions to the effect that in the case of re-employed military personnel, with a pension of Rs. 50 or less a month, no deduction should be made from their pay; and

(b) whether the State Governments have accepted the suggestions and implemented the same?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) Yes, Sir, provided the individual retired before attaining the age of 55. The rule applies to both civil and military pensioners.

(b) We have no information. There was no such suggestion made to State Governments.

चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

2781. डा॰ चन्द्रभान सिंह: स्या विस्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों में कानपुर में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा भ्रायकर विभाग के कार्यालयों में काम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि दी गई; भ्रौर
- (ख) ग्रांकड़ों में ग्रत्यधिक वृद्धि होने केक्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णानाचारी): (क) प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई राशि निम्न प्रकार है:

वर्ष	भ्रायकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों के लिये जोड़
	रु०
1962-63	64,888
1963-64	2,14,359
1964-65	4,57,376
जोड़	7,36,623

- (ख) इस खाते में खर्च की ग्रत्याधिक वृद्धि के कारण मुख्यतः ये हैं :
- (i) चिकित्सा उपचार नियमों तथा आदेशों का उदारीकरण जिस में अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को जिस हद तक जायज है उसी हद तक सुविधाशों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उपलब्ध बनाना भी शामिल है।
 - (ii) विभाग का विस्तार;
- (iii) दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि तथा बार बार इन्जैंक्शनों, ग्रधिक मूल्य की दवाइयों को निर्धारित करने के कारण ग्रधिक व्यय, तथा
- (iv) सरकारी कर्मचाि यों के परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि ।

Farakka Barrage

2782. Shri C. K. Bhattacharyya: Shri P. R. Chakraverti:

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

- (a) whether the completion of the Farakka Barrage Project will be delayed further;
- (b) the progress achieved in constructing the feeder canal to divert water to Hooghly to provide water for the Calcutta port;
- (c) the different phases for the construction of the barrage; and
- (d) whether arrangements have been made for importing machinery and equipment?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) The project is expected to be completed according to Schedule.

(b) Work in half the length is in progress and is expected to be completed by June, 1968. Arrangement

Is being made to take up the work of the remaining portion after completion of formalities.

- (c) Out of 109 Bays in Farakka Barrage, work on 12 Bays on the Right Bank and 30 Bays on the Left Bank is in progress. Work on the remaining portion of 67 Bays will be taken up after completion of formalities. In Jangipur Barrage, tender is being finalised and the work will be taken up shortly.
- (d) Orders for most of the equipment have been placed and they havestarted arriving.

प्राकृतिक चिकित्सालय

2783. े श्री प० ला० बारूपाल : श्री समनानी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

- (क) क्या राजस्थान में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाये गये प्राकृतिक चिकित्सा-लयों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार से धनुदान के रूप में कोई मांग की गई है; और
- (ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा॰ सुशीला नायर) : (क) ग्रीर (ख) प्राकृतिक चिकित्सालय, जयपुर, राजस्थान को भारत सरकार ने निम्न-लिखित ग्रनुदान दिये हैं :

	रुपये
 मोटापन तथा जठरकोप के उपचार सम्बन्धी ग्रनुसन्धान 	
के लिये	4,000
 एक वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्य- क्रम चलाने के लिये 	14,400
3. व्याधिकीय प्रयोगशाला के उपकरणों के लिये	5,000

प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र जोधपुर तथा राजस्थान चिकित्सा केन्द्र बीकानेर से भ्रीयक सहायता की प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं। इन प्रार्थनाभ्रों पर प्राकृतिक चिकित्सा सलाहकार समिति श्रपनी भ्रगली बैठक में विचार करेगी।

Contracts given to M/S Tarapur and Co.

2784. Shrimati Savitri Nigam: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

- (a) the number of times when M/s Tarapur and Co., have gone to the arbitration and litigation for the work done by them in the past; and
- (b) whether they have also been given import licence for importing machinery even before they got the order and finalised the contracts for taking up the work at Farrakka Barrage?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): Three cases only are known to this Ministry, one in Hirakud and two in Sharavathi Valley Project.

(b) No import licence has been issued to the firm so far. Consequent on the decision of the Farakka Barrage Contorl Board to accept the recommendation of the Tender Committe for award of the work on the Feeder Canal to Mis Tarapur and Co., a letter of intent was issued by the Chief Engineer, Farakka Barrage Project to this firm on the 15th January, 1965, intimating the acceptance of their tender and requesting them to take up the work, pending the execution of formal contract and issue of work order. The firm has already gone to the Project site and has started the preliminary works. One of the terms of the agreement with this firm is that Government would assist them in the import of some equipment and spare parts for machinery. The foreign exchange applications for these items have been received from the firm and are under consideration.

Bacteria-Destroying Textile

2785. Shri Warior:
Shri Vasudevan Nair:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

- (a) whether Government's attention has been drawn to a press report that a new bacteria-destroying textile has been perfected by the Moscow Textile Institute; and
- (b) if so, whether Government propose to get the know-how from the Government of U.S.S.R.?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) Government are not aware of the press report. It is, however, understood that a laboratory of the Moscow Textile Institute has developed fabrics which kill bacteria.

(b) The development of this fabric is still in its infancy and even in the U.S.S.R., it is expected to go into production only next year. The question of getting the know-how will be examined in due course.

Intra-Uterine Devices

2786. Shri Ramakrishna Reddy: Will the Minister of Health be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Prof. M. S. Thacker made a statement recently that a U.N. Agency has promised to ship equipment for manufacture of intra-uterine devices for birth control in India; and
- (b) whether no factories for the manufacture of such devices have so far been established in India either in public or in private sector?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) No. Prof. M. S. Thacker has only said that the Population Council, New York, has promised to supply some Intra-Uterine Contraceptive Devices to the Government of India.

(b) An existing Public Sector Factory at Etawah in Uttar Pradesh has

already taken up the production of Intra-Uterine contraceptive devices.

यमुना के जल का दूवण

2787 शी नवल प्रभाकर : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

- (क) क्या यह सच है कि दिल्ली में वजीराबाद तटबन्ध और श्रोखला तटबन्ध के बीच यमुना नदी के तटवर्ती काश्तकार गम्दे पानी का खाद के रूप में प्रयोग करते हैं;
- (ख) क्या इससे यमुनाका जल दूषित को जाताहै; श्रीर
- (ग) यदि हां, तो इस नित्य प्रयोग को नौकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्य--वाही करने का है?

स्वास्थ्य मंत्री (डा॰ सुंशीला नायर) = (क) जी हां।

- (ख) जी हां। यह बरसात में हो सकता है।
- (म) निम्निलिखित क्षेत्र के भीतर बेंती के लिये मल तथा कार्बनिक खाद के प्रयोग, उसके ले जाने श्रयवा जमा करने पर दिल्ली प्रशासन ने 14 जनवरी, 1965 से एक वर्ष के लिये प्रतिबन्ध लगा दिया है:---

"जमुना नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट से एक फर्लांग पूर्व और एक फर्लांग पश्चिम वजीराबाद पिंम्पग स्टेशन से 3 मील ऊपर की और तक का क्षेत्र।"

नदी के जल दूषण के खतरे को रोकने के लिये उन्हें इस प्रतिबन्ध को और प्रधिक क्षेत्र पर लागू करने के लिये कह दिया गया है। जमुना के जल को ठीक से शुद्ध करने को सुनिध्चित करने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध भी कर दिये गये हैं ताकि किसी सम्भाव्य दूषण से लोगों के स्वास्थ्य को खतरा न पहुंचे।

Rural Industries Projects

2788. Shri Shree Narayan Das: Shri D. S. Patil:

Will the Minister of Planning be pleased to state:

- (a) whether the question of further extending rural industries projects during the last year of the Third Five Year Plan has been considered; and
- (b) if so, the nature of decision taken and the areas selected in various States for the purpose?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

Kuttiyadi Irrigation Scheme 2789. Shri A. V. Raghavan: Shri Pottekkatt:

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

- (a) whether the District Development Council of Kozhikode District in Keraia has requested for an allotment of Rupees Fifty Lakhs to carry out the Kuttiyadi Irrigation Scheme for the year 1965-66;
- (b) the estimated cost of the project and the amount proposed to be spent during 1965-66; and
- (c) the steps taken to open a separate irrigation division at the spot?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Yes.

- (b) The project is estimated to cost Rs. 496 lakhs and a provision of Rs. 17.26 lakhs has been made for the project for 1965-66.
- (c) Creation of a separate irrigation division will be considered when additional funds are available for this project.

Budgets of Public Sector Undertakings

2790. Shri H. C. Soy: Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that suggestion has been made by Shri K. Santhanam and others that the budget for Public Undertakings be placed together and arranged in one separate lot; and
- (b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) Yes, Sir.

(b) Annexure XVII to the Explanatory Memorandum on the Budget of the Central Government for 1965-66 has been introduced from this year to give, at one place, the estimates of capital and loans to be provided by Government to public undertakings.

Supply of Unfiltered Water

2791. Shrimati Savitri Nigam: Will the Minister of Health be pleased to state:

- (a) whether Government have got any plan to supply unfiltered water to the kitchen garden growers and to the farmers in and around Delhi; and
 - (b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). No. Unfiltered water is already being provided by the Central Public Works Dpartment to the following:

- Lawns and gardens of New Delhi.
- (ii) Pusa Institute.
- (iii) Railways.
- (iv) Cantonments.
- (v) Government contractors and private parties for construction works.
- (vi) Some automobile service stations in New Delhi.

Development of Audhra Pradesh

2792. Shri P. Venkatasubbaiah: Will the Minister of Planning be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that during the recent visit of the Prime Minister to Hyderabad, representations were made by the Chief Minister and legislators that Andhra Pradesh had been grossly neglected by the Central Government resulting in great regional imbalance, and
- (b) if so, the steps Government propose to take to remove the regional imbalance?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) Yes, Sir.

(b) In the formulation of States' Fourth Five Year Plan, due care will be taken to see that balanced regional growth is promoted.

Consumer Goods

2793. Shri Sidhieshwar Pragad: Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) whether estimates have been made or any survey undertaken by his Ministry about the scale of expansion of the demand for a variety of consumer goods particularly from the rural section:
 - (b) if so, its main findings; and
- (c) the basis on which it has been made?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Government of India Press

2794. | Dr. Ranen Ser: | Shei S. M. Banerjee:

Will the Minister of Works and Housing be pleased to state:

(a) whether the committee for the Categorisation of the Government of India Press set up in 1983 has submitted any report and recommendations; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna); (a) Yes.

(b) The report of the Committee is still under consideration. After it has been examined and decisions taken, a detailed statement will be laid on the Table of the Sabha.

Conference of Municipal Commissioners

2795. Shri Rameshwar Tantia: Will the Minister of Health be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that a two day Conference of Municipal Commissioners in the country was held in New Delhi; and
- (b) if so, the subjects discussed and the decisions taken in the conference?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) The Commissioners of the Corporations of Calcutta, Bombay, Madras, Ahmedabad, Kanpur, Hyderabad, Bangalore and Nagpur were invited to a Conference by the Commissioner, Delhi Municipal Corporation.

(b) The subjects discussed and the Resolutions passed at the Conference are given in the statements attached. [Placed in Library. See, No. L.T. 4309/65].

Special Cell for Research

2796. Shri P. Venkatasubbaiah: Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of Planning be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Planning Commission proposes to set up a separate special cell for research;
- (b) the main functions of the special cell; and
- (c) when will it be set up and the additional financial expenditure involved in this connection?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) and (b). Planning Commission is considering a proposal to set up a small research group within the Planning Commission to undertake basic research into problems of economic and social planning. The group will act in close collaboration with universities and other institutions engaged on similiar basic research as part of an agreed long term programme.

(c) Details are being worked out.

Aid From Canada

Shri P. Venkatasubbaiah:
Shri Yudhivir Singh:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Hukam Chand
Kachhavaiya:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Rameshwaranand:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) Whether Mr. H. O. Moran, Director General of the Canadian External Aid Office held discussions with officers of his Ministry regarding the effective use of Canadian assistance in the last year of the Third Five Year Plan:
 - (b) if so, the points discussed; and
- (c) the extent to which Government have so far utilised the Canadian assistance and what are the short-falls, if any?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) and (b). Yes, Sir. The discussions centered on the utilisation of Canadian assistance to be pledged for 1965-66 [which has been since announced at the Consortium meeting to be in Canadian dollars—(i) 12.0 million in grants; (ii) 20.0 million in long term developmental loans and (iii) 12.5 millions in extended suppliers credit]. The proposals made by the Government of India are under consideration with the Government of Canada and it is likely

11818

to take a few fore weeks before the matter is finally decided.

(c) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT- 4310/65].

Flood Control in Andhra Pradesh

2798. Shrimati Lakshmikanthamma: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state the Fourth Plan provision for flood and drainage works in Andhra Pradesh?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): No decision has yet been taken about the fourth plan provision for flood-control and drainage works in Andhra Pradesh.

Vamsadhara Project in Andhra Pradesh

2799. Shrimati Lakshmikanthamma: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

- (a) whether clearance has been given to Vamsadhara Project in Andhra Pradesh; and
- (b) if not, whether Government will ensure that clearance is given during the Third Five Year Plan?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) No.

(b) The Cental Water and Power Commission examined the Vamsadhara Project and their comments were forwarded to the Govt. of Andhra Pradesh in January, 1965. The Project will be processed through the Technical Advisory Committee as soon as the replies of the State Government to the comments of the SW & PC are received.

Seizure of Gold in Bombay

2800. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the gold bars and ornaments worth Rs. 60,000 were seized by the Customs Officials at Santa Cruz, Bombay from

- a passenger from Kuwait on the 6th April, 1965; and
- (b) if so, the action Government propose to take in the matter?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) Gold Bullion and gold jewellery, collectively valued at Rs. 27,972 (approx) at the international rate and at Rs. 55,944 (approx) according to the existing market value, were seized by the Customs officials at the Santa Cruz Airport at Bombay, as smuggled, on 6th April, 1965, from 2 passengers who arrived from Bahrain.

(b) Further investigations in the matter are in progress, on completion of which, appropriate action will be taken.

Government Employees owning Houses in Defhi

2801. Shri Yashpal Singh: Will the Minister of Works and Housing be pleased to state:

- (a) whether those Government employees who own houses in Delhi and were in occupation of Government accommodation on 20th July, 1964 have been asked to pay rent at enhanced rates with effect from 20th July, 1964 without giving them any opportunity to vacate the accommodation occupied by them; and
 - (b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) and (b). Such persons have been given the option to pay rent at enhanced rates or to vacate the accommodation.

Government Employees owning Houses in Delhi

- 2802. Shri Yashpal Singh: Will the Minister of Works and Housing be pleased to state:
- (a) whether those Government servants who were occupying Government accommodations on 20th July, 1964 and who subsequently have built their own houses in Delhi

are required to intimate the fact of owning their houses within a period of 7 days of the completion of their houses; and

(b) the penalty proposed in case they fail to vacate Government accommodation?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes.

(b) If the intimation is given by the officers concerned to the Director of Estates in time, they have the option either to surrender the Government accommodation within 7 days or pay the standard rent as calculated under 45-B or pooled standard rent under F.R. 45-A, whichever is higher, with effect from the date of acquisition of ownership of the house. But, if the intimation is not given in time, the allotment is deemed to be cancelled with effect from the date of acquisition of ownership of the house in question and action is taken for recovery of damages equal to market rent and eviction from the house.

House Building Loans

- 2803. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of Works and Housing be pleased to state:
- (a) whether the cost of house construction has on an average increased since the scheme for grant of house-building loans for Central Government employees was made;
- (b) whether in view of the increased cost of construction Government propose to revise upward the limit of the loans that can be granted under the said schemes to different category of Government employees;
 - (c) if not, the reasons therefor;
- (d) whether any categories of employees are not covered by the scheme; and
 - (e) if so, which ones?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes. After the revival of the Scheme in April 1956, the cost of construction of houses has increased by about 30 per cent.

- (b) and (c). The amount of loan admissible to individual Government servants has already been increased from an amount equal to 24 months' pay to 36 months' pay, subject to a maximum of Rs. 25000. Low paid employees are given loans upto Rs. 4,800 even if this amount exceeds 36 months' pay. This Scheme is designed to cater to the requirements of Government servants belonging to low and middle income groups. The maximum amount admissible under the Scheme is already more than that admissible under the Middle income Group Housing Scheme for general public, which is Rs. 20,000. It is, therefore, not proposed to raise the ceiling of loan for Central Government servants.
- (d) and (e). The following categories of Central Government servants are not eligible for loans under the Scheme:
 - (i) temporary Central Government servants, who have not rendered ten years continuous service.
 - (ii) officers belonging to All India Services, such as the I.C.S., I.A.S., I.P.S., etc., who are on deputation to the Central Government on tenure basis for a period of less than six years.

House Rent Allowance

2804. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that although the dearness allowance has been marged in the basic pay of the Central Government servants, the limit for 15 per cent house rent allowance remains the same;
- (b) whether the feasibility of raising this limit has been considered;
 - (c) if so, the result thereof?

APRIL 29, 1965

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) Yes, Sir. The limit of pay upto which house rent allowance is admissible in 'A' class cities at 15 per cent of pay without verification of rent receipts remains Rs. 250 p.m.

- (b) Yes, Sir.
- (c) It has been decided not to raise this limit.

NEFA Micro Hydel Project

Shri D. C. Sharma: 2865. Shri Tula Ram: Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

- (a) whether the draft reports for three micro-hydel projects in North-East Frontier Agency have been completed: and
- (b) if so, the broad details thereof?

The Minister of Irrigation Power (Dr. K. L. Rao): (a) Sir. Project reports for three micro hydel schemes viz. (i) Bomdilla (ii) Passighat an i (iii) Tezu have been prepared by the Central Water Power Commission.

(b) The broad features of the schemes are:-

> Bomdilla.—The scheme envisages diversion of 2 cusecs of water from the Bomdilla Nallah and its utilisation over a gross head of 170 ft. by constructing a 1500 ft. long power channel and a power station with 3 nos. 30 KW each generating units installed. The scheme is estimated to cost Rs. 6.92 lakhs.

> Passighat.—The scheme sages diversion of 6 cusecs of water from the Sillekrong river and its utilisation over a gross head of 180 ft. by constructing a power channel

4220 ft. long and a power station with 4 nos. 40 KW each generating units installed. The scheme is estimated to cost Rs. 6.72 lakhs.

Tezu.—The scheme involves diversion of 9 cusecs of water from Derah stream and its utilisation over a gross head of 175 ft., construction of a power channel 5165 ft. long and installation of 4 generating units 90 KW each at an estimated cost of Rs. 8.07 lakhs.

Ceiling Fans in Government Quarters

Shri D. C. Sharma: 2806. ≺ Shri P. C. Borooah: Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of Works and Housing be pleased to state:

- (a) whether it is proposed to provide ceiling fans in the quarters allotted to class IV employees; and
- (b) if so, the amount to be spent and when the work is proposed to be completed?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes, in regard to those quarters which form part of the General Pool and are under the administrative control of this Ministry.

(b) It will take about two years to complete the work. The rough cost is likely to be Rs. 25 lakhs.

Longevity of Life

2808. Shri Krishnapal Singh: Will the Minister of Health be pleased to state:

- (a) whether the factors contributing towards longevity of life in the country have been studied:
- (b) if so, whether any conclusions have been reached as to the food and other habits which contribute towards long and healthy life and the habits which tend to shorten it; and

(c) whether Government propose to publish a brochure on the subject?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) to (c). No specific studies have been made by Government in regard to the factors contributing towards longevity of life in the country. Such factors as improved medical, public health, maternal and child health services including eradication or control of communicable diseases, improvements in environment and socio-economic conditions are known to be related with longevity.

The publication on health education covering different aspects in the forms of posters, brochures and pamphlets is being done by the Central and State Governments through the Central Health Education Bureau and the State Health Education Bureaus, respectively.

Income-tax assessees in Delhi

2809. Shri Shiv Charan Gupta: Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) the number fo assessees of Income-tax in Delhi as on the 31st March, in each of the years, 1951, 1956 and 1961 to 1965 respectively;
- (b) the assessment of income-tax in Delhi for the financial year 1964-65;and
- (c) the arrears of Income-tax in Delhi as on 31st March 1964 and 31st March 1965?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Chinese Goods smuggled into Assam

Shri Raghunath Singh:

2816 Shri P. C. Borooah:

Shrimati Renuka Barkataki:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a huge consignment of Chinese Goods smug-

gled into Assam through Pakistan across the Garo Hills was seized by the Customs recently;

- (b) if so, the nature and extent of the goods seized; and
- (c) the steps taken to prevent further smuggling of this nature?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) and (b). In the first week of April, 1965 the Customs officers seized thirteen bundles of Chinese made galvanized wire valued at about Rs. 1200/- while they were being carried in a truck across Garo Hills.

(c) Preventive measures have been tightened. Customs officers are keeping strict vigilance in co-operation with Border police.

Industries in Punjab

2811. Shri Daljit Singh: Shri Chuni Lal:

Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 515 on the 26th November, 1964 and state:

- (a) whether the investigation has since been completed and decisions taken for allotment of more funds for setting up heavy and medium industries in Punjab; and
 - (b) if so, the details thereof?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) Not yet, Sir.

(b) Does not arise.

Demolition of Jhuggis

Shri Balmiki: 2813. Shri Tulshidas Jadhav: Shri Buta Singh:

Will the Minister of Works and Housing be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than 70 jhuggis and jhopris were demolished at Rouse Avenue near Minto Bridge, Delhi on the 6th April, 1965;

- (b) whether it is also a fact that n_{ψ} notice was given to the dwellers; and
- (c) the steps taken by Government to make provisions for setting these people?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) to (c). 61 families squatting on Government land at Rouse Avenue, near Minto Bridge, were removed on the 6th April, 1965. They were all offered alternative accommodation under the Jhuggis and Jhopris Removal Scheme. Of these, 57 families accepted the offer and occupied the allotted plots in the colonies at Wazirpur and The remaining Seelampur. families did not avail of the offer and have presumably made their own arrangements.

Family Planning Directorate

2814. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of Health be pleased to state:

- (a) whether Government have had under consideration a proposal to upgrade the Family Planning Directorate, to the status of a Ministry;
- (b) if so, Government's decisions in the matter; and
- (c) the difficulties the present Directorate is encountering in implementing Family Planning Schemes, and how they are sought to be tackled?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) No.

- (b) Does not arise.
- (c) Procedural delays sometimes occur; measures are being considered to overcome them.

Rural Electrification in Madras State 2815. Shri Dharmalingam: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) the amount allotted for electrification of rural areas in the Madras State during 1984-65;

- (b) whether the entire amount has been utilised; and
 - (c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) The amount allotted by the Government of India is Rs. 300 lakhs.

- (b) Yes.
- (c) Does not arise.

Birth Control Pills

Shri Koya:

Shri Narendra Singh

Mahida:
Shri Buta Singh:

Will the Minister of Health bepleased to state:

- (a) whether Government's attention has been drawn to a statement by a Canadian Psychiatrist Dr. Victoria Voje that birth control pills made women more masculine;
- (b) her reaction to this statement; and
- (c) whether Government propose to discourage the use of these pills to preserve the faminine character of Indian women?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes.

(b) and (c). The oral contraceptives are not allowed for general use in India.

Yellow Fever

2817. Shri Shree Narayan Dag: Will the Minister of Health be pleased to state:

- (a) whether there was a joint discussion between the W.H.O., National Institute of Communicable Diseases and Indian Council of Medical Research over Yellow Fever; and
- (b) if so, whether any thing emerged which will lead to the eradication of this disease in India?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (2) Yes. A regular meeting of the Yellow Fever Advisory Committee was held on the 5th and 6th April, 1961, in New Delhi to discuss various items relating to yellow fever and other allied quarantine matters. The Directors of the National Institute of Communicable Diseases and the Indian Council of Medical Research are the regular members of the Committee, but the representatives from the W.H.O., Ceylon and Pakistan were also specially invited to attend the meeting to discuss quarantine matters of common interest.

(b) India is free from yellow fever. Hence the importance of quarantine etc. to prevent its introduction into our country. The question of eradicating this disease therefore does not arise. Measures to prevent the introduction of yellow fever into India, were discussed.

Transmission for Grid

2818. Shri Shri Narayan Das: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

- (a) whether any study is being made under the Indo-French Technical assistance to evolve any new system of transmission for the grid; and
- (b) if so, the precise nature of the problems which are being studied?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao); (a) Yes.

(b) The studies relate to the Eastern Regional Grid (comprising the power systems in the States of Bihar and West Bengal including the DVC system and Orissa) and are being carried out with a view to evolve the requirements of transmission system by the end of 4th Plan period and also to obtain a broad long-term picture of generation and transmission requirements for the 5th and 6th Plan periods.

V.D. in Kerala

2829. Shri Koya: Will the Minister of Health be pleased to state:

- (a) whether the Government have any scheme for the cure of venereal diseases in Kerala State on the lines of suggestions made by the Association for Moral and Social Hygiene in India; and
- (b) if so, the main features thereof?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). There is no scheme under consideration of Government in Kerala State on the lines of suggestions made by the Association for Moral and Social Hygiene in India. However, under the Centrally-aided V.D. Control Programme being operated in the country during Second and the Third Five Year Plans six District V.D. Clinics have been established in Kerala State. Central assistance to the extent of 75 per cent. non-recurring and 50 per cent recurring expenditure is being provided to the State Government. In addition to this, PAM is being supplied free of cost for the V.D. clinics and stipends are granted to the candidates sponsored by the State Government for training in V.D. Control.

Malaria Epidemic in Kerala

2821. Shri Koya: Will the Minister of Health be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Malaria is still rampant in certain cities in Kerala: and
- (b) whether Government have decided to withdraw the National Malaria Eradication Team; and
 - (c) if so, the reasons therefor?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) No.

- (b) Yes.
- (c) All the 14.5 National Malaria Eradication Programme units functioning in the State, after achievement

of Malaria Eradication, have entered the Maintenance phase where necessary vigilance services to prevent reintroduction of malaria are taken over by the general health services of the State. To that end the service is being strengthened.

Small-Pox in Kerala

2822. Shri Koya: Will the Minister of Health be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Smallpox was spreading in certain areas in Kerala State;
- (b) whether Government have decided to wind up the activities of the National Small-Pox Eradication Programme at such a stage; and
- (c) if so, the stage at which the matter stands at present?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) No. There have been only 24 cases and 6 deaths during the months of January, February and March, 1965 in the Kerala State which has a population of about 184 lakhs (mid-year estimated population of 1965). These cases were confined to three districts, namely, Kozhikode, Trichur and Cannanore. No cases were reported from the remaining six districts.

- (b) No. All the six eradication units set up during the previous year are functioning during the current year and are expected to complete the mopping up operations during the year in the entire State.
 - (c) Does not arise.

Seizure of Gold at Moradabad

2823. Shri Kindar Lal: Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a member of a gang of gold smugglers was arrested by the Central Excise Staff at the local bus stand at Moradabad while he was alighting from a bus on the 11th April, 1965 and gold bullion worth about Rs. 18,000 was seized from him; and

(b) if so, the action Government propose to take in the matter?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) On the 8th April, 1965 gold valued at about Rs. 7,500/- was seized by the Central Excise staff from a person at Moradabad Bus stand.

(b) The person was arrested. The case is under investigation.

12 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

AUDIT REPORT (COMMERCIAL) 1965

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): I beg to lay on the Table a copy of Audit Report (Commercial) 1965, under article 151(1) of the Constitution. [Placed in Library. See No. 2T-4299/65].

RESOLUTION TO RECOMMENDATION OF CENTRAL WAGE BOARD FOR PORT AND DOCK WORKERS

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya): I beg to lay on the Table a copy of Government Resolution No. WB-21 13)/65, dated the 27th April, 1965, regarding the recommendations of the Central Wage Board for port and dock workers at major ports. [Placed in Library. See No. LT-4300/65].

ANNUAL REPORT OF NATIONAL BUILD-INGS CONSTRUCTION CORPORATION, 1963-64 AND REVIEW BY GOVERN-MENT.

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

 (i) Annual Report of the National Buildings Construction Corporation Limited, New Delhi, for the year 1963-64,

(General), 1962-63

along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

(ii) Review by the Government on the working of the above Company.

[Placed in Library, See No. LT-4301/65].

AMENDMENT TO KERALA GENERAL SALES-TAX RULES AND NOTIFICATION UNDER CUSTOMS ACT

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

- (i) Notification No S.R.O. 44/65, published in Kerala Gazette dated the 23rd February, 1965, making certain amendment to the Kerala General Sales-tax Rules, 1963, under sub-section (3) of section 57 of the Kerala General Sales Tax Act, 1963, read with clause (c) (iv) of the Procdated the lamation March, 1965, issued by the Vice-President discharging the functions of the President, in relation to the State of Kerala. [Placed in Library. See No. LT-4302/65].
- (ii) Notification No. G.S.R. 569, dated the 9th April, 1965, under section 159 of the Customs Act, 1962.

[Placed in Library. See No. LT-4303/65].

12.031 hrs.

ESTIMATES COMMITTEE

EIGHTY-THIRD REPORT

Shri A. C. Guha (Barasat): I beg to present the Eighty-third Report of the Estimates Committee on the Ministry of Education-Visva Bharati University.

12.021 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

THIRTY-EIGHT REPORT

Shri Morarka (Jhunjhunu): I beg to present the Thirty-eight Report of the Public Accounts Committee on the Appropriation Accounts (Civil), 1962-63 and Audit Report (Civil) 1964 relating to the Ministries of Industry and Supply (Department of Supply and Technical Development), Information and Broadcasting, Transport (including Port Trusts of Calcutta, Bombay and Madras), Department of Social Security and Audit Report (Commercial), 1964 relating to the Ministry of Information and Broadcasting.

12.031 hrs.

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

THIRD REPORT

Shri Siddananjappa (Hassan): I beg to present the Third Report of the Committee on Government Assurances.

12.031 hrs.

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1962-63

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): I beg to present a statement showing Demands for Excess Grants in respect of the Budget (General) for 1962-63.

12.031 hrs.

REPRESENTATION OF THE PEO-PLE (AMENDMENT) BILL.

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): On behalf of Shri A. K. Sen, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950."

The motion was adopted.

Shri Jaganatha Rao: I introduce the Bill.

12.04 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS—contd.

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE
—contd.

Mr. Speaker: The House will resume discussion on the Demands for Grants under the Ministry of Food and Agriculture. Out of nine hours allotted, 2 hours 50 minutes have been taken, and 6 hours 10 minutes remain. Shri Radhelal Vyas to continue his speech.

श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़): मंत्रो महोदय बहस का जवाब कब देंगे ?

Mr. Speaker: Can the Minister sit for a few more minutes and reply today? (Interruption).

Several hon. Members: Tomorrow.

Mr. Speaker: All right; tomorrow.

भी प्रकाशबीर शास्त्री (बिजनीर) : ग्राध्यक्ष महोदय, मैं ग्राप से एक जानकारी बाहता था। ग्राप ने शायद भाज के समाचार पत्रों में इस श्राशय की खबर पढ़ी होगी कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मन्त्रिणी श्रीमती सुंचेता कृपलानी ने केन्द्रीय खरकार की जिम्मेदारी की चर्चा करते हुए। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में यह कहा है कि प्रलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय जो एक बिल्कुल पाकिस्तानी युनि-

सभा में यह कहा है कि भ्रलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय जो एक विल्कुल पाकिस्तानी युनि-वरसिटी हो गई है वह भ्रलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय केन्द्रीय सरकार के जिम्मे है

म्राप्यक्ष महोवय : म्राप ने मुझे इस बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी कि ग्राप यह मामला म्राज हाउस में उठाना चाहते हैं।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री: इस विषय पर मैंने आपको एक कौलिंग अटेंशन नोटिस दिया था जिसे कि आपने यह कह कर श्रस्वीकार कर दिया था कि वह राज्य सरकार का मामला है श्रीर वह उसके अधीन है लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्य मन्त्री ने विधान सभा में कहा है कि यह केन्द्र की जिम्मेदारी है...

प्रध्यक्ष महोदय: ग्राप मुझे लिख दीजिये या मुझ से मिल लीजिये ग्रीर हम दोनों इस पर बैठ कर बात कर लेंगे।

श्री मौर्य (भ्रलीगढ़) : म्रध्यक्ष महोदय, मैं श्रलीगढ़...

ग्रध्यक्ष महोदय: जब मैंने उनको इजाजत नहीं दी तो फिर ग्रापको कैसे दे सकता हूं? ग्राप बैठ जायें। श्री राधेलाल व्यास।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

ग्रध्यक्ष महोबय : कोई व्यवस्था का सवाल नहीं उठता है। एक काम खरम हुन्ना है ग्रीर दूसरा शुरू होने जा रहा है।

श्री रामेश्वरानन्तः पहला खत्म हो गया है श्रोर दूसरा श्रभी शुरू होना है तो मैं अपनी व्यवस्था का सवाल जो कि श्रध्यक्ष महोदय श्राप से सम्बन्धित है उसे उठा सकता हूं। मैं

^{*}Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 29th April 1965.

ग्रापं से जानकारी चाहता हूं ग्रीर ग्राप वह जानकारी मुझे दे सकते हैं।

श्रम्यक्ष महोदय: श्रगर मैंने उन दो मान-नीय सदस्यों को जानकारी नहीं दी तो फिर स्वामी जी श्रापको कैसे दे सकता हं?

श्री रामेश्वरानन्द : वह श्राप से सम्बन्धित है इसलिए मैं श्राप से उस बारे में जानकारी लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: फिर ग्राप मुझ से मिल लीजिये या जहां ग्राप कहिये मैं वहां ग्राकर ग्राप से मिल सकता हूं।

श्री रामेदंबरानन्व : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं...

भ्रष्यक्ष महोदय: इस वस्त कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है।

श्री रामेंडबरानन्द: मुझें ग्राप से जान-कारी लेनी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं हाजिर हूं मुझ से चैम्बर में आकर मिल लीजिये । अब मेहर-बानी करके हाउस की कार्यवाही मुझे आगे चलिन दीजियें ।

बी रावेसास स्यास (उज्जैन) : मन्यक महोदय, मैंने पिछले दिन यह निवेदन किया या कि हमारे देश में भनाज की कंसी की समस्या कई सालों से चली घा रही है घौर इस कमी को दूर करने के लिए कोई कार्तिकारी कदम उठाने की जरूरत है। म्राप देखेंगे कि सन् 1956 में हमारे यहां क़रीब 14 लाख टन मनाज बाहर से माया या जबकि 1964 में 62 लाख टन मनाज हमारे यहां विदेशों से आया है। यह स्थिति एक बड़ी गम्भीर स्थिति है और कुछ सोचने भीर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि यह बढती हुई भ्रनाज की कमी जल्द से जल्द क्षर की जा सके । मैं ग्राप से निवेदन करना चाहता हूं कि काफ़ी प्रयत्न किये गये लेकिन

भभी तक सफलता नहीं मिली है तो इसके लिए हमें कुछ दूसरे रास्ते भी अब्स्यार करने चाहिएं।

मेरा सबसे पहला सुझाव तो यह है कि गवर्नमेंट इस बात पर विचार करे कि जो किसान भनाज बोते हैं, जिन बेतों मैं भ्रनाज बोया जाता है उस पर लगान को न लें। सरकार यह घोषणा कर दे कि जो किसान प्रनाज बोयेगा. खाद्यान्न बोयेगा उससे लगान नहीं लिया जायगा । इसके साथ यह कर दिया जाय कि जो किसान खाद्यान्न के ग्रलावा भौर कोई चीज बोयेगा उस पर लगान को बढा दिया जाय । किसानों को खाद्यान उगाने के लिए इस तरह से प्रोत्साहन देकर अन्न की कमी को दूर किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि इस तरह से किसान काफी भनाज बोर्येग भीर यह जो करोड़ों रुपया हुम बाहर से भनाज मंगाने में खर्च करते हैं वह रुपया हमारा बच सकता है।

दूसरे हमारी जमीन में श्रनाज बढाने के लिए पैदावार प्रति एकड़ बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की है वह हैं खाद भीर पानी की। खाद के लिए केवल फटिलाइजर फैक्टरीज बनाने से ही काम नहीं चलेगा । भ्राप कितनी ही फर्टिलाइजर फैक्टरीज बनाइये लेकिन हमारा इतना बढ़ा देश है और इतनी श्रधिक द्याबादी वाला देश है भौर भाबादी बढ़ती चली जा रही है कि हमारी खाद्यान्न की मांग दिन पर दिन बढती ही चली जा रही है भीर फटिलाइजर की मांग भी दिनों दिन हमारी बढती जा रही हैं। फटिलाइजर की मांग श्रीर जरूरत केवल फर्टिलाइजर फैक्टरीज बनाने से ही पूरी नहीं होने वाली है। इसके लिए हमें कुछ ग्रीर भी प्रबन्ध करना पडेगा। एक तरफ़ तो हम खाद 12.10 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the chair] की आवश्यकता अपनी पूरी करने के लिए फरिलाइजर फैक्टरीज लगा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ़ हम देखते हैं कि गोबर ओकि

[श्री राधेलाल व्यास]

बाद है उसका सही उपयोग नहीं होता है और बजाय उसे खाद की तरह से इस्तेमाल करने के ईंधन की शक्ल मैं उस गोबर को उपयोग मैं लाया जाता है। गोबर का सही उपयोग

इसलिए भी नहीं हो पाता है कि स्राख्रिर वेहातों के लोगों को ईंधन चाहिए, लकड़ी जलाने को चाहिए, ग्रौर उसके ग्रभाव मैं गोबर के कंडे बना कर उनको जलाना पड़ता है। ग्रगर गोबर के कंडे बना कर न जलायें तो प्रपना भोजन वगैरह कैसे बना सकते हैं ? क्या गवर्नमेंट ने कभी इसके लिए सोचा है कि उनको ईंधन का कोई एक ऐसा साधन देवें जिससे गोबर खाद के काम मैं म्रा सके। उन्हें सौफ्ट कोक, गैस या श्रौर कोई साधन भ्राग जलाने के लिए देवें जिससे खाद का जो इस तरह से भारी नाश हो रहा है वह बच सके श्रीर ऐसा होने से इस गोबर की खाद का मधिक म्रम्न उत्पादन में बहुत म्रच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि हमारे ग्रनाज की पैदावार को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। श्राज गोबर रूपी खाद का जो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है भौर खाद का इस तरह से किमिनल बेस्ट हो रहा है उसकी रोकथाम करने के लिए गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है ।

ग्राज हम देखते हैं कि लकड़ी प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े दरख्त बड़ी बेरहमी के साथ काटे जा रहे हैं और ग्राज जब कि शूगरकेन का भाव 2 रुपये मन है तब लकड़ी 3, साढ़े 3 ग्रीर 4 रुपये मन बिक रही है। शहरों में बड़े बड़े दरख्त जितने कट कर ग्राते हैं उनके स्थान पर क्या नये दरख्त लगाये जाते हैं? यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है जिस पर बिचार करने की जरूरत है श्रीर ग्रगर इसका जिल्दी प्रबन्ध नहीं किया गया तो में समझता हूं कि श्रनाज की हमारी समस्या ऐसी ही बनी रहने वाली है भीर वह सुधर नहीं सकती है।

एक भौर बड़ी गम्भीर समस्या की भोर भी मैं शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह ठीक है कि हमारे यहां सुधरे हुए खेती के भौजार होने चाहिए भौर ज्यादा से ज्यादा दैक्टर बनाए जाने चाहिए। लेकिन क्या इतने बडे देश में इतनी संख्या में टैक्टर बनाए जा सकते हैं कि वे सारे देश में सप्लाई किये जा सकें ? भीर क्या हमारे किसान उन ट्रैक्टरों को ले सकेंगे ? इस लिए मेरा निवेदन है कि बग़ैर बैलों के इस देश में खेती नहीं चल सकती है। जब तक बैलों की तरफ़ ध्यान नहीं दिया जायेगा, तब तक खेती में सुधार नहीं हो सकता है भौर न उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। भाप देखिये कि पिछले सात ग्राठ सालों में बैलों की कीमत किस कद्र बढ़ती जा रही है। श्राज बैलों की एक जोडी की कीमत लगभग एक दो हजार रुपये हैं। एक छोटे किसान का एक बैल जब मर जाता है, तो उसकी खेती कमजोर रह जाती है भौर उसके पास इतने पैसे भौर साधन नहीं होते कि वह नया बैल खरीद सके।

इसका कारण क्या है ? मैं कोई धार्मिक वृष्टि से नहीं, बल्कि बिल्कुल ग्राधिक दृष्टि से कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश में गोबध को नहीं रोका जायेगा, तब तक किसानों को ग्रच्छे बैल नहीं मिलेंगे।

श्री बजराज सिंह (बरेली) : धार्मिक वृष्टि से क्यों नहीं ?

श्री राषेलाल व्यास : धार्मिक दृष्टि तो है ही, लेकिन ग्राप इस समस्या को ग्राधिक पहलू से भी देखिए । ग्राज स्थिति यह है कि भच्छी ग्रच्छी दुधारू गायें कलकत्ता ग्रौर बम्बई जाती हैं ग्रौर जब वे दूध देना बन्द कर देती हैं, तो लोग उन को ग्रौर उनके बछड़ों को कसाईखाने में बेच देते हैं। इस का परिणाम यह है कि माज हमारे देश में मच्छे मच्छे मवेशियों की कमी होती चली जा रही है मौर इस लिए बैलों का उत्पादन भी कम होता जा रहा है। इस मवस्था में बैल बहुत महंगे होते जा रहे हैं भौर दूध देने वाले जानवरों की संख्या भी कम होती जा रही है। किसी समय पंजाब गाय, बैल भौर भैंसों का घर समझा जाता था, लेकिन वहां भी उन की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। वहां से सारे देश में पशु जाते हैं भौर जब बे दूध देना बन्द कर देते हैं, तो उन की कटाई गुरू हो जाती है।

एक माननीय सबस्य : शेम, शेम ।

श्री राधेलाल व्यास: "शेम, शेम" कहने से काम नहीं चलेगा। जो भाई "शेम, शेम" कहते हैं, उनको गायों से कोई विशेष प्रेम नहीं है झौर वे गौपालन के लिए कोई काम नहीं करते हैं। केवल "शेम, शेम" करने से ही गोहत्या बन्द नहीं हो जाती है श्रौर गौपालन नहीं हो जाता है।

जब पहले यह सवाल पालियामेंट में उठा बा, तो एटार्नी-जैनेरल को बुलाया गया था और उन्होंने यह राय दी थी कि यह स्टेट्स का विषय है और केवल स्टेट गवर्नमेंट्स ही यह कानून बना सकती है। मैं समझता हूं कि अगर इस सम्बन्ध में कांस्टीट्यूशन में संशोधन करने की जरूरत हो, तो उस पर विचार किया जाये, आवश्यकता इस बात की है कि सारे देश में गोवध तत्काल बन्द किया जाये और जितने भी दूसरे दुधारू पशु हैं, उनके वध भी निषेध किया जाये। अगर ऐसा न किया गया, तो उसकी आड़ में अच्छे पशु भी कटते जायेंगे और उस का प्रभाव हमारी खेती पर पड़ेगा।

मध्य प्रदेश में उत्पादन हिन्दुस्तान के हर एक राज्य से कम है, लेकिन फिर भी वह स्टेट सरप्लस है। इस साल मध्य प्रदेश ने साठ करोड़ रुपये का चावल दूसरी स्टेट को दिया है। प्रश्न यह है कि ग्रनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन किसानों को

लोन नहीं मिल पाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बार-बार यह वादा किया है कि किसानों को जितना कर्ज चाहिए, वह दिया जायेगा। पिछले साल इस के लिए रकम इस लिए नहीं दी गई कि राज्य सरकार ने देर से उसकी मांग की। इस साल तो राज्य सरकार ने काफ़ी समय पहले ही मांग की है, लेकिन मुझे ग्रफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि किसानों को जितना कर्ज मिलना चाहिए, वह नहीं मिला है। मैं खाद्य मन्त्री ग्रौर वित्त मन्त्री से यह निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश एक पिछड़ा हम्रा राज्य है, जिसमें साधन बहुत कम हैं, बहुत ग़रीबी भीर बेरोजगारी है भीर इसके अतिरिक्त 34 प्रतिशत मादिवासी भौर हरिजन हैं। भगर शासन किसानों को देने के लिए कर्ज की व्यवस्था नहीं करेगा, तो वहां भ्रनाज की पैदावार नहीं बढ़ सकती है, ग़रीबी दूर नहीं हो सकती है श्रीर बेरोजगारी नहीं मिट सकती है। इसलिए मध्य प्रदेश को साधन उपलब्ध किये जाने चाहियें।

वह राज्य इरींगेशन में भी बहुत पीछे है। इसके लिए अधिक से अधिक रकम दी जानी चाहिए, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सके और उत्पादन में भी वृद्धि की जा सके।

काफ़ी दिन हो गए, गौहाटी और मध्य प्रदेश में फ़ारेस्ट्स के सम्बन्ध में रिजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का फ़ैसला किया गया था, लेकिन अभी तक उसकी मंजूरी नहीं दी गई है। एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में भी इस बात की शिकायत की गई है कि उस संस्था को अभी तक कायम क्यों नहीं किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस इंस्टीट्यूट को शीध्र से शीध्र मध्य प्रदेश में कायम करने की व्यवस्था की जाये।

चम्बल रेवाइन्ज डाकुओं का क्षेत्र बना-हुमा है। यह बड़ा गम्भीर सवाल है। जब कैरों साहब की हत्या हुई, तो उसका पता लगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी ताकत लग गई।

श्री राधेलाल व्यास]

लेकिन मध्य प्रदेश में तो एक एक गांव में एक एक दिन में ग्यारह ग्रादमी गोली से मारे जाते हैं। इसी कारण लोग देहातों की छोड़ कर गहरों की स्रोर जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस क्षेत्र को डवैलप करने श्रीर वहां की भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए एक स्पेशल प्राजैक्ट तैयार करे ग्रीर इस समस्या को स्वयं हल करने का प्रयत्न करे।

Shri Balakrishnan (Koilpatti): Mr. Deputy-Speaker, I rise to support the demands of the Ministry of Food and Agriculture. While doing so, I must first congratulate the hon. Minister of Food and Agriculture for the efficient manner in which he has tackled the food problem and averted a crisis which threatened our country some time back.

Food is a very important subject. Being an agricultural country, majority of the population depend on agriculture for their livelihood. Therefore, special attention and priority should be given to the development of agriculture. It is no doubt true that a good deal of development has taken place in the field of agriculture. During the British regime there was not even one big project in like Nangal or Damodar. But after independence, within seventeen years, so many gigantic irrigation projects have been taken up from Himalayas to Cape Comorin. Even then, country requires much more of development work in the field of agriculture because our country is still facing shortage of food. While country is facing food shortage, the population is increasing day by day. The rate of increase of population is on geometrical progression while production of food increased only by arithemetical progresssion. So, it is all the more necessary that special attention should be paid to the improvement of agricultural production.

other day, Shri Kailash Chandra, Secretary to the Depart-

Parliamentar_v Affairs, of arranged for the MPs a visit to some of the block areas under the Delhi Administration. So, I had the privilege of visiting some of the block areas. While travelling in the bus I saw a vast area of fertile land lying idle. I asked the block development authorities who were travelling with us the reason for such vast areas of fertile land lying idle. They that the Ministry of Housing had acquired about 10,000 acres of land for colonisation purposes and they lying idle for the last seven years. It is a national waste. If that land is required for construction work, until the construction starts it could be utilised for agricultural purposes. Therefore, I would request the Minister of Food and Agriculture to comtact the Ministry of Housing and see that this land is cultivated until the construction work is taken up.

Then, in the block areas I saw a farmers' club, which is a very good club. It is known as hundredmaunds club. The object of that club is to see that the production increases to 100 maunds per acre within a few So far only three members have joined that club. It seems now the average production is only 20 to 25 maunds per acre. They said that within two years of their starting the club they reached about 75 msunds per acre and the farmers believe that by next year they would reach the target of 100 maunds per acre. So, it is a very good club which creates enthusiasm and determination ong the farmers to produce more and more and I ask the Minister to popular se and extend such activities throughout the country.

Then, I saw the seed multiplication. I ask the farmers about hybrid maize and the farmers told me that hyorid maize gives double the yield. So, why could not this kind of variety be popularised throughout the country? Here, with your permission, I want to refer to the Report of the Estimates Committee. It said:—

"It is recognised on all hands that the available supply of improved varities of seeds falls far short of the country's requirements. For instance, out of a total acreage of about 10 million acres under maize, only approximately 82,000 acres are estimated to have been planted with the high yielding hybrid varieties in Kharif, 1963.

* * * *

The Committee would, therefore, urge the Government to launch without any avoidable delay, a country-wide crash programme for the multiplication of seeds of improved varieties as well as for the proper distribution of such seeds among the farmers."

This is the Report of the Estimates Committee about the hybrid variety.

When we compare the productive capacity of our country with that of other advanced countries, we that our productive capacity is very, very low because our farmers are using only the very old wooden type of ploughs and other farm implements. It is not because they do not want to use the advanced type of mechanical farm implements, but it is because they do not get the advanced types of mechanical implements. Wherever our ministers, whether Central State, go and whenever they the farmers, they advise our farmers to throw out the old type of farm implements and take to the mechanical type of implements. But who is supplying to them the advanced type of mechanical implements? The other day I saw in our newspapers that the Madras Chief Minister advised the farmers to use the mechanical type of farm implements. The are ready to take to the advice of the ministers in case the Government is prepared to supply them the implements.

496 (Ai) LS-4.

Last year our Deputy Food Minister announced in the House that the Government has issued licences to companies to produce small tractors, power tillers and crushers and other type of farm implements. But I do not know whether the companies are producing the implements or not. Anyway, I must request the Government to see that some industries in the public sector are started to produce these implements. This is a very important matter.

Regarding Cement, it is a common complaint—wherever we go the farmers are saying this—that they do not get cement in time for the purpose of construction of cattle sheds and wells. So, I must ask the Government to see that a special allotment is made only for the purpose of farmers' use.

Regarding minor irrigation schemes, there are some schemes which neither minor irrigation schemes nor major irrigation schemes. Such schemes become orphans. For ample, in my Taluk there are some schemes. I know, our hon. Minister knows it. There are three schemes-Palar-Purandalar, Kuthiraior Verdamma River schemes—which are neither major nor minor schemes and such schemes are given stepmotherly treatment. Such schemes should be given priority so as to be of benefit to the farmers as well as the country.

श्री बृजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हर साल बजट के समय में से कृषि के लिए भी कृष्ठ समय दिया जाता है, इस पर थोड़ी सी बहस करने के लिए समय दिया जाता है। इससे एसा लगता है कि जैसे कोई त्यौहार मनाया जा रहा हो या श्रंप्रजी में जिसे रिचुंग्रल कहते हैं, उसको पूरा किया जा रहा हो। खाली एनुग्रल एक्सरसाईज इस सदन में होती हैं। हर साल बजट पेश होता है, हम लोग इधर से कुछ सुझाव देते हैं लेकिन ये सुझाव भगवान जाने कहां चले जाते हैं। कृषि की

[श्री बृजराज सिंह]

हालत जैसी तब थी वैसी भी भ्राज रह गई होती तब भी कोई बात थी। तो भी हम भग-वान् भीर इस सदन को दुग्रांये देते, इस सरकार को दुधायें देते परन्तु हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। एक दुख सा हमेशा दिल में हुया है इसकी वजह से। ग्राज भी जो कार्य हुन्ना है या हो रहा है, उसके बारे में मुझे किसी शायर का यह शेर बार बार याद श्रा रहा है:

D. G.-Min.

मर्जद्रक पर रहमत खुदाकी। मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की ।

म्राप देखें कि दवाई करने वाले ये म्रालिम भौर फाजिल कैसी दवाई देते हैं। इनको मर्ज मालुम हैं, काइलकार का क्या मर्ज है, इसको ये भ्रच्छी तरह से जानते हैं लेकिन फिर भी उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। गरीबी के मर्ज का इलाज हिन्दुस्तानी तरीके से, हिन्दुस्तान कर नहीं पा रहा है। यूनानी, मिश्रानी, एलोपैथी, होम्योपैथी ग्रादि इलाज सोचे जा रहे हैं। हमें बताया जाता है कि जापानी मैथड करो, हमें बताया जाता है इजिपशियन मैथड करो, हमें बताया जाता है कि चीनी मैथड करो। क्या न करो, बस जो कुछ हिन्दुस्तानी है वह मत मत करो।

मैंने पिछले साल भी इस सदन में जब इसके बारे में कहा था तो लोगों की सीटें थोड़ी गर्म होने लगी थीं। मेरा विश्वास है कि इस साल भाप लोग शायद बरदाश्त का मादा लेकर भाये होंगे। मैं वही बात दोहराने जा रहा हूं। हमारी सरकार, मुझे एसा लगता है कि काश्तकार का ब्रेन वाशिंग कर रही है। सबसे पहले उसे यह समझाया जा रहा है कि तुम भ्रपने हृदय में यह समझ लो कि तुम से बड़ा उल्लू इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, तुम्हें कुछ भाता नहीं भौर जिस दिन तुम यह मान लोग कि तुम्हें कुछ घाता नहीं, उसी दिन तुम्हारी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। ए० **डी० ग्रो० साहब, बी० डी० ग्रो० साहब,**

श्रंडी इंसपैक्टर साहब सभी नई-नई चीजें ही उसको समझाते फिरते हैं। सभी यह कहते फिरते हैं कि काश्तकार उस सब को भूल जाये जो कुछ वह करता था रहा है। पहले तो इस तरह से उनका ब्रेन वाशिंग हमारी सरकार कर रही है। हमें यह बताया जाता है कि हे काश्त-कार भले की तेरे तन पर कपड़ा नहीं है, भले ही तेरे पेट में रोटी नहीं है पर तेरी सरकार तेरा कितना ख्याल करती है, इस बात को तू क्यों नहीं देखता है, इस बात की तरफ तू क्यों ध्यान नहीं देता है, तू यह क्यों नहीं सोचता है कि तेरी तरक्की हो रही है।

दूसरा हमारा ब्रेन वार्शिग पोस्टरों के जारिये से, सरकारी प्रस्तावों के जारिये से, ब्लाक हैडक्वार्टर्ज से तथा दूसरी जगहों से हमेशा यह समझाने का प्रयत्न करके किया जाता है कि तुम बड़ी तरक्की कर रहे हो श्रौर जब कभी कोई शार्ट-कॉमग्ज होती है, जब कभी हम नीचे गिरते हैं, कमजोर बनते हैं, फसल नष्ट हो जाती है तो यह मूल मन्त्र हमें समझाया जाता है कि यह तो भगवान् ने तुम्हारे साथ कीप कर दिया है, क्या करें, स्रोला पड़ गया, क्या करें बारिश नहीं हुई। जो मूल कारण है उसको जब हम बतलाने की कोशिश करते हैं तो कभी हमारी सरकार सुनती ही नहीं है। मैं इस सदन के हर पक्ष से निवेदन करना चाहता हुं कि वे ग्रभी भी चेतें, चेतें इसलिए कि ग्रपना कर्त्तव्य निभाने के लिए सरकार की भांखें खोलें ताकि वह जो भारतवर्ष के कृषक की मूल समस्या है, उसकी ग्रोर ध्यान दे। हम कभी उन्नति कर नहीं सकते हैं उस दिन तक जिस दिन तक हमारी कृषि उन्नत नहीं होती है। मैं विश्वास दिला कर कह सकता हूं कि उस वक्त तक न हमारे कारखाने चल सकते हैं, न हमारी सुरक्षा चल सकती है, न हमारे उद्योग बढ़ सकते हैं, न हमारा ज्ञान बढ़ सकता है, न हमारा मान बढ़ सकता है श्रीर न ही हमारा सम्मान बढ़ सकता है। सबसे पहले यदि हमें माती बनना है, जानी बनना है, शौर्यवान

बनना है, तो इस कृषि की समस्या को, अपने गल्ले की पूर्ति की समस्या को हमें हल करना होगा। जब तक ग्राप इस समस्या को हल नहीं करते तब तक इस देश की कोई उन्नति नहीं हो सकती। यह चीज ऐसी नहीं है जिस को मैं कहं कि मैंने ही समझा है। समझा तो सरकार ने भी है। हमारे पिछले प्रधान मन्त्री जब-जब भी खड़े हुए बोलने के लिये, जिस विषय पर खड़े हुए बोलने के लिये, उन्होंने सदा एक बात कही कि जिस देश की कृषि पूरी उन्नत नहीं है उस देश का कुछ भी उन्नत नहीं हो सकता । हमारे ग्राज के प्रधान मन्त्री ने भी बीसों बार कहा है कि इस बात को । वह समझते हैं। वह गांवों की हालत को भी जानते हैं। परन्तु इसका रास्ता क्या है, इसमें सदा बहकते हैं। बहकते इसलिये हैं कि वह अपने मनोबल में कमजोर हैं। वह समझते हैं कि जो हम जानते हैं वह सबसे ज्यादा गन्दा है, सबसे ज्यादा बेकार है भौर जो कोई बाहर वाला बतलायेगा वही एक रास्ता है जिससे हम उन्नत हो सकते हैं। मेरा एक निवेदन यह है कि ग्राप ग्रपने काश्त-कार के इस मनोबल को नीचा मत कीजिये।

में ग्रापको ग्रवनति के दो एक लक्षण बतलाता हं। मेरा निवेदन पहले से भी रहा है कि ग्राप ने इन चीजों को सोचा नहीं। ग्रगर काश्तकार श्रपनी सारी जमीन को बोने की तरफ ध्यान लगा दे तो क्या होता है कि उसे जलाने के लिये लकड़ी नहीं रह जाती, छप्पर डालने के लिये फुस नहीं रह जाता, चराने के के लिये चरागाह नहीं रह जाता, भीर भगर वह इन चीजों की तरफ देखता है तो उसके पास बोने के लिये जमीन नहीं रह जाती। जहां भी हम जमीनों को तोडने के लिये जाते हैं, वहां पर करोड़ों रुपये, ग्ररबों रुपये, खर्च करके जमीन तोड़ते हैं, परन्तू यहां का काश्तकार वहां जाने श्रीर काम करने के लिये तैयार नहीं होता । डिस्क्लेस्ड पर्सन्स को वहां ले जाकर हम बसाते हैं । उनके बसने के बाद भ्रापके स्वयम् के एक्सपर्ट्स तीसरे साल वहा जाकर बतलाते हैं कि वह जमीन कृषि योग्य नहीं है।

करोड़ों रुपये इधर फूंक दिये, करोड़ों रुपये उधर फूंक दिये, करोड़ों म्रादिमयों के मनोबल को खराब कर दिया; करोड़ों रुपये लगा कर म्राप ने दण्डकारण्य को तोड़ा। उसको तोड़ने के बाद एक्सपर्ट्स ने कह दिया कि वह जमीन कृषि योग्य नहीं है।

इस प्रकार के कारनामे होते इन लिये हैं
कि भ्राप को भ्रपने ऊपर भरोसा नहीं है, काम्तकार के ऊपर भरोसा नहीं है, भ्रपनी बुद्धि और
भ्रपने ज्ञान के ऊपर भनेसा नहीं है। भ्राप को
चाहिये क्या कि विलायत का कोई धर्मामीटर
भ्राकर रजिस्टर करे भ्राप की शक्ति को, बतलाये कि हमारे अन्दर बुद्धि है। तब हमारी
समझ में भ्राता है कि हमारे बुद्धि है। भ्रपनी
बुद्धि को जानने के लिये कोई विदेशी धर्मामीटर
लगाया जाये तब भ्राप को भ्रपनी बुद्धि मालूम
पड़ती है। यहां क्या होता है कि हम को हर
चीज विदेशी चाहिये। जो भी बात विदेशी भ्रा
कर बतलाये वह भ्राप करना चाहते हैं।

हमारे यहां गल्ला बाहर से श्राया । चलिये, श्राप विदेशों से गल्ला मंगाते हैं, श्राता है। उसके हैंडलिंग चार्जेज के लिये सारे यु० पी० के श्रन्दर मेरठ है, इलाहाबाद है, कानपुर है, एस्टिमेट लगाया गया । मेरा ख्याल है कि कोई दस लाख ६पये का एस्टिमेट लगाया गया हैंडलिंग चार्जेज के लिये कि इतना खर्च होगा । मगर वहां हमा क्या । ठेकेदारों के टेन्डर माने लगे ग्रौर ग्रपने ग्रपने इंटरेस्ट लोग चलाने लगे । कुछ म्राईटेम पर थोडा सा पैसा यहां दिखला दिया भ्रौर ऐग्रीगेट में थोडा पैसा निकला। कहा गया कि जो लोएस्ट टेन्डर है उसे देदो। जो छोटे-छोटे माइटेम्स थे उनको रह कर दिया । उनमें जो बहे-बड़े पैसे वाले भाइटेम्स थे उनको फायदा कराया, श्रपने साथियों का करोड़ों रुपयों का फायदा करवाया भ्रौर दस लाख के बजाय पच्चीस लाख रुपयों का फायदा करवाया ग्राप का एस्टिमेट न हो गया, तमाशा हो गया। हैंडलिंग के खर्च के लिये कोई विदेशों से ग्राये ग्रौर बतलाये कि ग्रमुक ग्रमुक तरीके करना।

[श्री बृजराज सिंह]

आप को अपने उत्पर भी कुछ विश्वास होना चाहिये। क्या बतलाये जायेंगे दस लाख रुपये और खर्च किये जायेंगे पच्चीस लाख रुपये। सिंदरी के कारखाने में 20 लाख रुपल्ली के फारेन एक्सचेंज की आवश्यकता थी क्योंकि वहां नई मशीनरी लगानी थी। वह नहीं लगाई गई, उसके बजाय दस करोड़ रु० इस में फूक देंगे ग्राप की भाई, सिंदरी का कारखाना चले या न चले, मगर विलायत के कारखाने जरूर चलने चाहियें। बहां की खाद यहां ग्राकर पड़नी चाहिये। यह क्या है। यह ग्राप कृषि की उन्नति कर रहे हैं श्रीर फिर तरह-तरह के ग्राप्यासन देते हैं।

जरा भाप गौर कीजिये, यहां बजट सेशन होता है। मैं प्रधान मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि वे जरा इस बात पर गौर करें । हमारा बजट सेशन होता है मार्च में । मार्च में हम निर्णय लेते हैं कास्त के मुताल्लिक कि हमारे पास इतना गल्ला श्रायेगा । जो गल्ला श्राने वाला होता है वह ग्राता है मई भीर जून में, लेकिन मार्च में श्राप भ्रपना बजट बना कर बैठते हैं भीर स्वयम को धोखा देते हैं, देश को धोखा देते हैं। नतीजा यह होता है कि श्राप को झुठ बोलना पड़ता है कि हवा जरा गर्म चल गई थी इसलिये यह नहीं हो सका, यह हो गया, हवा जरा तर चली भौर पानी चार दिन पहले बरस गया, हमारा बैरोमीटर धोखा दे गया यहां वाला, इस-लिये गलती हो गई श्रौर श्रनाज इतना नहीं श्राया । यह क्या मजाक है । श्रंग्रेज श्रपनी एक परम्परा छोड़ गये कि 31 मार्च को बजट पास होना चाहिये । क्या है 31 मार्च में । कौन सी सैंक्टिटी है उस की कि भारतवर्ष में भ्राप 31 मार्च तक बजट बनाते हैं । जब श्राप का सारा व्यापार दशहरा पर चलता है, दीवाली पर चलता है, श्राप के सारे त्यौहार परम्परा के हिसाब से चलते हैं, हर फसल के बाद एक त्यीहार हो जाता है, उस को हम मनाते हैं, तो कहते हैं कि यह कम्यूनलिस्ट लोग हैं, यह स्यौहार की बात करते हैं, लेकिन 31 मार्च को बजट आप बनाते हैं उस से आप झूठे हो जाते हैं। इस से आप का मनोबल नीचे चला जाता है, देश का मनोबल नीचे चला जाता है, लेकिन तारीख बदलने से आप को डर लगता है।

श्री राघेलाल व्यास : 31 मार्च तक दोनों फसलों का सही ग्रन्दाजा लग जाता है।

श्री बुजराज सिंह : ग्राप बैठ जाइये । **धा**प को सारी बातें मालुम हैं, धाप के दिल में भी तकलीफ है, लेकिन चुंकि जनसंघी बोल रहा है इसलिये आप उस की बात नहीं मान सकते ; में कोई शक नहीं है कि हमारे व्यास जी चाहते हैं कि गाय की हत्या न हो, उन को प्रच्छे बछड़े चाहियें लेकिन चुंकि इधर से जनसंघी ने कह दिया कि धिक्कार है इस सरकार पर, तो कहते हैं धिक्कार नहीं, धिक्कार मत बोलना । ग्रगर मैं ग्राज कह रहा हूं कि गोवध के खिलाफ कानून नहीं बना तो कहते हैं कि तुम्हारे कहने से नहीं बनेगा, हम कहेंगे तब बनेगा । यह क्या है । भ्राप समझते हैं कि यह तरीका गलत है। भाप जानते हैं कि इस से 45 करोड़ घादिमयों का लाभ है लेकिन चूंकि दूसरे क्वार्टर से भ्राया है इसलिये वह नहीं किया जायेगा । खैर जाने दीजिए इस को।

मेरा निवेदन है कि आप इन बात्नें की तरफ ध्यान दें। मैं आप को बड़ें। फैक्चुअल बातें बतलाऊंगा । आप गांव में जा कर देखिये तो आप को हैरत हो जायेगी । यहां कहा जाता है कि हमारे नेताओं को और बड़े अफसरों को गांवों में जाना चाहिये ।

and Agriculture दूसरे साहब कहते हैं कि मैं तेलहन इन्स्पेक्टर हुं। गेहूं हो या न हो मुझे तो तेलहन उगाने से मतलब है। दूसरी चीज चूल्हे में जाये।

of Food

हैं कि ग्रेन मैन्योरिंग जरूर करो। इस तरह से सोलह सत्तरह इन्स्पेक्टर वहां जाते हैं। इस तरह से हर तरह के इंजेक्शन मरीज

तीसरी तरफ बी॰ डी॰ ग्रो॰ साहब कहते

को दिये जाते हैं।

एकर्ॅॅॅमित्री को दस बारह गांवों में जाना चाहिये। मैं ग्राप से कहता हूं कि जरा वह लोग भ्रपने गरेबान में मुंह डाल कर देखें कि गांवों में जाने से क्या कोई लाभ होता है। जिस समय मालूम होता है कि फलां मिनिस्टर ग्राने वाला है, फलां ग्रफसर ग्राने बाला है, वहां मोटर दौड़ जाती है। उन लोगों के गांव में जाने से क्या लाभ होता है । मैं पालियामेंट का एक साधारण मेम्बर हूं। जिस समय मुझे बी० डी० म्रो • ज्लाक में ले जाता है वह तीन दिन पहले से बतला देता है कि रूपिन पी० झाने बाला है।

उपाच्यक्ष महोदय : ग्रव ग्राप का समय समाप्त हो गया ।

श्री बुजराज सिंह : मैं बड़ी मजबूत भ्रीर पायेदार बातें बतला रहा हूं। मुझ को कम से कम बीस मिनट दिये जायें। 20 मिनट में मैं खरम[ू]ंकर द्वंगा ।

तो पहले से बतला दिया जाता है कि मैं एम । पी । साहब को लाने वाला हं, प्रधान जी ग्रा जाना, फलाने जी ग्रा जाना । म्रा गये । उन से पूछा तुम्हारे यहां फलां चीज कैसी हुई, बहुत ग्रन्छी । टिपलर का क्या नतीजा हुमा, बहुत भ्रच्छा निकला। एक गांव में गया तो वहां एक ग्रादमी कहने लगा कि साहब हम ने पिंचर डाला था। मैं ने पूछा पिंचर क्या होता है। कहने लगा यह खाद होती है। बी० डी० ग्रो० ने जल्दी से कहा कि यह मिक्स्चर कह रहा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पहिले से बतला कर जाने से कोई नतीजा निकलेगा । देहातों के ग्रन्दर ग्राप जा कर देखें तो मालूम होगा कि एक मरीज के पीछे 75 डाक्टर लगते हैं । इतने डाक्टरों की वजह से काम खराब होता है। एक साहब कहते हैं कि हम तो ग्रंडी इंस्पेक्टर हैं, हमें श्रंडी उगाना है, दूसरी चीज भाड़ में जाये।

मैं सुझाब के रूप में कहना चाहता हुं। मेरा निवेदन है कि ऐग्रिकल्चर मिनिस्टर साहब इस वत्त को गौर से सुन लें । माज रेवेन्यु के एक छोडे ग्रफसर को, जिस को लेखपाल कहते हैं. रक्खा जाता है । वह खाली पड़ताल करता है। फिर एक पैट्रोल रक्खा जाता है जो पानी की ग्रामदनी के लिये कैनाल पर पैट्रोलिंग करता है। फिर एक रक्खा जाता है पंचायत सेकेटरी जो वहां जा कर पंचायत की मीटिंग करवाता है । भौर जो इस प्रकार के 17 इंस्पेक्टर हैं उन को हटा दीजिए । ग्रापको भारतवर्ष का कृषक इतना पैसा बरबाद करने को नहीं दे सकता । श्राप इन को हटा दीजिए । केवल एक काम कीजिए जो विलेज लेविल वरकर है उसको कोग्रारडिनेटेड दीजिए, उस की तनखाह बढ़ा दीजिए मौर हर एक गांव को एक विलेज लेविल बरकर के जिम्मे कर दीजिए। इस को ही सारा काम करने दीजिए, हम को दूसरे इंस्पेक्टरों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन इंस्पेक्टरों से दूसरा काम लीजिए। हर गांव के लिए एक विलेज लेविल वरकर हो ग्रौर उनके ऊपर एक बी॰ डी॰ ग्रो॰ हो। इन तमाम इंस्पेक्टरों की भावश्यकता नहीं है। उन से कोई भ्रौर काम लीजिए।

एक और सुझाव दूगा । भ्राप ने भ्रब तक लैंड रिफार्म के नाम पर जनता में गदर मचा रखा है। कहीं 12 बोर की चला दी और कहीं भी नाट भी चला

[श्रीबृजराज सह]

दी । कहीं कोई स्टैंडर्ड है तो कहीं कुछ भीर स्टैंडर्ड है । इस मामले में राज्यों में एक स्टैंडर्ड नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि सेंटर को यह कह कर छुटकारा नहीं मिल सकता कि यह स्टेट सबजेक्ट है, स्टेट जैसा चाहे वैसा करे । भ्राप को इस समस्या पर एक न एक दिन विचार करना पड़ेगा । जब तक सेंटर का इफेक्टिव कंट्रोल फूड भीर एग्री-कल्चर के मामले में नहीं होगा तब तक इस में कभी तरककी नहीं हो सकेगी भीर भ्राप पूरा नहीं डाल सकेंगे ।

एक उदाहरण इस मामले में मैं भ्राप को दूं। पिछले सन्न में यह तै हुआ। कि चीफ मिनिस्टसं की कानफरेंस बुलायी जाए जोनल सिस्टम के बारे में उन की राय जानने के लिए । ग्राप को मालूम हो गया था कि जोनल सिस्टम खराब है, श्रौर भ्राप ने सदन में भी मान लिया था कि हम जोनल सिस्टम खत्म करेंगे । लेकिन ग्राप की हिम्मत उस को खत्म करने की नहीं हुई । पुल्स आए, प्रेशर भाए । भ्रगर कोई भ्रा कर कह देता है कि भ्रगर तुम ने इन को हटा दिया तो भ्रगले चुनावों में कांग्रेस को बोट नहीं मिलेंगे तो भ्राप डर जाते हैं। मैं सदन में नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन भ्राप चाहें तो ग्राप को बता सकता हूं। बड़े बड़े कांग्रेस नेताभ्रों ने कहा कि ऐसा मत करना नहीं तो कांग्रेस हार जायगी, तो भ्राप ने डर के मारे मान लिया। इसरे ने भा कर कहा कि भगर तम ने इन को खत्म नहीं किया तो धारी भाप को बोट नहीं मिलेंगे। फिर भाप डर गए भीर कहने लगे कि हम सोच रहे हैं, ग्रभी जल्दी न करो । वह कह गया है इसलिए श्रभी हम जल्दी नहीं करना चाहते । हम ने इस की खराबी को समझ लिया है, खत्म कर देंगे, जल्दी मत करो । फिर आप एक चीफ मिनिस्टरों की कानफरेंस बुलाते हैं भीर उन के सामने यह मसला रखते हैं। द्माप चाहते हैं कि ग्रगर वे कह दें कि इन को खत्म किया जाय तो भाप खत्म कर दें, जिम्मेवारी उन पर पड़े भौर काम ग्राप का हो । मैं कहता हूं कि इस तरह काम नहीं चल सकेगा । धाप ने पांच सात बार चीफ मिनिस्टरों की कानफरेंस बुलायी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि पुल धाते हैं, प्रेशर भाते हैं भीर भाप रुक जाते हैं। भ्राप का कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। श्राप को सेंटर से इफेक्टिव कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी यह समस्या हल होगी । श्रौर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप को इस मामले में पार्टीजन स्पिरिट से ऊपर उठना होगा, श्राप को देश की समस्या को देश की दुष्टि से देखना होगा । श्राप को यह नहीं सोचना होगा कि ऐसा करने से हम जीतते हैं या हारते हैं। ग्राप को देश सेवा की भावना से यह काम करना होगा । हारजीत का खयाल नहीं करना होगा । भ्रपोजीशन की तरफ से कोई भ्रच्छा भी सुझाव भ्राता है तो आप सोचते हैं कि अगर इस को मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगा।

एक माननीय सदस्य : भाप यहां इलेक्झन की बात क्यों करते हैं।

श्री **वृजराज** सिंह : वह बात तो करनी ही पड़ती है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : भ्रार्डर श्रार्डर । श्रव भ्राप खत्म कीजिए ।

श्री बुजराज सिंह : मैं प्राखिर में यही निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टीजन स्पिरिट से ऊपर उठं श्रीर देश की सारी समस्या को समझ कर श्रपनी पुरानी निष्ठा से उस को सुलझाने का यत्न करें । श्राप ने जनता से कहा था कि तुम्हारी बहबूदी के लिए हम गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज्य

लेने जा रहे हैं, भ्रगर उसी निष्ठा से भ्राज भ्राप काम करें तो यह समस्या जल्य सुलझ जाये हैं।

Shri Jena (Bhadrak): Sir, the very existence of living being is possible only by taking food needed for its existence. Therfore, food is an extremely essential thing for everyone of us to live.

India is well known throughout the wide world as an agricultural country from time immemorial, and we are proud of it. It has been said many a time by visitors from outside that India produces gold or India is Swarna Prasoo.

Before the achievement of independence, we had numerous problems and difficulties for which we used to hold the foreign rulers responsible. Now we are independent and we are not to blame anybody for any problem, however tough it might be. We have been independent for the last 18 years, which is not a veryshort period, although we have not been able to solve our food problem in this period.

India is a vast country. We have got many problems. Of course we have a Planning Commission to plan for the solution of our problems and take the country forward. The Planning Commission consists of expert and eminent persons of the country who plan for our social, economic, cultural and social development. I must congratulate them on their good labour and hard work.

We have already completed two Five Year Plans; the Third is on the verge of completion. We have solved many problems, no doubt. But so far as the food problem is concerned, our progress is not appreciable. Almost every year, we are buying food from foreign countries. In 1961, we imported foodgrains worth Rs. 129 crores, in 1962 the cost of foodgrains imports was Rs. 141 crores, in 1963

the figure was Rs. 183 crores and last our imports of foodgrains were of the order of Rs. 200 crores.

Our import figures of foodgrains are rising from year to year which is not a healthy sign of an independent agricultural country like ours. As I said, we have completed two Five Year Plans and are very soon to complete the Third. Still we have not been able to depend on ourselves only in the matter of food, although we belong to a country which has already built a tradition for agriculture and 80 per cent of whose people are engaged in agriculture.

There is no doubt that there are some defects in our agricultural production plans and activities. These should be remedied. The question of shortage of food is a gigantic problem which should be looked at from a national angle of vision. I should say it is no less grave a problem than that of the defence of our country. Therefore, we should have as much regard for the farmers and agricultural labourers as we have for our jawans defending the country.

Now our country is passing through a very critical period, internally and externally. We have been attacked by our two big neighbours, who have proved hostile to us, I mean China and Pakistan. Therefore, we will have to be on our guard not only for the defence of our country but also in the matter of food. We should be on cur guard against any threat from every direction, whether on the defence front or on the food front.

A few days ago we were discussing here and pressing the question of producing low-cost cars in the country. I ask: is it so essential or so necessary for a country like ours at this critical juncture when it is facing a food problem in an acute manner, is it so essential as the production of foodgrains? Therefore, whatever we demand or whatever we do, we should bear in mind that the common man gets the benefit out of the same.

[Shri Jena]

Many of us always demand that there should be price fixation on foodgrains. I welcome the proposal, but side by side with the fixation of the price of foodgrains, the prices of other consumer commodities should also be fixed. Generally, whenever the price of any consumer goods is fixed, the cost of production is taken into consideration. So, I fail to understand why the cost of production is not taken into consideration while fixing the prices of foodgrains. When we ask the State Government whether the cost of proconsideraduction is taken into they say it is the tion, that Central Government who have fixed the price and not the State Government. I ask a straight question of our Minister, whether the cost of production is taken into consideration when the price of foodgrains, particularly paddy in Orissa, is fixed.

This year, the maximum price of rice and paddy have been fixed in Orissa. That is why the purchase has become very dull and the producers are facing great difficulty. I would request the Food Minister to look into this difficulty and help us in getting over it.

The food question is a delicate one. We have not only to look to the interests of the producer, but to the interests of the poor consumers also.

When we import food, we are required to pay a high price and sell the same at a price within the reach of the masses. Similarly, we should see that neither the growers lose nor the consumers suffer.

All these bottlenecks can be avoided if our production meets our demand. Till then we shall have to wait. It is a very important question. I may be excused if I say that our sense of patriotism becomes stained and our pride in traditional agriculture becomes meaningless as long as we are deficit in food.

Now I should like to make some suggestions to the Government for production of more food.

First of all, our farmers should be made to feel that their crops are secure from floods, drought and insects which are common in our country. Expert advice should be given to our farmers in time in the matter of scientific farming. Good seeds, improved agricultural implements and good manure should be made available to the farmer. Before that we shall have to make a thorough investigation and examination of the soil.

We have got rain-fed non-flooded lands, rain-fed flooded lands, partially irrigated lands and perennially irrigated lands. One soil differs in quality from the other. Therefore, before we advise the farmer to grow a particular crop in a particular land with the application of a particular manure, we should have a thorough investigation and examination of the soil.

So, it is a tremendous task, but the Food Minister has, unfortunately, no agency of his own in the States. So, the Block Development staff's assistance might be necessary. They should be asked to come to the help of this Ministry.

I come from a flooded area of Balasore District in Orissa, Because of floods, crops are damaged every year, and there is a national loss. I am happy that the Planning Commission is proposing to dam all the rivers of India and use every drop of water in a good way. That is a very good proposal, but that will take more time and more money. Of course, they are going to do it, and it is happy thing. But till then I would request the Minister to do something for the flooded areas by providing tubewells, which will be useful in the autumn season, so that paddy can be grown in this season after the floods are over. For that our Food Minister might say that money will be necessary. Of course, it will be necessary, but we can divert portion of the money which we are spending on the import of foodgrains towards the digging of tubewells.

of Food and Agriculture

Within a very short time the tubewells will give us a very good dividend, and there will be no loss at all. I hope the Food Minister will consider this. He may also consider question of using subsoil water irrigation purposes particularly in the flooded areas.

the With these words, I support Demands.

श्री रा० स० तिबारो (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत प्रतीक्षा करने के बाद कोई डेंढ साल के बाद जो श्रापने मुझे बोलने का समय दिया है उसके लिए मैं भापका भाभारी हं। कितनी ही बार मैं उठा, बैठा हूं तब मुझे यह जो भ्रापने भ्रवसर प्रदान किया भ्रपने विचार प्रकट करने का उसके लिए मैं भ्रापको श्वन्यवाद देता हूं।

मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूं भौर कृषि मेरा विषय है। मैं हमेशा खेती पर बोलता भाया हुं भौर इस नाते भी मैं भ्रापको धन्यवाद देता हं कि ग्रापने मझे खेती के ऊपर बोलने का प्रवसर दिया। खाद्य मंत्रालय का ग्रसर सारे देश पर है भ्रौर हर नर नारी के ऊपर है भ्रीर इसलिए यह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। चंकि भोजन की व्यवस्था इस मंत्रा-लय के हाथ में है स्रौर भोजन हर एक स्रादमी के लिए भ्रावश्यक है इसलिए समस्त देश की इस बारे में विशेष दिलचस्पी होना ग्रौर इस पर सभी भ्रोर से चर्चा की जानी बिल्कूल स्वाभाविक है। लेकिन मुझे यह कहना है कि हमारे बहुत से विरोधी पक्ष के सदस्य न मालूग इस को किस ढंग से पेश करते हैं कि उसके ग्रसली मन्तव्य तक कोई नहीं पहुंचता है।

मैं भ्राप से निवेदन करूं कि पाकिस्तान के बन जाने के बाद यहां खाद्यान की कमी क्यों हुई ? उसका कारण साफ़ है कि बंटवारे के फलस्वरूप पाकिस्तान को एक चौथाई जमीन मिली, एक चौथाई हिस्सा पाकिस्तान को मिला और तीन चौथाई हिस्सा हिन्दुस्तान को मिला। श्राबादी जहां पाकिस्तान में 17.5

करोड़ थी वहां यहां माबादी 82.5 रही। यहां पर खाने वालों की संख्या घ्रधिक रही ग्रीर भूभाग कम रहा जबकि पाकिस्तान की भुभाग ज्यादा मिलाम्नौर पापुलेशन कम मिली। इसके भलावा उधर पाकिस्तान में से बहुत से घल्पसंख्यकों को इधर चले ग्राने को बाध्य कर दिया गया भौर शरणार्थियों के भाते रहने के कारण भी उसका खर्चा प्रत्येक दिन भारत पर बढ़ता जा रहा है। ग्राज देश में 5 प्रतिशतः या 7 प्रतिशतः जो कमी है उसका एक कारण यह भी है। दूसरा कारण यह है कि खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया इसके लिए उन काश्तकारों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। ध्रगर भ्रव भी सरकार नहीं चेती तो मैं समझता हं कि सारे उद्योग तथा ग्रन्य कारोबार देश के पीछे पड़ जायेंगे । किसी भी मुल्क के व्यवसाय, तब तक उन्नत नहीं होते जब तक कि वहां की खेती को सफलता नहीं मिलती है। बेती का धंधा दरग्रसल राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़ाने का धंधा है श्रीर राष्ट्र के धनोपार्जन का एकमात्र तरीका है देश की ग्रगर उन्नति करनी है तो पहले खेती को उन्नत करना है बाद में व्यापार श्रीर व्यवसाय को उन्नत करने की बात भाती है। यह भारत की सबसे बडी इण्डस्ट्री है।

जहां तक व्यापार का सम्बन्ध है, करोड़ रुपए लगाये जाते हैं भ्रौर उससे सवा या डेढ़ करोड़ रुपये पैदा किये जाते हैं, लेकिन खेती की स्थिति यह है कि जमीन में मुटठी भर भ्रनाज बोया जाता है भौर उस से सैकड़ों, हजारों रुपयों की पैदावार होती है। इसलिए खेती का दर्जा सबसे ऊंचा है। लेकिन मैं निवेद बरना चाहता हं कि ग्राज इस देश में खेती के प्या में यह भावना नहीं है कि खेती राष्ट्र की सम्पत्ति है, राष्ट्र का धन है भीर इस लिए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह व्यापारी ही क्यों न हो, खेती को श्रपना मानना चाहिए । एक व्यापारी व्यापार करता है, लेकिन वह भी खेती पर निर्भर करता है। ग्रगर सरकारी कर्मचारी, पालियामेंट के

श्री रा० स० तिबारी]

सदस्य ग्रीर भ्रन्य सब लोग खेती को राष्ट्र की सम्पत्ति मान कर चलें, तो खेती की उन्नति हो सकती है, लेकिन भ्राज ऐसा नहीं होता है। इसका कारण यह है कि किसान बहुत सीधा-सादा भ्रादमी होता है भीर उसको नोचने के लिए, उसको लूटने-खसूटने के लिए, उसको परेशान करने के लिए हर एक व्यक्ति मौजूद है।

देश में खेती की पैदावार कम होने का मुख्य कारण क्या है? ग्राप को मालूम है कि देश में सोलह लाख ग्रादमी प्रतिदिन ग्रदालतों में खड़ रहते हैं—इसलिए कि ग्रगर किसी का बाप मर गया, तो उसको दाख़िल-खारिज करना है ग्रीर पटवारी से खसरे की नक्ल लेनी है। इस प्रकार के कामों में कई कई दिन ग्रीर महीने लग जाते हैं, जिसका परिणाम यह है कि प्रतिदिन सोलह लाख किसान ग्रदालतों में खड़े रहते हैं। इतने लोगों का नुकसान काम का कौन करवाता है? सरकार, जो उनकी बातों को या ग्रावश्यक खेती की चीजें जल्दी नहीं मिलती हैं ग्रीर उनकी कठिनाइयों की तरफ़ ध्यान नहीं देती है जिससे कृषि का काम न रुके।

एक विरोधी सदस्य ने ग्रभी कहा है कि कांग्रेस वोट लेने के लिए सभी उपाय नौकर-शाही से सहयोग लेकर करती है। एक कम्यु-निस्ट सदस्य ने कहा कि सरकार किसानों को ऋण नहीं देती है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खेती का काम केवल ऋण से नहीं चल सकता है। उसका काम तो तब चल सकता है, जब प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति खेती को राष्ट्र की सम्पत्ति माने।

श्राज एग्रीकल्चर, खेती, के लिए एजूकेशन की भी जरूरत है। ग्राज हमारे देहातों में इतने स्कूल खुल गए हैं और गांवों के लड़के वी० ए० तक पढ़ गए हैं। लेकिन वे लड़के थम के महस्य को नहीं समझते भीर मेहनत की इज्जात

नहीं करते हैं । मेरा एक मित्र, एक बूढ़ा व्यवित, एक कालेज में श्रपने लड़के को मिलने के लिए गया । वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए था । उस को देख कर उसके लड़के ने भ्रपने साथियों को उसको अपना बाप नहीं कहा, वल्कि अपने बाप का दोस्त कह दिया । इसकी वजह यह है कि वह लड़का मुक्त का खा रहा है, भ्रपने बाप का पैसा खा रहा है--वह परिश्रम की महिमा क्या जाने ? ग्राज हमारे देश में परि-श्रम को श्रादर की दिष्ट से नहीं देखा जाता है। हम देखते हैं कि जब कोई किसान तहसीलदार या म्राफिसर के पास जाता है, तो उसको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी जाती है, क्योंकि वह साफ़ सुयरे कपड़े नहीं पहने होता है, हालांकि वह अन्नदाता है और उसी की मेहनत और उत्पादन से अक़सर लोग अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन वे लोग निखट्ट हैं, मेहनत ग्रीर परिश्रम नहीं करते हैं ग्रौर इस लिए परि-श्रम को इज्जत भी नहीं करते हैं।

इसलिए ग्राज ग्रावश्यकता इस बात की है कि हमारे देश के दृष्टिकोण में सुधार होना चाहिए, परिश्रम का श्रादर होना चाहिए श्रीर श्रम की महिमा को समझा जाना चाहिए। जिस व्यक्ति की, जिस किसान की, देह में मिट्टी लगी हुई है, वह मेहनत करने वाला है, उसको नमस्कार करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसको कहना चाहिए कि "तुम दूसरे भगवान हो, तुम मेहनत करके हम को खिलाते हो स्रोर हम बेईमान हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं स्रीर स्रच्छे, सफ़ेद, गोरे कपड़े पहन कर कुर्सियों पर बैठते हैं।" वह भावना म्राज देश में नहीं है। जो लोग म्राज पढ़ कर निकलते हैं, वे खेती के काम में नहीं लगते हैं। हमारे देहात में कहावत है, "ग्रधिक पढ़े घर से जाये, तनक पढ़े हर से जाये।" हमारे यहां "हल" को "हर" कहते हैं। इसका ग्रर्थ यह है कि जो व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है, वह खेती का काम नहीं करना चाहता है।

मैं आप को ग्रपना उदाहरण देना चाहता हुं। मैं चालीस चालीस मील पैदल चला करता था, लेकिन 17-18 बरस पालियामेंट का मेम्बर होने से इतना निकम्मा हो गया हूं कि ग्रब पैदल नहीं चल सकता हूं, धुप लगने लग गई है। पढ़ने से लोगों में इस प्रकार का निकम्मापन श्रा जाता है कि वे मेहतत नहीं करता चाहते हैं। में समझता हुं कि जब तक हमारे देश के लोग परिश्रम की महिमा को नहीं जानेंगे, तब तक खेती का काम आगे नहीं बढ़ सकता भीर न ही उत्पादन में बृद्धि हो सकती है।

गवर्न भेंट ने विदेशों में से गल्ला मंगाने पर 400 करोड़ रुपया खर्च किया है और अगली योजना में गवर्नमेंट ने इसके लिए 500 करोड़ रुपया रखा है। भ्राज गवर्नमेंट की तरक से कहा जाता है कि देश में गल्ले की कमी है। लेकिन गल्ले की कमी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के कामों में बड़ी सुस्ती है। किसान के लिए बहुत से काम नहीं हो पाते हैं। भ्राज स्थित यह है कि हमारे प्रान्तों में बार्डर एरिया बना दिये गये हैं और वहां पन्द्रह, पच्चीस, नाठ रुपया पाने वाला चौकीदार यह देखने के लिए लगा हम्रा है कि गल्ला इधर से उधर न जाने पाए । मैं कहना चाहता हं कि जिस व्यापारी को अनाज इधर से उधर ले जाने में पांच सौ, हजार रुपया मिलता है, वह साठ रुपया पाने वाले चौकीदार को सौ रुपया दे देगा भ्रौर वह चौकीदार फौरन गल्ले को जाने देगा । इस तरह से गल्ला रोका नहीं जा सकता है स्रोर वह बराबर इधर से उधर जाता है।

मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हं कि ग्रापकी सम्बन्धित कमेटी गल्ले का जो भी भाव निश्चित करे, वही भाव सारे देश में होना चाहिए, ताकि गल्ले के एक स्थान से दूसरे म्थान जाने के लिए किसी कण्ट्रोल या रोक-टोक की जरूरत न रह जाये श्रीर वह सारे देश में इधर से उधर जा सके, मान ली जाये। यदि गल्ले का भाव बीस रुपये मन निर्धारित किया जाता है, तो सारे देश में, देहात में, शहरों में स्रौर सब स्थानों में, उसी भाव पर गल्ला बिकना चाहिए. उससे ज्यादा नहीं।

मान लीजिए कि गल्ले को कलकत्ता या दूर स्थानों में ले जाने की जरूरत है, तो रेल का भाडा गवर्नमेंट बदाश्त करे। जब गवर्नमेंट विदेशों से गल्ला मंगाने के लिए 500 करोड इपया खर्च करती है, तो क्या वह यह खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकती है ? श्रगर वह खर्च : नहीं करना चाहती है, तो वह कलकत्ते में भाव कुछ ग्रधिक कर दे---ग्रगर देहात में भाव रूपये का दो सेर है, तो कलकत्ते में पोने दो सेर कर दे और इस प्रकार रेल का भाडा निकाल ले देश भर में गल्ले का एक भाव हो जाने से कंट्रोल भ्रादि की गडबड़ी नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : ग्रब माननीय सदस्य ग्रपना भाषण खत्म करें।

श्री रा० स ० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय मैं साल में पहली मनंबा बोल रहा हं। मझे कुछ ग्रीर समय दिया जाये।

जहां तक कर्जी का सम्बन्ध है, भारत संसार में फ़र्स्ट नम्बर का कर्जदार है संसार में कर्जा लेने में ग्रगर किसी ने नम्बर मारा है, तो वह भारत है। पी० एल• 480 के श्रधीन जो गेहं श्रा रहा है, वह हमारे देश के घर घर रें पहुंच रहा है। श्राज हमारे देश के छोटे छोटे लड़के भी यह कहते हैं कि हम को ग्रमरीका वाला गेहं लेना है। इस प्रकार अमरीकी प्रापेगेंडा हमारे घर घर म फैल गया है। हमारे प्रधान मंत्री का भ्रमरीका-यात्रा के सस्बन्ध में जो श्रपमान हम्रा है, उस का कारण यह है कि भ्रमरीका समझता है कि इस भारत देश के खाने पर हमारी मोहर लगी हुई है स्रौर इस लिये हम उस को हर तरह से दबा सकते हैं। मैं मानता हं कि सरकार को ग्रावश्यकता के कारण पी० एल० 480 का गेहं मंगाना पड़ रहा है। मैं नहीं कहता कि वह क्यों मंगाया जाता है। भुखमरी के समय बाहर से भ्रनाज मंगाना ही पडता है।

भी भौंकार लाल बेरवा (कोटा) : वह परिवार-नियोजन के काम भ्राता है।

श्री रा० स० तिवारी: ग्रगर गवर्नमेंट परिवार-नियोजन न करें, तो स्थिति ग्रौर भी किंठन हो जायेगी । भगवान् ने माननीय सदस्य को, सरकार बनाने का ग्रवसर नहीं दिया, लेकिन ग्रगर कहीं उन को यह ग्रवसर मिल गया, तो वह केवल परिवार-नियोजन ही नहीं करायेंगे, वह सिर भी उड़वायेंगे जब हमारे देश की पापुलेशन बढ़ती जा रही है, तो परिवार नियोजन करना पड़ेगा । परिवार नियोजन करना पड़ेगा । परिवार नियोजन करने से ग्रादमी ग्रौर महिलाग्रों की तंदरुस्ती बढ़ेगी ग्रौर ग्रनाज की समस्या हल करने में भी सहनियत होगी।

हमारे यहां 11.5 करोड़ टन गोबर का खाद बनता है, जब कि सरकार 5,90,000 टन नाइट्रोजन देती हैं। ग्रगर सरकार गोबर के खाद को तरक्की दे, तो देश में खेती का काम ग्रागे बढ़ सकता है ग्रौर हमारा उत्पादन बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में खदानों में बहुत सा रही कोयला बेकार पड़ा हुग्ना है। ग्रगर सरकार वह कोयला जलाने के लिए देहातों में उपलब्ध करे, तो गोवर का खाद 11 करोड़ टन के बाजाये 22 करोड़ टन हो सकता है ग्रौर वह देश की तरक्क़ी के काम ग्रा सकता है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है ग्रौर वह सारे का सारा गोबर जला दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ग्रपना भाषरा समाप्त करें।

श्री रा० स० तिवारी : जहां तक ट्रैक्टरों का सःबन्ध है, उन के लिए कस्टम इ्यूटी के रूप में दो हजार रूपये पहले जमा करा लिये जाते हैं श्रीर ट्रैक्टर बरसों तक नहीं मिलते हैं। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं कि ट्रैक्टर के लिए कस्टम इ्यूटी जमा

है— भ्रीर वह गवर्नमेंट के पास जमा नहीं है, बल्कि बीच के ब्यापारी के पास है—, लेकिन वापिस नहीं दी जाती है। सरकार को इस भ्रीर भी घ्यान देना चाहिये।

ग्रगर किसान की कोई हलकी लकड़ी टूट जाये भीर वह जंगल से काट के, तो उस को तीन चार महीने तक भ्रदालत मैं दौड़ना पड़ता है भीर मुकदमा लड़ना पड़ता है। ड्यूटी जो है वापिस दिलाना चाहिये।

मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने केन्द्रीय सरकार को साठ लाख टन चावल दिया है। भगर केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश की कृषी तरक्की के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को पूरी सहायता दे, तो देश के लिए ज्यादा हितकर होगा भीर वहां से देश के लिए ज्यादा से ज्यादा खाद्य दिया जा सकेगा।

धन्यवाद ।

13 hrs.

Shri Alvares (Panjim): Deputy-Speaker, Sir, yesterday the House debated a very important issue in regard to the security of the country and the policy to be adopted to meet the menace of foreign aggression. The debate on food, though of a more prosaic character, is equally important. Modern wars or aggressions throw a great strain upon the econo-It is common knowledge that if aggressions have to be met in motimes, the strain that throw about in the economic also should be taken into considera-Unless the economic health of the nation is kept in complete trim, it is unlikely that we would be able to meet our difficulties in future. In the field of agriculture, where more than 70 per cent of our people are involved, it is imperative than we give this question of economic health of the agricultural community our utmost attention.

This Government, in the past 17 years, has failed to assess the dimensions of human want and, therefore we had a crisis towards the end of last year on the food front At the same time, this Government suffers from the traditional difficulties other economies have suffered from, whether it be democratic on socialist, in the sense, that they have always subordinated agriculture to industry. In a developing economy like where the overwhelming quota is agriculture, such a lapse on the part of any government is unpardonable. So, I hope this debate at least will able to throw the spot light on the state of agriculture in our country and be able to strike a new path in future.

The basic facts of our agricultural economy can be divided into parts production, prices and distributi**on**. In all these, government failed miserably. The total national income from agriculture is 50 per cent of the total national income of the country. So, we have to realise that over 75 per cent of our people live on less than 50 per cent of the total national income. The quota of production and distribution is against the agricultural community. Unless these imbalances are done away with and a proper balance is struck it is unlikely that we shall march forward towards social progress.

In the statistics some attempt has been made to explain the position. Here again on the agricultural front, we have failed more miserably than on others. The total agricultural productivity has grown only by 1 per cent. It may be argued that on the whole it is more than 3.5 per cent. But economic experts will tell us that 2:5 per cent increase in agricultural production is due to the extra acreage under cutivation, while increased productivity is only in the realm of 1 per cent. Such low increase in pro-

ductivity cannot give us any hopes of being able to avoid crises in future.

The second point we may take note of is the paradox of food consumption in this country. While for time the amount of foodgrains consumed per capita will and must increase, nevertheless, as the country marches towards economic progress, the dependence on foodgrains as part of the food quota is bound to diminish. Every modern industrial progressive community consumes less foodgrains per capita than in underdeveloped or developing countries. If government can tackle this issue on all fronts where food is availablemilk, vegetables, meat and fisheries-I am sure government's dependence on foodgrains will be relieved and the position will not be as series as it is now. The difficulty is that government does not realise the correct method of feeding the people. If this industry would be treated on a total basis just as we treat industrial production, with proper incentives and encouragement and protection, I am sure we shall have done better than we have done so far.

Our imports tell a tale of imbalance. While in 1962 our total production was 81 million tonnes and our imports were 36 lakhs tonnes, in 1964 when our total production was 79 million tonnes, we imported 62 lakh tonnes of food from outside. We imported proportionately more than the shortfall. This requires an explanation. Is our distribution machinery so inadequate and inefficient that we were not able to trace where the food lay and distribute it in proper areas? We were not able to reach the targets of sugar production we set for ourselves. While in food our shortfall is 21 million tonnes, in sugar we have a shortfall of 5 lakh tonnes. Therefore, the repercussions of this economy is so widespread that poverty has spread all over and there is hardly any chance in the present context of any improvement.

[Shri Alvares]

It is, therefore, necessary that government not merely makes a broad declaration of the basis of increased production, but sets about it in manner that will give evidence of its earnestness. We can, for instance, very profitably take up 1 taluka in each district—we have about 300 districts in India-and it can be made an experimental base for that district, both in the form of inputes like fertiliser, natural manure, credit facilities, rural housing, etc. so that the success tue experiment in one little island in a big district can bring about an awareness of the necessary measures that we put in; and also by a process of diffusion be able to invite the other surrounding talukas of that same district to do likewise. If this experiment is carried on seriously, I am sure not only will food production increase, but the model farm that can be set up will be an education for others.

The second important issue is prices. Agricultural prices, unfortunately do not receive the same consideration that industrial prices receive. suffer from a very great disadvantage that agricultural prices are not uniform all over the country. If in the vast of industrial products and wages, we have been able to achieve uniformity so that we tend our progress towards bringing India a uniform economic plan, it is obvious that we must do likewise on the agricultural front also. The setting up of the Agricultural Prices Commission and the establishment of the Corporation are surely very positive steps in this direction. regard to the Food Corporation, I hope government will not immediately hamstring it by only permitting its operations in certain limited areas. There is no reason why the Food Corporation should permit certain State Governments to function independently of its own operations.

If the Food Corporation is charged with the responsibilities of food pro-

duction, of procurement and of distribution, then it is obvious that parallel agencies should not function; they will detract from both the function and the operation of the Food Corporation. Therefore, I hope that while abolishing all zones, if we want to achieve uniformity on the food front, in respect of production, prices and distribution, the food Corporation must be given the maximum latitude and no parallel agency should be permitted to cut into its operation.

In respect of the question of prices,-this is the key point in agricultural production-we have seen this Government, and all governments all over the world, pampering the industrialists or industrial production Every time a certain measure comes up, the question of remunerative prices is raised by the industrialists. I submit that it is as imperative remunerative prices be paid to cultivator also. The Agricultural Prices Commission set up by the Government may be able to do this if the Government would enlarge its terms of reference to include all inputs and make them the basis remunerative prices on the basis profitability. All political organisations have passed resolutions that the rural economy must be improved. They have laid norms that a rural family should have about Rs. 3,600 annual income in this country. I am sure that this cannot be achieved unless we set about it with certain standards, if we take up certain norms. The Agricultural Prices Commission, which given a certain amount of limited responsibility, must see that in the procoss of determining remuenrative prices, inputs like capital, labour on the land of the whole family and of one individual loans taken, cost of fertilisers physical inputs etc., are all taken into consideration, as we take in industry, so that when the basis of remunerative prices determined or when the Commission sets about stating what is the remunerative price, we shall have the same basis of profitability assumed as we assume, or we are tending assume, as far as industry is conce**rned**. It will be tantamount continuing the imbalances in agriculture if we do not give it the same consideration that we give to industry and the inputs in industry. they be of labour, whether they be of capital, whether they be of raw materials, all these are scruplously taken They are deterinto consideration. mined by laws and by practice. such considerations apply to agriculture. It is time that this Agricultural Prices Commission, on which I great hopes, is able to make a study of all these problems, and unless it is given the freedom of determining these things it is likely that the norms, the objectives we have about for ourselves of improving the rural community, of trying to increase the minimum income of a family to Rs. 3,600, will be difficult to achieve.

Sir, one or two points more remain. One is in regard to the question of export prices. The trend in export prices of raw materials has tended to slow down. The experience today is that not only are the prices agricultural raw materials falling but, at the same time, the gap between the prices of raw materials and manufactured goods from those raw materials is tending to increase. sult is that while industrial nations, or industrialists in our own country also, are able to make fantastic profits from the goods manufactured from raw materials, the prices of those raw are not adequate. materials Government must be able to establish some machinery to determine this, and in the process of determining that it is necessary to find what is the fair share of the material produced that goes into the goods that are manufactured and in respect of which the prices of manufactured goods are constantly tending to rise. We know that we are able to calculate the prifits and the prices of industrial goods. If we can do that to a nicety, is it not possible for the

Government or the Finance Ministry to work out the equity prices of agricultural raw materials that go into these manufacturers. In an integrated economy which is planned, we cannot have a situation where agricultural prices are depressed and, at the same time, the prices of manufactured goods from those raw materials are allowed to fluctuate to the highest possible extent. There must be an inter-relation because there is inter-dependence of production. Therefore, one of the more urgent tasks that the Agriculture Ministry must set about, even if it is against the Finance Ministry, is that an adequate share of total productive prices of manufactured articles from organic raw materials must be so apportioned as to meet remunerative agricultural prices; at the same time, the agricultural raw materials exported to other countries must also receive similar considerations.

With regard to the question of distribution, how is it that, in spite of the fact that rice production in the last year was about 9 million more, we had a distribution The crisis last year was a crisis of distribution and the failure of government's administrative and distribution machinery to supply the figures supplied in From Review of the Food Situation published by the Government, I find that even to rice surplus States like Andhra, Assam and Madhya Pradesh the Central Government had to send a Central rice quota. The Central Government sent 43,000 tons rice to Andhra. Assam and Madhya Pradesh the it supplies rice both to Kerala and Madras. Assam is also a surplus State in rice but the Central Government had to send 14,000 tons of rice. So also to Madhya Pradesh which is also a surplus State the Government India sent 15,000 tons. There is something wrong in the distribution machinery of the Government, and do hope that while replying to the debate the Government will make a clarification on this issue.

Shri Reddiar (Tindivanam): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the debate on the Demands for Grants relating to the Ministry of Food and Agriculture

Sir, I want, in the first instance, that this Department of Food and Agriculture should be upgraded. This Ministry should be brought on a level with the Ministry of Defence if not higher than that, because it is on the production of agriculture that the country can sustain not only itself but can meet all the demands that the country may face from every section of the economy of the country. I am glad that this has been recognised, because when I look at the time allotted for discussion on the Demands for Grants relating different ministries. I find that this Ministry has been given 9 hours which is more than the time allotted to any other ministry. Due recognition must be given to this fact and this must be upgraded.

No financial difficulties should stand in the way of implementing the schemes which are being drawn by the Ministry of Food and Agriculture for increasing production of agricultural materials and also for their distribution.

Sir, I now come to the next point. We have a large number of schemes. We have got no dearth of schemes or reports. But we do not have them properly implemented, especially at lower stages. The people at the lower stages. The people at the lower stage, who generally implement these schemes, the extension officers. the T.S.Os., the revenue inspectors, all these people work the schemes in such a manner that they produce the results opposite of what was intended. For these there is no use blaming them alone.

I have seen, and I have experienced as an agriculturist and also as

member of some of the commodity committees that frequent transfers of these officers are taking place. The control is also diffused. The man working a scheme in Kerala, Madras has to look to Delhi for any small thing that he has to do to implement the scheme. There are several schemes like that. Some of them have been held up because Delhi would not give its sanction. know in the Central Oilseeds Committee, of which I was a member for a number of years, sheemes used to be formulated but it took four or five years before they are seanctioned. Those schemes used to be held up elther with the Centre or with the States.

The officers who are trained in the Agricultural Department for a certain purpose are utilised not for the purpose for which they were trained. They are being utilised for a different purpose. The B.Sc. (Agriculture) are asked to deal with graduates distribution and sale of implements, seeds, manures, etc. and keep account for it. They are not trained for that purpose. Their qualifications are for something else. Their services not used for the purpose for which they were intended. So, so much talent is being misused. I have also known of cases in which specialists utilised like this. There are specialists for each commodity. I know of the case of a sugar-cane here was specialist. Because chance for his promotion in the same section, he was transferred paddy section as specialist. From the time of entry into the department that man has been serving in the sugarcane department; he had training and experience only in that commodity; but, when it is found that his chances of promotion are blocked, he is put in as a paddy specialist, with which work he has had no connection and where he will have to learn a new the paddy crop problems.

Similarly, in the field of research; there have been a number of research

of Food and Agriculture

schemes which have produced good results. But what has happened to those results? They are kept only in the offices. They have not permeated person for whom researches are intended. They do not reach the farmers who should benethe results of researches? The extension service which is now put under the block development work of the panchayat is not unions streamlined. should be streamlined service they should be made to work in cooperation with the farmers because they very often move with farmers, they have close contacts with them, and they should be permitted to work with all enthusiasm which should be generated in them.

More often, these people are transvery frequently. Frequent transfers should be stopped, unless they are warranted in the interest of good administration.

In this connection, Sir, I wish refer to one important point which is contained in 'Agricultural Development; Problems and Prescriptions' published by the department. This contains all the problems which face agricultural production, and also, it gives certain prescriptions for increasing production. If that could be made use of, it would benefit the farmers. If all that is contained there could be implemented properly, from the top to the bottom, I am sure that within 2 or 3 years, nature helping the farmer, we could have more than what we need, of raw materials and foodgrains. That is the only way by which we could achieve increased production. I want that this aspect should be considered by the Government in all seriousness. Government is not serious enough; they do not realise it. In page 6 of the report, para 124, it is stated as follows:

"Supplies of agricultural quisites essential for increased production and improved techniques of production have to be 496 (Ai) LSD-5.

arranged in such a way that they are available to cultivators readily in the vicinity of their villages in time and at reasonable prices and supported bу adequate arrangements for credit."

Nothing more would be necessary to increase production. If this is implemented properly, Sir, then alone we will be able to increase production. But what happens? So far as credit concerned, credit is sanctioned, but there is delay by the time it reaches the lower levels. It reaches the panchayat union somewhere August or September. By that time the cultivator has to incur more than 50 per cent. of his expenses for raising the crop. So, credit should be supplied to him quickly, and there should not be any waste of time. In our parts we are having rains in June-July for raising the rain-fed crops. So, this work should be done in time.

One more point I would like to urge, Sir. I am glad that Government has appointed a commission to go into the question of prices. I am referring to the Agricultural Prices Commission. I am sorry to note that no representative of the farmers is commission, Agricultural that Prices Commission. It is absolutely necessary that farmers' representative should be in that commission, because it is only the farmer knows how to fix the price for commodity which he is producing.

As far as industry is concened, it is governed by a table. They allow so much for various items, for depreciation, etc. They allow all items like depreciation, etc. in respect of those articles, but here, we do not have all items. Depreciation those allowed for the machinery which the farmer uses, for the building he constructs, for the implement which he uses. For the work which he is supervising no allowance is made when the prices are fixed. All

[Shri Reddiar]

the items which go to make up the industrial production should also be taken into consideration in fixing the prices of these agricultural commodities.

I would urge upon the Government that the soil should be analysed first. It is not as if we can put forth manure, fertiliser, etc. quantity which you like and in any combination which you like. you analyse the soil, you do not know what particular manure, either nitrogen, phosphate or potash is required for that soil. We have very meagre facilities for testing the soil. In Tanjore district alone, I am told, it will take more than 5 or 6 years to complete that work. When a man sick, first of all, he must examined and then some medicine should be given, as also nourishment. Similarly, when the crop is to raised, we should find out what type of fertilizer is required, and in what proportion, for that particular and soil. So, I would suggest that we should make some determined effort to train a large number of soil analysts so that we could analyse the soil of the whole country within a short time.

Then, the water has also to be analysed. The water which is not good or fit for man is not good for the crop either. So, analysis of water is also important. I hope necessary action would be taken to do that also.

श्री किन्द्रिकी (रायचूर): उपाघ्यक्ष महोदय, श्राज कृषि तथा खाद्य मंत्रालय के खर्च की मांगों के सम्बन्ध में मैं श्रपने विचार संक्षेप में इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

यह तो सभी को मालूम है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। खेती यहां के लोगों का मुख्य उद्यम है श्रीर इस देश में किसानों की संख्या मधिक हैं। - कुल

भाबादी जो इस देश की है उस में लगभगः 80 प्रतिशतः लोग देहातों में रहने वाले। हैं। इस 80 प्रतिशतः में लगभग 70 प्रतिशतः लोग ऐसे मिलेंगे जो कि खेती पर ही ग्रपना जीवन निर्भर करते हैं। इसः इस के प्रलावा हम यह भी मानते हैं कि खेती एक सब से बड़ी इंडस्ट्री है श्रीर जो: भ्रन्य इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज की इसे मां भी कहते हैं। दूसरी इंडस्ट्रीज को बढाने के लिए पनपाने के लिए रा मैटीरियल पैदा किया जाता है। जब इतना महत्वः हम इस को देते हैं तो श्रीर इस को जानते भी हैं तो हमारा यह कर्त्तब्य हो जाता है किः इस खेती श्रीर खेतों के ऊपर निर्भर करने वाले जो लोग हैं जिनकी कि लगभग 70 प्रतिशतः जनसंख्या है, उन का जीवन सुधार भ्रवश्य होना चाहिये। इस दुष्टि से **बजट**ः में जो प्राविजन होना चाहिये था वह प्राविजनः इस में नहीं है।

इस समय में एक बात ग्रौर घ्यान दिलाना चाहता हं कि भवनेश्वर सैशन में यह जो रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसने एक प्रस्ताव पास किया । वहां यह ग्राभ्वासन दिया गया कि म्राने वाले दस साल में भारत की भ्रार्थिक परिस्थिति को इतना सुधारा जायगाः कि हमारी जो नेशनल इनकम, पर कैंप्टा इनकम है, गरीब से गरीब ब्रादमी की भी उतनी भ्राय होगी । जब हम इस चीज को घ्यान में रखते हैं ग्रौर मानते हैं ग्रौर एक ऐसी ग्रवस्था देश मैं निर्माण करना ग्रपना कत्तंव्य मानते हैं तो यह सवाल सामने माः जाता है कि म्राखिर इस देश की जो इतनी महान जनसंख्या है ग्रीर इस जनसंख्या मैं जर 70 प्रतिशत लोग किसान हैं तो जाहिर है कि उनकी भ्रभिवृद्धि जब तक नहीं होगी। भीर श्रन्न की पैदावार में इजाफ़ा नहीं होगा. क़ोई भी हमारे जजबात हों, कुछ भी हम करें लेकिन जो हमारा लक्ष्य है और निर्देश है उसको इम दस साल में भी प्राप्त नहीं कर

सकोंगे। इसलिए मुझे यह यहनाथा कि माज ग्रपने देश में, खेती के सम्बन्ध में यह तीन पंचसाला प्लान जो हमने चलाये हैं उस के परिणामस्वरूप भ्राज हमें क्या फल प्राप्त हुम्रा है ? इसमें जो प्रवृतियां निर्मित हई हैं भाषा वह खेती भीर किसानों के जीवन सुधार के लिए हानिकारक हैं या लाभदायक हैं जब तक हम उसकी छानबीन भौर म्रालोचना नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी उसमें प्रगति नहीं कर सकेंगे।

मैं खाद्य मंती को बधाई देना चाहता हं कि ग्रभी पिछले दिनों देश में जो खाद्यान्न का संकट उपस्थित हो गया था, स्रन्न की विषम परिस्थिति बन गई थी, उन्होंने उस संकट से दक्षता श्रीर दृढ़ता से निबटने की कोणिश की। उनका वह प्रयत्न स्तूत्य है भीर इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि भागे बह ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं होने हेंगे ।

हमारे तीन पंचसाला प्लान हो गये। हमारे पहले पंचसाला प्लान के प्रारम्भ में हमारे देश में जितनी एकड़ जमीन में खोती होती थी उसमें यह तीसरा पंचसाला प्लान खत्म होने तक लगभग 14 मिलियन हेक्टर जमीन का हमने इजाफ़ा किया है। इतनी ग्रधिक जमीन खेती के तहत ग्राई है। 14 मिलियन हैकटर जमीन खेती के नीचे माई है। इन पंचदर्षीय योजनाम्रों में खोती बढ़ाने के साथ साथ सिंचाई के लिये भी हमने प्रोजेकट्स बनाये हैं ग्रीर पानी प्रयीत् इरींगेशन की समुचित व्यवस्था करते जा रहे हैं। इतना सब होते हुए भी जब श्राहार परिस्थिति इस प्रकार की रहती है तो हमें सोचना पड़ता है कि म्राख़िर इसका कारण क्या है ? मेरे विचार में जो कारण मैं इसके लिए जिम्मेदार समझता हुं वह इस सदन के सामने मैं रख देना चाहता हूं। यह बात जरूर है कि हम ने सिचाई की सहलियतें पैदा की है, इरीगेशन

प्रोजैकटट्स चलाये हैं, ट्युबवैत्स सिंक किये हैं भीर भी सब बातें की हैं लेकिन दरश्रसल चीज यह है कि जो इरीगेशन फैसेलिटीज दी जा रही हैं वह सहलियतें ज्यादातर कैमा कौप्स की तरफ़ जा रही हैं। यह जो 14 मिलियन हैकटर जमीन इन पांच साला प्लान के तहत आई है उस के जब मैं आंकड़े देखता हं तो ज्यादा से ज्यादा जमीन जो इरीगेशन के तहत लाई गई है वह कैश कौप्स की तरफ़ा भारही है। इस में मैं किसान का कोई दोष नहीं पाता। उसका कोई दोप नहीं है। वह एक ऐसी म्रार्थिक भवस्था में जकड़ाहम्रा है कि जब तक वह कुछ कैश कौप्स पैदान करे वह इस समाज में एक मर्यादा के साथ श्रपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता श्रीर उसके लिए उसे यह कैश कॉप उगानी ही। पड़ती है मगर एक जबावदेही इसमें सरकार की भी है कि वह यह देखें कि खाद्यान का भी उत्पादन बढे। हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि ऐसी अवस्था निर्माण न हो जिसमें हम भ्रपने उद्देश्य में कामयाब न हो सकें। म्राज हालत यह है कि जितने फर्टिलाइजसं सप्लाई किये जाते हैं वह कोस्टिलिएस्ट होते हैं। भ्राज सारी दुनियां के मुकाबले में सब से ज्यादा कोस्टिलिएस्ट फर्टिलाइजर किसानों को हमारे देश में सप्लाई किये जाते हैं। उसकी शक्ति तो नहीं है मगर यह जो फटिलाइजर्स का ज्यादा उपयोगः हो रहा है वह किस दिशा में ज्यादा उपयोग कियाजारहाहै उसको भी हम देखेंगे तो. कैश कौप्स की तरफ़ जो कि नौन फुडग्रेंस कौप्स कही जाती हैं उन की तरफ़ यह केमिकल फ़र्टिलाइजर्स चले जाते हैं। यह ट्रेंड है जो कि हम देखते हैं। इस ट्रेंड को कायम रखते हुए ग्राप जो भी इरीगेशनः फैसेलिटीज बढाते जाइयेगा म्रनुभव उठाना पड़ेगा कि जितनी भी ज्यादा सहलियतें म्राप किसानों को देंगे वह कैम कौप्स ग्रर्थात् नौन फुडग्रेंस के ऊपर चली

[श्री चन्द्रिकी]

जायेंगी । जितने भी श्राप फर्टिलाइजर्स बढ़ायेंगे, कोस्टिलिएस्ट भी रखिये ग्रीर चंकि उसकी सम्लाई कम है ग्रीर डिमांड ज्यादा है इसलिये ब्लैंक मार्केट की श्रवस्था पैदा होती है भौर किसानों की उसे खरीदने की ग्राज शक्ति नहीं है। जो किसान फुडग्रेंस पैदा करना चाहते हैं उनमें इतने महंगे दामों पर उसे खरीदने की शक्ति नहीं है लेकिन, वह किसान जो कि कैशकौप पैदा करते हैं उनमें इतने महंगे दाम पर ख़रीदने की शक्ति जरूर है। कैश कौप बोने का श्राज किसानों में जो एक ट्रेंड हो गया है उस पर ग्रंकूश लगाने की जरूरत है। पह एक ऐसा विशेष सर्किल पैदा हो गया है कि जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत ₹

श्री उना० प्र० उचीतिकी (सागर) : जो गन्ना हमारे किसान पैदा करते हैं ग्रीर उससे हम चीनी बनाते हैं उस चीनी को हम दूसरे देशों को सस्ती बेचें लेकिन ग्रपने देश में हम चीनी के दाम महंगे रक्खें यह कहां तक न्यायसंगत है ?

क्षी चिन्त्रिकी : मैं मानता हूं। जब भी यह प्रश्न उठाया गया तो खाद्य मंत्री ने यही जवाब दिया है कि हमारे कुछ किमटमेंट्स हैं, हम ने बाहर किमटमेंट किया हुआ है इसलिये बाहर उस दर पर हमें चीनी सप्लाई करनी पड़ती है। खैर वह चीज दूसरी है। इस समय मैं खेती के सुधार की बात कर रहा हूं। खेती के लिए जमीन का सुधार होना है। आज बाद्यान्न के बारे में हमें ग्रपने तौर पर सैल्फ सफिशिएंट बनने की श्रावश्यकता ह भीर उस माने वाले छठ (?) पांच साला प्लान के खत्म होने तक हमें उस दिशा में जाना है। जब हम ने मिनिमम नेशनल इनकम कंट्री के पुग्ररैस्ट व्यक्ति को देने का ायदा किया है तो हमें इन चीकों को सामने रखते हुए इस चीज को सोचने की जरूरत है। इनवैस्टमेंट की श्राप्त पैदा कीजिये। बिना इनवैस्टमेंट के कोई चीज नहीं होने वाली है। ग्राप दस साल छोड़ कर बीस साल तक तपस्या कीजिये लेकिन कोई चीज नहीं होने वाली है। इनवैस्टमेंट की शक्ति ग्राज किसानों में होन का जरूरत है।

ग्राज टैक्स्टाइल पर सैस लेवी किया जाता है ग्रौर गवर्नमेंट हैंडलूम पर रीबेट देती है। मैं कहना चाहता हूं कि केश काप्स के लिए जो फ़र्टलाइजर दिया जाता है, उस पर सैस लगाया जाये ग्रौर फूडग्रेन्ज के लिए दिये जाने फ़र्टलाइजर पर रीबेट दिया जाये, उस को सब्सिडाइज किया जाये। यह व्यवस्था करने पर किसान ज्यादा फ़र्टलाइजर ख़रीद सकता है ग्रौर ज्यादा फूडग्रेन्ज पैदा कर सकता है।

फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, एस्टीमेट्स कमेटी का मेम्बर होने की हैसियत से मुझे उन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का ग्रवसर प्राप्त हुग्ना है। मुझे बहुत ग्रफ़सोस ग्रीर कटुता के साथ यह कहना पड़ता है कि उनमें जो इन्स्पायरिंग एटामस्फियर होना चाहिये, वहां काम करने वाले साइंटिस्ट्स ग्रादि को जो प्रोत्साहन मिलना चाहिये, उस का वहां पर ग्रभाव है। ग्राज उन संस्थाओं में वह बातावरण नहीं पाया जाता है, जिस में वहां पर काम करने वाले जूनियर साइंटिस्ट्स को स्फूर्ति ग्रीर प्रोत्साहन मिले।

एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट को जो पे-स्केल्ज दिये जाते हैं, वे इतने कम हैं कि कोई भी देश का नागरिक या नवयुवक इस दिशा में विद्या प्राप्त कर के सेवा करने के लिए तैयार नहीं होता है। इस के भ्रलावा वहां एक से दूसरे डिपार्टमेंट में को-आर्डिनेशन नहीं है। इन संस्थाओं में 11882

रिसर्च का बहुत ग्रच्छा काम हम्रा है। बे रिसर्च के परिणाम पेटेण्ट भी हो चुके हैं। लेकिन भाज जनता श्रौर किसानों पर उन का कोई प्रभाव नहीं है। उन को इस बात का पता ही नहीं है कि ऐसी कोई रिसर्च हई है, जो हमारे लिए लाभदायक है स्रौर इस से हमें लाभ उठाना है। यह जो श्रवस्था है, वह संतोषजनक नहीं है। रिसर्च के बिना प्रगति नहीं हो सकती है। इन रिसर्च इंस्टीट्युट्स में जो स्थिति है, उस के बारे में एस्टीमेट्स कमेटी ने जो विचार प्रकट किये हैं, यह मंत्रालय उन की तरफ ध्यान देगा, एसी मुझे आशा है।

म्राप ने जो समय दिया है, उस के लिए मैं भ्राप को धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती सत्यभामा देवी (जहानाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष जी, खाद्य भीर कृषि मंत्रालय की मांगों पर बहुत से माननीय सवस्य धपने विचार रख चुके हैं। इस सम्बन्ध में भापने मुझे भी कुछ बोलने का मौका दिया है, इस के लिए मैं भ्राप का धन्यवाद करती हुं।

बेती-बाड़ी के मामले में हमारा देश प्राचीन समय से ही दुनिया में अनुझा रहा है। लेकिन प्राज जमाना काफ़ी बदला हुआ है। बढ़ती हई आबादी का पेट भरने के लिए भनाज की जितनी उपज देश में होनी चाहिए, वह मभी तक नहीं हो रही है। "ब्रधिक श्रम्न उपजामी" के हमारे श्रान्दोलनों को कोई खास सफलता नहीं मिल सकी है। बही कारण है कि भ्रनाज के संकट का हमें समय समय पर सामना करना पड़ता है। यह संकट कभी बंगाल में, कभी उत्तर प्रदेश में. तो कभी केरल में भौर कभी बिहार में पैवा होता है। भौर लाचार हो कर अपने देश का पेट भरने के लिए भी हमें बाहर के देशों के सामने हाथ पतारने होते हैं। लाखों उन अनाज बाहर से लेना पड़ता है। जो विदेशी मद्रा देश के विकास में खर्च होनी

चाहिए, उस का बड़ा भारी हिस्सा देश का पेट भरने के लिए ही खर्च कर दिया जाता है ।

श्राजादी मिलने के बाद के 17, 18 साल की प्रविध में भी हम प्रनाज के मामले में भपने पैरों पर खड़े न हो सके । भारम-निर्भर बनने का हमारा सपना ग्रधुरा ही बना रहा।

इन संब का झाख़िर कारण क्या है ? इस हालत में हमारा क्या विकास होगा 🕽 इस हालत में हम अपने दूश्मनों से भी कैंसे निबट सकेंगे ? इस हालत में हमारी फ़ौजों की जरूरतें भी किस तरह से पूरी हो सकेंगी ?

सरकार की इस तरफ़ पूरा ध्यान देना होगा। मैं समझती है कि ग्रगर सिचाई की बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ साथ छोटी भीर मझोली योजनाओं पर पूरी तरह जोर दिया जाये, तो उपज बढ़ाने में बड़ी मदद मिले। गांव के किसानों को कूए, तालाब खोदने भौर पाइन भौर ब्राहर बनामे के लिए सरकार की तरफ़ से भरपूर मदददी जानी चाहिए ।

भ्रमी कुछ महीने पहले हमारे सिचाई मंत्री, डा॰ के एल राव, हमारे चुनाब के इलाके में नवादा सब-डिविजन के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने भपनी भांखों से देखा कि पटवन का इन्तजाम न होने के कारण किस तरह हजारों लाखों एकड जमीन सुखी और प्यासी रह जाती है। इस मंत्रालय को हमने कई बार पत्र लिखे हैं, लेकिन उसकी म्रोर से द्यूबवैल मादि के द्वारा सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जमीदारों के समय सिचाई की व्यवस्था करने के लिए ये सब काम होते थे, लेकिन जमीदारिया खरम होने के बाद इस तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया जाता हैं। ग्राज स्थिति यह है कि सब तालाब सूत्रे पड़े हैं भीर कुए टूट पड़े हैं 4 अप के एल राव ने दिन भर उस क्षेत्र

[श्रीमती सत्यभामा देवी] की स्थिति देखी, लेकिन ग्रंभी तक इस सम्बंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

बिहार सरकार कहती है कि हमारे पास प इन कामों के लिए रुपया नहीं है भीर केन्द्रीय ंसरकार कहती है कि यह काम बिहार सरकार करेगी। इस भवस्था में बिना पानी के किसान की खेती कैसे बढ़ेगी ? मैं मंत्री महोदय से •यह पूछना चाहती हूं कि उस क्षेत्र में पटवन का इन्तजाम करते के लिए उन्होंने क्या • किया । वह कम से कम राज्य सरकार को इस बारे में उचित सलाहतो देसकते थे।

सरकार को चाहिए कि वह देश के 🗸 िकसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए सब तरह ्रके जरूरी कदम उठाए। सिनाई सस्ती की : जाए, ताकि वे उसका पूरा फ़ायदा उठायें। • (संचाई की दरें घटाई जानी चाहिए।

इसी तरह किसानों को उनकी पैदावार ⁶ का सही मौल दिलाने का जिम्मा सरकार को लेना चाहिए । गीव गांव में खेती बाड़ी को विकसित करने के लिए पंचायतों के जरिये किसानों को कर्ज देने का प्रबन्ध करना ु चाहिए। कर्ज की वसूली का काम भी पंचायतों को ही सौंपना चाहिए । इस से हर साल कर्ज का हिसाब साफ़ रखा जा सकता है।

बेती-बाड़ी के नए उपाय सिखाने भौर ंनये श्रीजारों का इस्तेमाल कराने के लिए भी गांवों में प्रबन्ध होना चाहिए ।

14 hrs.

यह बड़े ताज्जुब की बात है कि सरकार 36 करोड़ रुपये खेती बाड़ी के काम पर खर्च करे ग्रीर 448 करोड़ बाहर से ग्रनाज खरीदने पर । यह ढंग बदलना चाहिए । बेती पर खर्च का अयोरा ठीक से सब कुछ समझ बुझ कर बनाया जाना चाहिये। मैं ग्राशा करती हूं कि हमारे खाद्य ग्रीर कृषि मर्जी मेरे सुझात पर भच्छी तरह गौर करेंगे।

मैं भ्रापका ध्यान इस भ्रोर भी दिलाना चाहती हूं कि किसान जोकि गरीब भी है ग्रौर मजदूरी भी करता है उसकी ग्राधिक भवस्था बहुत ही दयनीय है । वह इतनी कड़ी मेहनत करके पैदा करता है लेकिन इतना करने पर भी उसको पेट भर ग्रन्न नहीं मिल पाता है, पेट भर ग्रन्न वह उपजा नहीं पाता है। म्राखिर क्यों ऐसा होता है? इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि न तो उसके पास समुचित ज्ञान है भीर न खाद भौर न ही समुचित साधन है। अनपढ़ तो वह है ही । साथ ही उसकी भ्रन्य कई किस्म की दिक्कतें हैं जिस के कारण से उसकी स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है । उसकी मार्थिक दशा चिन्तनीय है । वहां पर मजदूरी की दर भी बढ़ गई है, श्रोर मजदूरों को भ्राज तीन गुना वेतन मिलता है लेकिन फसल डेढ़ गुना भी घ्रधिक नहीं हुई है। खाद का भाव भी बढ़ गया है। इन सब कारणों से किसान की श्रवस्था दयनीय हो गई है, चिन्तनीय हो गई है। हमारी सरकार में प्रयत्न किया है कि उसकी गरीबी दूर हो लेकिन बहुत ही कम प्रयत्न इस दिशा म हो पाबे है। किसान को ग्रपने बच्चों की शिक्षा पर, उनके पालन पोषण पर, दवा दारू पर, शादी ब्याह ग्रादि पर इतना खर्च करना पड़ता है कि उसके पास पैसे विकास कार्य करने के लिए बचते ही नहीं हैं।

सरकार ने इस साल के बजट में सभी वर्गों के लोगों को कुछ छूट दी है, कुछ रिलीफ दिया है जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उन सब को राहत दी है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनका मंहगाई भत्ता बढ़ा है। लेकिन किसान बेचारे को कुछ नहीं मिला है। वह जहां का तहां ही है। उसकी हालत में कोई सुधार लाने का प्रयत्न नहीं किया गया है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि नई पंचवर्षीय योजना में कुछ किसानों के लिए भी छुट दिये जाने की व्यवस्था ग्रापको करनी च।हिये। मैं चाहती हूं कि इस पर भी सरकार ध्यान दे।

Mr. Deputy-Speaker: Shri Mahida.

Shri Vishram Prasad (Lalganj): He is the second speaker from his party. I will be the first speaker from my party.

Mr. Deputy-Speaker: I will call you next.

Shri Narendra Singh Mahida (Anand): Sir, I rise to support all my cut motions Nos. 6, 7, 8, 9, 46 and 56. Agriculture is the biggest industry in India and we should be spending about 50 per cent of our national income on it but it is very surprising that we are spending only Rs. 36 crores per year and for the import of foodgrains we spend about Rs. 448 crores. This is rather a very sad state of affairs after our own rule of 17 years. I plead with the Minister of Food and Agriculture that agriculture should be put on a war footing. We shall fight the foreign aggression but, at the same time, we cannot neglect our food position.

The country is shouting for food. We are short of it and unless we put our Food and Agriculture Department on a war footing, I do not think we shall be able to feed our people. Just as West Germany did after the war and Japan performed labour after the war, we should also turn all our lawns in our homes into small gardens and grow vegetables, potatoes or whatever food it is possible to grow. Unless we take such measures, I am afraid, we shall only talk but shall not produce any food.

It is rather very ironic that the cheapest food today, as far as my State, Gujarat, is concerned, is imported wheat. It costs about Rs. 8 a maund and we have to eat that imported wheat. The cheapest food for eattle also is wheat because it is cheaper than bajra or any other foodgrain. So, thanks to the policy of the Government, humans and cattle, at least in my State, are put on par.

Another peculiarity of ur Government is that though they have been encouraging many industrial workers' unions, there is no farmers' organisation worth the name. We have "Bharat Krishak Samaj", a very small affair which is not fully representative of the farmers as it should be. So, I very humbly request the Government and Members of Parliament that there should be a very farmers' organisation in the country. We have barbers' associations, cobblers' associations and various other associations, but there is not a single association of farmers. The farmer's organisation should be the most powerful organisation in this country. I had pleaded some time back when Shri Dhebar-was a Member of Parliament that there should be a farmers' forum in this Parliament.

Shri Inder J. Malhotra (Jammu and Kashmir): There is.

Shri Narendra Singh Mahida: The forum is there but I do not know how many members are actually connected with farming.

An hon. Member: There are many.

Shri D. S. Patil (Yeotmal): You are requested to join it.

Shri Narendra Singh Mahida: I request the Minister of Food and Agriculture that it should be a forum stronger than the Socialist Forum or any other forum.

Shri Inder J. Malhotra: It is the strongest forum now.

Shri Narendra Singh Mahida: We have not heard about it in the renal areas. Let it be situated here, but it should be the loudest in representing the rural areas. We have not heard of a single meeting of the forum.

Shri R. S. Pandey (Guna): Only yesterday we had a meeting.

An hen. Member: There have been more than six meetings.

Shri Narendra Singh Mahlda: The farmers have been looted by all. The

[Shri Narendra Singh Mahida] Moghuls came; they looted the farmers. The Britishers came; they looted the farmers. The landlords looted them; the moneylenders looted them and their position has not much improved.

D. G.-Min.

An hon, Member: The Maharajas footed them.

Shri Inder J. Malhotra: And Swatantra.

Shri Narendra Singh Mahida: Even today, in all humility I submit, the farmers are only slightly better off, not fully. If they were better off, their lands would not have been taken away for the Koyali Refinery. In this very House I pleaded that the The mers' interest should be seen. best lands of Gujarat near should never have been taken for the Koyali Refinery. In my own constituency of Anand the best lands of farmers should not have been taken for the Amul Dairy. In my Gujarat, in every single Government Gazette I notice that people are being deprived by acquisition of land to the extent of 300 farmers per gazette, that 4s, per week. So, it comes to about 20,000 farmers being removed farming every year; yet we say that farming is the most important factor in our country. I refute that. are slowly removing the people from the rural areas by taking away their lands for industrial purposes, roads or railways—they are necessary but we are not rehabilitating them on farming at all. If there is any hon. Member who is doubting it, I will request him to come with me and I will show him that so many farmers have been uprooted from lands in Gujarat and have been turned into labourers.

I propose the following means for the improvement of farmers. Farmers should get fertilisers, manures, loans or credit, plant protective chemical and better seeds. I am a farmer myself and most of my income today is only

from farming sources. Some sort of incentive to the farmers should given to produce more and more progressively. Measures should be taken to discourage the production of cash crops which the Government has been encouraging to earn foreign exchange. I do not know what prevents the Government from restricting growth of cash crops.

In my State of Gujarat, on the one side, we are saying that there is shottage of food and, on the other, the farmers are growing tobacco and cotton. Why can we not compel the farmers to grow three-fourths of the required foodstuffs? Ever_y village in my State is deficient in foodstuffs today and we are shouting that there is no food. How can it grow unless we bring about some sort of compulsion by law or otherwise so that the farmers may be self-sufficient, that they grow more of food crops than cash crops?

My other suggestion is that necessary technical advice should be given to farmers to enable them to make the best use of their land. I have in my constituency an agricultural institute. We have agricultural colleges also round about but these colleges are only for upper class farmers, that is, mostly for sons of who are educated or who understand English. But these institutions are not helpful to the neighbouring villages even. There is nothing common between those institutes and the neighbouring villages. People want service and the Agriculture Department gets the benefits. So, I request that these institutions should have contacts with the villages round give information about and knowledge to the farmers.

Irrigation and water supply facilities should be increased and dependence on rains should be minimise as far as possible and multiple cropping should be enlarged. As far as irrigation is concerned, in my State, Gujarat, it is very poor. I will show

11892

by facts that Gujarat suffers probably most in this country. The area irrigated in percentage is only 5.9 in Gujarat as compared to all-India percentage of 17. The cost of import of food for Gujarat alone is Rs. 100 crores per annum. If this amount of Rs. 100 crores is spent on the Narmada Valley Project, it will not only remove the deficiency in irrigation facilities but it will entirely change the face of Gujarat. I hope the voice of the people of Gujarat will be heard by those in power. I am prepared to wait even for 15 years. Though I may not see it in my life time, at least my children will see the accomplishment.

When there was composite Bombay State, there was a scheme to irrigate the land in Kutch by taking water from Indus through Banni, which of course is not possible now. It has gone over to Pakistan. very problem of Kutch about which we are talking so much now, would have been solved by this. Ten lakh acres of land in Kutch can be brought under cultivation if the Narmada verted into a fertile area if the Rann of Kutch, which is today the hot-bed of invasion from Pakistan can be converted into a fertile area if the Rann of Kutch can be dammed in certain places. Then this question of useless and marshy land would go away and Kutch would be a fertile area. Kutch has receptive soil and only irrigation facilities are to be provided. Whether this problem can be taken up or not is a question for the Government to decide.

The former Governor of Maharashtra, Shri Prakasa has written recently a very interesting article in which he has criticised the Government's policy of imposition of ceilings on cultivable land. He has very rightly said this and I quote him:

"Imposition of ceilings on cultivable land destroy possibilities of enhanced food production. Small holdings today are the bane of rural life."

We expect more production from land. When we have small holdings, when people have land which can just feed them, how can we expect more production? They cannot improve it because they cannot introduce modern methods of cultivation, which are possible only on large holdings. Neither they can use tractors nor they can afford to use chemical manures on such small holdings. I was myself a zamindar and I chose to become an ordinary person by donating lands to the farmers long before the Bhoodan movement was started. Today I have only 60 acres of land. It is so fragmented that I cannot use a tractor. The Government has a good scheme for supply of improved variety of seeds, manures and also for adontion of modern methods of agricultural operation. But it has not proved a success because the people resist it. That is because they cannot take advantage of this on small holdings. I would request the Government to pay early attention to the question of removing this ceiling on land heldings. Then only we can expect more production from the land. In Maharashtra and Gujarat income from land is limited only to Rs. 3,600 per year according to the land ceiling. I cannot earn more than that from my land. While the people in metropolitan areas like Delhi, Bombay or Ahmedabad can make any amount of income, why are we limited to earn Rs. 3,600 per year. How do you expect me to buy a tractor or adopt modern methods of cultivation with this small income? If I want more for agricultural purposes, money . neither the Government would give us assistance nor the Co-operative Banks would offer us the help. The Banks point out that our land holding is too small. The land ceiling is not necessary in this country. Is it the Government's intention to distribute land equally to all the landless? We should distribute the land to those people only who are interested in

[Shri Narendra Singh Mahida]

developing it and in growing more food. While I agree that the landless must be employed, instead of uistributing lands to them the Government can introduce small industries for the benefit of landless people. I know of many cases in my own village. The landless who have got the land are neither interested in developing it nor in growing more food. They just grow 10 to 12 maunds of bajra for their maintenance. The ceiling on land has considerably reduced our food production. It has not led to more production. This is not only my view but this is the view of many prominent senior politicians in our country. As generations pass, fragmentation will be intensified and will make matters worse than they are today.

I shall now come to co-operative farming. It is no doubt a fine ideal. What about co-operative kitchens? Let the Ministers try co-operative house-keeping also? This appears good on paper. But co-operative farming has failed miserably. 95 per cent of the societies in my State have failed. There is a village called Pala between Baroda and Panchmahals. The late Maharaja Sayajirao Gaekwad, an intelligent and foreseeing ruler, had introduced co-operative farming in 1930s. He had a rule then those who did not want co-operative farming should get back their lands and the debts should be wiped of and paid by the State. I know that very lately Russia has also done the same thing. They have also wiped the debts of the farmers. Why cannot we also take firm resolve that where the co-operative farming fails in a particular area the farmers should get back their lands and they should not be made to suffer for the debts incurred.

Malhotra: It Inder J. Shri already there because it is only voluntary.

Shri Narendra Singh Mahida: In this village Pala, the people have been deprived of their land and the responsibility of clearing the debts also is sitting on them heavily. I can take Mr. Malhotra to Pala and show him these things. Let us rethis stalemate. question is to be re-examined. lands must be restored to the farmers and the debts also should be cleared by the State.

Let me now come to the question of credit facilities to the farmers. If a farmer loses his bullock, the only society to which he can go is the Co-operative Credit Society. also he has to wait for so many months. The credit facilities should be made available immediately. The Co-operative Credit Societies should be made to act promptly.

As we are all interested in the United Nations Organisation for the peace of the world, I request that there should be a United Food Organisation with whose help this question of poverty would be removed from this earth. Unless the poverty is removed, nothing is going to stop the quarrels between various regions. I request that the Farmers Forum clamour for a United here should Food Organisation.

An hon. Member: It is there already.

Shri Narendra Singh Mahida: It is not powerful enough. With these few words, I thank you, Sir, for giving me opportunity to address the House.

भी शशिरंजन (पुपरी) : उपाध्यक महोदय, में कृषि तथा खाद्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। ब्राज दो दिनों से इस विषय पर बहस हो रही है। पहले भी खांच की समस्याची पर चर्चार्थे हुई हैं। लेकिन मुझे दृ:ख इस बात का है कि यह चर्चायें इधर दी शालों से ही होने लगी हैं। अगर यह प्रविचे पहले हुई होती हो शायद इम आज

इर्रा स्थिति में न होते। जैसा स्रभी श्री चिन्द्रका ने कहा, यह देश कृषि प्रधान देश है स्रौर 70 फी सदी श्रादमी कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। बिहार में तो 80 फी सदी श्रादमी खेती पर निर्भर हैं। जैसा कि उन्होंने कहा खेती सारे उद्योगों की मां है। जिस प्रकार कि सौर मंडल में सूर्य का मुख्य स्थान श्रौर सारे नक्षत्र उसके चारों श्रोर घूमते हैं, उसी श्रकार सारे उद्योगों में खेती का मुख्य स्थान है श्रौर सारे उद्योगों उसी से प्रेरणा पाते हैं।

बेती के बारे में हमने दो पंचवर्षीय योजनाओं में कोई खास ज्यान नहीं दिया और उसी का नतीजा है कि आज ढाई वर्षों के बीच में खाद्यान्न की कीमत डेढ़ गुनी हो गयी है और हमको बाहर से पहले की अपेक्षा तीन गुना अधिक खाद्यान्न मंगाने की आव-ध्यकता पड़ गयी हैं। हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है, यहां के खेत इतने उपजाऊ हैं, गैजेटिक बैली जैसी उपजाऊ भूमि यहां है, और फिर भी अगर खाद्य की कमी हो तो यह सचमुच में बड़े शर्म की बात हैं।

लेकिन सिर्फ बातों से श्रीर चर्चा सो से इस काम को पूरा कर सकें यह सम्भव नहीं हो सकता । यह हर व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह खेती के बारे में खुद भी सोचे श्रीर श्रपने क्षेत्र में जो भी इसकी जानकारी रखते हैं उनको बताए। लेकिन हम सिर्फ बात करके रह जाते हैं। सारी जवाबदेही सरकार पर डाल देते हैं श्रीर सिर्फ यह सोचते हैं कि सरकार ही इन सारी मुसीबतों को दूर कर देगी। लेकिन यह सम्भव नहीं है।

मैं खाद्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि इन चन्द वर्षों में उन्होंने इस समस्या के विभिन्न पहलुग्नों पर विचार किया है ग्रौर विभिन्न पहलुग्नों की पुष्टि की है ग्रौर इसकी खामियों को दूर करने की कोशिश की है ।

काफी चर्चाएं हुई हैं.। मैं इन चर्चाओं से भिन्न कुछ अपनी विनम्ध्र राय देना चाहता

हं कि हम भ्राखिर खेती किस तरह से बढाएं। हमारे सामने दो समस्याएं हैं, एक है कि उपज बढ़े ग्रौर दूसरी है कि वितरण कैसे हो। लेकिन उपज बढाने की समस्या सबसे बडी है। उपज बढ़ाने के लिये हमें क्या करना चाहिए? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दशाब्दियों पूराना विभाग है ग्रीर इस पर हम हर वर्ष काफी पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इस डिपाटमेंट से, मुझे निजी तजरबा है, खेतिहर को कोई विशेष लाम नहीं हो सका है क्योंकि कोई खेती का जानने वाला भ्रादमी किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। वह भी सोचता है कि क्राखिर पहुंचे तो क्या ले कर पहुंचे । इसलिए यह जरूरी है कि हम ब्लाक लेविल पर कुछ ऐसा काम करें, कुछ इस प्रकार भ्रपने विचारों को कार्या-न्वित क**रें** कि जो सरकार का श्रक्सर हो ब्नाक में, वह हर व्यक्ति के पास जाए ग्रीर उसको कुछ रचनात्मक सुझाव दे। कु% तत्र्रवा ले कर जाए ग्रीर उनको बतावे कि यह कैसे हो सकता है। इसलिए मेरी राय है कि हर ब्लाक में एक प्रयोगशाला हो श्रीर उस प्रयोगशाला में खेती को बढ़ाने वाली श्रीसतन सब चीजें हों, ट्रैक्टर भी हो, फर्टीनाइजर भी हो, इनसेक्टीसाइड भी हो ग्रीर उसर्वे सोयल टेस्टिंग की भी व्यवस्था हो । हमारे खेती करने वाले यह नहीं जानते हैं कि उनके बेत म किस केमिकल की कमी है, किस प्रकार का रसायन डालने से उनकी खेती की उपज बढेगी । सोयल टेस्टिंग का काम बहुत ग्रासान है। इसमें बहुत दिक्कत की बात नहीं है। ऐसी ब्यवस्था की जाए कि खेती करने वालों को ये सुविधाएं पहले बिना कीमत लिए दी जाएं, प्राफिट शेयरिंग बेसिस पर, श्रौर उनकी भौसतन तीन साल की जो उपज है, उससे जितनी उपज इन चीजों के कारण ज्यादा हो उसका माधा भाग या जो भी म्रापका खर्चा हमा हो, उसके अनुसार उन से ले लिया जाए । इससे खेती करने वालों को नकद पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा और उनको इससे लाभ भी बहुत भ्रच्छा होगा । लेकिन बहु व्यवस्था ग्रभी तक नहीं हो पायी है।

[श्री शशिरंजन]

मभी हमारे खेती करने वाले मामूली बातें नहीं जानते, जैसे रोटेणन ग्राफ काप्स एग्रोनोमी, इकानमिक होल्डिंग ग्रादि । मैं एक खेतिहर परिवार का व्यक्ति हं। ग्रौर मुझे याद नहीं है कि कभी भी कोई भी एग्री-कल्चर डिपार्टमेंट का भ्रादमी हमारे यहां गया हो श्रीर उसने यह बताया हो कि तुम श्रपने मसलों को इस तरह से हल करो या उसने पूछा हो कि तुम्हारी क्या दिक्कतें हैं। इसलिए यह जरूरी है कि किसानों को जनाया जाए कि किस फसल के बाद कौन सी फसल रोपनी चाहिए, कितनी कितनी दूरी पर रोपनी चाहिए कुछ लोगों के इतने इतने छोटे खेत हैं कि जिनमें वे ग्रासानी से हल भी नहीं घुमा सकते **उनको तोड़ कर धौर धापस में मिलजुल कर** उनको बड़ा करना चाहिए ताकि वह होर्ल्डग इकानमिक हो सके ।

हमारी भ्रनाज की कमी करीब भ्राठ या नौ फीसदी है। मैं समझता हूं कि भ्रगर इन सब प्रयोगों को काम में लाया जाए तो हम भ्रपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं।

हम लोंग सिंचाई की बात करते हैं, सूबे की बात करते हैं, बाढ़ की बात करते हैं। यह संच है कि सूखा भी भाता है, बाढ़ भी भाती है भीर उन पर हमको काबू भी पाना है। पर इन पर काबू पाना तुरन्त सम्भव नहीं है, उसे करने में समय लगेगा। लेकिन जो चीजें मैंने ऊपर बतलायी हैं उनको हम तुरन्त कार्योन्वित कर सकते हैं भीर उन से इम को लाभ हो सकता है।

हमारी कांग्रेस ने भी कोश्रापरेटिब कार्मिंग के बारे में कुछ बातें पहले की थीं भीर उसकी उपादेयता को लोगों के सामने रखा था । लेकिन चन्द जगह इसका प्रयोग किया गया पर अनुभव अच्छा नहीं भाया । लेकिन मैं समझता हूं कि इसको ठीक से समझा नहीं गया, सोग कोश्रापरेटिव माइंडेड नहीं हुए, उनको यह नहीं मालूम कि इस काम को कैसे कार्यान्वित किया जाए । ये चीर्जे पहले किसानों को समझाने की जरूरत है। ग्राज व्यक्तिबाद का जामना नहीं है । ग्राज सहकारिता का माजना है । हम भले ही इसको न समझें यह ग्रीर बात हैं ।

एक माननीय सबस्य : किसानों को समझात्रो ।

श्री शशिरंजन : किंसान को समझाने की तो बात ही है। श्रभी श्रभी दिल्ली के कुछ ही दूर, कोई दस मील एक जगह है, जहां लोग भूखे मरते थे। वहां उन्होंने सह-कारिता के प्राधार पर एक कुंचा खुदवाया भीर उससे सिचाई की व्यवस्था की है। आज वहां पर यह ग्रवस्था है कि किसान नोग कहते हैं कि जिस जमीन को वे एक हजार रुपया प्रति एकड़ बेचने को पहले तैयार थे उसकी वे पांच हजार प्रति एकड़ में भी बेचने को तैयार नहीं हैं। तो सहकारिता का एक यह भी पहलू है। यह जरूरी नहीं है कि हम सब की खेती को मिलाकर के ही सहकारिता शुरू करें। हम सिंचाई का बन्दोबस्त सहकारी रूप में कर सकते हैं, खाद का बन्दोबस्त सहकारी रूप से कर सकते हैं। तो इसके विभिन्न पहलू हैं। उन पर हमें नौर करना चाहिए, श्रौर किसानों बताना होगा कि किस तरह से वे भ्रपना काम करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बेती की पढ़ाई हम लोगों को प्राइमरी और सैकंडरी क्लास से गुरू करनी चाहिए क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे बच्चे जन्मजात बेती के बारें में थोड़ा बहुत जानते हैं और अगर खेती की पढ़ाई की व्यवस्था हम उन के लिए प्राइमरी स्कूल से कर दें, दो तीन साल की ट्रेनिंग प्रगर हम उन्हें दे दें तो मैं समझता हूं कि उस से काफ़ी साम होगा। प्राज हमारे खेती के ग्रेजु-

11900

एट्स इंटरमीडिएट पास करने के बाद, तीन, चार साल पढने के बाद वह खेतों में जाना पसन्द नहीं करते । उन के पैर में कीचड़ लगती है। वह सोचते हैं कि एक इंजीनियर, एक डाक्टर भ्रौर एक भ्राई० ए० एस० जब हमारे ऊपर बैठकर शासन करता है तो मैं ही वहां की चड़ में क्यों जाऊं? इसलिए पहले हम लोग यह सोचें, उन का मानस ऐसा बनायें कि वह उसकी उपादेयता समझें तभी खेती की उन्नति संभव हो सकेगी । इसके लिए हम प्राइमरी श्रौर सैकैंडरी क्लास से ही खेती की पढ़ाई शुरू कर दें। मैं समझता हं कि खाद्य मंत्री उस पर गौर करेंगे भौर इस पर अमल करेंगे।

श्रभी हम लोगों को जो एक रिव्यु दिया **गया है** उसके छठे पुष्ठ पर विचार सरकार ने रक्खा है । मैं उस विचार से सहमत हूं लेकिन मैं भ्रपने शासक भाइयों को कहना चाहता हूं कि क़ानून के जरिए न कर के लोगों के सहयोग के जरिए इस को भ्रमल में लायें

चूंकि श्रब समय नहीं रहा है इसलिए मैं केवल एक, दो शब्द ग्रीर कह कर समाप्त करूंगा। ग्राज जो हमें कमी महसूस होती है उस में मुख्य कारण कंट्रोल को ऋियान्वित करने का है। इस में हम ने भूल की है। कंट्रोल को हम सही तौर से कार्यान्वित नहीं कर सके हैं? उसका नतीजा यह है कि एक भ्रादमी का सारा दिन भर का समय कंट्रोल की दुकानों में भ्रपने लिए खाद्यान्न उपलब्ध करने में लग जाता है। चूंकि सामान लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है भीर लोग ऐसा समझते हैं कि म्राज जो मिल रहा है पता नहीं वह कल को मिलेगा भी या नहीं इसलिए जिसकी जितनी क्षमता होती है उसके मुताबिक वह अपनी पुरचेज कर लेता है। खरीद कर ले जाता है। मैंने देखा कि जो रोज खरीद कर खानें वाले लोग होते हैं, पहले तो रोज का रोज खरीद कर खाते थे भव कंट्रोल हो जाने के कारण जिसकी जितनी क्षमता है एक हफ्ते की, एक महीने की या छै महीने की उतना वह खरीद कर रख लेता है।

मैं एक बात भीर कहना चाहता हूं भीर बह यह है कि खेती करने वालों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये लेकिन आज उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। माज हमारा भौद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ रहा है इसका खास कारण यह है कि हमारी खेती की उपज नहीं बढती है भीर जब तक खेती की उपज नहीं बढ़ेगी तब तक हम उद्योगों में तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार को बड़े बडे भी खोगिकों को, बैंक कर्णधारों को, इस दिशा में सोचना पड़ेगा धीर गांबों में **बैंक खोल कर किसानों को सहुलियत देनी** पड़ेगी । खेतिहर लोगों को सभी सम्भव सविधायें प्रदान करनी पडेंगी ताकि वे उनका लाभ उठा सकें धीर इस देश को कम से कम समय में खाद्यान्न के मामले में ग्रात्म-निर्भर बना सकें और हमें विदेशों से मनाज मंगाने के लिये बाध्य न होना पड़े।

श्री समत प्रसाद (मुजफ्फरनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि का मुल्क की भाषिक उन्नति में बड़ा हाथ है। हमारे देश में लगभग 70 प्रतिशत भादिमयों का इस खेतीबाड़ी पर दारोमदार है।

पिछला साल एक बड़े संकट का साल हमा भौर उस समय गेहं की कीमत देश के बहुत से भागों में 50 रुपये मन तक चली गई। नतीजा उसका यह हुन्ना कि हर जगह महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिये घान्दोलन किया जाने लगा । टीचर्स, डाक्टर्स, कूली मजदूर भौर क्लर्कस सारे के सारे लोगों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिये मतालका हुमा। मब हकीकत यह है कि मगर हम प्रपनी खेती की सम्हाल नहीं सके, उसकी प्रगति नहीं कर सके तो हमारी योजना

[श्री सुमत प्रसाद]

सफल होने वाली नहीं है। हमारी भौद्योगीकी करण विकास भी खेती के ऊपर निर्भर है। तीन पंचवर्षीय योजनायें खत्म होने को माई । पहली पंचवर्षीय योजना में यह ख्याल था कि हम स्वावलम्बी होने जा रहे हैं। लेकिन इसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्याम का संकट हमारे सामने ग्राया ग्रीर तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी वही चीज सामने ग्राई। ग्राज तक कोई खाद्यान्न की एक खास नीति हमने निर्धारित नहीं की। 1957 में एक फुड ग्रेन इनक्वायरी कमेटी बनी थी। श्री मेहता जोिक, श्राज-कल डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमिशन के हैं उन्होंने ग्रपने कुछ सुझाव दिये थे। उनका एक सुझाव प्राइस सपोर्ट पालिसी का था। उसके लिए उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को एक बफर स्टाक बनाना चाहिये ताकि जब खाद्यान्न के दाम सस्ते हों तो वे खरीद कर लें भौर भगर दाम बहें तो उसको फरोख्त करे। उस बफर स्टाक के बनाने में भी इमको कोई खास सफलता नहीं मिली।

पिछले साल 6 मिलियन टन से ज्यादा गल्ला हमने बाहर के देशों से मंगाया भीर भगर वह गल्ला हमको नहीं मिलता तो इस वेश की स्थिति बड़ी गम्भीर हो जाती। धाज देश एक संकट के समय में से गुजर रहा है इसलिये यह जरूरी है कि इस वक्त चीजों के दाम न बढ़ें ग्रौर वे मुनासिब कीमत पर रहें। लेकिन यह तभी मुमकिन है जबिक खेती की उपज बढ़े। एग्रीकलचरल मिनिस्टरी ने एक किताब हम लोगों को दी है जिसका कि नाम एग्रीकलचरल डेवलप-मेंट प्राबलम ऐंड पर्सपैनिटव है। इसके मैंने कुछ ग्रांकड़े देखे तो उन ग्रांकड़ों को देखने . से यह पता चलता है कि म्रगर सन 1949 से 1952 की भौसत लिया जाय तो 4 प्रति-इत हर साल बड़ोतरी सन् 1962 तक बेसी की उपज में हुई है। भौर भगर सन 52 से 55 तक का श्रीसत लिया जाय तो

केवल 3:23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। माबादी भी 2·5 परसेंट के करीब बढ़ी है। डेवलपमेंट ग्रौर डिफेंस के खर्चे की वृद्धि की वजह से लोगों के पास रुपया ज्यादा पहुंच रहा है भीर उसकी वजह से लोगों का जीवनस्तर थोड़ा ऊंचा हो रहा है, इस-लिए गल्ले की भौर भी भ्रधिक जरूरत है। यदि हम गल्ला पर्याप्त माल्ला में पैदा करने में कामयाब न हुए तो चीजों की के मतों को एक मुनासिब स्तर पर हम नहीं चला सर्केंगे ।

14.40 hrs.

SHRIMATI SAROJINI MAHISHI IN THE CHAIR]

जैसे एक इंडस्ट्री है, खेती को भी ठीक उसी तरह से एक इंडस्ट्री माना जाना चाहिये। जितनी खेती के लिए चीजों की जरूरतें हैं, जैसे पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है, बीज की जरूरत है वे सब पर्याप्त मात्रा में मौर ठीक समय पर किसान को अगर नहीं मिलेंगी तो वह खेती की उपज को नहीं बढ़ा सकेगा ।

खेती का काम इंडस्ट्री से एक कारण से ग्रीर मुश्किल है। किसानों की संख्या साढें छः करोड़ के करीब है श्रीर वे तमाम देश में फैले हुए हैं। उनमें से साठ परसेंट ऐसे किसान हैं जिनके पास पांच एकड तक ही भूमि है। इस पांच एकड़ में ऐसे भी श्रापको मिलेंगे जिनके पास एक एकड यादो एकड भुमि है। मुझे बड़ी श्राशा थी कि कोश्राप्रेटिव फार्मिग कामयाब होगा। मैंने भी अपनी कांस्टिट्यएंसी में दो जगह को ब्रोप्रेटिव फार्मिंग चलाने की कोशिश की है भौर हर एक सहलियत उनको दिलाई है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि तीन साल तक वह कोम्रोप्रेटिव चली ग्रौर बाद में उसकी खत्म करना पड गया।

of Food 11904: and Agriculture

सरकार के लिए यह बात भी सोचने की है कि जो छोटे छोटे होल्डिंग्ज हैं उनको किस तरह से इकोनोमिक होल्डिंग्ज में बद्धला जा सकता है, ग्रीर किस ढंग से चला जाए जिससे की हमारी उपज बड़े।

एक बात भीर है। इस खेती में सब से कम ग्रामदनी होती है। सरकारी नौकरी में ग्रादमी जो हैं उनकी श्रामदनी ग्रच्छी है, इंडस्टो में जो हैं उनकी ग्रच्छी ग्राधिक परिस्थिति है । लेकिन जो किसान का लड़का कालेज में या युनिवस्टि में पढ़ने के लिये जाता है ग्रीर जो एग्रिकलचर सबजैक्ट्स भी लेता है वह भी इसी कारण से बाद में खेनी में नहीं लगना चाहता। इसका नतीजा यह होता है कि जो टेलेंट खोती में ग्रानी चाहिये वह टेलेंट खोती में नहीं लगती । जिस किताब का मैंने ऊपर हवाला दिया उस में यह भी है कि हमारी उपज अगर साइंटिफिक वेसिस पर खेती को चलाया जाए, नए मैथड लगाये जायें, यह देखा जाए कि भूमि कैसी है, उसको टैस्ट किया जाए, किस जगह किस किस्म के रसायन खाद की जरूरत है, किस किस्म का बीज वहां पर डालां जाए, ये सब साधन उपलब्ध हों तो तीन चार गुना उपज बढ़ सकती है। यही एक जरिया है किसान की मामदनी को बढ़ाने का। भ्रगर कीमतें बढ़ाते चले गए तो यहां का इकोनोमिक स्ट्रक्चर सब डिसग्रार्डर में हो जाएगा। भगर खेतों की उपज बढ़ेती किसान की मामदनी भी बढ़ेगी श्रीर उससे कैपिटल फार्मेशन भी होगा।

दूसरी बात सोचने की यह भी है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करने जा रहे हैं। उसको हम बहुत महत्व दे रहे हैं। यह इंड-स्ट्रियलाइजेशन ग्राप किसके लिये करने जा रहे हैं? ग्राजकल दुनियां में कोई ऐसी खुली हुई मार्किटें थोड़े ही हैं कि जहां हम यहां की मशीनें भौर चीजें दूसरे मुल्कों में ग्रासानी से भेज सकें । यह इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट तभी कामयाब होगा जब यहां जो सत्तर परसेंट किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं, उनकी माली हालत सुधरेताकि वे उन चीजों को खरीद सकें। इसी सूरत में इंडस्ट्री में भी कामयाबी हासिल हो सकती है।

मैं कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ग्रपनी इस पुस्तिका में गम्भीरता से खेती की उपज बढ़ाने पर गौर किया है। पेज 4 पर इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। इनको मैं पढ़ कर ग्रापको सुनाना चाहता हं। इन्होंने लिखा है:——

"In India, this task has to be accomplished through about 65 million cultivators of whom 60 per cent operate less than 5 acres individually. The role of Government in this task falls broadly into the following categories:—

A—Undertaking and promoting development programmes such as irrigation, land reclamation and soil conservation.

B—Developing arrangements for the production and distribution of essential supplies like fertilizers, improved seeds, pesticides, cement, agricultural machinery and implements.

C—Undertaking measures for increasing the efficiency of the factors of production, through research, extension, etc.

D—Provision of economic incentives such as remunerative prices; marketing, subsidies.

E—Undertaking institutional reforms with a view to creating conditions conducive to greater investment in agriculture."

ध्रगर ये सब चीजें उपलब्ध की जा सकें ग्रौर उनको पूरा किया जा सके तो मुझे विश्वास है कि खेती की उपज बढाने में हम काफी [श्री सुमत प्रसाद]

सफल हो सकते हैं ग्रीर यह देश खाद्य समस्या में स्वावलम्बी हो सकता है ।

इसके साथ साथ मुझे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी कुछ कहना है। जब स्केरसिटी होती है तब समाज के कमजोर वर्ग के लिए कंट्रोल लाग् करना भ्रावश्यक होता है । लेकिन कंट्रोल तभी कारग्रामद हो सकता है जब उसको लागु करने के लिए ग्रापके पास एफिशेंट मशी-नरी हो। यह खेद की बात है कि हमारी मशीनरी बिल्कुल इनएफिशेंट हैं। म्राप देखें दिल्ली में जब गेहूं का भाव चालीस किलो का तीस ग्रौर बीस रुपये था तब गाजियाबाद में जो बिल्कुल दिल्ली के साथ लगता है गेहूं का भाव 45 श्रीर 50 रुपये तक पहुंच गया था । इतने भ्रन्तर वाली बात चलने वाली नहीं है । इस से कुदरती तौर से भ्रष्टाचार बढ़ता है । यही गुड़ की बात थी । मुजफ्फरनगर मेरठ डिस्ट्रिक्ट गुड़ प्रोड्यूसिंग सैंटर हैं। यहां पर गुड़ के बाहर जाने पर रेस्ट्रिकशन यी । वहांपर गुड़ की कीमत कम थी ग्रीर राजस्थान में तथा दूसरी जगहों पर गृड़ की कीमतें बहुत ऊंची थी । पिछले साल रेस्ट्रिकशन लगाया गया था। लेकिन मौजूदा कृषि मंत्री ने उस रेस्ट्रिकशन को हटा दिया भौर उसका मतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में गुड़ के भाव ठीक हो गए । इन्होने ऐसा कर के इमेजिनेशन ही से काम लिया या । ठीक यही हालत भ्राज खण्डसारी की भी है। बरेली में, मुजफ्फरनगर मेरट में खण्डसारी भरी पड़ी है ग्रौर दूसरी जगह उसकी जरूरत है । लेकिन उस पर रेस्ट्रिकशन है । इसको भी ग्राप देखें ।

इरिगेशन के साथ-साथ बाटरलागिंग की प्राब्लैंग भी स्नाप पैदा हो जाती है। मेरी कांस्टिट्यूएंसी में गंगा कैनाल है लेकिन उसके किनारे हजारों एकड़ का रकबा सेलाइन हो गया है, वहां पर बाटर- लागिंग हो गया है श्रीर उपज के काबिल नहीं रह गया है । ऐसी ही समस्या मेरठ के कुछ इलाके में भी है । इन चीजों पर भी गौर किया जाए श्रीर इनको भी ठीक किया जाए ।

इंडस्ट्रीज में जब तक इनपुट न लगाया जाए तब तक श्राउटपुट नहीं होता है । उसी तरह से यहां भी जब तक पर्याप्त साधन न लगाये जायें, सब साधन न जुटाये जायें तब तक खेती किसान के लिए लाभ-दायक नहीं बना पायेंगे । उसका जीवन स्तर उठे, वह श्रपने लड़के लड़िकयों को तालीम टीक तरह से दे सके, उसकी समाज में एक पोजीशन हो, उसके पास साधन हों तभी वह खेती में श्रपना पैसा लगा सकेगा श्रीर मेहनत कर सकेगा श्रीर तभी उसको इस में कामयाबी हासिल हो सकेगी, यह निश्चित बात है । इस वास्ते इस श्रीर सब से पहले श्रापका ध्यान जाना चाहिये।

श्री विश्वाभ प्रसाद : सभापित महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ग्रट्ठारह साल की ग्राजादी के बावजूद भी जिस देश में जमीन इतनी ग्रच्छी हो कि एक क्या दो या तीन फसलें भी ली जा सकें, उस देश की खाद्य समस्या ग्राज तक हल नहीं हुई है। यह उस सरकार के लिये ग्रीर सरकार के कर्मचारियों के लिये, जिसके लिये भी कहिये, बड़े शर्म की बात है। जो सरकार देश की खाद्य समस्या नहीं हल कर सकती वह ग्रीर क्या कर सकती है। वह लड़ाई के लिये क्या कर सकती है? ग्रीर प्रोडक्शन के लिये क्या कर सकती है?

ग्रभी-श्रभी मुझे बतलाया गया कि 250 म्यूनिसिपैलिटीज ऐसी हैं जहां पर 6 लाख लोग भूखों मरते हैं। ग्रगर इस पर विश्वास न भी किया जाये तो भी जो ग्रादमी बिना भोजन नहीं, एक व दो वक्त को छोंड़कर तीसरे वक्त भोजन पाता है वह भी एक तरह से चुल भूल कर मरता है।

धगर इस तरह से देखा जाये तो इस देश भुखमरी बहुत है। यह राशन देती है चार छटांक। सरकार चार छटांक के राशन में कैसे काश्तकार खेत में काम करे या किसी मिल में काम करे या कैसे लड़ाई के लिये काम करे। इस देश के श्रन्दर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे भी लोग हैं जिनका साल में कई महीने भोजन वर का गोदा, श्राम की गुठली, गन्ने का रस ह चोटा है, मोलैंसेज, जो कि मिलों से निकाला जाता है, जिस को शीरा कहते हैं, महुग्रा, होता है । सब से बड़े शर्म की बात यह है कि हम जिस को गोबरहा कहते हैं, जिस की परिभाषा मैं इस सदन में पहले भी बता चुका हं , ग्रर्थात् बैल जब मंडाई के लिये जाते हैं तो कुछ ग्रन्न चुन कर खा जाते हैं। उस से जो पाखाना निकलता है उसमें से प्रनाज निकाल कर उसे खाने वाले लोग भी इस देश में बहत हैं। ग्राज इस विभाग का बजट कुल मिला कर है 5 ग्ररब, 89 करोड़, 55 लाख, 72 हजार है। इस को पास तो हो ही जाना है क्योंकि कांग्रेसी मैजारिटी है। लेकिन इस के साथ साथ ग्राप जरा पैदावार को देखिये :

> सन् 1960-61 में 810 लाख टन सन् 1961-62 में 810 लाख टन सन् 1962-63 में उस से कम 784 लाख टन

सन् 1962-63 में उसने थोड़ी ज्यादा 794 लाख टन

भगर पैदावार भ्रच्छी हो जाये तब तो कहेंगे कि हमारी प्लैनिंग बड़ी भ्रच्छी, लेकिन भ्रगर पैदावार फेल हो जाये तो भगवान को दोष । वेदर खराब था, पानी नहीं बरसा। मैं पूछना चाहता हूं कि भ्राज भ्राप करोड़ों रुपये ऐप्रिकल्चर पर फिर क्यों खर्च करते हैं। भ्राज भ्राप दतने रुपये का गल्ला बाहर से क्यों मंगाते हैं। भ्राप जरा भ्रायात 496 (Ai) LSD—6

के आंकड़े भी देखिये:

सन् 1962—36 लाख 40 हजार टन सन् 1963—45 लाख 56 हजार टन सन् 1964—62 लाख 65 हजार टन म्राज इस देश के अन्दर जहां 80 या 75 फी सदी किसान खेती करते हैं, आप कन तक गल्ला बाहर से मंगा कर खिलाते रहेंगे। आप के बजट में इस साल 4 अरब, 48 करोड़, 38 लाख रुपये सिर्फ गल्ले के पर्चेज के लिये रक्खें गये हैं। इस का कारण यह है कि आप ने गांवों के किसानों को बिल्कुल छोड़ा हुआ है। वह बिल्कुल नेगलेक्टेड रहे हैं। इसी तरह से सरकार ने भी कृषि विभाग को छोड़ा हुआ है।

श्राज श्राखिर पैदावार बढती क्यों नहीं है । कारण यह है कि जो लोग खेत जोतते हैं उन के पास काफी जमीन नहीं है। जिन के पास जमीन है वह खेती नहीं करते हैं। इस देश के भ्रन्दर चकबन्दी नहीं है। खेती करना लोग इस लिये पसन्द नहीं करते कि खेती से जो पैदावार होती है उस से लोगों को ग्रामदनी ग्रच्छी नहीं मिलती । इस देश के अन्दर सिंचाई के लिये पानी नहीं है । साल में सिर्फ तीन महीने पानीं बरसता है, नौ महीने सूखा रहता है, । 🥻 फिर जितना पानी वर्षा वगैरह से प्राप्त होता है उस का मुश्किल से 8 या 10 फी सदी पानी इस्तेमाल होता है। खाद महंगी है। लोग कहते हैं कि हम कैश काप बोयेंगे क्योंकि उस में पैसा ज्यादा मिलता है । जब उस को कैश काप में पैसा ज्यादा मिलता है तो वह फड काप क्यों पैदा करे। प्लैनिंग में यह सिद्धान्त माना गया है कि ग्रगर एक एकड़ जमीन में सिंचाई होगी तो छः मन ग्रधिक गल्ला पैदा होगा । लेकिन यहां 336 मिलियन एकड़ में कुल खेती होती है। यह सरकारी भांकड़े हैं। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि इस में कुल 70 मिलियन एकड़ में सिचाई होती है तथा उस में से भी सिर्फ 48 मिलियन एकड ऐसा है

[श्री विश्राम प्रसाद]

जिस में दो फसलें उगाई जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए इस देश में सिचाई का इन्तजाम कर दीजिये। भौर वह सिचाई कैसी हो। चीप, टाइमली भौर श्योर सप्लाई। सस्ती, समय से भौर पक्की सिचाई की व्यवस्था हो। क्या माज म्राप पानी पूरा दे देते हैं। किसान जानता है कि खाद डालने से ज्यादा पैदावार होती है, प्रच्छा बीज डालने से ज्यादा पैदावार होती है, लेकिन मजबूरी हो जाती है जब समय से पानी नहीं मिलता है। पानी न मिलने से जो केमिकल खाद होती है उस से खेती जल जाती है। भगर सिचाई की व्यवस्था अच्छी हो जाये तो एक नहीं हम दो या तीन फसलें यहां उगा सकते हैं।

इस देश में सिचाई के रेट भी बहुत ज्यादा हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिड़ला की ग्रल्युम्-नियम फैक्ट्री के लिये 3 न० पै० फी यूनिट पर बिजली मिलती है. किसानों के लिये सिचाई की व्यवस्था करनी हो तो ट्यूब वेल्स के लिये १६ न० पै० युनिट मिलती है । लिफ्ट कनाल बनाई जा सकती है, कुएं बनाये जा सकते हैं। रहट लगाये जा सकते हैं। व्लाकों पर कुल पांच सालों में साढ़े सत्तरह लाख रुपये खर्च हुए हैं, जिस का कोई फायदा नहीं है। ग्रगर साढ़े सत्तरह लाख रुपयों में उस जगह में ट्यूब बेल लगा दिये गये होते, कुंए बना दिये गये होते तो शायद इस देश की खाद्य समस्या जो है वह बहुत पहले हल हो गई होती । मेरी प्रार्थना यह है कि सब से जरूरी चीज पानी है ? सिंचाई के पानी का इन्तजाम भ्राप चाहे जिस कीमत पर भी करें, चाहे किसान को फी दें या सब्सिडा-इज्ड रेट पर दें, चाहे जैसे भी हो, उसे सें।

जो फर्टिलाइजर हमारे यहां बाहर से मंगाई जाती है वह 200 रू टन पर माती है । हमारे यहां वही बनती है सिंदरी में 370 रु० टन । लेकिन किसानों को वह दी जाती है 436 या 438 रु० टन पर । म्राप कहते हैं कि किसान पैदा-वार बढ़ायें । कहां से बढाये । इस में ऐप्रिकल्चर डिपार्टमेंट भी कुछ प्राफिट कमाता है । हालां कि वह कहता है कि हम प्राफिट नहीं लेते, लेकिन फर्टिलाइजर पर वह प्रोफिट जरूर कमाता है । यह विभाग किसानों को खाद देता है लेकिन किसान खाद कहां डाल सकेगा । म्रगर पानी नहीं मिलेगा तो उस की फसल जल जायेगी । म्रापर पानी न दे कर भी म्राप चाहेंगे कि वह खाद का इस्तेमाल करे तो कैसे काम खेलेगा ।

दूसरी बात भी मैं भ्रापको बतला दूं। एक अमोनियम क्लोराइड की फर्टिलाइजर है। उसे बनारस से, जौनपुर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से बनिये लोग दिल्ली के भ्रन्दर लाते हैं। भ्राप जाकर शहर में देख सकते हैं। उस का वह नौसादर बनाते हैं।

सरकार बहुत शोर मचाती है कि उसने गोबर गैस प्लान्ट बनाया है । कौन सा गोबर गैस प्लान्ट बना है यह देखने में नहीं भाता । सिर्फ कागज में जरूर वह स्नाता है जिस से कहा जाता है कि किसानों के ईंधन का काम चल जायेगा । गोबर की खाद तभी बन सकती है जब इस देश के किसानों की ईंधन की समस्या हल होगी।

एक माननीय सबस्य : गोबर होता है बैंलों का ।

श्री विश्राम प्रसाद: गाय का गोबर भी गोब रही होता है ।

दूसरा भी एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारी सरकार जानती है कि नाइट्रोज़ेनस फर्टिलाइजर जो है, भीर फास्फेटिक फर्टि-साइजर जो है दोनों का मिश्रण ठीक होना चाहिये। भगर नाइट्रोजेनस फर्टिलाइ-जर ज्यादा दिया जायेगा भ्रीर फास्फेटिक फर्टिलाइजर कम दिया जायेगा तो जमीन ऐसिडिक हो जायेगी जो कि पैदावार के लिये बहुत खराब है। इस लिये खेती के लिये बैलेन्स्ड खाद देने की जरूरत है।

भाप ने यहां पर पैकेज प्रोग्राम चलाया है। इस के अन्दर लिखा हुआ है कि इस से 20 से लेकर 78 फी सदी तक पैदावार बढ़ी है। धगर ऐसा है तो क्यों नहीं श्राप हर जगह पर पैकेज चलाते हैं।

इसके साथ मैं थोड़ी सी रिकमन्डेशन भी रखना चाहता हूं। नालागढ़ रिपोर्ट के **प्र**न्दर लिखा हुमा है कि ऐग्निकल्चर डिपार्टमेंट में 30 से लेकर 80 फी सदी तक लोग टेम्पोरेरी हैं। हमारी सरकार समझती है कि आई० ए० एस,० और आई० सी॰ एस॰ वाले लोग सब से ज्यादा होशियार भादमी हैं भौर सब कुछ कर सकते हैं।

एक माननीय सबस्य : हरफन मौला **1**

थी विश्राम प्रसाद: जी हां, हरफन मीला हैं। चाहे कोई टेकनिकल काम हो या दूसरा काम हो, माई० ए० एस० मीर भाई ० सी० एस० भादमी को रख दो । चाई कोई डाक्टर हो या बात ग्रच्छा टेकनीशियन हो मगर उस के कार भाई । सी । एस । या भाई । ए । एस । का कंट्रोल इस काम के लिये रख दिया जाता है। यह बड़ी भूल इस लिये मेहरबानी करके एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट में जो टेव निकल लोग हों उनको ही वहां पक्का किया जाय । घ्राज जो 30 से 80 फी सदी तक लोग टेम्पोरेरी हैं उनको परमनेन्ट किया जाय । मैंने देखा है

कि यु० पी० में जो सोलह सोलह भीर सत्तरह सतरह साल से नौकरी कर रहे हैं वह भी टेम्पोरेरी रक्खे जाते हैं। मैं चाहता हं कि उनको फौरन परमानेंट किया जाय।

of Food

इस के बाद मैं कहना चाहता हूं कि भगर किसान की पैदावार को बढ़ाना है तो भ्राप को इस का प्रबन्ध करना चाहिये कि उस को भ्रपनी फसल के लिये भच्छा पैसा मिले । जब किसान की पैदावार उस से खरीदी जाती है तब सस्ती होती है। लेकिन जब बाजार में जाती है तब वह महंगी होती है नतीजा यह होता है कि किसान को ग्रपनी चीजों के लिये बाजार से खरीदने में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है । इस बात का ध्यान रक्खा जाना चाहिये कि जिस हिसाब से किसान की फसल बिके उसी हिसाब को ध्यान में रख कर उस को जरूरत का मिलना चाहिये कहना चाहता हं कि जब किसान बेचता है उस समय जो कीमत होती है उस में भीर बाजार की कीमत में एक माना सेर से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिये।

यहां किसान के इन्सेन्टिव की बात कही गई है। जब तक उस को इन्सेन्टिव नहीं दिया जायेगा तब तक किसान की पैदावार नहीं बढ़ेगी।

15 hrs.

दूसरी प्रार्थना यह है कि भ्राप बफर स्टाक रखें ग्रीर जब देश में ग्रापत्काल द्यावे तो उसका प्रयोग किया जा सके।

जोनल सिस्टम बहुत बेकार चीज है। पंजाब का ग्रादमी खाए 25 रुपए मन गेहं भीर बम्बई का खाए 60 रुपए मन यू. पी. 50 रु मन । भीर इसमें पकडे वे लोग जाते हैं दिल्ली ग्रीर गाजिया-बाद के पास जो कि सेर दो सेर गेहूं ले कर जाते पाए जाते हैं, पर क्लैक

[श्री विश्राम प्रसाद]

11913

मारकैटियर लोग पुलिस को रुपया दे कर टूक के टूक ले जाते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता ।

किसान को कर्ज देना है तो बिना सूद के दें या बहत कम सूद लें। ऐसी व्यवस्था होने पर ही किसान पैदावार बढ़ा सकता है। म्रादिवासी इलाकों में तो म्रगर वे कर्ज नहीं वापस कर पाते तो उनकी जमीन ही नीलाम कर दी जाती है।

दूसरे मेरा निवेदन है कि श्राप 3600 की शहरी आमदनी पर इनकम टैक्स नहीं लेते । उसी तरह ग्रापको उस किसान से जो कि 3600 रुपए तक पैदा करता है लगान नहीं लेना चाहिए।

किसानों को खाद उचित भौर सस्ते दामों पर दी जाए । सिंचाई की म्रच्छी व्यवस्था की जाए जैसा कि मैं पहले कह चुका हं।

जहां तक जमीन के बटवारे का सवाल, जमीन उसी को दी जाए जो खुद खेती करता हो श्रौर उसके साथ यह शर्त रहनी चाहिए कि ग्रगर वह एक एकड़ में दस मन से कम पैदा करता है तो उसकी जमीन वापस ले ली जाएगी।

चीनी के बारे में मुझे यह कहना है कि भ्राप 35 परसेंट तो सैस ही ले लेते हैं। ग्रौर चीनी के वितरण के बारे में मुझे यह कहना है कि यहां जो म्रकेला बादमी है भीर होटल में खाता है उसको भी सात किलो चीनी देते हैं भीर जो बच्चों वाला है उसको भी उतनी ही चीनी देते हैं। मेरे यहां नौ प्राणी हैं, मुझे नौ किलो मिल जाती है। लेकिन बहुत से प्रादमी जो होटल में खाते हैं श्रीर श्रकेले 🖁 उनको भी सात किलो चीनी दी जाती

गन्ने का किसान को उचित मृल्य मिलना चाहिए । मेरी प्रार्थना है कि गन्ने के लिए भ्राप तीन रुपए मन का भाव निर्धारित कर दें, नहीं तो भ्रागे श्रापको किसान गन्ना नहीं देगा ।

खेती ग्राधुनिक ढंग से होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि जो लोग एग्रीकल्चर में डिग्री लेते हैं उनको कम से कम दो तीन साल के लिए गांवों में खेती करनी पड़े उसके बाद उनको नौंकरी करने की इजाजत दी जाए । ग्राज कल तो यह देखा जाता है कि ये लोग एक दन नौकरी के लिए भागते हैं।

एक माननीय सवस्य : ऐसे लोगों को पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी खेती में जरूरत है।

श्री बिश्राम प्रसाव : ग्रापने टारजेट मुकरेर कर रखा है कि ग्रगर इतना फरटीलाइजर दे दिया जाए तो इतना उत्पादन बढ़ जाता है, ग्रगर सिंचाई हो गई तो 6 मन प्रति एकड उत्पादन बढ़ जाएगा । मगर ग्रापको जो बी० डी० ग्रो० फिगर देते हैं वें सही नहीं होते, श्रापको उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए । ध्रगर भ्राप ऐसा करेंगे तो भ्राज की तरह बाहर से घावों रुपए का गल्ला मंगाते रहेंगे ।

पशुपालन के बारे में मेरा कहना है कि शायद पंजाब भ्रीर गुजरात की गाएं प्रच्छी होती हों, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश म्रादि में छोटी छोटी गाएं होती हैं । पश्-पालन विभाग एक ग्रच्छा सौंड तक सप्लाई नहीं करता ।

भ्राप खाद्य भ्रौर कृषि दोनों के मंत्री हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि म्राज जब कि हम को ग्राजाद हुए १८ साल के करीब हो रहे हैं भीर भ्रापका बजट 150 करोड़ से 2300 करोड़ हो गया है भीर भापकी टैक्स की ग्रादमनी 50 करोड़ से

बढ़ कर 1100 करोड़ हो गयी है, श्रापको ऐसी योजना बनानी चाहिए कि देश के गरीज श्रादमी को दोनों वक्त भरपेट भोजन मिल सके ।

श्री लहेंदन चौधरी (सहरसा) : महोदया, खाद्य समस्या के निदान के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और उसने इस बात का निश्चय किया है कि जो उत्पादक है उसको प्रोत्साहन दे और ऐसा मूल्य निर्धारित हो जिससे उपज की वृद्धि में सहायता प्राप्त हो । दूसरा कदम यह है कि मूल्य का नियंत्रण हो ताकि ज्यादा मूल्य न बढ़ सके ।

जहां तक इंसेंटिव देने का सवाल है मैं देखता हूं कि ग्रगर सन् 1952-53 के ग्रांकड़ों का सूचक ग्रंक 100 माना जाए तो सन् 1963 में ग्रनाज के मूल्य का सूचक म्रंक 102.8 था, किन्तु जो दूसरे निर्मित सामान हैं, उनका मूल्य ग्रधिक बढ़ गया । जैसे मन्य निर्मित वस्तुम्रों के मूल्य का सूचक श्रंक 129.8 हो गया श्रीर मिल के कपड़े का सूचक भ्रंक 131.9 हो गया। जब यह हुआ तो यह सोचा गया कि किसान को इंसेंटिव देने के लिए इस तरह के मृल्यों को निर्धारित किया जाए जिससे कि इस श्रसमानता का अन्त हो जाए, भ्रीर वैसा किया गया। सन् 1962 के बाद कीमतें बढ़ने का एक ट्रेंड स्वयं भी चला श्रीर सरकार ने भी सन् 1964-65 में जो कीमत निर्धारित की उससे भी दाम बढ़े। श्रीर श्राज सन् 1965 में 23 जनवरी सन् 1965 को भ्रनाज के मूल्य का सूचक भ्रंक 144.9 हो गया, निर्मित वस्तुम्रों का सूचक म्रंक 140.7 हो गया और मिल के कपड़े के मूल्य का सूचक श्रंक 133.7 हो गया । इससे स्पष्ट है कि जो सरकार का विचार था इस दिशा में वह पूरा हो चुका ग्रौर खाद्य की कीमत उस स्तर पर ग्रा चुकी जिस स्तर पर कि दूसरी वस्तुग्रों की कीमतें हैं। सदन में यह विचार व्यक्त किया गया कि किसान की

पैदावार की कीमत ग्रौर बढ़ायी जाए उसे मैं गलत समझता हूं। ग्राज कीमत का ग्रौर बढ़ना उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि किसानों को जितना पैसा मिले उतना ग्रच्छा है, लेकिन उससे ऐसी स्थिति न पैदा हो जाय कि जो दूसरे लोग हैं, जो उपभोक्ता हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको मुसीबत पड़ जाए। तो एक बात तो यह हुई।

दूसरा प्रक्न यह बाकी रह जाता है प्रोड्यूसर के लिए जो मूल्य सरकार ने निर्धारित किया है उसका पूरा लाभ किसान को मिलता है या नहीं। मैं कहता हूं ग्रौर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कि छोटे किसान को उसका लाभ नहीं मिला है। मैं जानता हूं कि जब छोटे किसानों की फसल खेतों में तैयार खडी होती है उसी वक्त बड़े बड़े व्यापारी उनको पैसा पेशगी दे देते हैं, भ्रीर मैं जानता हूं कि ग्राठ रुपए मन के हिसाब से उनका धान ग्राज बिका, जब कि म्राप ने उसका भाव 15 मीर 16 रुपए का तै किया । जो किसान की खड़ी फसल थी उसके लिए ग्रगर उसको एक एकड़ में 60 या 70 रुपए कम मिले तो उसको काफी नुक्सान हो गया । तो इस प्रकार सरकार ग्रपनी कार्यवाही से छोटे किसानों को राहत नहीं दे सकी । किसान की उपज खरीदने की उचित व्यवस्था नहीं थी भ्रौर उसको कोई समय पर पैसा देने वाला नहीं था । सरकार इसका इन्तजाम कर नहीं सकी। न कोई ऐसी व्यवस्था थी कि वह जा कर भ्रपना भ्रनाज उचित मुल्य पर बाजार में भी बेच सकता । छोटे किसान गरीबी के मारे होते हैं। जब वे उपज को बाजार में लाते हैं उस वक्त सरकारी व्यवस्था उसको खरीदने की नहीं होती। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो हमने चाहा दह नहीं हो रहा है। भाज हम जितना भ्रनाज प्राप्त करना चाहते हैं वह नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हमारे पास बफर स्टाक की कगी है। जो मदद छोटे किसान को मिलनी चाहिए वह नहीं मिली है। इसके लिए मेरा सुझाव

[श्री लहटन चौधरी]

है कि किसान को उसकी खडी फसल के खिलाफ एडवांस दिया जाए या नहीं इस पर सरकार विचार करे। मैं समझता हुं कि इसमें कुछ दिक्कतें होंगी, कम्पलीकेशन होंगे । लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को इस दिशा में काफी गम्भीरता से सोचना चाहिए। किसान को, विशेष कर छोटे किसान को इस प्रकार एडवांस देने की व्यवस्था होनी चाहिए । सरकार चाहे तो यह काम फुड कारपोरेशन द्वारा करा सकती है। जिस तरह भी हो उसको एडवांस दिया जा सके भ्रौर उसमें नियमितता भ्रौर एकीशेंसी रखी जाए । ग्रन्यथा ग्राप उनसे ग्रनाज नहीं ले सकेंगे ।

मैं ग्रब दूसरी बात कहना चाहता हूं धौर वह है उच्चत्तम विकय दर के सम्बन्ध में । सरकार ने उच्चतम मूल्य निर्धारित किये लेकिन क्या उस में उन्हें सफलता मिली ? स्पष्ट है कि सारे लोगों की यह राय है श्रीर सरकार भी जानती है कि उसमें सफलता नहीं मिली । इस का क्या कारण हुन्ना ? एक तो बड़े व्यापारियों की सट्टेबाजी भीर दूसरी ग्रोर बडे किसानों को भ्रनाज संग्रहकर रखना भ्रौर बाजार में उसे नहीं लाना । एक तरफ छोटे किसानों के हाथ का प्रनाज निकल गया ग्रत्यन्त कम दर पर ग्रीर वह व्यापारियों के हाथ में चला गया और जो बड़े किसान हैं वह ग्रपने ग्रनाज को मभी भी भपने हाथ में रखे हुए हैं भीर वह बाजार में उसे माने नहीं देना चाहते हैं भौर यह कृत्रिम कमी पड़ जाती है जिससे कि हमारी दिक्कत बढ़ जाती है। मैं चाहता हं कि प्रोक्योरमेंट के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए भ्रौर जो उसका तरीका है उस में सुधार किया जाय । मैं नहीं चाहता कि सरकार इस बात में हिचके कि जो बड़े किसान हैं उनसे लेवी न ली जाय । ग्राज जो लेबी का सिस्टम है वह बहुत ही डिफेक्टिव है, बहुत ग्रापत्तिजनक है। मैंने बिहार में जहां

कि लैवी ली जाती है देखा है कि जो बड़े बड़े स्टाकिस्ट्स हैं उन से यह लैवी नहीं ली जाती श्रीर जो बड़े किसान हैं उन से भी लैवी नहीं ली जाती है। जो पांच हौर्स पावर का एक छोटा सा हलर चलाते हैं ग्रीर जहां कि गांव वाले या या कर प्रपना ग्रनाज उस में से कुटवा कर ले जाते हैं उस पर लैवी लगाते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि अगर दस किलो उनके पास धान कटान को लाया जाता है तो पांच किलो तो लेवी के नाम पर रख लिया जाता है। जरूरत इस बात की है कि सरकार भ्रपनी पालिसी बदले भ्रौर भ्राप उनको एडवांस की सुविधा दीजिये । दूसरी बात यह है कि भ्रगर भ्राप उच्चतम मुल्य पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो भ्राप केवल भ्रपना बफ़र स्टाक बना कर इस तरह से कोशिश कीजिये ताकि ग्राप उसे नियंद्रित कर सकें। धगर धाप उच्चतम मृल्य का निर्धारण एफिशिएंटली नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिये लेकिन गलत चीज न फैलने दीजिये । भ्राज हम देखते हैं कि बाजार में चोरबाजारी चलती रहती है श्रौर श्रापका कानून उसे रोक नहीं पाता है। जरूरत इस बात की है कि सरकार कानून का इस तरह से पालन कराये ताकि यह चोरबाजारी जो कि माज चल रही है वह बन्द हो जाय।

बस मैं एक बात भीर कह कर समाप्त करूंगा । जुट के बारे में भ्राप सभी लोग जानते हैं कि जुट हमारा फोरेन एक्सचेंज का सबसे बड़ा जरिया है। चीनी से हमें 22.12 करोड़ रुपया मिलता है, चाय से 125.36 करोड़ मिलता है वहां जूट से 176.10 करोड़ रुपया मिलता है। लेकिन जुट के उत्पादकों की हालत सबसे शोचनीय है। जुट के उत्पादकों से जिनसे कि हमें इतना प्रधिक पैसा मिलता है वह सबसे प्रधिक उपेक्षित हैं। वह मनी क्रोप है लेकिन इसके लिए उन्हें किसी तरह की सुविधा नहीं दी जाती है। मैं बतलाना चाहता हं कि उत्तर

विहार जहां से मैं भाता हूं, सहरसा जिला, मैंने एक बार श्रौर भी इसे कहा है हिन्दुस्तान से जितना जुट बाहर जाता है उसका दसवां हिस्सा धकेले यह जिला पैद करता है और इसलिये सरकार को इसकी भ्रोर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये । प्रजीब हालत है कि जो सपोर्ट प्राइस सरकार ने तय की है किसानों को उस सपोर्ट प्राइस से कहीं कोई सरोकार नहीं है। व्यापारी लोग भौर स्टाकिस्ट्स इन बेचारे जूट उत्पादन करने बाले किसानों को बेतरह लुटते हैं लेकिन सरकार इस चीज को नहीं देखती है। मैं चाहता हं कि सरकार सबसिडी के रूप में इनकी सहायता करे । इसके म्रलावा सरकार कम्युनिकेशंस की वहां पर समुचित व्यवस्था करे। ग्रभी जो वहां पर इसका ग्रभाव है उसको पूरा करे भौर कम से कम छोटी छोटी कच्ची, पक्की रोड्स वहां पर बनाने की कोशिश करे ताकि उन्हें 30-30 श्रीर 40-40 मील इंटीरियर से जो भ्रपना सामान मार्केट में महंचाना पड़ता है भीर बड़ी दिक्कत उन्हें मेश भाती है उसमें उन्हें सुविधा हो सके। बहां के जुट उत्पादन करने वाले किसानों को सरकार को सुविधा देनी चाहिए भौर उन्हें सहायता देनी चाहिये क्योंकि सरकार को बृट के जरिए बहुत भ्रधिक फौरेन एक्सचेंज प्राप्त होता है । मैं इन शब्दों के साथ प्रपना श्राषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती शशांक मंजरी (पालामक) । सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है । यहां लगभग 80 प्रतिशत लोग बोती करते हैं किन्तु दु:ख की बात है कि यह 80 प्रतिशत लोग शेष 20 प्रतिशत जनता का पेट भरने में सफल नहीं हो रहे हैं। हर साल लाखों मन ग्रनाज विदेश से मंगवाना पड़ता है जिससे कि हमारे देश में चीजों की क़ीमतें भी बढ़ रही हैं। खाद्य समस्या को हल करने के लिए सरकार भी बहत कुछ कर रही है । सिचाई के साधनों का विकास कर रही है और किसानों को बढिया बीज द्धेक्टर व ग्रन्य उपयोगी कृषि ग्रौजार दिलाने

की व्यवस्था भी कर रही है। इस सब के बावजूद देश में सन्न की कमी क्यों है। इसका कारण यह है कि जो सहायता दी जा रही है वह पर्याप्त नहीं है ।

जिले की खाद्य समस्या दिन पर दिन विषम होती नजर मा रही है भीर सारा सरकारी यन्त्र असफल दिखाई पड़ रहा है। जब से मंत्रियों ने हल्ला मचाना गुरू किया है तो इतना तो जरूर लाभ हम्रा कि व्यापारी कुछ डर गये फिर भी नागरिक लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मृत्य वृद्धि रोकने की विशा में इसका असर नहीं पड़ा है। पहला कारण यह है कि व्यापारियों से मिल कर ग्रधिकारियाने खाद्य पदार्थों का जो बाजार भाव निश्चित किया, उस पर व्यापारियों ने ग्रमल नहीं किया बल्कि उलटे सस्ता गल्ला बाजार से उठा कर देहात के गोदामों में रख दिया ग्रीर शहरों में भी गल्ले का स्थानान्तरण कर दिया गया । उस के बारे में सरकार को जबरदस्त कदम उठाना चाहिए । जो ग्रादमी पकडा जाए उस को जबर्दस्त सजा दी जाय। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया ।

भनाज भीर खेती के बारे में सरकार की तरफ़ से पूरा ध्यान दण्डकारण्य में दिया जाना चाहिए । वहां ग़ैर-ग्राबादी जमीन बहुत पड़ी हुई है । उस जमीन को उपयोगी बनाने की जल्दी जल्दी कोशिश की जाये। ऐसे विकट समय में सरकार लगातार व्यापारियों एवं व्यवसायियों को चेतावनी, धमकी भौर भय देने से चुक नहीं रही है। मुनाफ़ाख़ोरी, संचयकारी, कालाबाजारी स्रादि का खले ग्राम उपयोग किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि ग्राज की विषम खाद्य समस्या के पीछे सरकारी रीति-नीति, भ्रदूरदर्शिता तथ योजना (या योजनाहीनता या गलत योजना) का ही कारण है। जब जब सरकार ने प्रश्न के स्रावागमन पर संक्रुश लगाया, नियंत्रण किया, क्षेत्र बनाया है, तब तब ग्रन्न का स्वाभाविक सहज प्रवाह श्रवरुद्ध हुन्ना है मीर

[श्रीमती शशांक मंजरी] महगाई बढ़ो है। लोगों को सामान प्राप्त करने में कठिनाई हुई है। घुसखोरी ग्रौर भ्रव्टाचार को बढ़ावा मिला है। साधारण जनता को, जिसे ग्रधिक मृत्य देना पड़ता है, सामान प्राप्त करने में कठिनाई उठानी पड़ती है ग्रौर इस दरबाजे से उस दरवाजे तक दौड़ लगाने स्रोर खुशामद करने को विवश होना पड़ता है। ऐसा एक बार नहीं, भ्रनेक बार हमा है। एक बार भी ऐसा नहीं हमा कि सरकार ने व्यापार के साथ छेड़छाड़ की हो ग्रीर उसका नतीजा दूसरा निकला हो । हाल में ही चीनी के नियंत्रण का नतीजा सब को याद होगा । अतः यह आवश्यक है कि नियंत्रण के नतीजों सभी को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों एवं सरकार जन-जन के जीवन के साथ ऐसी खिलवाड करना बन्द करें।

D. G .- Min.

बिहार को जो पूरा कोटा मिलता है, उसका एक-तिहाई हिस्सा बिहार के दस बड़े मिलों ग्रीर ग्राटा चिक्कयों को दे दिया जाता है। वे खुले-म्राम तेरह, चीदह रुपये प्रति बोरा मधिक ले कर ग्राटा बेच रहे हैं।

चावल की स्थिति किसी भी कीमत पर सुधरने की स्राशा नहीं है। लेकिन यदि **मच्छा गेंह भी लोगों को मिलता रहे, तो** स्थिति श्रधिक नहीं बिगड़ने पायेगी। निगरानी कमेटी बनी है, लेकिन उसके सभी सदस्य सूस्ती बरत रहे हैं।

एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में भ्रनाज भेजने पर जो रुकावट डाली गई है, उस को हटा देना चाहिए । कंट्रोल भ्रौर परिमट प्रथा उठा देनी चाहिए । उस के कारण मंहगाई बढ़ती है। सरकार को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, जिस में सामानों की प्राप्ति जन-साधारण के लिए सुलभ हो सके, अन्न का प्रवाह पूर्ववत कायम हो जाए तथा जनता को भूखों मरने की स्थिति से बचाया जा सके ।

कंट्रोल की व्यवस्था से बिहार देहातों में बड़ी फठिन स्थिति पैदा हो रही है। वहां पर प्रत्येक भादमी के लिए पांच छटांक ग्रौर बच्चे के लिए तीन छटांक का कोटा निश्चित किया गया है। लेकिन वह कोटा भी एक दिन मिलता है भीर फिर दस पन्द्रह दिन तक नहीं मिलता है। ऐसी हालत में ग़रीबों के लिए बहुत कठिनाई पैदा हो गई है स्रोर उन को खुले बाजार में बड़े मंहगे भाव पर अनाज लेना पड़ता है।

11922

बिहार के देहात में बहुत ग़रीबी है। वहां पर लकड़ी भी मिलना बड़ा मध्किल है। जो भ्रौरत लकड़ी लेने के लिए जाती हैं, उनको बहुत बेइज्जत किया जाता है। वहां पर जौतो मुड्ठी भर भी नहीं मिलता है। पहले लोग दो तीन श्राने पाव के हिसाब से चने का सत्तू खा कर पानी पी लेते थे श्रौर इस प्रकार ग्रपना पेट भरते थे, लेकिन ग्राज उस सत्तु की बिक्री दो रुपये के हिसाब से हो रहो है। ऐसी हालत में ग़रीब लोग किस तरह भ्रपना पेट पाल सकेंगे।

बहुत लोगों ने देखा होगा कि कलक्ता में सड़कों पर जो कड़ा-कंकर फैंका जाता है छोटे छोटे लकड़े उस कुड़े में से खाने की चीजों निकाल निकाल कर खाते हैं। हम रेलों में भी छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए देखते हैं। मैं सरकार से यह पूछती हूं कि क्या यह भारत की जनता नहीं है श्रीर क्या उन लोगों पर दया नहीं करनी चाहिए । सरकार को सोचना चाहिए जो बच्चे इस समय कड़े में खाने की चीजों निकाल निकाल कर खा रहे हैं भीर रेलों में भीख मांग रहे हैं, उनकी जिन्दगी क्या होगी, बडे होने पर उनका श्राचरण क्या होगा । वे चोरी करेंगे या जेब काटेंगे। इसलिए सरकार को उन लोगों की तरफ़ ध्यान देना चाहिए।

बिहार प्रान्त में कहीं कहीं तो पानी के श्रभाव से पूरी खेती नहीं हो पाती है ।

11924

इसलिए भावश्यकता इस बात की है कि वहां पर सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाए।

सभापति महोदय : ग्रव माननीय सदस्य को म्रपना भाषण समाप्त करना चाहिए ।

श्रीमती शशांक मंत्ररी : बिहार में बटाई दारी कातून के लागू किये जाने की सरकारी घोषणा से किसानों, मजदूरों ग्रीर बटाई जोतने वाले लोगों में घबराहट ग्रीर बेनैनी फैल गई है। लोगों में सर्वत्र इस बात की चर्चा है कि इस कात्त से सिवाय हानि के के हैं लाभ नहीं होगा । खेत वाले जमीन की केवल इस लिए बोधाई करेंगे कि कानन से उनको रक्षाहो सके। इस प्रकार ग्रन्न उत्पादन पर भी इसका बहुत बुरा ग्रसर पड़ेगा । कहते हैं कि दस पांच बीघे जमीन जोतने एले छोटे छोटे किसान भी अपने हरवाहों को उनके ग्रार्थिक निर्वाह के लिए कुछ न कुछ बटाई ग्रवण्य देते है । किन्तु इस कार्य का स्पष्ट परिणाम यह होगा कि खेन मालिक बटाईदारों को हटा देंगे । मेरा म्रनुरोध है कि सरकार इस पर ध्यान दे।

श्री बसवन्त (थाना) : महाराष्ट्र के एक भी सदस्य को मौका नहीं दिया गया

श्री लाखन वास (शाहजहांपुर) सभापति महोदया, मेरा नाम भी है।

Shri P. Venkatasubbaiah (Adoni): From Andhra Pradesh no speaker has been called so far. No Member from Andhra has spoken.

Mr. Chairman: Order, order. Shri R. G. Dubey.

Shri R. G. Dubey (Bijapur North): I rise in support of the Demands under the control of the Ministry of Food and Agriculture.

Mr. Chairman: I request the hon. to conclude within 10 Members minutes.

Shri R. G. Dubey: I am sure that the man who is at the helm of affairs of this Ministry is one of our best Ministers in this country. I not like to go into the of the working of this Ministry, but I should confine my remarks only to some broad features such as the policy, etc., to emphasise the exact role of agricultural production or the agricultural economy in the general economy of the country.

As the late Prime Minister used to say, agricultural sector is the biggest industry in the private sector. So, it is necessary that we have a proper perspective or appreciation of the role of agricultural production, because, what we call the balanced price structure in the country largely depends upon the success we attain in the field of agricultural production. For the last two or three years, there was a shortfall in the production of agricultural commodities, and it affected the price level in the country. Not only that. The fall in the prices of agricultural commodities affected the whole range of our economy. So, we should look at this problem from a very wide perspective. Not only we should aim at attaining self-sufficiency in foodstuffs to meet the requirements of our people, but actually we should have surplus production in agricultural commodities. The late Comrade M. N. Roy used to say—there were so many plans in the country then like the Tata-Birla plan, etc.—that if we have surplus production in agriculture, that will help the development of other industries in the different sectors of economy. It was a very good suggestion and that should be our attitude.

Unfortunately, the Food and Agriculture Ministry is in a very embarrassing position, because primarily the responsibility of making efforts in this direction lies on the State Governments. Only in providing funds for minor irrigation, fertilisers, arranging for proper coordination between the

[Shri R. G. Dubey]

Centre and States, the Agriculture Ministry comes into the picture. In that field, they are doing their best. The rest lies with the States Governments. There the picture is not very heartening. I do not know where lies the defect. We discuss this matter seriously here saying the requirements of agriculture should be met, etc. But at the district or block level, there is hardly that kind of seriousness. Some State ministers are good, but by and large, they do not take this matter very seriously. There are instances where the agriculture minister will attend to all other matters except his own problems. The minister in charge of a subject should spend the maximum time at his disposal looking into the difficulties of his department.

For example, if a person goes to the tehsil office for a taccavi loan, it takes many months to get the sanction. The poor agriculturist-sometimes he is not the proprietor, but only a tenant cultivator-has to spend his time and money in going to the tehsil office. He may have a small piece of land only. Such tenant cultivators, the middleclass cultivators as they are called, are very large in the villages. Of course, we know there are financial difficulties. But within the resources, we should see that maximum effort is made. Much more than in the secretariat, in the block level or district level, we should have something like a special committee. There are district development councils, but they meet only once in 2 or 3 months and within 2 hours they dispose of 50 or 60 subjects. They come by one train and go away by the next. This is not the way of tackling the problem of food production. So, at the district level, there must be a committee with the Deputy Commissioner of the area as chairman, a small and compact committee to attend to matters connected requirements of agriculture. This committee should have adequate powers and funds and be in a position to function effectively. It must meet frequently once in a week at least, not once in 3 or 6 months. So, whatever requirements are to be provided for the agricultural sector, within the limited funds, maximum effort should be made. Actually I am told in Madras when Mr. Kamraj was Chief Minister and Mr. Subramaniam was Finance Minister, in some cases loans were taken to the door of the cultivators there. That is the ideal thing. Some such thing should be attempted in every State.

With these words I thank you for the opportunity you have given me to speak.

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan): Mr. Chairman, I am getting an opportunity to participate in the debate after a long time. Previously when I was an ordinary membre, I got several opportunities to speak. I have listened with rapt attention to the speeches and I find that there was not much of criticism against the activities of this ministry. So, I take it that the policies adumbrated in the review of the food situation are acceptable to the members, because they have been evolved after mature consideration and deliberation and they are the best policies under the present circumstances.

I can call that policy as productionoriented, price control and distribution policy. I say it is productionoriented. because for the first time since my senior colleague took charge of this ministry, it has been accepted in principle that remunerative prices should be given to the cultivators. There may be difference of opinion as to the quantum. Whether the price fixed by the Jha Committee, was an ad hoc committee, was proper or something more should be paid, is a matter of opinion. But we all accept in principle that remunerative prices should be given to the cultivators. In pursuance of that policy, the agricultural prices commission has been set up. It will go into the problem, collect

11928

data and scientifically evolve the prices, taking into consideration all the factors in the economy. Under the present circumstances, it is the best policy and I am glad members have endorsed this.

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur); Question.

Shri D. R. Chavan: One or two hon. members criticised the policy of government with regard to grant of licences to cooperatives, particularly. Shri Sivamurthy Swamy made a criticism to the effect that the industrialists are being given encouragement to set up sugar mills, while cooperatives are being discouraged. That is one part of the criticism. Then, concerning the local problems, he said that the Chief Minister and the State Government had both recommended the setting up of co-operative sugar factories but in spite of that no encouragement is given by us and that the co-operative movement should be encouraged by the Government.

Concerning the growth of co-operative sector in the sugar industry I would like to place before the House certain facts. What was the position in the beginning of the First Five Year Plan, and how has the co-operative sector in the sugar industry grown? These are the things that will have to be seen. At the beginning of the First Five Year Plan there were 139 sugar factories in the country out of which there were only two co-operative sugar factories, one at Etikoppaka in Andhra Pradesh and the other in Pravarnagar in Maharashtra. What was the total capacity of the industry at that time? It was 16.7 lakh tons out of which only 0.14 lakh tons was in the co-operative sector. If this point is seen as to how this co-operative sector has grown up. the criticism that has been levelled will appear to be absolutely not legitimate criticism. The establishment of factories as growers' co-operatives has been given encouragement during the

licensing of additional capacity in the Five Year Plan by preferential licensing and liberal financial help. During the Plan period the total number of factories that were licensed was 70 and the total capacity that was sanctioned was 10.6 lakh tons. Out of these 70 factories, 54 were co-operative sugar factories and the total capacity licensed in the co-operative sector was 8.56 lakh tons. In addition to that, two co-operative sugar factories which already existed at the beginning of the Plan and one cooperative sugar factory which was a joint stock company and which was taken over and converted into a cooperative sugar factory at Anakapalle in Andhra Pradesh were also in full production. So the present licensed capacity is 33.77 lakh tons out of which the co-operative sector has 8.56 lakh tons. It commenced with 0.18 lakh tons and now it has come to 8.56 lakh tons.

Shri K. N. Tiwary (Bagaha): Will the hon. Deputy Minister mention something about expansion of old factories?

Shri D. R. Chavan: I am coming to that question. Another criticism made by another hon Member was that the people there have not been granted licences for setting up new sugar factories because it appears there is a powerful lobby which is preventing sugar mills being set up in the south. Out of the 57 sugar factories which have been establishin the co-operative sector, how many have grown in the south? What is the split up of these factories? You will be surprised to find that in alone about 20 co-Maharashtra operative sugar factories have come into existence, 3 in Gujarat, 9 in Andhra Pradesh, 2 in Kerala, 6 in Madras, 4 in Mysore, 4 in Uttar Pradesh, 1 in Bihar, 6 in Punjab, 1 in Assam and 1 in Orissa.

Shivaji Rao S. Deshmukh Shri (Parbhani): What is the number of applications pending from Maharashtra?

Shri D. R. Chavan: I would request hon. Members to have patience. I am now talking of the co-operative industry.

Shri Basappa (Tiptur): He has given the figure about Maharashtra?

Shri Shivaji Rao S. Deshinukh: That is about the licensed ones.

Shri D. R. Chavan: I am coming to the point referred to by my hon. What happened in 1959-60 and 1960-61? Licensing in sugar industry was stopped on account surplus production of sugar. As the House will remember, in 1960-61 the production of sugar was 30.2 lakh tons. The previous year's carry-over was also there and the total stocks much more. available were question before the Government that time was concerning the disposal of surplus stock. Therefore, licensing in sugar industry in 1959-60 was The question was again stopped. reviewed in 1963. Then it was decided to grant an additional capacity of 8 lakh tons. Applications called and the total number of applications that were received by the Government was 229. Out of these, 108 applications were for expansion and 121 were for establishment new factories. These 108 applications for expansion have been screened by Screening Committee. Screening Committee submitted their recommendations to the Licensing Committee. As a result of that, about 62 expansion cases have been cleared and letters of intent have been issued. What is the capacity that has been cleared? Out of 8 lakh tons additional capacity, these 62 cases covered a capacity of 3.96 lakh tons. Out of these 62 expansion cases, 22 are in the co-operative sector having a capacity of 1:66 lakh tons, and there are about 40 joint stock companies with a capacity of 2.26 lakh tons.

As regards the other applications which are pending with the Government, nearly 121 applications were for establishment of new factories.

These applications are pending consideration. Out of these 121 applications, 34 to 35 cases were recommended for spot study. Spot study in respect of 32 or 33 cases have been completed and a consolidated report will be prepared and submitted to Government for consideration.

Shri Basappa: Why did Screening Committee take so much

Shri D. R. Chavan: The requisite data had to be collected. The availability of cane had to be considered in respect of the place where factory was asked for. Whether there are potentialities of further growth has also to be considered. All these factors will be looked into very soon and the recommendations of the Screening Committee will be submitted to the Licensing Committee.

A point was made by one hon. Member saying that the per-acre yield has got to be increased. Nobody denies it, because the per-acre productivity in our country is very low, particularly in the field of sugar industry. What is the average per acre yield today and what was before? The per-acre yield in 1952-53 was only 11.9 tons. Now, account of several developmental projects that have been undertaken by the Government, like the intensive cane development scheme and the sugarcane development scheme, the yield has gone up. The sugarcane development scheme was introduced in 1948. It was continued in the First Plan, it was expanded in Second Plan and it is being continued in the Third Plan. On account of these activities the per-acre yield has gone up to 18.4 tons though in between there were certain years in which the yield achieved was not maintained in the subsequent season.

15.49 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Then I come to the factual position with regard to production in the country. What was the consumption during the last year, what was the export and what is the export that has been planned for this year? Let us also see what are going to be the losses on account of export and what is going to be our foreign exchange earning. Generally, a criticism is made that why should we export at the cost of internal consumption and when the international price is so low why should we not suspend our exports. All types of criticisms Therefore, I will made. tell House what was the position last year and what is going to be the position during this year, that is, 1964-65. During 1963-64 the sugar supply position in the country was very very difficult due to a shortfall in production and very little carry over of the previous year. Therefore, the regulation of price and distribution of sugar had to be continued in order to facilitate equitable distribution of available supplies at reasonable prices.

The production of sugar during 1963-64 was about 25.67 lakh tons, as against 21.52 lakh tons in 1962-63. This production, though higher than that of previous year, fell short of the earlier estimate of about 3 million This was on account of the tons. damage to the sugarcane crops due to adverse weather conditions during the period of growth and large-scale diversion of sugarcane from sugar to gur and khandsari. With a carry over of a little over 1.76 lakhs from the previous year, the total availability of sugar during the year was only 27.43 lakh tons. The off take of sugar from sugar factories for internal consumption during the year 1963-64 was only 23:36 lakhs tons as against 24.86 lakh tons during the previous year. Besides, a quantity of 2.34 lakh tons was exported and on the 31st October 1964 there was a carry over of 1.59 lakh tons. Now. of sugar during 1964 the export amounted to 2:34 lakh tons as against 3.73 lakh tons in 1962 and 4.79 lakh tons in 1963. Due to the higher international prices, even though th? sugar export during 1964 was less to the last as compared

we years, earned foreign exchange to the tine of about Rs. 19 crores. Due to the short supply position of sugar in the country, exports were curtailed in 1964.

Now, what is our export programme for 1965? The question of export during 1965 was carefully considered vis-a-vis our internal supply position. It was decided that sugar export should be continued but the quantum should be limited, the first instance, to 2:5 lakh tons. It was also decided that the position should be reviewed again some time later on to find out whether further exports could be possible in the light of production prospects during the current season.

Shri K. N. Tiwary: If you are going to have 5 lakh tons more this year than last year and you can meet your internal consumption, are you not thinking of exporting more sugar to earn more of foreign exchange?

Shri D. R. Chavan: That is what I have said. It will be considered in view of the production prospects.

In pursuance of the above decision, agreements have been made for exports of sugar to the following countries: about 91,000 to USA, 1,27,000 tons to UK and Canada under the Commonwealth Sugar Agreement and about 20,000 tons to Malaysia. total quantity that would be exported would be 2.38 lakh tons.

A question is often raised as whether any export at all should be made in view of the low production and at the cost of internal consumption. So for as production is concerned, we have already produced 29 lakhs tons up to 22nd April 1965, which is about 4.79 lakh tons higher than the production during the corresponding period of last year. Here I want to tell hon. Members that on the 22nd April out of 198 factories which worked only 94 factories were closed 104 factories are still working.

Shri P. Venkatasubbaiah: But you have not reached the target of 30 lakhs.

Shri D. R. Chavan: I am now talking only of the figures as on 22nd April. On that day 104 factories were working as against 36 factories that were working on the same date last year. Therefore, our expectation of reaching 30 lakh tons is likely to be exceeded. I am very happy to announce that to the House.

As regards internal consumption, the position is that, we are releasing every month nearly about 2 lakh tons. So, the internal consumption would be 24 lakh or 25 lakh tons.

A question is always asked about the exports. It is estimated that by the export of 2.38 lakh tons we are likely to get about Rs. 10 crores worth of foreign exchange. The loss by way of subsidy would be Rs. 12 crores. A question is often raised about the subsidy paid by the Government to meet the loss on exports. It is argued, why should we export at such a loss? Why should export of sugar not be suspended for present because the international price of sugar is very low? to be appreciated that loss on exports is dependent on the international price, which we cannot control.

Due to a variety of factors, our internal cost of sugar has been going up. The price of sugarcane has been increased to Rs. 5.36 per quintal as against Rs. 3.86 per quintal in 1958-59. This incerase in cane price has, during the last five years, been alone responsible for increasing the cost of Indian sugar by Rs. 150 per ton, thus entailing an additional loss of about Rs. 1.5 crores on exports of one lakh tons of sugar. The minimum prices for sugarcane are being fixed as a deliberate policy for giving price support to the growers who grow sugarcane on small holdings with inadequate irrigation and fertilizers, resulting in low per acre yield and poor quality. Besides this, increase in cane price, there has been further increase in the cost due to implementation of the Wage Board recommendations. There has been a general increase in the cost of raw materials.

15.59 hrs.

[Mr. Speaker in the Chair]

The cost of sugar f.o.b. Indian ports is also high because of heavy railway freight paid on movement of sugar from factories to ports of shipment. Further, it has to be appreciated that any scheme for export of sugar cannot be based on "as and when you like" basis, according to our convenience, depending on surplus available or when international for export, high. The importing prices are countries, we have to remember, are highly developed and prefer to import sugar from such countries as are regular and dependable suppliers. Further, sales for export can be made only at international prices, in competition with other countries. Regular exports are also necessary to retain a foothold in the various markets.

16 hrs.

Another consideration which has to be borne in mind for formulating an export policy is fulfilment of the obligations under the international agreements, such as the US Sugar Act under which we have got a quota of 91,000 tonnes and the Commonwealth Sugar Agreement under which we have got an overall Agreement quota of 1,27,000 tonnes.

Our realisation in a particular year depends upon the prices in the international market during the prescribed pricing period of various contracts. market has been The international highly erratic which displays very wide price fluctuations. In this regard I would like to inform hon. Members that the international price. that is, the London daily price, which is an index of the international prices, was £105 per ton in October and November 1963. Gradually, the price came down to £90 in the month of January 1964 and the price was £23.50 per ton on the 7th April, 1965.

An hon. Member: A terrible drop.

Shri D. R. Chavan: Therefore when we export our f.o.b. realisation from the foreign countries depends upon the international price that prevails there. Hon. Members have got to remember that the supply of sugar in the world market is much more than the demand; therefore, we have got to compete in the international market. By securing the quota under the US Sugar Act and under Commonwealth Sugar Agreement—the quota under this is called the Overall Agreement Quota—our foreign realisation on an average will be about Rs. 434 per ton. Had we sent this sugar to a general destination in the world market, our realisation would have been much less; it would have been Rs. 250 as against the average price that is likely to be realised because we are selling sugar in the preferential market. We, in Department of Food, have succeeded in getting a quota allocated to under the US Sugar Act and under the Commonwealth Sugar Agreement, that is, the Overall Agreement Quota, of 91,000 tonnes and 1,27,000 tonnes respectively at a price which is much higher. This has got to be appreciated in the light of the fact that had we sent this sugar to a general world destination, our realisation would have been Rs. 250 as against the cost price at the port of shipment of Rs. 960. Therefore, this has got to be appreciated.

The question then that is before us is as to how to reduce this loss and how we can sell our sugar in the international market at a competitive rate. That is the point that is before us. Reduction in loss on exports would be possible only when and if the per acre yield and quality improves for which of sugarcane development schemes are in progress as I have just now mentioned. sugarcane development schemes which were introduced in 1948-49 were continued in the First Five Year Plan, Second Five Year Plan and the Third Five Year Plan and expanded. Then there are the intensive sugar development schemes. The idea under the intensive sugar development schemes is to develop about 400 acres near about a factory and carry on intensive cultivation by giving fertilisers, irrigation, seeds, improved varieties and all types of things so that the per acre yield in a factory area should go up.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): This we know. How far are you giving this to the growers?

Mr. Speaker: The hon. Member is not in his own seat.

Shri Inder J. Malhotra: Moreover, he has already spoken.

Shri D. R Chavan: I may point out to hon. Members that there are tremendous potentialities of increasing the per acre yield. Recently at Jaora there was a prize distribution All India cane crop ceremony. competitions were held by the All India Central Sugarcane Committee in which a number of cultivators from the north and the south participated. The results that were obtained were astounding. For the purpose of crop competition the entire country was divided into two regions southern -northern region and region. The northern region comprised of the States in the north and the southern region comprised of Maharashtra, Gujarat, Mysore, Andhra Pradesh, Kerala and others. Crop competitions were held in four types of crops, that is, Adsali, Eksali, short duration and Ratoon. So far as Adsali is concerned, it is grown in northern India; it is grown only in southern India. So far as Eksali crop is concerned, the results achieved in northern India were that the first prize winner got as high a yield as 86:51 tonnes per acre and in the southern region the first prize winner got 147.92 tonnes per acre. For the Adsali crop also the first prize winner got at high a yield tonnes per acre. 156.97 83 indicates both in respect Eksali and Adsali crop-Ratoon crop also-that there are tremendous:

[Shri D. R. Chavan]

possibilities of increasing the per acre yield provided the facilities that are necessary for growing a good quality sugarcane crop are made available to the cultivators. It is for that very reason that all the developmental schemes—sugarcane development schemes and also other schemeshave been undertaken.

D. G.-Min.

As I have narrated to hon. Members, the yield per acre which was 11.9 tonnes in 1952-53 has gone up to 18.6 tonnes. Though I cannot say that it is a considerable achievement, there are tremendous potentialities of increasing the yield to 30 tonnes on an average.

This is the position with regard to the supply, distribution, internal consumption and our export gramme so far as sugar is concerned.

Shri Basappa: Can you tell us the average in the northern and the southern regions?

Shri D. R. Chavan: The average for the southern region, particularly Mysore State is about 34 tonnes, as against 13 or 14 tonnes in the northern region. In Maharashtra it is about 29 tonnes. Though it is not as high as Mysore, the recovery Maharashtra is very high. In Mysore the recovery is 10.4 or 11 and in northern India it is 9.4 or 9.6, whereas in Maharashtra it is 12.5.

Shri K. N. Tiwary: There is a report that without irrigation, manure etc. the average yield per acre is only 300 or 400 maunds but if these facilities are given, the average yield goes up to 600 maunds initially rising gradually to 1,000 manuds per acre.

Sh-i D. R. Chavan: Therefore I said that provided that all facilities in respect of irrigation, fertilizers, improved seeds are given, there are tremendous potentialities of increasing the yield per acre. I have seen the area on the Bihar side and I was very much surprised to find that quite a lot of water is available there, the lands are very, very fertile, very very rich and I came to the conclusion that not only sugarcane could be grown there but even human beings could be grown. Such a fertile land is there. Even then the per acre yield is very low, particularly in Bihar. Therefore, what is needed is initiative on the part of the cultivators and particularly those persons who are interested in the welfare of the rural people. It is for them to go amongst the masses, encourage them and initiate them into production.

Shri K. N. Tiwary: Facilities like those given in Maharashtra southern India are not given.

(Nagpur): What Dr. M. S. Aney are you there for?

Shri D. R. Chavan: When per acre yield could be increased in Maharashtra, when per acre yield could be increased in U.P., then per acre yield could be increased there also. These increases are coming at the initiative of the people. It is not that the Government should go there and cultivate the land and all that the people in Maharashtra are getting fertilisers, if the people Mysore are getting fertilisers, are these persons not putting pressure....(Interruption).

Mr. Speaker: Order, order. The Minister is not yielding. The hon. Member may resume his seat.

Shri D. R. Chavan: It all depends upon the initiative of the cultivator. the cultivator has a lot of dynamism and initiative, he can get as much yield as it has been obtained in other places.

Then, I come to some other activities of the Department of Food.

An hon. Member: He has already taken 35 minutes.

Shri D. R. Chavan: I will take five minutes more.

and Agriculture

Shri H. C. Soy (Singhbhum): All the time the Minister has been talking about cash crops. Will he talk something about the food crops?

Mr. Speaker: The reply to debate would come from the Minister at the end. He is only intervening. Whatever he chooses to say, allow him to say that.

Shri D. R. Chavan: I am now coming to some other activities of the Department of Food. There is the subsidiary food programme of the Department of Food. The schemes included in the subsidiary food programme of the Department of Food represent an effort to increase production and popularisation of nutritious food articles which would promote diversification of the diet by lowering excessive consumption cereal3 and increasing the consumption of other nutritious foodstuffs. I was reading the other day a very interesting article where it was mentioned that when the per capita income of the man increases, his per capita consumption also goes up and the difference that has been pointed is that if the per capita income goes up by 1 per cent, his consumption goes up by 6 per cent. Now, with the intention of reducing his dependence on the consumption of cereals, this programme has been undertaken by the Department of Food.

Then, a Food and Nutrition Board has been set up as a part of the Department of Food for securing an accelerated, coordinated and effective implementation of the programme of the development and popularisation of subsidiary and protective foods. The Secretary to the Government of India, Department of Food, will be the Chairman of the Board. In addition, the Board will have ten comprising of eminent members scientists and technologists and representatives of various Departments. What are the schemes which have been included under this programme? One of the schemes is UNICEF-ussisted Groundnut Flour Project. What is this project? Two units for the production of edible groundnut fiour have been installed. one each at Bombay and Coimbatore with the assistance from UNICEF in collaboration with the private industry. Both the plants have carried out trial runs successfully and are ready to start regular production

There are then the multi-purpose food plants. The State Governments of West Bengal, Uttar Pradesh and Kerala are establishing multi-purpose food plants with the capacity of one ton per day in collaboration with the Department of Food.

Two more units, each of one tonne capacity per day are also proposed to be set up in the Institute of Catering Technology and Applied Nutrition at Bombay and Madras.

(Trichur): What do Shri Warior they produce?

Shri D. R. Chavan: I have not myself tasted it. Unless I taste it I cannot say about it.

A proposal to establish two units of capacity each of 200 pounds a day of protein rich for the production biscuits based on edible groundnut flour, one each at the Institute of Catering Technology and Applied Nutrition, Bombay and Delhi, is under study.

project called the There is the mobile food and nutrition extension This project concern Food and Nutrition Extension Service which has been designed to bridge the gap between the existing knowledge and its application in the field of food and nutrition.

A beginning has been made by commissioning four Mobile Units with headquarters at New Delhi, Bombay, Madras and Calcutta. These units systematic campaign conducting a for the application of food preservation, prevention of wastage promo[Shri D. R. Chavan]

tion of sutable dietary habits, popularisation of low cost balanced diets, spreading the knowledge of scientific techniques of cookery and utilisation of food. Two more units will be pressed into service during the year.

Then, there are community canning and food preservation centres. With a view to salvaging valuable nutritious foodstuffs, that are being lost due to deterioration, projects have been initiated for the promotion of food preservation not only at commercial basis but also at the home scale basis. The Department of Food sanctioned Demonstration-cum-Community Canning and Food Pieservation Centres, one each at Bombay, Madras Calcutta and Delhi. The Unit at Delhi is already functioning. I do not know whether Members have seen this unit which is already functioning. It is very interesting to see how it is working. When there is a bumper vegetable crop, you have to harvest the crop and bring it home which may not be consumed at the same time in full. Then this preservation process becomes very important. These community canning and preservation centres are meant for the purpose of educating the people how to preserve vegetables and fruit. There is some equipment provided. If you go there, you can get your foodstuffs and vegetables processed and canned at a nominal rate.

All the four Institutes of catering Technology and Applied Nutrition at Bombay, Madras, Delhi and Calcutta. included in the Third Five Year Plan have commenced courses. The Delhi Institute has now entered the thirdyear of the Diploma Courses in Catering Technology and Hotel Management while the Institute at Bombay is running all the years of various The Institutes at Calcutta courses. and Madras have entered the secondyear of the three-years Diploma Courses in Catering Technology and · Hotel Management.

The question would be as to what is the pattern of assistance from the Central Government. As I just now mentioned there are four institutes that have been established at Delhi. Calcutta, Bombay and Madras. far as the Institute at Delhi is concerned, the pattern of assistance is that both recurring and non-recurring expenditure of that Institute is borne by the Food Department of the Government of India. So far as other Institutes which have been located at Bombay, Calcutta and Madras are concerned, the non-recurring expenditure is to be borne by the Food Department of the Government of India and 50 per cent of the recurring expenditure is borne by us and 50 per cent is borne by the State in which the Institute is located.

These are some of the activities which have been undertaken under this subsidiary food programme of the Department of Food. All the;e are working satisfactorily. There is the Community Canning and Preservation Centre function in Delhi. It is located in Kidwai Nagar. If the hon. Members want to visit this centre, I would welcome it. They can see how the food is preserved. It is a small centre with a small equipment. The idea is to spread this disseminate knowledge, and knowledge amongst the people and thereby save our valuable foodstuffs which are likely to be deteriorated and lost to the people and the public at large.

Sir there are certain other points also which I wanted to mention. But as the hon. Member just now said that I have taken more than 35 minutes, I would not like to take more time of the House. After two or three years I got this opportunity to participate in the debate and I thank you for the same.

Dr. L. M. Singhvi: Whenever education or agriculture or health are debated upon in this House, invariably the excuse is trotted out and paraded before us that the primary responsibility in these fields is that of the Governments of the States, and that, therefore, there is precious little that the Government of India could have done to redeem the present position. I am sure the House sympathises and commiserates with the variou: Ministers who perhaps would like to take shelter under these excuses, but I am sure that the House also feels strongly that these excuses are by and large purely lame excuses.

It is not enough to say that the primary responsibility under the distribution of Constitution and powers in the Constitution lies with the State Governments, because it is well known that the Union Government i: accustomed to intervene effectively in most matters concerning the jurisdictions of the State Governments. As a matter of fact, as we find the working and the operation of the Constitution today, federal framework has come as a de facto to be revised very substantially, I would like the hon. Minister, when he rises to reply to the debate, to spell out the difficulties he encounters on account of the distribution of powers enshrined in the Constitution. I would like him to tell us the nature of the difficulties. I would like him for ever thereafter to hold his peace and not allow these ground: to be paraded in this House. It is no use trying to make all the State Governments poor scape-goats. It is true that there are many sins of omission and commission on their part. the same time. by and large, the responsibility lies with the Union Government, in fact, both politically and administratively because it is they who pay the money and, therefore, it is they who call the tune. I should like, if necessary, the Food Minister to tell us whether he con iders that it is necessary and advisable and desirable to revise the federal framework enshrined in the Constitution rather than to rely every now and then on this ground or allow

the Government to rely on this kind of an excuse.

I also feel that the forces of coordination and forces of centralisation perhaps must have hegemony in our country, if we are to augment agricultural productivity in our country, but if that is so, then the Food and Agriculture Minister and the Government of India must courageously come forward to say that they are confronted with these difficulties because of the distribution of powers enshrined in the Constitution and that there should be a revision in the distribution of these powers.

I should like in this context to remind thi; august House that I had occasion to outline an idea for the purposes of better co-ordination for the constitution of a desert development authority, an authority which could launch an integrated, co-ordinated and massive programme of development of the arid regions in this country which are very considerable and large. When I first outlined this idea to the hon. Minister of Irrigation and Power, I found a responsive approach being applied to this whole thing. I know that a committee was appointed to go into this whole thing, and the committee had also reported a long time ago. The matter has been hanging fire or has been at least pending consideration for almost two years or more, and yet we find no decision having come forward. I should like to remind the House that this Government had given a specific commitment and an assurance on the floor of the House that such a body would be brought into existence very soon, and yet several months have elapsed since this assurance was given.

I know that there are difficulties in bringing into existence such a body and that it is difficult to secure at all times the willing co-operation of all the States. But in the cause of developing these large desert regions which are the only regions where the density of population is not very

[Dr. L. M. Singhvi]

11945

great and which offer great potential for agricultural development in country, a greater sense of dynamism and urgency was what we had expected from Government. I thought that such an authority should comprise to start with, at least the States of Punjab, Rajasthan and Gujarat which have desert regions.

But it is quite conceivable that such a board or authority should also have its jurisdiction extended to the arid regions of Ladakh as well as the arid regions of Rayalaseema in the south.

Shri Ranga (Chittoor): Madhya Pradesh also.

Dr. L. M. Singhvi: Wherever there are arid regions, because this is a problem which is scientifically considering, a functional problem. not so much a problem of political jurisdiction as a matter of approaching the problem from the point of view of technology. Unless we apply such superior technology to the matter of augmenting our agricultural productivity, I am not sure that all the promises given out to us by the hon. Minister can ever be redeemed.

I know that the Arid Zone Research Institute at Jodhpur is doing excellent work. I should like to pay a tribute to the small band of devoted scientific personnel who work at this Institute and who have done really remarkable work. But it is this Institute which shows the way to the Government as to what can be done on a much bigger scale. At the moment, the activities of this Institute are, to say the least dimunitive in extent. The size, very limited in make an effort Government should and see that the results of these researches are actually brought into operation by way of demonstration, by way of example, by way of dissemination of knowledge among the this country. In this farmers of particular matter, I feel that the

Government has done very little to enthuse us.

I shall briefly refer to a fact which has come to my notice sometime last and about which I feel concerned. I understand there was a serious and firm offer of Israeli collaboration for desert development in our country. In the field of technical collaboration, we have always enunciated the principle that irrespective of partisanship, political policy or political considerations we would always extend our hand of cooperation. Israel, as we all know, is the most leading country in the world today in the field of desert development and the results they have achieved are really notable and outstanding. I should know why the very much like to Government at the intervention, believe, of the External Affairs Ministry, even after certain negotiations had taken place between the Agriculture Minister of Rajasthan Government and the Government of Israel, have spurned the offer. I should very much like the Agricultural Minister to satisfy the House as to why these offers of technical collaboration are dealt with in such a cavalier and careless manner.

I should like to pay a tribute to the work of the Estimates Committee who have brought out very valuable reports on the working of this Ministry. I would only briefly refer to two of them, the 80th Report and the 75th Report for 1964-65. In the summary of recommendations, they say:

"The Committee are surprised to note that Government have thought of setting up the Institute in such an important matter as grasses and fodders only in Third Plan particularly when fodder scarcity is almost a regular feature. They think that considering the importance of the subject Government should have taken steps to fill the gap during the preceding ten years. The Committee are distressed to find that despite adequate financial provision being made in the Third Plan there has been dilatoriness in setting up the Institute. The Committee hope that Government would lose no further time in developing the full potentialities of the Institute and achieving the objectives underlying its establishments."

"The Committee regret to find that it would be possible to utilize only about Rs. 16 lakhs from a Plan provision of Rs. 45 lakhs for the Institute. They cannot appreciate the leisurely manner in which the Union Government have gone about in developing the Institute which admittedly can play a very effective role in augmenting the scarce fodder and grass resources for animals."

"The Committee need hardly stress that Government as well as the Institute should aproach the whole problem of fodder and grass resources with a sense of urgency so that it can play an effective part in increasing the scarce resources for feeding animals particularly the milch cattle."

This Report is replete with observations which constitute a very serious indictment of the manner in which Government have approached the problems concerning the augmentation of agricultural productivity. It is really a pity that matters such as augmenting our fodder and grasslands resources have received no attention for the first ten years of our planning, and even when they receive some attention Government are slothful enough not to utilise the provisions made in the Plan.

The story is equally distressing when we come to the programme of soil conservation. In Paragraph 34 of the summary of recommendations, the Committee says:

"The Committee regret to note that the Central Soil Conservation Board, which is charged with the responsibility to initiate, organise and co-ordinate research in soil and water conservation, has not been meeting more frequently. The Committee recommend that if the Soil Censervation Board is to discharge its duty more effectively, it should meet regularly at least once a year, if not twice."

It meets not even once a year, I understand. This is a distressing and sad commentary on the working of a body as important as the Soil Conservation Board.

The Committee have made several recommendations in the field of soil conservation. I would like to know whether and in what way the Government hopes to implement the various recommendations of the Committee, what its programme is both in respect of soil survey and soil conservation.

In respect of agricultural productivity, it is quite obvious that unless the whole framework of research is made more dynamic, made to yield much more than it is yielding today, we cannot take strides forward in the field of agriculture. I find on the testimony of this Committee that very little indeed has been done in the field of doing enough for the scientist who devotes his tes his whole life to the technology in the field of cause of agriculture. Very little thinking has gone into planning our curricula in the field of agricutural education.

Time does not permit me to go through all the various recommendations and observations made by this Committee, but I should like the Minister very much to tell us in detail what he proposes to do in respect of streamlining and improving the quality and content of agricultural research in our country.

Before I conclude, I should like to draw the attention of the Government to an item in today's issue of Economic Times in the first page [Dr. L. M. Singhvi]

which makes somewhat alarming reading. It says:

"The Union Finance Ministry is understood to have turned down the Food and Agriculture Ministry's proposal for conducting farm management studies with a view to determining the cost of production of the various agricultural commodities for a scientific fixation of their prices."

This matter is spelt out in this long despatch on the front page of Economic Times. It is a matter of considerable concern for us that such an important recommendation is allowed to be shelved and thrown out merely because the Finance Ministry feels that there is already an Agricultural Prices Committee which will go into the matter. It seems to me that those who actualy scrutinise such schemes in the Finance Ministry have no idea of what the implications of such a scheme would be. The Agricultural Prices Committee is an ad hoc appointment, it would go into the matter in the light of the materials available to it readily, but it would not constitute a permanent study cell regarding the components of agricultural prices. I would like the hon. Minister to let us know as to what is the real position in respect of these farm management studies, how it is that the advice of technical committees that and technical personnel is ignored in such a manner. I think it is a matter that we should all reflect on. It is not a partisan issue, it is a matter which I think is very important for the very working of technical Ministries. Unless we are prepared to accept and abide by the advice of people who are qualified to technical grounds, it advise us on would not be possible to make the kind of progress and breakthrough which technology alone can yield in this country.

I hope the hon. Minister would take lote of all the points I have made and would have the time and care to reply to them.

Shri Inder J. Malhotra: They very first question I want to ask the hon. Minister is this: What is our agricultural policy? He would recall that about a year back Shri S. K. Patil, the then Food and Agriculture Minister, said on the floor of the House that from then on the agricultural policy of this country was going to be farmer-oriented. I would like to know whether during this period the Minister has given any thought to the announcement which his predecessor made in this House; and, if so, what the Government thinks the various aspects of a farmer-oriented policy on agriculture would be and how far they have been able to mould the agricultural policy towards the goal of farmer-orientation.

In agriculture, the farmer is the most important man. I do agree, but, at the same time, I would like to draw the attention of this House and of the country to another man who really matters in the agricultural programme, and that is, the agricultural scientific research worker. I do not know whether Shri C. Subramaniam can recall that it was in February, 1960 when that very unfortunate incident happened in the Indian Agricultural Research Institute, namely, Dr. Joseph committing suicide. At that time, when that issue was raised, it was also promised on behalf of the Government that the Government would look into the various departmental procedures and other difficulties which are being faced by the agricultural scientists in respect of agricultural research in the country. Unfortunately, I have to say this: that in the past five years nothing of any significance has been done to see how the Government can create better working conditions for the agricultural scientist not only in the IARI but in all other research institutes of this country. I would, therefore, very humbly submit to the hon. Minister that he should kindly take personal and see what steps interest in this can be taken to improve the working conditions of agricultural scientists.

To my mind, agricultural research programme has been playing, and it has to play, a very important role, such as the availability of fertilisers, seeds and other amenities to the farmer. Unfortunately, our agricultural research programme has not delivered to us the amount of goods which the agricultural research programme is capable of doing.

The most disturbing factor in this programme has been that not only in the ICAR but even in certain other research institutes, there have been non-technical people who have been put as head of the institute. They had no required vision for research; they had no required technical background and so they could not appreciate the difficulties of agricultural research workers and the bottlenecks which used to come in the way of implementing the better agricultural research programmes.

I would like to congratuate the hon. Minister when I read the other day a news item that from now on, Indian Council of Agricultural search is going to be headed by agricultural scientist, and I belive, if I am not mistaken, that Dr. B. B. Pal, who had been the Director of Pusa Institute is now going to head the ICAR. I would like to pay my tribute to Dr. Pal who is an outstanding agricultural scientist of country. He has really contributed to the growth of agricultural research in that he has given us better strains not only in wheat but in so many other crops, and more especially, he is known as, and I can say that he is, the rose-king of this country.

Now that the hon. Minister has taken this step, I would request him to take another step. The function of the ICAR is not only to scrutinise the schemes submitted by the State Governments and give them financial aid from time to time. We have been told that the Indian Council of Agricultural Research is the central body which has to co-ordinate and supervise over the research programmes all

over the country. In the past that has not been happening. Since scientist like Dr. Pal is now going to head this organisation, I would like to suggest to the hon. Minister that he should see that all other research institutes should also be under ICAR so that this body can better coordinate the work as between various other research institutes also. I would not like to say much the folies and faults of ICAR since the minister has taken steps to improve. But I was realy shocked to see in the PAC report that for many years the ministry has been investing in securities the money which was given to it for research schemes. What a shocking state of affairs! On the one hand we want agricultural development on scientific lines. But if this is the state of affairs in premier research organisation, what organisacan we expect from other tions dealing with agriculture?

We should learn from our mistakes and try to improve. In the past so many times it has been said that the grades of agricultural officers and workers should be brought on services and par with other Indian Agriculture Service should be created. Nalagarh Committee commended it so many years Every year an assurance was given here that a Bill would be brought forward soon. It is often said that the agricultural services do not attract the best talent as IAS or IFS. The simple reason is this. Unless you bring the emoluments of the agricultural services equal to those of other services, the best talent would be diverted to other services. So, the minister should see that this recommendation of Nalagarh Committee is fully implemented as soon as possible.

About 1½ years back, there was a hill development seminar at Simla. As a result of its recommendation, the ministry created a hill development board. The significance of this board now is greater when we are having trouble in the borders. All the hill

[Shri Inder J. Malhotra]

areas have remained undeveloped in the past and not much attention was paid to them, wheather in Jammu and Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh or elsewhere in the country. So, the board was created. But it has met only once and decided that within six months, the ministry would prepare a sort of blue-print for agricultural schemes, and schemes to develop communications in those areas and those schemes will be scrutinised by board. I am a member of this board, but I am not aware whether blue-print has been prepared or not.

16.44 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair.] If the minister in charge changes it does not mean that the most important work should be neglected.

In NEFA area, popularisation vegetable growing was undertaken. If that is still in operation the minister may see that it is expanded and more facilities are provided in those areas for vegetable growing and other crops as well. Our late Prime once made a remarkable statement.

He said there is no mystery about Indian agricuture, the only thing we lack is the implementation of scheme. Just by repetition of this word "implementation" we are not going to achieve anything. I would, therefore, request the hon. Minister to take the necessary steps. I want to congratulate him for the steps he has By creating the Agricultural taken. Prices Commissission he has done a very good job of serivce to the cause of the farmers. But I would request him that he should see that there must be one or two members who can really project the point of view and act as a sort watchdog on behalf of the farmers in that Commission.

In the end, Sir, I want to say this, that to increase agricultural production it is very necessary that where

you give all your concern to the farmers you should never forget agricultural research workers.

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (झज्जर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव भ्रापके सामने रखना चाहता हुं। हमारा⁻ किसान राष्ट्र का प्रमुख ग्रंग है। वह धरती को बो कर भ्रम्न देता है राष्ट्र को, पशुपालन करके घी दूध देता है, स्रोर सेना केलिए सैनिक देताहै। तो यह राष्ट्रकाः सब से आवश्यक अंग है। इसके उत्तर हमें ध्यान देना चाहिये।

पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हुं कि भारत के इतिहास में, संस्कृत के इतिहास में महाभारत से पहले केवल एक दुर्भिक्ष का वर्णन ग्राता है। पहले कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ा। कारण क्या था? कारण यह था कि हमारे पशुबहत होते। थे। उनसे दूध घी म्रादि मिलता था। यदि स्राज हम इस बात पर ध्यान दें तो। ग्रन्न की समस्या सुलझ सकती है। दूधा, घी का ज्यादा प्रयोग होने से स्रन्न का प्रयोग कम हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले. श्रावश्यक है कि पशन्नों की रक्षा की जाये। गौ की हत्या तो भ्रापको एक मिनट में बन्दः कर देनी चाहिए, पर गौ के अलावा अन्य पश्रमों की हत्या भी बन्द करनी चाहिये । भेड़ बकरी से हमको दूध भी मिलता है श्रौर बाल भी इनके काम के होते हैं। इसी तरह से दूसरे पशुपक्षी भी उपयोगी हैं। यहां तक कि सांप भी जहरीली वाय को चसता है और यह सन्न के लिए उपयोगी है। तो मैंने इसलिये पशुम्रों की रक्षापर बल दियाः कि इससे मन्न की समस्या सुलझेगी।

सरकार कहती है कि खालों से हमको. विदेशी मुद्रा मिलती है। मेरा निवेदन है कि कम से कम ग्राठ दस साल के लिए पश्यों की हिंसा बन्द कर दी जाए,

इतने पशु हो जायेंगे कि मरने वाले पशु श्रों की ग्राप चाहें जितनी खालें बाहर भेजें। लेकिन एक बार मैंने जो कहा वह तो करके देखिये।

दूसरी बात पानी की है। पानी की एक समस्या है। मैं पहले भी यह बात कह चुका हूं कि ग्रगर फिर दूहराता हूं, शायद म्राप इसको म्रसम्भव मानेंगे। यदि गोधन की रक्षा हो तो उसकी रक्षा के साथ पानी की समस्याभीहल हो जाएगो। गोबर से बहुत अच्छी खाद बन सकती है। गोधन होने से श्रापको खाद के लिए बड़े मड़े कार-खाने नहीं बनाने होंगे। मेरा सुझाव है कि ग्रगर किसी किसान के पास सौ बीघा भूमि है तो उसे चाहिये कि 75 बीघा भूमि में खेती करे, बाग लगावे, सब्जी पैदा करे, पर 20 या 25 बीघा भूमि गोचर के लिए छोड़ दे जिसमें लकड़ी भी पैदा होगी भौर गाएं भी चरेंगी भ्रौर भ्रापको बाहर से खाद मंगाने की श्रावश्यकता नहीं रहेगी।

भ्राप एक तमाशा देखिये। भ्राज गन्ने जैसी चीज, जिससे गृड़ बनता है, का दाम दो रुपया मन भ्रापने तै किया है भ्रौर जंगली लकड़ी, जिसे बेकार लकड़ी कहा जाता है वह पांच ग्रौर 6 रुपये मन गीली बिकती है। पता नहीं सरकार के विचार करने वाले लोग कैसे विचार करते हैं? उस की कीमत तो इतनी दें भ्रौर उस भ्रमृत रस को देने वाले गन्ने की कीमत सरकार 2 रुपये मन से मागे नहीं बढाना चाहती। इतना ही नहीं बल्कि लाखों एकड़ भूमि बजाय खाद्याम उगाने के उस पर तम्बाकू जैसा बहर बोने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्यों बोया जाता है तम्बाकु ? यह किस काम भाता है ? सिवाय इसके इस से हमारा नुकसान हो लाभ कुछ भी नहीं है। तम्बाकु की खेती को बन्द करना चाहिये ।

ग्रागे चीज यह है कि ग्रन्न के मुल्य किसानों को समुचित नहीं मिलते हैं। किसान जो खेतीबाड़ी करते हैं, गेहूं, जौ, बाजरा ग्रीर ग्वार गन्ना ग्रादि पैदा करते हैं ग्रीर उनमें रात दिन एक करके जी तोड़ मेहनत करते हैं स्रौर बीज, खाद को मिला कर जो किसान की अपनी उपज की लागत आती है उस लागत को देखा कर किसानों को कम म्ल्य दिया जाता है। जरूरत ग्राज इस बात की है कि किसानों को उनकी फपल के ग्रधिक मुल्य दिये जायं जिससे कि उनमें ग्रधिक ग्रन्न उगाने के लिए उत्साह भैदा हो ग्रोर वह स्रधिक सन्न पैदा करके देश को इस' मामले में स्वावलम्बी बनायें ताकि यह देश सुखी ग्रीर समृद्धशाली बन सके।

of Food

and Agriculture

ग्रधिक ग्रन्न उगाने केहेतु ग्राप यह जितनी समितियां बनाते हैं, श्रन्नोत्पादन में वृद्धि के लिए यह सब बातें श्राप भ्रवश्य करते हैं लेकिन ग्राश्चर्य इस बात का है कि समितियों के म्रन्दर जो परम्परा से खेती करने वाले लोग हैं उनका कोई प्रति-निधि उनमें नहीं लिया जाता है स्रौर उन समितियों में वही लोग रहते हैं जिन्होंने कि एग्रीकलचर में जा कर के बी० एस० सी० या एम० एस० सी० कर लिया है, ऊंची डिगरियां प्राप्त कर ली हैं लेकिन जो कि खोती के काम को स्वयं नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल ज्ञान जिनको कि उस बारे में नहीं है। जिन लोगों को इस बारे में प्रैक्टिकल ज्ञान है, भनुभव प्राप्त है उनको भ्राप इन समितियों में लेते नहीं हैं तो फिर यह खेती का उत्पादन कैसे बढ सकता इसलिये मेरा यह भी सुझाव है कि समितियों के ग्रन्दर बराबर उन किसानों को लीजिये जो कि परम्परा से किसानी करते ग्राये हैं, खेती करते ग्राये हैं।

मभी एक भाई ने कहा या कि वह नजफ-गढ़ के पास गये थे। पहले एक हजार

[श्री जगदेव सिंह सिद्धांती]

रुपये एकड़ भूमि का भाव या ग्रीर बेच देते थे लेकिन ग्रब 5000 रुपये एकड़ के भाव पर भी देने को तैयार नहीं हैं। मेरा कहना है कि उस भाई को पता नहीं है खेती की कीमत का। एक हजार रुपया बीघा एक रुपये गज मिली । कोई किसान एक हजार रुपया बीघा ग्रपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। बेचारे को पता तो था नहीं ग्रीर किसान समस्या पर बोलने केलिए खड़ा हो जाता है। ग्रन्न की समस्या को उसी तरह से सरकार को लेना चाहिए जैसे कि यद्ध स्तर पर कोई काम किया जाता है। अगर ऐसा किया जायेगा तो हम सफल होंगे चीर देश ग्रधिक ग्रन्न उपजा सकेगा। और समैं पहले भी कह चुका हूं हमें स्वयं ग्रपने देश में श्रधिक मन पैदा करने का प्रयास करना चाहिये ग्रीर उसके लिए किसानों को सभी तरह से प्रोत्साहन देना चाहिये भ्रौर यदि ऐसा होता है तो हमें बाहर से श्रन्न मंगाने की श्रावश्यकता नहीं रहेगी। श्राज पाकिस्तानी आक्रमण के फलस्वरूप हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है ग्रीर हो सकता है कि उसका श्रीर विस्तार हो जाय श्रीर उधर चीन के साथ भी हमारा युद्ध हो जाय तो अभी हम जो श्रमेरिका, कनाडा अर्ौर श्रास्टेलिया श्रादि से श्रावन मंगाते हैं, जहांजों में भर कर उधर से श्रन्न हमारे देश को म्राता है म्रौर हमारे ये शत्रु लोग उन जहाजों को डुबो दें तो क्या होगा ? इसलिये भ्राप भ्रपने घर में अधिक अनाज पैदा की जिंग ग्रीर भ्रापकी तमाम समस्यायें भ्रपने ग्राप हल हो जायेंगी। सारी ताकत घर की घर में रहेगी। बाहर के भरोसे पर राष्ट्र को जीवित नहीं किया जा सकता है बल्कि हमें ग्रपनी भ्रावश्यकता की समस्त चीजें भ्रपने घर में ही पैदा करनी चाहिये।

ग्राज, चारों ग्रोर देश में महंगाई की चर्चा होती है। लोग बढ़ती हुई इस

महंगाई से परेशान हैं, चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका स्थायी हल यही है कि हम ग्रपनी ग्रावश्यकता का सामान स्वयं ग्रपने देश में निर्मित करें क्योंकि जब तक म्रादि बाहर के देशों से सामान मंगाते रहेंगे यह महंगाई घटने वाली नहीं है भौर भ्राप कितना ही एलाऊंस महंगाई का देते चले जायं यह विषस सर्किल टूटने वाला नहीं है। ग्राप कितनी ही वृद्धि महंगाई भत्ते में करते जाइये यह मंहगाई शैतान की श्रांत की तरह बढ़नी ही रहेगी। उसका एक ही उपाय है स्रोर वह है देश को स्रात्मनिर्भर बनाना। भ्राप बेशक ग्रन्न का मृत्य कम कर दें लेकिन जिस हिसाब से जिस अनुपात से ग्रम्न का मुल्य प्रापने कम किया है उसी हिसाब से किसानों को भ्रावश्यकता का सामान, बीज, खाद, कृषि ग्रीजार ग्रादि ग्रावश्यक चीजें भी उसे कम दामों पर सप्लाई करें।

एक बात मैं चलते चलते कृषि मंत्रालय
के बारे में कृषि मंत्री जी से निवेदन कर दूं।
हिन्दी के ग्रिधकाधिक प्रयोग के संबंध में गृह
मंत्रालय ने हाल में ग्रपने श्रादेश जारी किए
थे। कृषि मंत्रालय को भी यह श्रादेश पहुंचे
थे कि ग्रपने वहां हिन्दी के शब्दों का प्रयोग
किया जाए लेकिन मुझे पता लगा है कि कृषि
मंत्रालय द्वारा उनकी श्रवहेलना की जा रही
है ग्रीर हिन्दी शब्दों का प्रयोग नहीं किया
जा रहा है।

इसके म्रलावा जो म्रंग्रेजी के पोस्टर्स छपते हैं, किताबें छपती हैं मौर विज्ञापन म्रादि छपते हैं तो गांव वालों को उनसे कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा है मौर वह म्राप के ढेर के ढेर पोस्टर्स यहीं पर पड़े रहते हैं। म्रगर म्राप चाहते हैं कि किसान लोग समस्या को समझें जो इसके लिए हिन्दी में यह तमाम चीजें छापी जायें मौर जो प्रादेशिक भाषायें

and Agriculture

हैं उनका इस बारे में ग्रधिक से ग्रधिक प्रयोग किया जाए । मैंने इस भ्रवसर पर यह चन्द एक सुझाव दिये हैं भ्रौर मुझे भ्राशा है कि उन पर सहानुभृतिपूर्वक विचार किया जाएगा। ऊपर से भले ही देखने में भ्रापको मालुम पड़े कि व ठीक नहीं हैं लेकिन वे हैं दरग्रसल लाभदायक ।

Mr. Deputy-Speaker: Shri Balgovind Verma.

Some hon, Members rose-

Mr. Deputy-Speaker: I am prepared to sit even beyond six o'clock

Shri R. S. Pandey: That is very good.

Shri Subodh Hansda (Jhargram): Give a chance to each State.

श्री बालगोविन्द वर्मा (खेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि एवं खाद्य मंत्रा-लय की खर्च की मांगों का समर्थन करता हं श्रौर मंत्री महोदय तथा उनके द्वारा उन के मंत्रालय के सभी अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हुं जिन्होंने कि ऐसी विषम परि-स्थितियों में भी देश को जोकि ग्रन्न-संकट के बीच में फंसा हुन्ना था उसको उन्होंने काफी हद तक बचाने की कोशिश की।

यह तो निर्विवाद है कि खेती के ऊपर ही हमारे बहत से यह जो उद्योग हैं वे चल रहे हैं। इसलिये यदि देश में लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा करना है तो खेती को बढावा देना पडेगा। उसकी उन्नति करने के लिये सिन्निय कदम उठाने पहेंगे। जो भी काम ग्रभी तक इस दिशा में हम्रा है उस से मैं कम से कम सहमत नहीं हूं। उसके लिये बहुत कुछ करना है। ग्राखिर ग्रपने देश के भ्रन्न संकट को दूर करने के लिये हम कब तक विदेशों पर निर्भर रहेंगे ? विदेशों पर हम हमेशा निर्भर नहीं कर सकते। प्रत्यक राष्ट्र

के जीवन में ऐसा समय प्रक्सर ग्राता है जबिक बाहर से श्रन्न मंगाना कठिन हो जाता है । ईश्वर जाने, ऐसी परिस्थितियां कभी भी हमारे सामने ग्रा सकती हैं। जैसे कि ग्रास-पास के राष्ट्र इस बात पर तुले हुए हैं कि वे गडबड करें तो हमें गम्भीरतापूर्वक इस बारे में सोचना पड़ेगा श्रीर भ्रपने देश में ही श्रधिक श्रन्न उपजाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमारे राष्ट्रनायक जवाहरलाल जी देश के बारे में बड़े बड़े स्वप्न देखते थे भ्रौर जीवन भर उसको साकार करने के लिये प्रयत्नशील रहे। वह चाहते थे कि हमारे देश के ग्राम लोगों का जीवनस्तर ऊंचा हो, उनको खाने पीने की सुविधा हो, हमारे यहां के गरीब किसानों की हालत सुधरे, उनके घरों में बिजली हो, रेडियो हो ग्रौर उनके रहने के मकान पक्के बने हए हों। ग्रभी उनकी वह कल्पनाएं साकार होनी बाकी हैं। लेकिन युझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्रकार से हमारी नीति कृषि के बारे में चल रही है उसके रहते हम कभी भी वह कल्पना साकार नहीं कर सकते ।

श्रभी हमारे उपमंत्री महोदय ने बतलाया कि हमारी पालिसी फारमर ब्रोरिएंटेड पालिसी है हमारी प्राइस सपोर्ट की पालिसी है। मैं तो नहीं जानता हं कि कौन सी रेम्यु-नरेटिव प्राइस वह किसानों को उसकी उपज के लिए देने जा रहे हैं ? ग्रब 20 रु० मन का दाम गेहं के लिए रक्खा गया है अब आप ही बताइये कि जब किसान को कैश कोप में इस से कहीं श्रधिक पैसा मिल सकता है तो वह यह खाद्यान्न, गेह, चना, जो, बाजरा स्नादि बोने में अपना समय और श्रम क्यों लगायेगा ? जब तक भ्राप इस के लिए किसानों को उनके खाद्यान्न के उचित मल्य नहीं देंगे तब तक वह खाद्यान्न उगाने के लिए प्रोत्साहित कैसे होंगे ? यही कारण है कि किसान ग्रब केश कोप ज्यादा बोने लगे हैं क्योंकि उसमें उन्हें ग्रधिक लाभ होता है ग्रीर भाप इस बारे में ग्रांकड़े उठा

[श्री बालगोविन्द वर्मा]

कर देख लें कैश कोप किसान ज्यादा बोने लगे हैं भीर जाहिर है कि गल्ले की कमी भ्रापको पड़ेगी ही क्योंकि म्राज कोई भी म्रादमी गल्ले को पैदा नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे दाम उसके मुनासिब नहीं मिलते हैं । स्रावश्य-कता इस बात की है कि देश में ग्रधिक ग्रन्न उपजाने के हेत् म्राप किसानों को रेम्युनरेटिव प्राइत इंसेंटित प्राइत दें, जितना भी ग्रधिक से ग्रधिक प्रोत्साहन इसके लिए दे सकते हैं वह ग्राप किसानों को दें। यह कोई नई बात हमारे सामने नहीं है । जापान, ग्रमेरिका म्रादि जैसे समृद्धिशील देशों ने यह किया है। जब उनके यहां खाद्य समस्या थी, उनके यहां ग्रन्न की कमी थी तो उन्होंने किसानों भ्रनाज ड्योडे दामों पर लिया भौर उपभोक्ताभ्रों को वहां की सरकारों ने कम कीमत पर सप्लाइ किया । यही चीज भ्रापको भी यहां करनी चाहिए। भ्रगर भ्राप देश की उन्नति करना चाहते हैं, खाद्यान्न की स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो ग्रापको किसानों को उपज की ग्रच्छी क़ीमत देनी होगी ग्रौर उप-भोक्ताग्रों को सबसिडाइज्ड रेट पर ग्रनाज भ्रापको महैयया करना पडेगा । यह चीज म्रावश्यक है स्रीर बिना इसके म्राप प्रपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सकते हैं। भाज यह चीज हमारे यहां नहीं हो रहो है। धाज हम को 5000 करोड़ इपये का गल्ला बाहर से मंगाने में बहुत श्रासानी मालुम पड़ती है लेकिम यह समस्या का कोई स्थायी हल नहीं है वल्कि खाद्यान्न के बारे में ग्रापको देश को श्रात्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए भ्रीर जाहिर है कि उसके लिए भ्रापको किसानों को प्रोत्साहन देना पडेगा भौर उनको उनकी उपज के भ्रच्छे दाम देने पहेंगे।

17 hrs.

यहां पर बारबार यह कहा जाता है कि गल्ले के दाम कम किय जाय, प्राइस कंट्रोल किया जाये । मैं यह कहना चाहता हूं कि **भ्रगर हम किसानों को 45 रु० मन भी दें** तो वह कोई ज्यादा रकम नहीं होगी, क्योंकि जब तक किसानों को उचित दाम नहीं दिये जाते हैं, तब तक उनमें इन्सेंटिव पैदा नहीं होगा और जिन लोगों ने गन्ने या अन्य कैश काप्स में ग्रपनी जमीन लगा रखी है, वे उसको गल्ले में नहीं लगायेंगे । भ्रगर भ्राज नहीं, तो कल सरकार के लिए इस पर विचार करना जरूरी हो जायेगा । सरकार को गल्ले की कीमत कैंश ऋाप्स की कीमत को देखते हए ही तय करनी पडेगी, क्योंकि किसान को कैश काप्स से ज्यादा कीमत मिलती है बनि-स्बत गल्ले के । इस लिए वह गल्ला पैदा करना कभी भी म्नासिब नहीं समझेगा, जब तक कि उस को उचित दाम न दिये जायगे ।

माज किसान को जो थोड़े बहुत दाम मिलते हैं, उन का एक बड़ा भाग आढ़ितये, मिडलमेन, ले लेते हैं । यह ठीक है कि कुछ क्रय-विकय समितियां बनी हुई हैं, लेकिन चूंकि मेरा भी क्रय-विकय समितियों से सम्बन्ध है, इस लिए मैं जानता हू कि आढ़ती लोग किस प्रकार उन के मार्ग में रोड़े अटका कर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसका हमारी संस्थायें नहीं पनप रही हैं । मैं यह भी बता दूं कि कुछ ऐसी भी जगहें हैं, मंडियां हैं, जहां क्रय-विकय समितियां स्थापित नहीं हो पाई हैं।

मैं घापको घ्रपने जिले, लखीमपूर खेरी, के बारे में बताना चाहता हूं कि किसान कई नदी-नाले पार करके घ्रस्सी नव्बे मील की दूरी से मंडी में घ्रपनी फसल लाते हैं। मंडी में घाढ़ती लोग देखते हैं कि किसान घाठ दिन के बाद घपने गांव से यहां पहुंचा है, घ्रगर हम इस को परेशान कर दें, तो यह सस्ते भाव पर गल्ला हमारे यहां डाल कर चला जायेगा। घीर एक्चुघली यही होता है। इस लिए यह जरूरी है कि क्य-विक्रय समितियों की

तरफ़ ज्यादा ध्यान दिया जाये, जिस से हमारे किसानों को ग्रपने गल्ले की समुचित कीमत मिल सके. ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि में उस समय तक उन्नति नहीं हो सकती है, जब तक इरिगेशन ग्रीर पावर ग्रीर सह-कारिता मंत्रालय ग्रलग ग्रलग बने रहते हैं। ग्रगर सरकार वास्तव में कृषि की उन्नति करना चाहती है, तो उसको विद्युत ग्रौर सिंचाई तथा सहकारिता मंत्रालयों को कृषि मंत्रालय के स्रधीन करना पडेगा—–इन सब को एक साथ मिलाना पडेगा । स्राज हम देखते हैं कि यदि किसी किसान को सिंचाई के लिये टयबवैल बनाने के लिए कर्जा मिल जाये, तो फिर बरसों तक इस बात की नौबत नहीं ग्राती है कि उस को पावर मिल जायेया भ्रगरवहऋण लेना चाहता है, तो उस को आसानी से ऋण मिल जाये । यदि ये सब डिपार्टमेंट्स कृषि के भ्रन्तर्गत भ्रा जाते हैं, तो उनमें कोभ्रार्डिनेंशन भ्रा जायेगा और वे सब एक-साथ मिल कर काम कर सकेंगे भ्रौर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यह जरूरी नहीं है कि कुछ ग्राद-मियों को खपाने के लिए ये ग्रलग ग्रलग मंत्रा-लय कायम रखे जाये। भ्रगर कृषि को बढ़ावा देना है, तो सिचाई, विद्युत ग्रीर सहकारिता के विभागों को कृषि के साथ मिला देना चाहिए । तभी कृषि के क्षेत्र में कुछ उन्नति हो सकती है, वर्ना नहीं।

जहां तक माइनर इरिगेशन स्कीम्ब का सम्बन्ध है, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है, लेकिन इस सम्बन्ध में कर्जा मिलने में परेशानियां होती हैं। अब यह जरूरी हो गया है कि हम कर्जा देने की व्यवस्था करें। सरकार उस के लिए जो भी व्यवस्था और साधन अपनाना चाहे यह अपनाये। लेकिन अगर वह किसानों को उन्नत करना चाहती है, तो वह एक साधन रखे, पचासों साधन न रखे। किसान जितना भी कर्जा चाहते हैं, उन की जरूरत और साख को देखते हुए वह उन को दिया जाये। इस से उन लोगों की उन्नति हो सकेगी।

of Food

and Agriculture

एक माननीय सबस्य : गवर्नमेंट केडिट को देखती है ।

श्री बालगोबिन्व वर्मा: मैं ने कहा है कि सरकार उन की साख, क्रेडिट, को देखे, लेकिन उनको छूट देनी पड़ेगी। छूट के बग़ैर तरक्की नहीं हो सकती है।

श्रगर किसी किसान ने ट्यबवैल बनाना है श्रौर बिजली की लाइन वहां से एक मील के फासले पर हैं, तो श्राठ हजार रुपया वह ट्यूब-वैल पर लगाए श्रौर साथ ही श्राठ हजार रुपये बिजली वालों को दे, तब उस को कने-क्शन मिलेगा । श्रगर सरकार समझती है कि इस तरह से कृषि में उन्नति होगी, तो यह कोरी कल्पना होगी श्रौर वह इस में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगी ।

बिजली के रेट्स के सम्बन्ध में हमारे देश में उत्तर और दक्षिण में जो भेदभाव किया जाता है, वह बहुत ही मन्यायपूर्ण है । मभी तक यह देखने मैं भ्राया है-भ्रगर इस बीच सरकार ने कोई परिवर्तन किया हो, तो वह मझे मा-लम नहीं है, लेकिन ग्रभी तक यह स्थिति रही है--कि ट्यबवैल के लिए जो बिजली दी जाती है, उस के लिए उत्तर में 28 पैसे पर-युनिट श्रीर दक्षिण में 9 या 10 पैसे पर-युनिट चार्ज किये जाते हैं। सरकार इंडस्ट्री को सब्सिडाइज्ड रेट्स पर बिजली देती है। मैं समझता हूं कि कृषि के साथ भी वही व्यवहार करना उचित होगा । ग्रगर सरकार सारे देश में समान रूप से सुविधायें नहीं देती है भौर हर जगह एक युनिट के लिए एक दाम नि-श्चित नहीं करती है, तो कृषि में उन्नति नहीं हो सकती है। ग्राप जानते हैं कि पानी देने में बिजली खर्च होती है, इसलिए बिजली के दाम इतने मधिक भीर भिन्न-भिन्न रखने से कृषि के विकास में वाधा पड़ती है। सरकार

[श्री बालगोविन्द वर्मा]

को यह मोचना होगा कि चिंसाई के लिए बिजली की कम से कम कीमत रखी जाये।

यह टीक हैं कि खेती के लिए खाद बहुत जरूरी है। लेकिन ग्राप देंखे कि किसान चाहे कहीं से भी कर्जा लेना चाहे—चाहे वह केन डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या की-ग्रापरेटिव डिपार्टमेंट हो, सरकार की ग्रीर से उस पर सीलींग लगा दी गई है कि उस को पच्चीस या तीस फ़ीसदी खाद लेनी पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को पर्सुवेशन से खाद लेने का प्रयत्न करना चाहिए। ग्रापर वह जबदंस्ती खाद नाद देती है, तो हुं उस से किसानों में रिवल्शन पैदा होती है, दुर्भावना पैदा होती है। चूंकि में किसानों के बीच में रहता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि वे किस प्रकार इस को बुरा मानते हैं।

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam): Where is this compulsion?

Shri Balgovind Verma: It is there in my district, namely Lakhimpur-Kheri.

मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट मैं ही नहीं, बल्कि सारे उत्तर प्रदेश में यही ब्यवस्था होगी ।

यदि सरकार ने कुन्नां बनाने के लिए छ: हजार रुपये का ऋण दिया और ऋण के साथ यह शर्त भी लगा दी कि पच्चीस फी-सदी ग्रर्थात् डेंड हजार रुपये की खाद लेंनी पड़ेगी, तो फिर किसान कुन्नां कैसे बना पायेगा? ग्रगर उस के पास पैसा होता, तो वह कर्जा ही क्यों लेता? क्या सरकार बह समझती है कि यह इस तरीके से खाद के उपयोग को बढ़ावा देने जा रही है? सरकार महले कुन्नां बनवाए ग्रौर फिर खाद दे, क्यों कि मगर कुन्नां नहीं होगा, तो किसान खाद को क्या करेगा?

मेरा जिला, लखीमपूर खेरी, हमेशा एक सरप्लस जिला रहा है, लेकिन ईश्वरीय प्रकोप के कारण, वर्षा न होने के कारण वहां पर फ़सलें नहीं हो पाई हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां पर सिचाई का प्रबन्ध किया जाये।

मैं ने पिछले साल भी कहा था कि कुद्र जगहें ऐसी हैं-- कम से कम उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी जगहें हैं--- जहां मेकेनाइज्ड फ़ार्मिगं होती है भौर इस लिए उन जगहों में दैक्टरों की मर-मत स्रादि के लिए वर्कशाप बनाए जाने चाहिएं। हमारे यहां ज्यादातर मेकेनाइज्ड फार्मिंग होती है, इस लिए वहां पर एक वर्क-शाप खलवा दिया जाये । ग्रगर कोई किसान टैक्टर ले जाता है ग्रीर थोडे दिनों के बाद उस का कोई पूर्जा ख़राब हो जाता है, तो उसकी मरम्मत की व्यवस्थान होने के कारण या तो वह बेकार पड़ा रहता है या वह किसान कौ-डियों के मोल किसी दूसरे को बेच देता है। मैं ने सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि सरकार हमारे जिले में एक वर्कशाप खंलवा दे। केवल मेर जिले में ही नहीं, जहां जहां मेकेना-इज्ड फार्मिग होती है, वहां पर छोटे छोटे वर्कणाप खोले जाने चाहिए। सरकार किसानों से मरम्मत के लिए चार्ज कर सकती है। इस से सरकार को भी लाभ होगा ग्रौर किसानों को भी लाभ होगा।

मैं चाहता हू कि ट्रैक्टर के लिए जो मोबिल ग्रायल दिया जाता है, उस पर सबसिडी दी जाये। मैं यह भी चाहता हूं कि घनकुट्टी मशीनों पर से रेस्ट्रिक्शन हटा दी जाये, क्योंकि ग्रब गरीब लोग भी ग्रपना समय बचाने के लिए घर पर घान कुटवाना पसन्द नहीं करते हैं, बल्कि उस के लिए मशीनों पर जाते हैं।

Shri Maniyangadan (Kottayam): There are certain States from which no Member has yet spoken. Mr. Deputy-Speaker: There are many Members who want to speak. If necessary, I am prepared to sit till eight o'clock. Let us go on with the speeches.

Shri Maniyangadan: Even then there is no guarantee that we shall get a chance to speak.

Shri Brij Raj Singh-Kotah (Jhalawar): Please extend the time for this debate.

Shri Maniyangadan: We have no objection to sitting till 8 P.M. But what I am submitting is that there are certain States from which no Member has spoken so far.

Shri K. N. Tiwary: Please extend the time.

श्री हु० च० सोय : उपाध्यक्ष महोदय, श्राप ने यह क्या तरीका श्रपनाया हुग्ना कि जो माननीय सदस्य ग्राप के पास जाते हैं, उनको तो बुला लिया जाता है ग्रीर जो लोग डिसि— प्लिन्ड तरीके से बैठे रहते हैं, उन को ग्रवसर नहीं दिया जाता है ।

Mr. Deputy-Speaker: I am calling the hon. Members one by one. The hon. Member may await his chance.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: No Member from Maharashtra has spoken so far.

An Hon. Member: Two Members have spoken from that State. (Interruptions).

श्री श्रोंकार लाल बेरवा : उपाघ्यक्ष महोदय, वह क्या सब्जी मंडी बना रखी है? पालियामेंट में कुछ अपनुशासनरखना चाहिए।

Mr. Deputy-Speaker: Shri K. N. Pande.

Shri K. N. Pande (Hata): Taking into consideration the size of the problem, I think nothing more can be

done than what the Ministry has done so far. But there are so many things which require their serious consideration.

If we take into account the figures of import of wheat and other foodgrains from 1953 to 1964, they are of the value of Rs. 1,324.8 crores. It is true that when there is a shortage of foodgrains in the country we have to make some arrangements so that the requirements may be met for the time being. The easiest way to do that is to import foodgrains from foreign countries. But how long can we depend on foreign countries? There are two things which we must bear in mind. First, we have to pay Second, we are not a large sum. realising that the main responsibility for meeting the food requirements of the country when there is a shortage, and therefore the responsibility for adequate food production, is that of our own country. I want to ask the Minister whether instead of spending such a huge sum on importing foodgrains will he take into consideration the question of giving some help to the cultivators so that they can increase our food production. There are two ways of helping the cultivators. One is to provide them with adequate irrigation facilities. other is that they have to be given better seeds, fertilizer and financial help, so that they may purchase the necessary implements and other things for his agricultural operations.

What is our achievement so far as provision of irrigation facilities is concerned? This matter is really causing us anxiety. The target fixed in the Third Plan to provide facilities for irrigation was 29:47 million acres, but the achievement is 23.16 million acres. If this is the pace at which we are providing facilities for irrigation, I do not think we will ever be able to increase our food production. When there is a shortage of foodgrains, it is the Food Minister who is charged. So he has to see that all requirements concerning food production of the country are met.

[Shri K. N. Pande]

He has to see that the target of irrigation facilities is achieved. So he has to arrange in consultation with the Irrigation Ministry that what is provided for in the Plan is really achieved.

Now I would say something about the sugar industry. When the Deputy Minister was speaking, he referred to the yield per acre in the north and south. For his information, I want to mention here that it is not that in the whole of Maharashtra they are able to produce more cane per acre. It is only in a certain belt and in some districts. So do not be so proud That time can never about that. come when you will be able to meet the requirement of the whole country from there. The land there is fertile. It is the fertile land which counts. Also, there is the facility of irrigation. In that belt, they have got canals from which they can get as much irrigation as they need. So unless you provide all these facilities to the north also, you cannot challenge us this way.

Then again, it is the recovery which is important. Also, we have to see as to how much relief the consumer is going to get due to these advantages in south. In the south, it is only in Maharashtra and Mysore that recovery is good; I can tell you in Andhra, the recovery is not to that level. Similarly in Madras. In Kerala, it is 8 per cent. I want to say that recovery cannot be increased as and when you wish. It is due to a good variety of cane which can give us a better yield. In spite of the fact that you are having a higher yield, the consumers have to pay more price in the south than what their counterparts pay in the north? Why? If there is higher yield, the cultivators get more money. But the price of sugar which is paid by the consumers is much more in Maharashtra, in the south, than in the north. So you have to take into consideration that also.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: They have to pay more for sugar?

Shri K. N. Pande: For sugar.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Or for cane?

Shri K. N. Pande: Cane also. They have demanded more. I agree with that proposal. Still, the consumers are not getting any relief because the prices are high.

Shri C. Subramaniam: In Maharashtra the price is the lowest.

Shri K. N. Pande: What is the price paid by the consumer? You compare.

After all, unless the economic position of the entire country is improved, it is no use talking of improvement if a certain belt which is economically well off. For instance, a commission was appointed to fix the different prices for commodities because there is so much divergence. Recently I went to Rajasthan. I saw that in Ganganagar area because the cultivators are getting more price for cotton, they have now stopped producing cane. It is due to the sugar factories that the economic position the cultivators has improved. Therefore you cannot say that as these factories are not economic units, that these factories are running at a loss, therefore they should be shifted to the South or Maharashtra.

Shri D. R. Chavan: Nobody said

Shri K. N. Pande: So many people say so sometimes. Therefore, you have to provide facilities to these people, so that they may also fall in line with those who are economically well off.

Shri J. P. Jyotishi: The causes of the deficiency should be studied.

Shri K. N. Pande: That is what I want.

The hon. Minister knows that Western U.P. has got certain problems. It is not that the problem has

emerged just now. It is a permanent feature. In spite of their best efforts, these sugar factories have not been able to compete with gur and Khandsari. The result was that the sugar factories in Western U.P. had to close for some months intermittently. How do you think the condition of these factories can be improved. The Government had announced some rebate in the excise duty in order to have better production, but in spite of the announcement, the condition has deteriorated, and the result is that it is not only factories which are affected, but it is hitting workers more. They were asked to sit down. Naturally they were entitled to relief of half pay. In these days when the prices are so high, if the workers are asked to sit down and are paid only half pay, how do you think they can live and make both ends meet?

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Have more sugar factories in the cooperative sector.

Shri K. N. Pande: You are in a better position. That is why you are saying this. Otherwise, if the recovery is lower, the co-operative cannot do anything. That is a different matter.

So, let the hon. Minister find out a permanent solution, so that these factories in western U.P. may be in a position to improve their condition.

There was a proposal of the Ministry that if there were two or three uneconomic units, they should be merged together. A committee was appointed by the UP Government, and its report has come and is going to be discussed in the development coun-At that very time I raised my objection to such proposal. Hitler used to say that two fools cannot make a wise man. Unless you expand those factories and make them economic, if two uneconomic units are merged, how can they become econo-This is a matter for consideramic? tion.

Although this matter has not been decided and no final action has been taken by the Food Ministry on the isssue, they gave permission to the Rampur sugar factories to together, as in that way these factories accordingly to them will become economic. What was the motive behind Was it to dispose of 700 people out of employement? I do not know how this order was issued. I want the Minister to kindly consider that order. It is not going to be tolerated so easily; that the workers in thousands could be thrown out of employment and disposed of like that. If you want to pursue such a policy, I think you will not be able to produce sugar in order to meet the requirements of the country. I therefore urge upon you to consider all these aspects before taking a decision and also to consult the labour representatives before issuing such an order.

of Food

and Agriculture

Mr. Deputy-Speaker: Shri Warior.

Some Hon. Members: Are we sitting only till 6 o'clock?

Mr. Deputy-Speaker: Seven, or even eight if you want. But Members who want to speak must be here. (Interruption).

Shri Warior: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I wanted to participate in this debate firstly to focus the attention of the Government, especially of the Ministry, on the very acute situation in respect of the food problem in my State of Kerala. It is not after all a new problem. But the only fact is that at times it becomes very grave and dangerous and sometimes it eases a bit. At present, the report is that the ration shops in Kerala are distributing only raw rice and that also not a very good stuff. Hence, reports are coming to the effect that the epidemic of Cholera has already started even in the capital city of Trivandrum. Formerly, it had been there in Alleppey and other districts, but now it has spread and is spreading,

[Shri Warior]

11973

and the people are very much agitated over it. The central godowns of Kerala, I am told, are having some stock of parboiled rice, but the Supplies Department is reported to have no such authority to direct the depots to the various places which require parboiled rice, and it is left to the depot-keepers themselves or the Superintendents of the depots, whoever is responsible for the depots. to distribute it according to their own whims and pleasure. Then, there is also much discrimination which is experienced, and I want the Government to look into this matter and see that the agitation of the people is removed and parboiled rice is supplied equally to all the places.

.The second problem is this; now, the lean months are coming and the monsoon will be very heavy on Kerala coast, and as usual, from time immemorial even, we call these months the most roguish months. when the people do not have any income, do not have any work or they do not have anything to eat also. In those months, Kerala used to experience even on previous occasions. diseases like cholera, diarrhoea and so on. So, I plead with the Minister to see that sufficient stocks are even now rushed to Kerala so that at least the four lean months will be covered by adequate supplies.

The problem is not only that. is only about two kilos of rice that is now supplied by the fair price shops which are converted into ration shops. We suggested and the Kerala Food Advisory Committee also suggested that there should be statutory rationing. We had hopes formerly, when the Food Minister announced that at least in the principal cities like Bombay and Calcutta and other cities as well as in the deficit State of Kerela, they were thinking in terms of statutory rationing, and in the beginning, informal rationing would be instituted. Now informal rationing has come, but the informal

rationing did not have as much impact as was expected on the open market. The prices are rising even now, and the papers are reporting that rice per bag now costs Rs. 100; at times it goes to Rs. 120 or Rs. 125. It had come actually to Rs. 80 or Rs. 90, but now it is again going up. this variation in the price level is agitating the mind of the people, and I think that instead of this informal rationing in which the Government does not accept the responsibility to feed the people, the Government must take the responsibility through statu-We are spending tory rationing. Rs. 60 to Rs. 80 crores or even Rs. 100 for purchasing rice crores Andhra. Will it not break the economy of such a small State, which is on the verge of viability or nonviability, if we spend so much on rice alone? The price in Andhra is exorbitant, much more than Madras. The anomally is in Tanjore rice is kept without anybody to take it. Even Madras is not consuming that. When rice is sold there at about Rs. 42, we have to pay so much in Andhra.

Before the second world war, we got enough supplies from Burma and we exported our prawns and fish. Almost a barter system was in existence, and we did not feel the pinch of the rice problem. But that has stopped. Now Government is importing rice from Burma and other places. Even if sufficient stocks of Burma rice are kept in Kerala, its result will be that we may not have to pay that exorbitant price for Andhra rice.

Shri Ranga: Do you want the producers to be exploited?

Shri Warior: It is the middlemen, the merchants coming from the open market of Kerala, who are boosting up the price of rice in Andhra. I know it is a very sensitive spot for Mr. Ranga.

Shri Ranga: For all kisans, not only for me.

Shri Warior: I have no grudge against Andhra cultivators. But it is the middlemen who purchase rice at whatever price it is available in Andhra and they come and sell it at black market prices in Kerala. Should that be allowed? Guaranteeing an economic price or even a profitable price for Andhra cultivators, why should not enough Burma rice be stocked in Kerala, so that Kerala merchants will not be able to justify their claim that they have paid much more in Andhra and so they must charge more in Kerala? That can be done. Otherwise, Kerala's economy will be reaching the breaking point.

In Kerala, we are actually exporting much of our agricultural produce. The erstwhile Governor of Kerala, Shri Giri, said that if the Government of India did not undertake to supply enough of rice from imported rice, Kerala must be allowed to switch over whatever foreign exchange we are earning to purchase rice. Otherwise, we have to shift our cultivation from cash crops to paddy. Will it be in the interest of the entire economy of the nation? It is a national service that our cultivators are doing by earning so much foreign exchange through agricultural crops. If that is not compensated by giving them at least food, how can they go on for any length of time? We can, of course, produce more. We can not only intensify our cultivation but we can also convert our cash crop areas for production of foodgrains. But even then the problem will be there.

The Deputy Minister was saying, the higher the income, the lower the consumption of grains. That correct. That was also stated in some of the economic journals. But where is that higher income? Where is it coming from? If the Kerala people are given more income through the efforts of the Agricultural Ministry as well as the Ministry of Commerce, if the Kerala people are helped to get more for their cash crops and the income is raised, they will not depend upon foodgrains. We have sufficient stock of other things like vegetables, fish and other things.

of Food

and Agriculture

What has the Government done in this fish industry? In their report they say that about 4000 diesel engines are necessary and they can supply only 1000. The question of deep-sea fishing is there. We do not know whether the Norwegians in the coastline of Kerala are actually fishing fish or something else. That is yet to be seen. Only after some time we can realise that. Anyway some good has been done. But what is the. actual state of affairs as far as fishing is concerned. The recent delegation which visited Japan and other Australasian countries have reported that Japan alone is importing annually 20,000 tons of prawns and our share in that is only 1000 tons. This industry can be greatly developed. There is a very wide market for it. They have not yet explored it. There is a market in Australia, New Zealand and other countries. This prawn industry alone can sustain any number of fishermen who are now withany help and succour in the coastline of Kerala. This also will help to solve the food problem in Kerala.

Another point is, I cannot understand why everybody is speaking about production only. It is all very good. Production must be increased, Actually, we have increased our production. Where is that increase in production going? Has the Government given any thought to it? About rice, I know the position is very weak. But what about wheat? Minister after Minister has been coming and telling here that the import of PL. 480 is for creating a buffer-stock. But after creation of these bufferstocks, after all these imports, why is it that the Government had to face a very critical situation in the last months of last year? The Government must scrutinise that matter. My submission is that the malady actually in distribution.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member should conclude now.

Shri Warior: Should I close, Sir?

Mr. Deputy-Speaker: Yes. Shri Venkatsubbaiah.

Shri P. Venkatasubbaiah: Let me at the outset, Sir, congratulate the Minister of Food and Agriculture for giving us this white paper on agricultural development and also on the food situation.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: It is sufficiently black.

Shri P. Venkatasubbaiah: I do not agree with my hon. friend. This is a document which will certainly provide guidance to the farmers and to those people who are interested in agriculture. Agriculture to Shri Subramaniam is only just like water to fish. He comes from the sturdy peasant stock of Tamilnad. He knows the problems of agriculturists and their difficulties. I would only place certain facts before the Minister in this context.

Sir, this Ministry suffer from several handicaps, the main handicap being that as we are in the federal structure it does not have that much of administrative control over the various State Governments and, ultimately, those are the agencies who have to implement the policies of this Ministry and also the State Governments. Therefore, if the agricultural problem has to be solved, if the food production has to be increased in this country, the Minister should take courage and come before this House and say in what way he will have effective control over the agricultural ministries in the various States so as to effectively implement the agricultural production programme.

Then, some time back, he has been speaking about formulating a separate agricultural plan. I do not know whether it will be fitted into the broad framework of our national plan or it

will be a separate agricultural plan, from 1961 to 1976, as has been stated in this booklet. In any case, in what manner is he going to implement effectively the various policies of this Government?

Then, coming to the problems of the agriculturists, sufficient attention and care have to be paid to meet with their difficulties. Take, for example, the utilisation of irrigation potential. It has been mentioned by many hon. Members here that we are lagging behind in the utilisation of irrigation potential. We have to consider where the fault lies. It has been stated that during the third year of the Third Plan lack of utilisation is to the extent of 4.9 million acres. What are the difficulties or reasons which make the agriculturists not to utilise the available irrigation potential?

In my opinion, the agriculturists are today suffering from various difficulties in the matter of getting credit, good seeds, sufficient quantity of fertilizers and in plant protection measures. To what extent will the Minishelp them in solving problems? Now when a farmer goes for credit, it takes a very long time. So, I would suggest for the consideration of the Ministry a scheme whereby the agriculturist gets a credit card from the co-operative society on the presentation of which he will get the credit as and when required by him. In that case, the agriculturist can effectively use this credit for agricultural purposes.

Then, in the matter of supply of electricity, the Ministry should consider the desirability of a scheme whereby while the agriculturists will use power throughout the year, the charges will be collected from them only during the period of harvest.

Coming to fertilizers, so far as my State is concerned, it is used not only for irrigated land but also for dry land. The demand has outstepped supplies and we are not able to meet

and Agriculture

the entire demand of the agriculturists. Only the other day, the Minister of Food and Agriculture was saying that the production of fertilizer by this country falls short of demand by nearly 350,000 tons and that this quantity has to be imported from abroad. In this connection, have the Ministry seriously considered the substitutes for chemical fertilizers? The main substitutes are compost manure, green manure and dung manure. Are the Government encouraging the agriculturists to produce and utilize these substitutes?

Then, the machinery at our disposal for implementing our agricultural policy is very much out of date. The whole machinery has to be reoriented to suit to modern conditions and the needs of the present day agricultu-The Agricultural Department rists. which was constituted so many decades ago under the British regime cannot naturally be expected to have the capacity, the vision, the dynamism to cater to the needs of the modern agriculturists.

That is the greatest problem facing the Ministry today. Policies are all right, but for the actual implementation of all the policies of Government the entire machinery has to be reoriented to suit the conditions and aspirations of modern agriculturists. what extent is the Government taking measures-I would like to know.

I am happy to learn the Ministry is proceeding in the direction of the formation of an all-India agriculture cadre. I hope, it will be done soon and we will be able to attract the best talent in our country to fulfil the aspirations of the agriculturists.

More than once we have urged on the floor of this House that so far as plant protection measures are concerned Covernment is not taking as serious attention as it ought to have taken. Many people have suggested and even in the recent AICC meeting also a suggestion had been made that Government should come forward to supply pesticides freely to agriculturists; not only supply them but evolve an organisation whereby they can readily come to the help of the agriculturist to eradicate the pests.

I can compare an agriculturist to an industrialist or to an ordinary man who is having a car and all these things. When his car goes wrong or when electricity goes wrong, he has to telephone and get an engineer and get things done. But what is the fateof the agriculturist? He does not have the technical know-how or a. service organisation upon which he can depend and get his things done. By the progressive use of fertilisers, pests and diseases are multiplying in this country and nearly Rs. 50 crores worth of foodgrains are being lost on account of these pests every year. I would like to impress upon the Minister that he should take a bold stepand see that these inputs and other measures that are taken are being given to the farmers.

One great problem of the agriculmarketing. turists is However whatever resourceful he may be, efforts he has put to increase agricultural production, if it is not marketed in time and properly, he will not be able to get a reasonable price. In the various organisations that are working in this country as at present, there is much of duplication so far as storage and marketing facilities are concerned. Several organisations have been engaged in this work with the result that the Ministry is not able to focus or pinpoint its efforts on providing marketing facilities to these people.

Coming to the last point, I would only request the hon. Minister to see that the impetus is given, as is envisaged in the White Paper that he has published, to the agricultrists and they should feel that they can readily have the support of the Government and financial assistance from Government. To whichever quarter they go, whether it is a co-operative society APRIL 29, 1965

[Shri P. Venkatasubbaiah]

or a taccavi loan, whatever it is, they will be able to get ready credit, put in agriculture and get a better price.

Mr. Deputy-Speaker: Dr. Aney.

17.44 hrs.

WRE: REPORTED CEASE-FIRE TALKS ON KUTCH-SIND BORDER

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): Sir, before you call upon Dr. Aney, there is a very disturbing news and we want the Prime Minister or the Defence Minister to make a statement. In the House yesterday we adopted a Resolution to drive out the aggressor in Kutch, that is, Pakistan. Now we hear a rumour that there is already a move for a ceasefire agreement between India and Pakistan. Who is the mediator, who is the person-we do not know. What are the terms of the agreement—that also we do not know. Yesterday, when the Prime Minister spoke here, he mentioned about the agreement on the 13th April proposal, that is, maintaining the status quo ante. that mean that before we agree to any cease-fire whatsoever, they will also vacate Kanjarkot and the areas in the possession of the respective countries before January would be retained? Before they agree to anything they must make a statement here. Parliament must know as to what is going to happen. Before that is done we would not agree to any proposal or anything being done behind the back of Parliament. Would you please convey this feeling of the House, because everybody here is anxious to know as to what is the actual position today?

Mr. Deputy-Speaker: Dr. Aney.

Shri Nath Pai (Rajapur): Before you proceed to call Dr. Aney, may I make a submission? We know that this is not strictly within rules but the stake is too important even for

the rules. We do not want to be confronted tomorrow with accompli that a cease-fire agreement has been signed. The whole nation will be afire if a dishonourable ceasefire agreement is entered into by this Government. Here is a senior Miniswho once made а announcement to Parliament. him convey our anxiety-I think everybody shares it-to him. It is no use putting us down. We want an assurance....

Mr. Deputy-Speaker: Dr. Aney.

Shri Nath Pai: Mr. Deputy-Speaker, you are not a part of the Government. Mr. Subramaniam is a senior Cabinet Minister. Let him go and tell Shri Shastri and let him announce to the nation tonight on the Radio that these rumours are baseless. India wants to see that the traitor, aggressor, is pushed off the frontier. Do we have it that the assurance is coming?

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): We also share the anxiety. We would like the Prime Minister to assure this House that the aggressor will not be allowed to have his way.

Some Hon. Members: Yes.

Shri Bhagwat Jha Azad: You must tell us whether you are calling the Prime Minister to tell us this.

Mr. Deputy-Speaker: I have sent in a word. Dr. Aney.

Shri Frank Anthony (Nominated-Anglo Indians): May I have a minute? I want to say this that we have heard that a cease-fire agreement has almost been concluded this evening. We are all very disturbed about it. The Prime Minister gave a categorical assurance that his terms of the 13th April proposal were that we would never agree to cease-fire unless the status quo ante was restored. First of all, the House must be taken into confidence. Here is a senior Cabinet Minister. We want to know

Cease-fire talks on Kutch-Sind border

they mean and whether the status quo ante will mean complete vacation of all the territories which belong to us including Kanjarkot. This is a very serious matter.

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam): How can the Government bypass the Parliament? After all, if any such situation arises, I am sure, the statement would be made in Parliament (Interruption).

Shri Vidya Charan Shukla (Mahasamund): Since this matter has been raised in this House and it will be reported in the press tomorrow, I think, it would be in the fitness of things if there is a conclusive statement by the Government on this matter. Otherwise, it will create all kinds of confusing thoughts among the people.

Mr. Deputy-Speaker: I have communicated the intention of the House to the Prime Minister and the Defence Minister.

Shri Brij Raj Singh-Kotah (Jhalawar): Before the House is adjourned, we should be told something.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh (Parbhani): While there are rumours about the cease-fire, there are also rumours to the contrary that the enemy has occupied Biar Bet. On this issue also, the Parliament should be informed.

श्री घोंकार लाल बेरवा (कोटा) : प्रधान मंत्री जी ने तीन दफ़ें इस हाउस में ऐलान किया है कि जब तक हम ग्रपने कजरकोट को पाकिस्तानी भाकमणकारियों से खाली नहीं करा लेंगे तब तक हम सीज फ़ायर के बारे में बातचीत भी नहीं करेंगे लेकिन जसा कि सभी कहा गया है सगर प्रधान मंत्री जी न ऐसा कर दिया है तो यह देश की जनता के साथ बड़ा भारी भ्रन्याय होगा।

17.48 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS-Contd.

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE-Contd.

Dr. M. S. Aney: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I hope the Prime Minister will be coming in here and will make a statement as desired by the hon. Members. In the meantime, you have called me to speak on these Demands.

In the course of the debate, I have heard many hon. Members and I find that they want to know what is the policy; of the Government in regard to agricu'ture and economy. I believe that the hon. Members of this House know that the policy of this Government generally is one of selfsustaining and self-generating nomy. That is the ideal of the economic policy that has been laid down some time before and I believe that nothing has happened for the Government to say that that policy has been abandoned. The agricultural policy also, which Government will adopt, will be consistent with the ideal of se'f-sustaining and selfgenerating economy. If I were to put it this way, it is a policy of "Swadeshi" by which you must produce what you want to use and you must use what you produce. Unless the country generally takes to these methods, it will not be able to attain that economic prosperity which it is desiring to reach.

As regards agricultural policy which has been agreed to by all, the greater need of the day is production, and agricultural production is an essential need of the country. We afford to depend upon other countries for the sake of feeding our people. That being so, all attempts should be made by Government to attend to all those minor matters which would help to add to production.

I would invite the attention the Food and Agriculture Minister to one point in this connection. If production has to be increased, which [Dr. M. S. Aney] is the aim, then all those minor matters which would help to produce more have to be very carefully attended to by the Ministry. It has been agreed to that among the various methods which we have to use for this purpose, the use of fertilisers is an important one.

15.52 hrs.

[Shri Thirumala Rao in the Chair] From the report of the department of Agriculture we find that:

"The use of nitrogenous fertilisers has been increasing steadily, but it has not been possible to meet the full requirements on account of inadequate internal production and shortage of foreign exchange."

I am sorry to say that our production as regards fertilisers is not coming up to expectations. But apart from that, there is another point to which I would like to invite the attention of the hon. Minister, namely that whatever fertilisers are produced are not properly distributed. That is another trouble. And I would like to take this opportunity to bring to the notice of the hon. Minister an instance of extreme carelessness on the part of those who are in charge of the distribution of fertilisers.

Last year, the Maharashtra was not able to supply the required quantity of fertilisers to the Vidarbha Co-operative Marketing Society Limited which has its headquarters at Nagpur, and which is the wholesale distributor for all the societies in all the of Vidarbha. districts eight Therefore, on their advice. they placed an order for supply Regional Director (F), Calcutta. The Regional Director (F) at Calcutta had despatched the supplies to this society. I would not like to narrate the whole thing and read out the complaint which has been submitted, but I shall send these papers on to the hon. Minister for his careful perusal. When

the consignments sent in the wagons. by the railways were received, it was found that the bags were completely tattered, and some bags were torn, and there was also loose stock in the wagons. More than half the quantity was wanting. Thousands of were received in that condition. When the bags were received in that condition, the persons concerned took careto get the officers and in their presence, every thing (consignment) was: inspected, and the records were prepared. The matter was then reported to Government. For several months, nothing further happened. Later on one gentleman called a Deputy Director was sent there.

On 30th December 1964, the Under-Secretary to the Government of Maharashtra intimated them that Shri P. C. Mathur, Deputy Director (Fertiliser Planning), Government of India, would be visiting a few selected places in Vidarbha districts to look intothe complaints. This officer visited only four or five centres. The documents and relevant records showing the condition of the bags, re-bagging done and shortages observed in the consignments were shown to him. The Government of India officer said that as the Maharashtra Government had sent their inspector to Calcutta and he had given a certificate to them that the stocks were received by him by 100 per cent weighment, he was not inclined to bother himself by shortages observed by the consignees at the time of taking delivery. He desired to see only those unrebagged bags which were received by the consignees in their original packing. Since the bags which were received in original packing could not be removed from the station without rebagging and since most of the stocks were: sold out, the bags in original packing were not available for his inspection. He wanted to see the old tattered bags in which the fertiliser was sent. When these were not there, and the new bags in which the fertiliser was repacked were shown, he said 'I have nothing to do with this'.

17.57 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

Thus he closed the inquiry. No useful purpose has been served by the visit of the officer from the point of view of inquiring into this matter and doing justice by the parties who have suffered. His stand was that the Maharashtra Government had, sent their officer to Calcutta and he had passed a receipt. So he would not do anything. Thus he closed the inquiry.

This is a matter which took place in August 1964. These persons have incurred extra charges by way of rebagging expenses. There has been delay. Then the question of compensation for the shortages in stock remains unsettled.

This is how these societies have suffered. This is how things are going Hundreds of consumers suffered. There is no one to inquire into the matter. This is the way the cultivators are being protected by the agricultural department. The vators incur losses for no fault of theirs. They ask for an investigation so that they can get justice. But this is what ultimately happens. I would like to tell Government that they are judged by their performance, not by their promises. Promises by themselves are of absolutely no value to the people.

I will send all these papers to the Minister. Let him look into the matter, order an inquiry and try to see that justice is done to the hundreds of farmers, members of the society, who have suffered in this matter. They look up to him for justice in this matter. This is a very important matter which I wanted to bring to the notice of the hon. Minister. Thank you.

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha): I would like to say something about the cease-fire or the point just raised by some hon. Members.

Mr. Deputy-Speaker: Not now. I have sent word to the Prime Minister. He will be coming in a few minutes.

Shri Maniyangadan: I rise to support the Demands for Grants of this Ministry.

It cannot be said that the food situation in the country is satisfactory. There are several shortfalls. But the whole blame for that cannot be laid on the Ministry of Food and Agriculture. There are various factors, for many of which this Ministry is not directly responsible, which have brought about this situation.

I wish to mention two or three . things. One is the non-availability of sufficient quantity of fertiliser. Also, there is shortage of foreign exchange for importing a sufficient quantity of fertilisers. Then again, there is insufficiency of irrigation facilities. There is also the fact that all the facilities created have not so far been utilised. These are some of the factors which have gone to create the present situation. In assessing merits or demerits of the Ministry, we have to see how things have been done within the limitations that exist now.

18 hrs.

It has to be remembered that the present Minister took over charge at a time when the food situation was very critical, and I have no hesitation in congratulating him on turning the corner. It has to be said to his credit that due to the various measures adopted by him, the situation has improved considerably. Of course, much remains to be done.

There have been suggestions that all controls should be removed, and free trade should be allowed. There was also a suggestion on the other side that complete control should be introduced. Personally speaking, I am not a votary of controls. I believe that if controls are imposed, that will

[Shri Maniyangadan]

create further problems, but we know the circumstances because of which controls have to be introduced at pre-So it will be cruel if the controls are removed now. It will be experimenting with human lives. the most developed countries, where there is abundance of production of foodgrains, they can afford to give up contro's, but here, in the scarcity conditions that prevail, my submission is that a certain amount of control is necessary.

The establishment of the Food Corporation and also the setting up of Prices Commission the Agricultural are some of the good things done and I hope that these institutions will discharge their functions properly.

Coming to the State of Kerala. which is the worst affected area in country, informal rationing was introduced some time ago, and it is still continuing there. I have to inform the House that the situation there is still very bad. The quantity of ration is very meagre, also the stuff we get is often very bad. The people of Kerala are not used to wheat, and they are used to on'y parboiled rice. This has been referred to by Warior

I know the difficulties and also the anxiety of the Government to tide over the situation. I have to make certain suggestions. I am not for statutory rationing. Shri Warior gested that statutory rationing should be introduced. I for one would not agree to that proposal. It will create so many new problems, and as a consequence the country or the State will not be benefited.

I submit that this informal rationing is meant only for supplying minimum quantity of rice. One of its objects is to control the prices in the open market. So, it presupposes the availability of some rice in the open market. So, if the purpose is to be achieved, the sources from which rice

comes to the market should not be closed. But in Kerala, what is happening is that what is produced there is being procured by the Government under the levy system. Added to that, the traditional markets from where rice used to come to Kerala, namely the neighbouring States of and Andhra, are being closed. Formerly rice used to come to but now no rice is being brought from those areas. The State is cordoned off under the policy of each being one zone. I would suggest that the levy system in Kerala should be completely abolished, though concession has been given to the agriculturists recently, and also that free movement of rice from the neighbouring States of Andhra and should be allowed. They are surp'us States and my information is there is rice in large quantity available there. If that surplus rice can be allowed to be sent to Kerala, this difficulty could be got over.

The recent reports in the papers from Kerala state that the price of rice has gone up very much. As Shri Warior has stated, the price of rice per bag in the open market has gone up even more than Rs. 100. If that situation is to be eased, the only method is to remove these restrictions: that is, to remove the ban on bringing rice from the neighbouring States and also to stop the levy system. If that is done, I am sure the situation will ease and the price in the open market will come down, and there will be sufficient stock.

The present ration is 80 grams of rice and 80 grams of wheat. That is not sufficient for an individual. But if that is to be supplemented as submitted, this source of availability of rice in the open market must be opened. If that is done, I am sure there will not be much difficulty. As I stated the recent reports of pricerise in the open market leads to a very serious situation and there is the former situation arising again. So, I would request most humbly that the

Food Minister should look into the question immediately and see that the situation does not go from bad to worse.

Again, I have to make another submission and that is regarding the fixation of price of paddy. In Kerala, for the system of levy, the price has been fixed by the Government. My first submission is that levy shou'd be completely abolished. Whatever be the price of paddy in Kerala, it is not sufficient. It has absolutely no relationship whatever with the cost production. The main rice-producing area in Kerala is Kuttanad. There, the agricu tural operations are very peculiar, and they are not so in any other part of the country. The backwaters around the Vembanad kayal place where they are growing paddy. Big bunds at heavy costs are put up every year, and water is pumped but, and then cultivation is going on. Apart from the dangers and the risks involved, it is a very costly operation. Considering all these matters, it is not possible to satisfy the cultivator with the present price that is fixed. If the cultivator is to get an incentive price, he must be paid very high. What I suggest is that the cost of production must be reduced. For this, instead of putling up temporary bunds, if a permanent bund could be put up at Government cost, then, the cost of cultivation would come down. The Minister of Food and Agriculture is a member of the sub-committee of the Cabinet looking into the Kerala affairs during the President's rule. I appeal to him to look into this matter and see that necessary things are done. I also suggest that electricity and fertilisers should be supplied to areas at subsidised prices. Another point is that the construction of the Thannirmukkam bund was several years ago, but the progress is very slow. If it is expedited, and the other things which I suggested are carried out, I am sure that the production of paddy in Kuttanad will be less costly and there will not be much difficulty.

Another point is with regard to the fair price shops. With the introduction of informal rationing, the system of fair price shops has been abolished there. The poor people who used to get rice at a low price are not given that facility now. I therefore submit that that should be reintroduced to ease the food situation there.

I now wish to make another suggestion. Tapioca is a commodity which is being used by the people as a supplementary food, but the situation now is, the people are afraid to cultivate tapioca because of the fluctuation in price. I would submit that if a minimum price is assured to the cultivator, more tapioca will be cultivated and that will ease the food situation there. I would suggest that the present rations must be increased at least during the coming three or four months. Through the fair price shops more rice was being supplied during this period in previous years. So, I suggest it should be done. Otherwise, it will not be possible to get any rice in the open market during this period.

During the third plan, no new irrigation scheme has been started in the State. The second plan schemes are being continued and several of them are still remaining incomplete. There are very good schemes in certain areas in the State and if they are implemented, the present rice crop production would increase. Single-crop lands can be converted into double-crop lands. From papers supplied by the Ministry of Irrigation and Power we find in Kerala cent per cent of the irrigation potential made available is being utilised and not an ounce of water is wasted. So, the minister should look into this also.

Mr. Warior referred to fisheries. I would like to refer to some commercial crops like arecanut, cocoanut, etc. I am sorry, the report mentions nothing about the cocoanut and arecanut plantations. Specially the cocoanut plantations are facing a very serious situation. There are so many dis-

[Shri Maniyangadan]

eases. Research is being done in the research centres there; I am not blaming anybody, but I suggest that it must be taken up more seriously.

श्री श्रोंकारलाल बेरबा: मैंने रिपोर्ट को पढ़ कर देखा तो बड़ा क्लेश हुन्ना क्योंकि हमने जितना रुपया खर्च किया है उसका ग्रगर ब्याज भी द्या जाता तो कुछ सब हो जाता । इस सनय हमारे राजस्थान की जनता तो बकरी के समान है । जिस तरह से बकरी सारे श्रनाज, सारी चीजें खाती है, फुल, पत्ती सब खाती है उसी तरह से राजस्थान की जनता चना, बाजरा, ज्वार. दाल. चाहे जो भी सख्त से सख्त चीज उसे खाने के लिये दी जाये, वह खाने के लिये तयार है। लेकिन ग्रफसोस की बात है कि ग्राज बहां पर भी ग्रनाज का ग्रकाल है। ग्राज राज-स्थान की जनता में 29 लाख किसान ऐसे हैं जिनके पास बिल्कूल जमीन नहीं है, ग्रीर जमीन है भी तो सिचाई के लिये पानी नहीं है। राज-स्थान का क्षेत्र ऐसा है जहां पर कि पहले सोना उगला जाता था, लेकिन म्राज वहां धूल उड़ रही है। मैं मन्त्री महोदय से पूछता हं तो कहते हैं कि राजस्थान हरा भरा हो जायेगा । लेकिन देखते हैं कि गाड़ी के पहिये के पीछे धूल उड़ती जाती है।

श्रफसोस की बात है कि इतनी बात हुए भी हमने जब से शासन सम्भाला तभी से विदेशों की तरफ हमारी निगाह है। श्रमरीका से हमने जितना श्रश्न मंगवाया उसके श्रांकड़े मेरे पास हैं कि किस किस साल में कितना कितना श्रना श्रांगवाया पी० एल० 480 में

1961-62	86.3
1962-63	121.4
1963-64	167.2
1963.	84.4
1964.	107.4

यह आज हमारे देश की हालत है। इतना ही नहीं, बल्कि जो दुश्मन राष्ट्र हैं छोटे मोटे, जो हम से कुश्ती लड़ रहे हैं उनसे भी मंगवाया। खाली संयक्त राज्य ग्रमरीका से 5,253.7 हजार मीट्रिक टन, कैनाडा से 106.8 हजार मीटिक टन, भीर ग्रास्ट्रेलिया से 260.9 हजार मीट्रिक टन । यह तो गेहुं मंगाया है । चावल सारा मिला कर 6285.9 हजार मीट्रिक टन हमने मंगवाया है-संयुक्त राज्य **धमेरिका से 332.4, बर्मा से 151.9, पाकि-**स्तान से 71.1. थाईलेंड से 35.1 कम्बोडिया से 25.2, संयुक्त ग्रारव गरा राज्य से 28.8 हजार मीट्रिक टन । मैं सोचता हूं कि कहीं यही कारण तो नहीं है कि उन लोगों के सामने हमारे शस्त्र उठ्ते नहीं, शायद इसी लिये हम को बाहर की धौंस उठानी पड़ रही है, वर्ना क्या कारण हैं कि छोटे से राष्ट्र से भी हम पीछे हट जायें।

श्रव की मैं राजस्थान के दौरे पर गया था। वहां पानी की कमी हैं। इसके लिये वहां 250 नलक्पों की मंजूरी दी गई। मगर खाली 37 खोदे गये। उनमें से भी 13 काम कर रहे हैं 24 मुंह ताक रहे हैं। राजस्थान की जनता से मैंने कहा कि तुम्हारा क्या हाल है। उन्होंने कहा कि ग्रनाज दो हथियार दो ग्रीर दृश्मन का मंह पीछे मोड दो । लेकिन क्या करें न ग्रनाज है न हथियार है । इसलिये मैं म्रापसे निवेदन करता चाहता हं कि राजस्थान के बार्डर की जनता को पानी स्रौर जमीन स्रौर हथियार दिये जायें। जमीन तो वहां बहुत सी है लेकिन पानी दे दिया जाये तो ग्रनाज की कमी शायद सारे देश में नहीं म्रायेगी । राजस्थान के म्रन्दर म्रनाज की कमी पूरी करने के लिये पानी चाहिये । पानी वहां के लिये जरूर दिया जाये ।

इसके बाद कृषि काले जों और स्कूलों की बात श्राती है। लिखा गया है कि 300 स्कूल खोले जायेंगे। मैं राजस्थान के बार में बतल। सकता हूं, खास तौर से कोटे का हाल। इतना बड़ा एरिया होते हुए भी, इतनो नहर वगैरह होते हुए भी वहां पर एक भी कृषि काले ज नहीं है। जब सारे देश भर में 300 कृषि स्कूल

कोलने हैं वो वहां पर भी खोले जायें। किसी तरह लड़का गांव मैं पढ़ता है तो वह शहर की तरफ देखता है क्योंकि किसानी के काम में उसकी रुचि नहीं है। ग्रगर स्कलों में पढ़ाया जाता कि बेती का काम क्या है तो यह हालत न होती । इसलिये मेरा सुझाव है जितीसरे या चौथे क्लास से कृषि की शिक्षा श्रनिवार्य कर दी जानी चाहिये ताकि कृषि के काम में लोगों की रुचि बढ जाये।

इसके बाद खाद की बात ग्राती है। उसकी खपत दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। विदेशी खाद जो हमारे यहां झाती है वह महंगी है। एक काये में तीन श्राना खाद देनी पड़ती है। खाद की खपत कितने से बढ़ कर कितनी हो गई है यह भी मैं श्राप को बतला द्यं:

> 1949-50 में 64 हजार टन 1960-61 में 2 लाख, 83 हजार टन।

लेकिन कृषक बेबारे को पता ही नहीं है कि खाद कितनी देनी है भ्रौर किस तरह से देनी है । हस्ने श्रमरीका से सौदा किया कि तुम को दस हजार टन देना पडेगा । बीच में एक कम्पनी ग्रा गई ग्रीर कहने लगी कि तेल का साझा रक्खो तब खाद देंगे वर्ना नही । उसने 10 में मे 5 कर दिया। हम उन लोगों के मह की तरफ देखते हैं कि खाद कहां से ग्राये। सिंदरी कार-खाने में 5 वर्ष से 2 करोड हाए साल का नकसान होता ग्रा रहा है उसके लिये फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त की गई थी सन 1963 में कि उसे विदेशी मुद्रा दे दी जाय। लेकिन 15 लाख रु० की विदेशी मुद्रान देकर 10 करोड़ द० का नुकसान कर दिया। 10 करोड़ ६० की खाद विदेशों से मंगाई। ग्रगर 15 लाख रु० की विदेशी मुद्रा दे दी जाती तो स्राज 15 हजार रु०रोज का नुकसान सिंदरी कारखाने को न होता भीर भौर न हमें विदेशों का मुंह देखना पड़ता।

दूध की हालत देखती हैं तो हमारे यहां एक डेरी फार्म बना हुन्ना है जिस पर बम्बई का

कोई सेठ बैठा हुआ है। वह दिल्ली के डेरी फार्म पर दांत लगाये बैठा है कि कुछ ले देकर वह सौदा बन जाये तो उसे कम्पनी का रूप दे दिया जाये । वहां पर 3.83 लाख र॰ का यन्त्र जो सन् 1960-61 में लिया गया वह म्राज तक काम में नहीं लाया गया । मुरादाबाद के प्रन्दर कोई गोदाम किराये से लिया है जिस का 20 हजार ६० महीना किराया लग रहा है। कोटा के भ्रन्दर भ्राज छः साल से गोदाम बना हुमा है, लेकिन बरसात में उस में गधे बन्धते हैं। यह हाल है हमारे देश का । करोड़ों रुपयों के गोदाम बना दिये लेकिन अनाज दो पैसे का भी नहीं। जिस जिस चीज को हमने कण्टोल किया उसकी यह हालत है।

हमारे किसानों से श्रफसरों ने श्राकर कह दिया, नाजिम भौर पटवारी ने कह दिया कि तुम गन्ना बोग्रो । गन्ना लगा दिया लेकिन घाज कोटा स्रोर बुंदी रियासत में गन्ना खड़ा खड़ा सुख रहा है। जब वहां एक भी मिल चीनी की नहीं है तो गन्ने का म्रार्डर क्यों दिया। म्रगर उनके साथ भ्रन्याय करना था तो वेसे ही कह देते कि जमीन परती रख दो। वहां के किसानों ने कर्ज लेकर गन्ना लगाया लेकिन वह म्राज पड़ा पड़ा सड़ रहा है। क्या कारण है कि इधर उधर चीनी मिलें खुलती जा रही हैं लेकिन कोटा के अन्दर एक भी चीनी मिल नहीं, कोई कृषि कालेज नहीं। भ्रगर राजस्थान की जनता की तरफ ध्यान देना है तो पानी से लगा कर कृषि कालेज तथा उत्पादन के सारे साधन श्राप को देने होंगे।

राज्यों के पास से 8 लाख टन ग्रनाज की मांग प्राई, लेकिन प्राप ने उन को भेजा कितना। 2 लाख टन । वह बेचारे क्या करें । दुकान पर जाते हैं तो 100, 100 मादिमयों के क्यू लगते हैं, भ्रौर मिलता कितना है,पांच सेर । कितने दिन का, सात दिन का । भ्रब ग्राप ही बतलाइये कि चार भौंस गेहं चना या ज्वार उनको मिले तो कैसे काम चलेगा। राजस्थान के ग्रन्दर चार ग्रींस ग्रनाज तो लोग सबेरे वैसे ही फांक जाते हैं। वे बेचारे खायें क्या, मजदूरी कैसे करें।

[श्री ग्रोंकार लाल बेरवा]

जो मजदूर भाज बारह भीर चौदह भींस खाने बाला है वह चार ग्रींस खाकर कैसे रह सकता है। बच्चे बच्चियों को राशन की दूकान पर भेजे तो राशन नहीं मिलता है। स्वयम् जाये तो पैसे खत्म हो जायें। बगैर मजदूरी के कहां से लाये । उसके लिये बड़े श्राफत का सामना है। जो ग्राप्त किया हुन्ना गेहूं है उस पर भी कण्टोल लगा दिया। सरकार की गलती से घाटा हुआ बीस करोड़ का श्रौर उसको लाद दिया जनता पर ग्रीर गेहं का भाव बद्रा दिया । राजस्थान की जनता को मोटा मनाज भी पेट भर भिल जाए तो वह लड़ा ें में दुश्मन का सामना करने को तैयार है। सामना तो भूखों मरते भी करेंगे, चिन्ता की बात नहीं है। लेकिन राजस्थान के लिए पानी का प्रबन्ध होना चाहिए भ्रौर खेती के लिए दूसरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तकावी के लिए जहां 1000 करोड़ चाहिए था वहां ग्रापने 200 करोड़ दिया है, यह बहुत कम है । किसान को सहायता देनी है तो उित सहा-यता दी जाए । उसको कुवें के लिए 500 रुपया चाहिए तो 50 रूपया दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि वह एक साल में जितना खोदता है वह दूसरे साल में पट जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भ्रगर किसानों को सहायता देनी है तो पूरी दें, उनकी जरूरत के मुताबिक दें।

मैं इतना कह कर धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर भी यह कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए जो मूल्य तै किया गया है उसको बीच के बिचौलिया न खाने पाएं, किसान को उचित मूल्य मिले तो किसान उत्पादन बढ़ाने में दिल खोल कर लग सकता है।

श्री नरः ि पटेल (बुलसारः) : उपा-ध्यक्ष महोदय, भाज दो दिन से मैं यहां कृषि भीर फूड मन्त्रालय की बहस सुन रहा हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने श्रांकड़ों के इन्द्रजाल बताए, लेकिन मैं वह इन्द्रजाल के भांकड़े नहीं बताना चाहता हूं। इस देश में क्या करना चाहिए, वह मैं कहना चाहता हूं।

सन् 1947-48 में स्वर्गीय माननीय पंडित जी ने एक वायु प्रवचन किया था । उस समय हमारे देश में भ्रनाज की परिस्थिति बहुत गम्भीर थी। उन्होंने कहा था कि हर एक श्रादमी ने भ्रपने बगीचे में, श्रपने खेत में, बल्कि कु है में ग्रनाज बोना चाहिए। मगर कितने भादिमियों ने ऐसा किया मुझे नहीं मालूम । उस समय मैं बम्बई में विलेपारले में था। उस वक्त वहां की माबादी इतनी नहीं थी। मेरे मकान के पास मेे एक दोस्त की एक या डेढ एकड जमीन थी। उसके ग्रन्दर मैंने चावल बोए श्रीर उसमें मैंने 21 बंगाली मन पैडी पकायी । उस समय वाला साहब खेर बम्बई के चीफ मिनिस्टर थे, उनके सुपूर्व वह मैंने कर दी। 1949 में मैंने जो पैडी पकायी वह मैंने खुद इस्तेमाल की । मेरा यह अनुभव है कि जब तक इस देश के भ्रन्दर हर एक ग्रादमी भ्रपने लिए खाद्य नहीं पकाएगा तब तक इस देश की खाद्य समस्या हल नहीं होगी। श्राज भी मैं एक पेंसे का चावल नहीं लेता हूं। हमारे यहां गेहूं भ्रीर ज्वार नहीं पकती है। मझे जितने गेह ब्रौर ज्वार की जरूरत होती है मैं चावल बेच कर ले लेता हुं। मैं किसी के ऊपर ग्राश्रित नहीं हूं ।

पंडित जी ने जो कहा था कि कू े में बोग्नो उसका मतलब यह था कि किसी किस्म की भूमि को भी खाली न रखो। ग्राज हम देखते हैं कि सारे देश में रेलबे लाइन के दोनों बाजू जमीन खाली पड़ी है। उसका हिसाब लगाइए। मेरा सुझाव है कि उसके बाजू में जिन लोगों की जमीन है उन लोगों से एग्रीमेंट करके उनको लीज पर वह रेलवे की जमीन दे दी जावे ग्रीर ग्रीर उनसे कहा जाए कि तुम इसमें धान बोग्नो। धरती माता है। संसार में कोई ऐ हो माता नहीं है कि जो ग्रपने बच्चे को भूखों मारेगी। एक माननीय सरस्य : म्राज म्रापने यह बात सदन में कही है, किसी ने पहले नहीं कही।

श्री ना० नि० पटेल : मेरी प्रार्थना है कि जो ऐसी जमीन फालतू पड़ी है उसमें धान नहीं बोया जाएगा तो हमारी समस्या हल नहीं हो सकेगी । श्राज 17 साल में कई फूड मिनिस्टर श्राए श्रीर गए, श्रीर श्राएंगे श्रीर जाएंगे पर इस तरह हमारी समस्या हल नहीं होगी ।

प्राज सरकार ने विदेशों से करोड़ों रुपए का प्रनाज मंगाने का इन्तिजाम किया हुआ है और भी प्रनेकों इन्तिजाम खाद्य समस्या हल करने के लिए किए हैं मगर आप देखें कि एक बाजू खाद्य का उत्पादन बढ़ता है और दूसरी बाजू पापुलेशन भी बढ़ती जा रही है। प्रगर हम पापुलेशन की समस्या हल नहीं करेंगे तो हमारी ग्रप्त की समस्या भी हल नहीं होगी। खास कर देहातों में ग्राजकल पापुलेशन बहुत बढ़ रही है। और लोग तो समझते हैं कि खेल का खेल और बच्चा नफे में, उनको यह नहीं मालूम इसको कहां से खिलाएंगे, कहां से इसको कपड़ा लावेंगे। तो इस प्रश्न को हैल्थ मिनिस्ट्री के साथ रिल कर तै करना चाहिए।

हमारे देश में भूमि तो ज्यादा होने बाली नहीं है, इसलिये हमें श्रपनी भूमि का पूरा उपयोग करना चाहिए । पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े इंडस्टियलिस्ट बड़ी बड़ी जमीनें रख लेते हैं ग्रौर वे फालतू पड़ी रहती हैं। उन को कहा जाना चाहिए कि जिस जमीन में तुम्हारी फैक्टरी नहीं है उसमें खाद्य का उत्पादन करो। मेरी कांस्टी-ट्यूएंसी में पांच हजार एकड़ में खार लेन्ड है. जिस में समन्दर का पानी ग्राता था। गवर्नमेंट की स्कीम थी कि उस का बांध बना कर उस को मीठा बनाएंगे। यह जमीन बलसार डिस्ट्विट में श्रमलसाड के पास है। लेकिन इस की खबर किसी इंडस्टियलिस्ट को लग गयी भ्रौर उस ने भ्रफसरों से मिल कर उस को ले लिया। भ्रगर ऐसा हम्रा तो काम कैसे चलेगा ? सारी जमीन इस

तरह चली जाएगी, तो उत्पादन कंसे बढ़ेगा। तो स्टेट सरकार के साथ मिल कर केन्द्रीय सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए।

जिस वक्त हमारे माननीय ग्रजित प्रसाद फुड मिनिस्टर थे उस वक्त मैं ने उन को बताया कि बम्दई जाते हुए बोरीबिली स्टेशन से सांताकुज स्टेशन तक पूरव की बाज् में भैंस के गोबर के बड़े बड़े डुगर लगे हैं। मैं ने उनसे कहा कि यह खाद के काम में धा सकता है, लेकिन यहां से इस को ले जाने का 120 रुपया प्रति वैगन किराया लगता है, इस को श्राधा किया जाय तो इससे लोगों को बहुत लाभ हो सकता है। उन्होंने वैसा कर दिया। श्रभी मैं गया तो मुझे बताया गया श्रौर मेरे पास चिटिठयां भी श्रायी हैं कि जो गोबर का खाद गोरेगांव से आता है वह एक मानापली ठेकेदार के द्वारा श्राता है। लेकिन उसने क्या चालाकी की है कि जो एक वैगन में चालीस बैलगाडी खाद निकलता था ग्रब उसमें सिर्फ 25 बैजगाड़ी निकलता है भ्रौर भगर इस खाद को मंधेरी या जागेश्वरी स्टेशन से लात्रें तो पूरा रेट लिया जाता है। मेरा सुझाव है कि रेलवे मिनिस्टर से मिल कर इस पर विचार किया जाना चाहिये ।

ग्राप दिन प्रति दिन फरटीलाइजर के कारखाने बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में चालीस करोड़ फरटीलाइजर फैक्टरियां हैं। उनको चलाने के लिये करोड़ों रुपये का भनाज परदेश से मंगाना पड़ता है। लेकिन इन का उपयोग नहीं होता ग्रौर इस खाद को पवित्र नदियों में बहा दिया जाता है। ग्रौर इसका उपयोग किया जा नहीं सकता। हम दिल्ली से जाते हैं तो देखते हैं कि गटर का चैनल बना दिया गया है ग्रौर वह गन्दा पानी खेतों में जाता है। वहां का ग्राप गेहूं देखें तो ग्राप को मालूप होगा कि यह पानी खेती के लिए कित उप ग्रोगी है।

Food and Agriculture

[श्रीना० नि० पटेल]

बम्बई में भी एक बहुत बड़ा गटर है, लेकिन उस को समुन्दर में गिरा देते हैं। मेरा सुझाव है कि आगे जो नए गटर बनाए जायें उन को तो कम से कम इस तरह बनाया जाय कि उन का पानी खेती के काम आ सके। इस पर विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है।

श्रीना० ति० पटेल : बस एक, दो बात मुझे ग्रीर कहनी हैं। एक बाजू हमारी सरकार कहती है कि खेती का उत्पादन बढ़ाम्रो मौर उस के लिए वह पैसे भी देती है, तकावी भी देती है भ्रीर लोन भ्रादि देती है लेकिन दूसरी तरफ़ हम देखते हैं कि ताजे फलों ग्राम, चीकु ग्रादि के फेट रेट्स बजाय कम करने के म्रत्यधिक बढ़ा दिये गये हैं श्रीर बजाय फारमर्स को प्रोत्साहित करने के उन को भीर इस काम में निरुत्साहित किया जा रहा है। हमारी बुलसार भीर सूरत डिस्ट्रिक्ट ग्राम ग्रीर चीक की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं ग्रीर देश के सारे भागों में बहुत अधिक माका में आम, और चीक टोकरियों में भर कर रेल के जरिए पार्सल किये जाते हैं। हमने ग्रभी देखा कि 1-4-65 से फेश फुट्स की पार्सल की फोट रेट्स रिवाइज कर दी गई हैं श्रीर वह दुगनी कर दी गई हैं। ग्रभी पाटिल साहब जब सूरत 13 तारीख़ को गये थे तो फल उत्पादक उन से इस सम्बन्ध में मिले थे भौर उनको अपनी हार्डशिप बतलाई थी जिस पर कि उन्होंने कहा था कि उनके पास भी कम से कम 1000 तार इस ग्राशय के भ्राये हैं कि यह फोट रेट इस तरह से दुगनी न की जाय क्योंकि इस से किसानों को बड़ी कठिनाई पेश ग्रायेगी। मैं ने भी इस बारे में रेलवे मंत्री महोदय को पत्न लिखा था जिस के कि जवाब में वह यह लिखते हैं कि एक क्विंवटल फल की टोकरी का 50 किलोमीटर का 1-4-65 के पहले रेट 79 पैसे था

जोकि भव 1-4-65 से 1 रुपया 19 पैसे हो गया है। इसी तरह से 200 किलोमीटर के लिए एक क्विटल का भाड़ा जो 1-4-65 के पहले 2 रुपये 30 पैसे था वह 1-4-65 से 3 रुपये 93 पसे हो गया है। 500 किलो-मीटर के लिए एक क्विटल का रेल भाडा 1-4-65 के पहले 4 रुपये 24 पैसे होता था जोकि भव 1-4-65 के बाद से 7 रुपये 45 पैसे हो गया है। 800 किलोमीटर के लिए एक क्विटल का फ्रेंट 1-4-65 के पहले जहां 5 रुपये 83 पैसे था वहां म्रब 1-4-65 के बाद से वह बढ़ कर 10 रुपये 35 पैसे हो गया है। 1000 किलोमीटर के लिए एक क्विटल के लिए 1-4-65 से पहले भाडा था 6 रुपये 91 पैसे लेकिन श्रब 1-4-65 के बाद से वह बढ़कर 12 रुपये 31 पैसे हो गया है। इस हिसाब से देखा जाय तो फ्रीश फुट्स का फोट पहले की भ्रपेक्षा डबल हो गया है। भ्रब एक तरफ़ तो सरकार हम से कहती है कि उत्पादन बढ़ाम्रो भीर दूसरी बाजू रेलवे इस तरह से ज्यादा पैसा चार्ज कर रही है तो यह कहां तक उचित है ? हमारे यहां बुलसार डिस्ट्क्ट से कम से कम 25,000 टोकरे भ्राम के बम्बई, दिल्ली भ्रादि स्थानों को जाते हैं। खास कर चीक हमारे यहां से ब्राता है ब्रौर मैं फीगर्स दे कर कोट करना चाहता हूं कि पहले की घ्रपेक्षा घाज चीकु की बास्केट्स का रेल भाड़ा कितना प्रधिक बढ़ा दिया गया है:---.

"For e.g. during the British rule we used to pay Rs. 3·37 for about 40 kgs. of chikoo-basket despatched from here to Delhi at hair parce rate. After the respite given in the freight rate from half to quarter by our National Government, freight for the same package came to Rs. 2·37. This amount stood at Rs. 2·90 on 31st March, 1965. Now with 100 per cent increase in rate, the amount will be Rs. 5·60. From this, it

12004

will be realised how far the freight expenses has risen."

हमारे भ्रमलसाड से तीन, चार लाख टोकरियां भ्राम व चीकु की जाती हैं भ्रौर इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो 100 परसेंट रीसैंट इंक्रीज फेट रेट में की गई है यह अनुचित है ग्रौर इस से उन को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहुंगा कि हमारे खाद्य मंत्री महोदय किसानों को प्रोत्साहन देने के हेतु इस बारे में रेलवे मिनिस्टर से बातचीत कर के इस को कम करवा दें। बस मेरी यही प्रार्थना है।

श्री गुलशन (भटिंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश भारत श्राज एक गम्भीर ख़तरे के बीच में से गुजर रहा है। इस ख़तरे का सामना दो ही संस्थाएं कर सकती हैं। मोर्चे के ऊपर शस्त्रास्त्र ग्रादि से लैस हमारे फीजी जवान श्रौर खेत में हल चलाने वाले किसान । जहां मोर्चे पर तैनात फौजियों को हमें हर तरह से हथियारों म्रादि से लस करना है वहां किसानों को ग्रधिक ग्रन्न उगाने के लिए खाद, पानी, भ्रच्छे किस्म के बीज भ्रादि की समस्त सुविधाएं सुलभ करनी चाहिएं। कृषि के काम ग्राने वाले इम्प्लीमेंट्स भी उस को सस्ते दामों पर मुहैय्या किये जायें। इस के साथ ही किसानों को उन की उपज के मुनासिब दाम मिलें भ्रौर ग्रगर ऐसा किया जाय भ्रौर किसानों को प्रोत्साहन दिया जाय तो हमारे देश के किसान मोर्चे पर जझ रहे सैनिकों के लिए ग्रीर यहां उन के परिवार वालों के लिए श्रौर तमाम देश के नागरिकों के लिए ग्रनाज की या खुराक की कभी कमी नहीं होने देंगे। इस वक्त 45 प्रतिशतः हमारी कृषि से भ्रामदनी होती है। 6 करोड़ 30 लाख परिवार कृषि पर निर्भर करते हैं। दूसरी तरफ़ वह जमाखोर भीर मुनाफाखोर देशद्रोही पूंजीपति लोग हैं जो मुनाफ़ाखोरी का छुरा बग्रल में ले कर देश को भूखा मारने की घात लगा कर बैठे हुए हैं। जहां ग्राज देश बाह्य शतुग्रों के भाकमण और बुरे इरादों से चितातुर है और अपनी आजादी की रक्षा करने के 496 (Ai) LSD-9.

लिए सभी संभव उपाय कर रहा है वहां उसे देश के ग्रन्दर मौजूद ख़तरे के बारे में भी गाफिल नहीं होना चाहिए । जहां उसे चीन श्रीर पाकिस्तान से निपटना है वहां हमारे देश को ऐसे देशद्रोहियों से भी निबटने की जरूरत है। न मालुम सरकार इन से क्यों डरती है ? बड़े बड़े सट्टेबाज, जमाखोर ग्रौर मनाफ़ाखोर प्रजीपतियों पर वह हाथ नहीं डालती है, बड़ी मछलियों को वह नहीं पकड़ती है भौर वह छोटी, छोटी मछलियों को पकड़ लेती है। बड़े बड़े गुदामों पर छापा नहीं मारती है भौर उन के खिलाफ़ कानुनी कार्यवाही नहीं करती है लेकिन तीन मन गेहूं, 20 किलो म्राटा, 3 छटांक चीनी या तीन तोले तेल गैरकानुनी पकड़ कर सरकार बडी तीसमारखां बनने लगती है। मिलावट या जमाखोरी म्रादि के म्रपराधों के सिलसले में मजदर छोटे किसान भंगी या पैटी शौपकीपर्स श्रीर रैहड़ी लगाने वाले पकडे जाते हैं। पूंजीपतियों को पकड़ते समय सरकार का हाथ कांपता है इसलिए यह पूंजीपति मनमानी करते हैं स्रौर क़ीमत स्थिर नहीं रहने देते हैं। ग्राज नई फसल बाजारों में ग्राना शुरू हो रही है लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि ग्रभी दस दिन पहले पंजाब में 83 रुपये क्विटल के भाव से गेहं बिका है।

एक माननीय सदस्य : गेहं का भाव गिर गया है।

श्री गुलशन: भाव तो ग्रब गिरा होगा लेकिन मैं यह बात दस रोज पहले की कह रहा है।

म्राज देश में व्यापक पैमाने पर मिलावट चल रही है। खाद्यान्नों में भ्रौर ग्रन्य वस्तुग्रों में खुब मिलावट चल रही है यहां तक कि दवाइयां भी ग्रसली नहीं मिल रही हैं। भ्रब भ्राप ही बतलाइये जब खाद्यान्नों भ्रादि में मिलावट होगी तो इस देश के लोगों की सेहत को कै से सम्हाला जा सकता है ? ग्राज मैं ने देखा है कि दाल मिर्च, मसाला, हल्दी, नमक, जीरा, साबुन तेल, घी, दूध, मतलब यह

[श्री गुलशन]

चीज असली नहीं मिलती है, सब में मिलावट चल रही है कपड़ा लोहा, तांबा, पीतल, सोना श्रीर चांदी कोई भी वस्तु इस मिलावट से बची नहीं है। खाद्म मंत्रालय शायद जहर की मिलावट से मुक्त न हो मैं तो एक बात फहना चाहता हूं ग्रीर वह यह है कि पंजाब व्यापारो मंडल के भ्रध्यक्ष श्री मसन्द ने १६ श्रप्रैल के समावारपत्रों के श्रन्तार सरकार को एक धमकी दो श्रीर सरकार उस धमकी के भागे झुक गयी जिसका परिमाण यह हुआ कि एक दमसे पंजाब में ८१ रुपये किंवटल गेहं के भाव बढ़ गये।

इलाहबाद में कांग्रेस समिति की मं दिंग में बोलते हुए प्रधान मंत्री जीन कहा था कि नई फसल बाजार में ब्राते ही की मन समान हो जर्येग: । इस के उलट सरसों, तिलहनम्रादि तेल के मुल्य म दस रुपये प्रति क्विटल वृद्धि हुई। गुजरात सरकार ने 16 म्रप्रैल, 1965 को समाचारपत्नों की सूचना के अनुसार यह घोषणा की कि राज्य से बाहर ग्रनाज ले जाने वालों की खबर देने वाले को पांच सौ रुपया इनाम दिया जायेगा । क्या इस का मतलब यह समद्या जाये कि सरकार का गुप्तचर विभाग ठीक काम नहीं कर रहा है या यह सरकार की कमजोर नीति का प्रतीक है ?

मुझ से पहले एक माननीय सदस्य ने देश मं ग्रनाज की कमी के सम्बन्ध में रेलवे लाइन के साथ पड़ी हुई बहुत सी खालो जमीन का जिक्र किया है। में समझता हुं कि हमारी नहरों श्रीर सड़क़ों के साथ जी जामीन खाली पड़ी हुई है। कुछ ऐसी जमीन भी है, जो ग़ैर-म्राबाद है मौर जिस के लिए पानी की जरूरत है। ग्रगर यह जमीन भूमिहीन लोगों को दी जाये, तो मैं समझता हूं कि देश ग्रनाज के संकट से बच सकता है।

जहां मैं ने सड़क़ों, नहरों ग्रीर रेलवे की पटरियों के साथ पड़ी हुई जमीन का जिक किया है, वहां मैं यह भी कहना चाहता हं कि हमारे मंत्री महोदयों की जो बड़ी बड़ी कोठियां हैं, उन के साथ पांच दस

एकड़ जमीन पड़ी हुई है। इस के अलावा उन के बड़े कर्मचारियों की कोठियों के साथ भी पांव पांच, दस दस एकड जमीन पड़ी हुई है। इसी तरह हमारे देश के जो नेता स्वर्गवासी हो जाते हैं, सौ सौ एकड़ जमीन उन की समाधि के लिए रखी जाती है। इस प्रकार समाधियों स्रौर कोठियों के लिए इतनी ज्यादा जमीन रख कर सरकार देश को भुखामारने की चाल चल रही है।

सरकार ने जो जोनल स्कीम बना रखी है, जिस के मातहत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गेहूं नहीं जाता है, में समझता हूं कि वह स्कीम ख़रम हो सकती है। ग्राज फ़सल निकल रही है। जो पूंजीपति चोर-बाजारी करता है, वह माज गेहूं ग्रीर ग्रनाज का भंडार कर लेगा स्रौर थोड़े समय के बाद वह सरकार की आंख में ऐसी धूल डालेगा, न मालूम क्या जादू चलायेगा कि वह ग्रनाज चोर-बाजारी से बेच देगा । मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि उस ने जो पाबन्दी लगा रखी है, वह ख़त्म की जा सकती है। कैसे? जो पूंजीपति म्राज म्रनाज का भंडार करता है, उस की कीमत ग्रौर उस पर होने वाली कास्ट गिन ली जाये भ्रौर जब तक वह भ्रनाज सम्भाल कर रखा जाये, उस रकम का तब तक का सूद गिन लिया जाये। उस के बाद वह जहां भी उस का जी चाहे, जा कर बेचता है, तो उस की कीमत भीर कास्ट गिन कर उस को मुनाफ़ा दिया जाये। इस तरह सरकार ने जो पाबन्दी लगा रखी है, वह खारम हो सकती है।

में कुछ सुझाव दे कर बैठ जाना चाहता हूं। जलहीन जमीन को कैनाल ग्रौर ट्यूबवैल से पानी मिलना चाहिए। ट्रैक्टर ग्रीर ट्यूब-वैल के लिए डीजल ग्रौर बिजलो भो सस्ते मृल्य पर मिलनी चाहिए। जो जमीन म्राज खाली पड़ी हुई है, वह भूमिहोन किसानों भ्रीर बेरोजगार भ्रनुस्चित जातियों के लोगों को मिलनी चाहिए । किसान की जिन्स की पूरी क़ीमत किसान को मिलनी चाहिए, मिडलमैन को नहीं।

में भ्राप को धन्यवाद देता हूं।

RE: REPORTED CEASE-FIRE TALKS ON KUTCH-SIND BORDER—contd.

Shri Nath Pai: Mr. Deputy-Speaker, you were saying that the Prime Minister would be coming.

Mr. Deputy-Speaker: I have sent word.

Shri Nath Pai: Why has he not come so far?

श्री प्रकाशबीर शास्त्री (बिजनीर) : प्रधान मंत्री श्रा रहे हैं या नहीं ?

Mr. Deputy-Speaker: I have not yet received any message from him.

Shri C. Subramaniam: I may say that there is no statement to be made today.

Shri Nath Pai: This is complete disregard and contempt of the House. The request came from all sides of the House, not from one section only.

Mr. Deputy-Speaker: There is no statement to be made today.

Shri Nath Pai: We are not in a mood to be treated like this. We are utterly anxious to know what is happening. We made a request to you that the Prime Minister should be called.

श्री श्रोंकार लाल बेरवा : प्रश्नान मंत्री श्रा रहे हैं या नहीं ? हम कितनी इन्तजार करें?

Shri Nath Pai: Is this the way of treating the House? It did not come from the Opposition alone, but Congressmen joined in making the request.

Mr. Deputy-Speaker: I have sent word to him.

Shri Surendranath Dwivedy: You say there will be no statement. He must come and say something.

Mr. Deputy-Speaker: He has nothing to inform the House just now As soon as there is anything, he will inform.

Shri Ranga (Chittoor): Is it the policy of the Government not to consult the leaders of the Opposition?

Shri Kandappan (Tiruchengode): By not repudiating they are only confirming our suspicions.

Mr. Deputy-Speaker: As 600n as there is any information, it will be given to the House.

Shri Ranga: We want to know before anything happens.

Shri Surendranath Dwivedy: Whether it is there or not they have to say. So, what is the meaning of saying that there is no statement.

ं श्री झोंकार लाल बेरवा : मैसेज दिये हुए काफी देर हो गई है । हम कहां तक इन्तजार करें ? यह बहुत ग्रन्याय है ।

Shri Brij Raj Singh-Kotah: We would like to know what exactly the situation is.

Mr. Deputy-Speaker: Has he consulted the Prime Minister?

Shri C. Subramaniam: I have said that there is no statement to be made today.

Shri Surendranath Dwivedy: Something would happen. They will finalise it and make a statement tomorrow. We do not know what is going on. We want to know whether there has been any talk between the representative of the Government of Pakistan or any mediator and the Prime Minister or his representative, whether any talk is going on behind the back of Parliament, and whether they are agreeing to a cease-fire without the withdrawal of Pakistani troops from our territory.

Shri C. Subramaniam: This is very strange. We deal with the situation as it arises, and when it becomes necessary, a statement will be made.

Shri Nath Pai: May we know if he can assure us that no cease-fire agreement will be made with the aggressor which will involve giving away even an inch of our territory, which will depart from the solemn resolve of the House? What is preventing him from giving that assurance? It means that something wrong is happening. Why is he hesitating to give that assurance? It is not only the Opposition which is wanting, Congressmen are as much interested in it.

Shri C. Subramaniam: We will take care of the Congressmen.

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha): This matter is very serious and urgent, and I also share the anxiety and the distress of the other Members here, but I feel that it is not for the House to demand to know whatever the Government is doing. If the leaders of the Opposition are taken into confidence that should suffice. Otherwise in such a serious matter, if the Lok Sabha is to be taken into confidende, if the public is to taken into confidence, to carry on the defence of the country, it cannot be done, it should not be done, according to me. Of course, I share the anxiety and distress, but we should not be excited about it. I agree that the Opposition has a right, and that some of their leaders should be taken into confidence, and they should be informed of what is going on.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Subramaniam will convey the feelings of the hon. Members to the Prime Minister.

Shri Ranga: What is it you are conveying? Here is a member of the Cablnet who has received a message from the Prime Minister saying that no statement is going to be made. You have heard what some of our Members have already stated. We want the Prime Minister as well as this Government to clearly understand one thing, that the leaders of their party appart, the leaders of the Opposition have a right to be consult-

ed before any final decision is taken by this Government, whatever may be that decision. They should be consulted, and their advice should be given proper weight in their Cabinet counsels and thereafter alone they should reach decisions and then implement them. I do not know what they are going to do between now and tomorrow morning,—

श्री श्रोंकार लाल बेरवा : यह तमाम देश का सवाल है। ऐसा कोई काम श्राप न करें जिस से श्राप देश में मुंह दिखाने के काबिल न रहें।

Shri Ranga: —but, if anything is sought to be done between now and tomorrow morning when the House meets, then, I would like the hon. Minister who is present here to convey to the Prime Minister our wish that he should take expeditious steps to send for us and then consult us and afterwards take their own decision.

Mr. Deputy-Speaker: Shri K. N. Tiwary. Does the House like to sit beyond 7 O'clock, or till 7.30?

Shri Yashpal Singh: 7.30.

Mr. Deputy-Speaker: All right.

Shri Brij Raj Singh-Kotah (Jhalawar): We have been sitting here from this morning.

18.51 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS—contd.

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE—contd.

श्री क० ना० तिवारी: उपाध्यक्ष महोदय, में फूड एंड एप्रिकलचर मिनिस्ट्री की गिमांड्ज को स्पोर्ट करता हूं। साथ ही मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि श्रव तक हिन्दुस्तान की एप्रीकलचरल पालिसी में जो बात नहीं हुई वह इन्हों ने की है। इन्होंने प्राइस फिक्सेशन को श्रमल में लाया है, चाहे वह टैम्पोरेरी ही हो। उस का नतीजा यह हुआ है कि जो भाव

गिर जाया करते थे वे भाव इस साल नहीं गिरेबल्कि श्रन्न के भाव बराबर ऊंचे रहे हैं।

बहुत सी बातों में जाना मैं नहीं चाहता हुं। दो एक सुझाव ही मैं मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हं। भ्राज उत्पादन बढ़ाने का सवाल हमारे सामने है। कृषि का सम्बन्ध लोगों से श्राज से या पचास सौ बरस से नहीं है, वह बहुत पूराना है किसान को ग्राप के शहर वालों के लिये डिवेलेपिंग इंडस्ट्री के लिए, फौज के लिए, श्रीर तमाम उन लोगों के लिए जिनके पास जमीन नहीं है जो खेती नहीं करते हैं, जो उत्पादन नहीं करते हैं, ग्रन्न पैदा कर के देना होता है। ग्रन्न तथा दूसरी चीजें जो देश के लिए भ्रावश्यक हैं, वह किसान को देनी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, विदेशी मुद्रा जितनी हम इंडस्ट्री वगैरह से कमाते हैं उस का श्राधा हम एग्रिकलचर से कमाते हैं. फिर चाहे वह ज्यूट हो, शूगर हो, कैंशूनट हो या कोई दूसरी चीज हो। इसलिए किसान पर कितनी बड़ी रिसपांसिबिलिटी है इस को ग्राप बहत ग्रासानी से समझ सकते हैं।

श्रभी यहां का पापुलेशन 2.5 बढ़ रहा है श्रीर उसके साथ साथ हमारा एग्रीकलचर जो है वह तीन प्वाइंट बढ़ रहा है । इसके बारे में लोगों के दो मत हैं । एक मत तो यह है कि एग्रीकलचर से जितनी पैदावार श्राज हो रही है उससे ज्यादा नहीं होगी । दूसरा मत है कि इस से ज्यादा पैदावार हो सकती है मैं इसको ग्रापके सामने पढ़ देता हं:-

"...it is interesting to note the controversy as to whether agricultural production in India can at all increase as envisaged in the Five Year Plans. Prof. Arthuer Lewis for instance in his model of Indian Economic Growth (1955) assumed that even with the best of effort, food output in India can be raised only by a total of about 45 per cent in the 25 years between 1955 and 1980. A 45 per cent increase in populatoion

and 118 per cent increase in national income during the same period will however need an increase of 90 per cent in the volume of food supply as it was in 1955."

श्राग चल कर उनसे डिफर करता है फोर्ड फाउंडशन जो कहता है :

"But the Ford Foundation which inquired into the possibilities of increased food production in India holds a different opinion. According to them the average performance in productivity is low compared with other advanced countries of the world though the best in Indian agriculture compares very favourably with the best elsewhere."

उसके लिए जरूरत है जो हम लोग बारबार कहते हैं:

"The team therefore felt that pushing up the low performance to the high levels attained by some Indian farmers would be difficult of achievement, provided better techniques and implements were made available along with the intensive use of good seeds, manures and irrigation and these suggestions are already being carried out in selected areas and the results of the full implementation of this programme are awaited with interest..."

बराबर यह कहा गया है कि हमारे यहां पर इन सब चीजों को उपलब्ध करने की जरू—रत है। पानी ग्रीर खाद की सब की जरूरत है। गवर्नमेंट श्राफ इंडिया की जितनी पबलिकेशंज ग्राती हैं उन सब में ये बातें कहीं जाती हैं लेकिन डिफिकल्टी यह है कि लोएस्ट लेवल तक जाते जाते इनका इम्प्लेमेंटेशन नहीं हो पाता है। इसके दो कारण है। एक कारण यह है कि सामुदायिक विकास का जो विभाग है उसके हाथ में इसका इम्प्ले—मेंटेशन है ग्रीर जहां तक पालिसी का सवाल है, उसको बनाना एग्रीकलचर मिनिस्ट्री के हाथ में है। इसलिए मेरा सुझाव है कि

[श्री क॰ ना॰ तिवारी]

सेंद्रल गवर्नमेंट जो शंकर कमेटी मुकर्रर की थी उसकी जो रिपोर्ट थी, उसका इम्प्लेमेंटेशन होना चाहिये ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि एक सेंट्रल पालिसी होनी चाहिये। जब कोई सवाल हम लोग करते हैं तो कह दिया जाता है कि यह प्राविशल मैंटर है झीर जब प्राविशल मैंटर वह हो जाता है तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह लाचार हो जाती है। इस लिए सेंट्रल पालिसी एक होनी चाहिये। सेंट्रल सर्विस इसकी होनी चाहिये ताकि फूड के प्रोडक्शन के मामले में किसी तरह की कोई बाधा न पड़े।

ग्रब मैं जोंज के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। जब जोंज को समाप्त करने की मांग की जाती है ग्रीर कहा जाता है कि जोनल रेस्ट्रिकशंज को हटा दिया जाय तो कहा जाता है कि हम को बफर स्टाक करना है। हमें गेहं दो मिलियन टन ग्रधिक मिलने जा रहा है। दो मिलियन टन राइस हम को ज्यादा मिला है। इसी तरह से लास्ट यीग्रर के प्रोडक्शन से चार मिलयिन टन ग्रनाज ज्यादा पैदा होने की सम्भावना है। पी० एल० 480 में भी ग्राप इम्पोर्ट करने जा रहे हैं । जब म्राप बफर स्टाक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ग्रापको एक सुझाव देना चाहता हूं। पर एकड़ के पीछे ग्रेडिड लेवी ग्रगर लगा दी जाए तो जो मकसद ग्रापका है वह भी पूरा हो सकता है स्रौर जोंज को भी समाप्त किया जा सकता है । इससे कंट्री का इंटेग्रशन बहुत खतरे में पड़ गया है । महा-राष्ट्र, बम्बई, तथा दूसरे स्थानों के लोगों की हालत यह हो गई है कि कोर्स ग्रेंज पर भी ग्रगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, पल्सेज के ऊपर भी धगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि रेस्ट्रिकशंज न हो तो भी वे लगा देती हैं। इस वास्ते जब तक कोई सेंट्रल पालिसी नहीं होगी तब तक यह बीमारी दूर नहीं होगी। एक पार्ट के लोग दूसरे पार्ट से ग्रन्छी तरह से खायें भीर दूसरे हिस्से के लोग तकलीफ़ में रहे, यह चीज चलने वाली नहीं है । दूसरा इसका रिजल्ट यह होगा कि जब रेस्ट्रिकशंज रहेगी तो जहां सरपलस है वहां के किसानों को कम दाम मिलेंगे । कल मैंने सुना था एक पंजाब के एम० पी० को कहते हुए कि जो श्रापने प्राइस फिक्स की है उससे चौदह रुपये फी क्विंटल भाव गिर गया है फिर भी श्रापके पास वहां कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि श्राप उसको खरीद कर सकें ।। इसलिए मेरा सुझाव है कि जोनल सिस्टम को श्राप जल्दी से जल्दी हटा दें ।

कंट्रोल का भी सवाल है। प्राइस फिक्सेशन के लिए कोई साइंटिफिक बेसिस ग्राज पक नहीं निकाला गया है। यहां तक कि शूगर केन तक के लिए इतने बरस हो गए हैं फिर भी ग्रापके यहां कोई मैथड नहीं है। मेरा सुझाव है कि ग्राप जिस तरह से लेबर के लिए कास्ट ग्राफ प्रोडकशन फिगर्ज निकालते हैं ग्रीर उसके लिए जो मशीनरी है वैसी ही मशीनरी ग्रापकी यहां भी होनी चाहिये जिससे कि कास्ट ग्राफ प्रोडकशन जिले के स्तर से लेकर प्राविस के स्तर तक निकाली जा सके।

शक्कर के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस साल शक्कर का उत्पादन 31 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है जो कि पिछले साल से पांच लाख टन के करीब अधिक है। इंटरनल कंजप्शन आपकी 26 लाख टन होगी। करीब चार पांच लाख टन आप के पास चीनी बच जाएगी। इसको आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फारेन एक्सचेंज कमानी चाहिये।

लास्ट यीग्रर शूगर का जितना प्रोडकशन हुग्रा था उस पर वैंक्स ने 70 से 75 परसेंट तक एडवांस दिया था । यह कंट्रोल्ड कमोडिटी है । जब वैंक एडवांस करते हैं तब उसमें से मिल वाले ग्रोग्नर्ज को पैसे देते हैं । जब एड-वांस नहीं मिलता है तो ग्रोग्नर्ज जो केन सप्लाई करते हैं, उनका पैसा भी रूक जाता है । मेरा निवेदन यह है कि जो ग्रापका पांच लाख टन

ज्यादा प्रोडकशन हुन्ना है उस पर भी उसी हिसाब से पैसा बैंकों को देना चाहिये ताकि ग्रोग्नर्ज को मिल वाले पैसे दे सकें।

जो पुरानी मशीनें हैं जैसे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में हैं, नार्थ बिहार में है तथा दूसरी जगहों में हैं, उनके बारे में ग्रापकी पालिसी यह है कि इनको एक्सटेंशन वगैरह सब दिया जाए । लेकिन डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि कहीं फाइनेन्स में जाकर मामला रूक जाता है, कहीं कोई श्रीर कमी रह जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कहीं मामला रुके नहीं। उन को टाइम लगता है। जो सुविधा मिलनी चाहिये वह मिले जिस में समय से वह लोग म्रपना एक्सटेंशन कर सकें ग्रौर शुगर को ग्रच्छी तरह से तैयार कर सकें। ग्रगर ऐसा नहीं होता तो ग्रोधर्स को बड़ी तकलीफ होती है। ग्रगर यह एक्सटेंशन नहीं हुन्ना तो गन्नाखेतो में पड़ा रह जायेगा। 19 hrs.

श्रीमती गंगा देवी (मोहनलालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी प्रतीक्षा के बाद मुझे बोलने का समय मिला है, इसके लिये मैं श्रापका धन्यवाद करती हूं।

खाद्य समस्या कोई नई समस्या नहीं है। है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश को बराबर इसका सामना करना पड़ रहा है और तब से अभी तक खाद्याओं की कीमतें बराबर बढ़ती जा रही हैं। किन्तु सन् 1963-64 में जो समस्या उत्पन्न हो गई थी और जिस प्रकार के दृश्य हमारे सामने देखने में आये उनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर भी हमारे खाद्य मन्त्री ने बड़े परिश्रम और लगन के साथ देश में फैली उस अशान्ति को किसी हद तक शान्त किया है। इसके लिये मैं उनका धन्यवाद करती हूं। किन्तु चारों और से जो भुखमरी के समाचार आ रहे हैं उनको समाप्त करने का कोई उपाय अभी तक नहीं हम्ना है।

भारत एक विशाल देश है श्रौर इसका इतिहास बतलाता है कि यह एक कृषि प्रधान देश

रहा है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ इस देश में उत्पन्न होता है। ग्रम्न से लेकर फल, तथा जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं सभी देश के किसी न किसी कोने में पाये जाते हैं। देश के बटवारे के बाद देश की खाद्य समस्यापर बडाखराब प्रभाव पड़ा। पंचवर्षीय योजना की स्कीम रक्खी गई। लोगों को बड़ी श्राशा हुई कि पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजनाम्रों का समय निर्धारित होने से हमारी खाद्य समस्या घासानी से हल हो जायेगी । पहली पंचवर्षीय योजना में 361 करोड रु॰ जो कि प्रथम योजना की निर्धारित धन राशि का 17.4 प्रतिशत था. कृषि तथा खाद्य की उत्पत्ति में लगाया गया। इसके साथ 561 करोड़ रु० सिंचाई की स्कीमों में लगाया गया । भ्रन्य विभागों से भ्रधिक पैसा खाद्य तथा कृषि में लगाने का निश्चय सरकार कर रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 20 प्रतिशत रुपया कृषि तथा सिंचाई पर लगाया गया। इसी प्रकार 1718 करोड़ रु जो पूरी योजना का 25 प्रतिशत है कृषि भौर खाद्य मन्त्रालय की तीसरी योजना पर लगाया गया । काफी पैसा इस भ्रोर खर्च किया गया है किन्तू फिर भी उत्पत्ति में कुछ भ्रधिक प्रगति दिखाई नहीं पडती । दिन पर दिन खाद्य पदार्थों की कीमतें बढती चली जा रही हैं।

खाद्य समस्या को हल करने में सरकार ने विशेष दिलचस्पी और परिश्रम से काम किया किन्तु सरकार ने कृषि फसलों की कोई सही प्लैनिंग नहीं की है। इसी कारण इस विभाग पर सबसे अधिक पैसा भी खर्च हो रहा है किन्तु फिर भी कोई प्रगति नहीं हो रही है। आफिसर पर आफिसर बढ़ा दिये गये, दफ्तर बढ़ा दिये गये किन्तु सब कागजी काम बढ़ रहा है। यदि प्लैनिंग सही होती तो जो रुपये हम नए नए आफिस खोलने में, एग्रीकल्चर आफिसर, डायरेक्टर्स आदि की सैलरीज में खर्च करते हैं वह धन किसान को खाद, बीज सिचाई आदि साधन देने में खर्च कर सकते। यदि हम ऐसा करें तो किसान अपना कार्य अच्छी तरह करेगा

[श्रीमती गंगा देवी]

भौर ऋधिक से ऋधिक श्रन्न की पैदावार करके देगा।

हमने बड़े बड़े डैम बनाये, लाखों करोड़ों रुपये उनमें लगाये श्रीर लगाते चले जा रहे हैं। किन्तु किसान को उन से कोई लाभ नहीं। इतने रुपयों से यदि गांव गांव में ट्यूबवैल लगा दिये जाते तो किसान की पानी वाली परेशानी दूर होती श्रीर दुगुनी श्रीर चौगुनी फसल वह पैदा कर सकता था। श्राज भी यदि सरकार इस प्रकार का प्लान न बना पाई जिससे देश का प्रत्येक व्यक्ति दो समय भरपेट खाना खा सके, तो उसके सारे प्लान बेकार हैं।

ग्राज देश चारों श्रोर से शतुश्रों से घिरा हुन्ना है। हम बाहरी देशों से मन्न मंगाते हैं। उस पर देश निर्भर कर रहा है। यदि यह सब बाहरी खाद्य सामग्री भ्राना बन्द हो जाये क्या परिस्थिति हमारी यह एक गम्भीर प्रश्न हमारे सामने है। इस कारण मेरा सरकार से नम्म निवेदन है कि श्रन्य दूसरे सभी प्रोजैक्ट्स में श्रधिक धन न लगा कर कृषि इण्डस्ट्री पर पूरी ताकत लगाने, जिसकी इस समय श्रति श्रावश्यकता है। जिससे हमारा देश खाद्य समस्या में ग्रात्म निर्भर हो सके । दूसरी भौर तीसरा पंचवर्षीय योजनायें भी समाप्त हो गईं हैं किन्तु हम ग्रपने निर्धारित लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाये। तीसरी योजना के मन्त तक कृषि उत्पादन 105 मिलियन टन हो जायेगा, यह निश्चय था, पर भ्रांकड़ों से पता चलता है कि कृषि उत्पादन 90 मिलियन टन हो पाया है। यह उत्पादन लक्ष्य से काफी कम है। लक्ष्यपूर्ति नहीं हो पाई। जरूरत से ज्यादा पैसा भी खर्च हो रहा है श्रीर फिर भी उत्पादन जरूरत से काफी कम हो रहा है।

उत्पादन अपने लक्ष्य तक न पहुंचने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण जमीन उन लोगों को न मिलना, जो वास्तव में किसान नहीं

हैं ग्रर्थात् जो स्वयं खून पसीना बहा कर काश्त करता है जमीन उसको नहीं मिली। जमींदारी उन्मलन के बाद बड़ी बड़ी जोत की जमीनें स्रौर बंजर जमीनें भी उन लोगों को दी गई, जो बड़ी पुंजी वाले हैं। जो टैक्टर खरीद कर भ्रपनी जमीनें जुतवाते हैं। जो कल जमींदार थे, वे माज बड़े बड़े फार्मों के मालिक बन गये हैं । हम समाजवाद की बात केवल कहते हैं, किन्तु उस पर ग्रमल नहीं करते हैं। बड़े फार्म वाले जो उत्पादन करते हैं वह स्टोर में जमा हो जाता है। वह बाजार में नहीं जाता। या तो वह ब्लैंक से बिकता है या बाजार में उस वक्त जाता है जब कीमतें खब चढ जाती हैं। वे लोग तो इसी इन्तजार में रहते हैं कि कब मुल्य बढ़ें श्रीर कब वे गल्ला बेचें। इस प्रकार के समाज विरोधी तत्वों के कारण कई स्थानों पर गल्ले पर लुटमार मची। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार के एण्टी सोशल एलीमेंट्स को समाप्त करने के लिये उसे कोई सस्त कदम शीघ्र उठाना चाहिये । क्योंकि व्यापारी श्रीर बड़े स्तर का प्रोड्यूसर्स होडिंग ग्रीर ब्लैक करने में लगे हुए हैं। उन्हें पैसा चाहिये भले ही गरीब श्रादमी भूखों मर जाये। यदि सरकार कानुनी तरीके से शीघ्र ही इस प्रकार के एलिमेंट्स को समाप्त नहीं करेगी तो इस प्रकार के एजिटेशन बराबर होते रहेंगे।

यदि हम खेतिहर मजदूरों व भूमिहीन किसानों को जमीन दे देते तो देश को आत्म निर्मर होने में बड़ी सहायता मिलती। आज भी देश में बहुत बड़ी जमीन ऐसी पड़ी है जो जोतने और बोने योग्य है। किन्तु वह बेकार पड़ी है। कुछ जमीन उन लोगों के हाथ में है जो न जोत सकते हैं न बो सकते हैं। मेरे कहने का आभ-प्राय यह है कि जो जमीन बेकार घिरी हुई है और ऊसर है उस सब को फौरन भूमिहीन किसानों को दे देना चाहिये। सन् 1950 में उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून बना। उस कानून के अनुसार पड़ती, बंजर, ऊसर जमीन जो जुताई के काम में आ सकती थी वह

सब गांव सभा के मधिकार में दे दी गई। कानून में यह प्रतिबन्ध होते हुए भी कि उप-रोक्त भूमि का वितरण भूमिहीन श्रौर खेतिहर मजदूरों को देने में प्राथमिकता दी जायेगी. जमींदारी खत्म हुई, ग्राम पंचायतें भ्राई, फिर भी वह भिम उन्हीं ताकतवर सोगों के हाथों में चली गई है जिनके पास पहले थी। ग्राज यदि पूछा जाये कि कितने भूमिहीनों लोगों को ग्राम सभा की जमीन मिली तो उत्तर "ना" में मिलेगा। कहने का श्रिभन्नाय यह है कि म्राज जनतन्त्र भौर समाजवादी युग में भी सरवाइ-वल ग्राफ दि फिटेस्ट ग्रर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस की डारविन थिग्नरी ही ग्रमल में लाई जा रही है। हमारी ग्रो मोर फुड की पालिसी कहां गयी ? किसानों को जब तक साधन उपलब्ध नहीं होते तब तक हमारी स्कीम सफल नहीं हो सकती भौर हम भ्रपने

हमने सरकारी दक्तरों में कृषि विशेषज्ञों की संख्या खुब बढ़ा ली है, किन्तू फिर भी कृषि उत्पादन में हानिकारक तत्वों को हटाने के लिए इन विशेषज्ञों ने भ्रभी तक कोई उपाय नहीं निकाला है। कृषि की उन्नति करने के लिए ग्रन्छी जमीन, खाद, पानी ग्रौर उपयुक्त जलवाय की भावश्यकता है। सरकार ने इस समय दो संस्थाएं बनायी हैं, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन भौर फुड कारपोरेशन श्राफ इण्डिया ।

लक्य को प्राप्त नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : ग्राप बैठ जाएं, मैं दूसरे मेम्बर को बुलाता हूं।

श्रीमती गंगा बेवी : फूड कारपोरेशन किसानों से उनका भ्रनाज उचित मुख्य देकर लेगा और उसको जनता को सही दामों पर बेचेगा । यह बहुत बड़ा कार्य कारपोरेशन को सौंपा गया है। मगर यह मेरी समझ में नहीं श्राता कि यह कारपोरेशन मद्रास में क्यों खोला गया. दिल्ली में क्यों नहीं खोला गया जहां खाद्य ग्रीर कृषि मन्त्रालय के सभी दफ्तर हैं। यह कारपोरेशन यहां होना चाहिए या, या वह

उत्तर प्रदेश में होता जहां किसानों की संख्या ज्यादा है भीर सभी प्रकार का खाद्य उत्पादन वहां मिलता है । मद्रास में यह कार्पोरेशन सफल नहीं हो सकता।

of Food

उपाध्यक्ष महोदय : ब्रार्डर, ब्रार्डर, ब्राप रैंड जाएं। मिस्टर देशमुख ।

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Mr. Deputy-Speaker, Sir, while discussing these Demands for the Ministry of Food and Agriculture, I am conscious of the fact that what is uppermost in our mind now is Demands for Grants for this Ministry but what happens on the Kutch-Sind border. But I have a feeling whatever happens there has something to do with what happens on our fields and factories. Therefore spirit we are all concerned with the Demands of this Ministry as well.

I have no doubt that Shri maniam to agriculture is what fish is to water, but my fears are that he is more a Food Minister than an Agri-Minister. Therefore, culture moment we think of him as a Food Minister we think of a fish out water and we wish that something must be done to see to it that the sturdy peasant and the sharp intellect which Shri Subramaniam undoubtedly commands go to the benefit of agriculture more than to the Department of Food.

While discussing these Demands my fears are that this annual ritual threatens to be an annual sermon on the funeral of agriculturists. I am very sorry to say this, but the agriculturists of today have got this feeling that whatever be their fate, the politicians, the administration party in power, who have claimed that they stand by agriculture, when it comes to deeds, lagged behind. We want that everything that is possible should be done to strengthen the hands of the agriculturists. We on this side of House are prepared to go to

[Shri Shivaji Rao S. Deshmukh] length to strengthen the hon. Minister's hands to see to it that he does something useful for the agriculturists of India.

It has been stated that the White Paper which has been submitted as the policy decision of the Ministry of Food and Agriculture marks thing like a step ahead. I had also intervened then saying that it black things to say. I am sorry to say this, but it remains a fact that it has something to say about our policy decision on the pricing policy; it has something to say that they had established, what they call, a Jha Committee which was to recommend on an ad hoc basis what should the price fixation of wheat as support price. What is the decision of this Jha Committee? It is that the support price of wheat should range from Rs. 40 to Rs. 50 per quintal. These rates prevailed in this country twelve years back. How can we now imagine ourselves that the rates which prevailed twelve years back in the field of agriculture can have any 10ta of supporting the prices? We are yet to believe that the price support and the pricing policy should evolve round a principle of remunerative prices. When it comes to paying lipsympathy to the agriculturists. rival with each other and claim that we are for remunerative prices for agriculturists. But when the agriculturists look at us as to what remunerative prices are, we have to show h.m. twelve years back and say these constitute the support price.

We have also seen the unhappy spectacle that the prices of wheat in Punjab have fallen to the base, have even fallen beyond the so-called support prices and yet our Government, we find, is not in a mood to move. What for have they established the Food Trading Corporation? We expected that the Food Trading Corpo-

ration will support agriculturists on their procurement prices. nately, the Food Corporation is not in the picture in Punjab. It has headquarters in Madras and Madras we expect that they will support, leaving aside the distance, the agriculturists of Punjab. But we have seen that they are not in a mood to support the agriculturists of Punjab. Why this unhappy state of affairs has arisen is singularly because of our reluctance to abolish this zonal system. We have seen for two years the unhappy spectacle of artificially suppressing the foodgrains prices in Punjab, Uttar Pradesh and other surplus States and at the same time we have done nothing to see that the prices in deficit States do not rise beyond our The result is the Government was reluctant and the reluctance of the Government has resulted in sugarcane area being diverted to gur and the result is that the sugarcane production which Government boasted that it would rise to 30 lakh tons did not come up to even 25 lakh tons. How much had we gained? We would have gained four times in terms of foreign exchange had we exported sugar and had we not been pound foolish and penny wise then. So ours is the tragic story of failure after failure with no hope of success. If we are not to be drawn into that malady of wrong policy and if we are to take out agriculture and give it a push, give a shot in the arm, then nothing short of bold action will save our agriculture. If agricultural production increases to 82 million tons, we say our policy has given rise in agricultural production. If the production falls, then we seek nature's help and say that nature has been unkind to us and that is why the production has fallen. So, for all these 17 years, we have left agriculture to the nature. What sort of nature we have left it to? We have left it to the nature of our own self and not to the nature of mother's creation. We have year after year followed certain policies which we knew are not going

and Agriculture

to pay us dividends. That the cultivators in the surplus States stand to lose and the cultivators in the deficit State do not stand to gain because in the deficit States also they have got, what they call, the monopoly procurement price, the monopoly procurement system. For instance, the agriculturist in Maharashtra gets for his jowar Rs. 42 as the maximum price, not the support price, and the agriculturist in some of the other adjoining jowarproducing States gets as the price of jowar something which is uncomparable to what the agriculturist gets in Maharashtra.

Why is this distinction between the agriculturist of one State and the agriculturist of another State? Why is this distinction between the agriculture of one State and the agriculture of another State when we claim that the subject agriculture and the pricing policies are definitely guided by the principles which emanate from Delhi? So, all the ills of agriculture today in India are due to our Central authority and those ills are precise because of our reluctance to enforce the Central authority or the federal authority. If today we have seen the unhappy spectacle of Centre's not working in the State, it is because the Centre does not want its writ to work in the State. If we want our writ to work in the State, we must see that our writ should have certain relations with India's existing conditions in agriculture today.

Now, for instance, coming to sugar, we had the unhappy spectacle of the Deputy Minister of Food stating that when the international price of sugar was 105 pounds per ton, we were not in a position to export sugar. Why were they not exporting sugar? It is because one year back. when this House demanded unanimously that Rs. 2 should be the minimum price per maund of sugarcane with 9 per cent recovery, And yet we have foolishly insisted on those policies. Those policies have been ad hoc. have never thought how scientifically the cost of production could be work-

ed out. We have established an Agricultural Prices Commission, and my congratulations are definitely due to the hon. Minister for having set up that commission. But after establishing that commission, Government have carefully seen to it that agriculturists are miles apart from the commission. is just like having a butchers' commission on the prevention of cowslaughter. I think that we should have seen to it that agriculturists are not only adequately represented but more than adequately represented on the Agricultural Prices Commission, because this commission has something to do with agriculure. When we say that we should also look to the consumers' interests, we should not do so at the expense of the agriculturists, but unfortunately that what we are doing.

Take, for instance the position in regard to cotton textiles. The Cotton Textile Advisory Board has taken a firm decision that whatever should be the ceiling price of cotton should be the floor price of cotton and the ceiling should be removed, but in name of the consumer Government are reluctant to agree to this; they say that if this decision is put into effect it would mean that the consumer would have to pay more. But we have seen the spectable of our Finance Minister abolishing excise duty coarse and medium cloth to the extent of 50 per cent in the hope that the prices of cloth will come down and that the consumer will benefit, but what has actually happened is that on the next day, in the next breath, another Minister increased the index price on the basis of which cotton prices were calculated, and the result was that the textile prices had gone up by 30 per cent instead of falling by even a paisa. I am afraid that all our economic policies are geard only to one interest, and that interest is to safeguard the interests of the private capitalists and private monopolists. If the hold of the private monopolists is to be broken, then we must take courage to see that the monopolists

[Shri Shivaji Rao. S. Deshmukh] and the profiteers are not allowed to tamper with the problems of agriculture and that the agricultural problems are dealt with only by those who know something about agriculture, and by a Minister who is well conversent with it. If this could expected from the present Minister of Food and Agriculture, from who are we to expect this? The country looks to Shri C. Subramaniam for a lead in the field of agriculture, and the country is anxiously waiting to hear from h's mouth what specific help he wants in the formulation of the Fourth Plan in this regard.

We see that 23 per cent of the funds are earmarked for agriculture in the Fourth Plan. When we know that 50 per cent of our income comes from agriculture and 50 per cent of our export earnings come from agriculture, we find at the same time that only a paltry sum of 23 per cent of the total outlay on the Plan has been earmarked for agriculture. If the hon. Minister is going to sit with tight lips and he is going to do nothing to increase this, then I would submit that that is a sorry spectable which this House would not like to see enacted.

Therefore, I would urge that the hon. Minister should do everything possible to see that agriculture makes a breakthrough, and that agriculture ir India proceeds on the scientific lines on which we want it to proceed.

Shri Brij Raj Singh-Kotah: I am very grateful to you for giving me this chance to speak....

श्री यशपाल सिंह (कैराना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर एक वंटे का समय श्रीर बढ़ा दिया जाय । इस पर समय बढ़ना चाहिए यह तमाम हाउस की राय है इसलिए इस पर एक वंटे का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव मैं सदन के सामने पेश करता हूं।

Some hon. Members: We can sit

Shri S. C. Samanta (Tamluk): May I point out that there is no quorum in the House? How can the time be extended without quorum?

Mr. Deputy-Speaker: The count is being taken.

Shri Brij Raj Singh-Kotah: I am very grateful to you, for at last I have caught your eye, and tired as we all are, I am sure.....

Shri S. C. Samanta: I am pressing for quorum.

Mr. Deputy-Speaker: The quorum has been challenged.

The hon. Member may now resume his seat.

The quorum bell is being rung-

There is no quorum. The House stands adjourned till 11 A.M. to-morrow.

19.26 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April, 30, 1965/Vaisakha 10, 1887 (Saka).